कुलदिप नायर

बनाम

भारत संघ और अन्य।

22 अगस्त, 2006

[न्यायमूर्तिगण वाई. के. सभरवाल, सीजे , के. जी. बालाकृष्णन, एस. एच. कपाडिया,

सी. के. ठाकर और पी. के. बालासुब्रमण्यन]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; एस. 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 & 20 / लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। 3 , 59 , 94 और 128 संशोधन के साथ 2003 का अधिनियम 40/भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 19, 55, 66, 80, 249, 251, 324, 327, 368 और 379; संघ सूची की प्रविष्टि 72 और इसकी दसवीं अनुसूचीसंविधान/भारत सरकार अधिनियम, 1915, 1919 और 1935/लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम; नियम 7, 8, 364, 365, 367 और 367 ए, 367 बी/लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम।राज्यों की परिषदः नियम 7, 252, 253 और 254:

राज्य परिषद के लिए चुनाव–पात्रता–प्रतिनिधित्व किए जाने वाले राज्य के अधिवास की आवश्यकता–आर. पी. अधिनियम से संशोधन द्वारा हटाना, 1951 – की संवैधानिकता–आयोजितः संविधान का विधायी इतिहास यह बताता है कि ऊपरी सदन के गठन के लिए निवास कभी भी संवैधानिक आवश्यकता नहीं रही है–निवास संघवाद की एक घटना है जिसे संसद द्वारा योग्यता के रूप में विनियमित किया जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत एक विषय वस्तु–इस प्रकार किया गया संशोधन, नहीं बदलता है। राज्यों की परिषद का चरित्र क्योंकि चुनाव कानून बना रहता है, निर्वाचित सदस्य राज्य का प्रतिनिधि बना रहता है और प्रतिनिधि चुनने के बारे में चुनाव और निर्णय राज्य के पास रहेगा। विधानसभाएँ–यह विशेष रूप से विधान के मामले में राज्य परिषद के सदस्यों की भूमिका, भविष्य के विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करता है केवल राज्य परिषद के चुनाव के लिए विचार का दायरा बढ़ाया गया है इसे संसद द्वारा अपनी विधायी क्षमता में पारित किया जाता है, संविधान के भाग–III के प्रावधानों या संविधान के किसी अन्य प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना, इसलिए असंवैधानिक नहीं है।

आर. पी. अधिनियम, 1951 में संशोधन–संघवाद का सिद्धांत–संघ का प्रभाव संशोधन–आयोजितः संविधान में प्रमुख संघीय सिद्धांत और इसकी बुनियादी विशेषताओं में से एक है लेकिन यह क्षेत्र से संबंधित नहीं है–यह आवश्यकता नहीं है [2 इस सिद्धांत का कि राज्यों का प्रतिनिधि उस राज्य से संबंधित होना चाहिए–यह मतदाता हैं जो राज्य के हित का प्रतिनिधित्व करेंगे।इसलिए, संसद द्वारा आवासीय योग्यता की आवश्यकता को हटाना संघवाद की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन नहीं होगा। यद्यपि निवास/अधिवास का प्रावधान 1951 के अधिनियम में मौजूद था, एक सांविधिक अधिनियम,

लेकिन यह संवैधानिक आवश्यकता नहीं थी, इसलिए संशोधन के माध्यम से इसे वहां से हटाना असंवैधानिक नहीं है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है।

राज्य के हितों की रक्षा में राज्य परिषद के सदस्यों की भूमिकाराज्य–आयोजितः वे संबंधित राज्य के आदेश पर संसद में मतदान नहीं करते हैं, बल्कि अपने स्वयं के विचारों और पार्टी संबद्धता के अनुसार मतदान करते हैं।

राज्य परिषद के सदस्य–आयोजित की जाने वाली योग्यताएँः प्रावधानसंविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्यों की परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता में अधिवास की आवश्यकता को नहीं जोड़ा गया है।

राज्य प्रतिनिधि–योग्यता के रूप में निवास–आयोजितः अनुपस्थिति मेंएक योग्यता के रूप में निवास की व्यक्त आवश्यकता, इसे पढ़ा नहीं जा सकता हैसंविधान के अनुच्छेद 80 और 84।

आर. पी. अधिनियम, 1951 में संशोधन करने में संसद की शक्ति–आयोजितः 1951 अधिनियम हैसंसद द्वारा किसी भी अन्य कानून की तरह अधिनियमित–इसलिए, संसद को किसी भी अन्य क़ानून की तरह इसमें संशोधन करने का अधिकार है।

चुनाव से संबंधित कानून को बदलने में संसद की शक्ति–आयोजितः द.संसद को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 80 (4) और 327 संविधान से।

' मतदान का अधिकार 'और' स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव–के बीच संबंध–आयोजितःमतदान का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का एक घटक नहीं है–वास्तव में, अधिकारमतदान एक ऐसी अवधारणा है जो स्वतंत्र और स्वतंत्र होने की प्राप्ति की अवधारणा को जन्म देती है।

निष्पक्ष चुनाव। राज्यों की परिषद के लिए चुनाव–बाहरी लोगों को अनुमति नहीं देने वाले प्रावधानचुनाव लड़ने के लिए, संसद ने वास्तव में चुनाव का विस्तार किया है अपने चरित्र को बदले बिना चुनाव।

गोपनीयता में मतदान का अधिकार–धारा 59, 94 में प्रावधान का प्रभाव जोड़ा गया और

148 आर. पी. अधिनियम, 1951 का एक अपवाद के रूप में खुले मतपत्र का प्रावधान

राज्यों की परिषद के चुनाव में गोपनीयता का नियम–आयोजितः ऐसा नहीं है।

सदस्यों के मतदान के अधिकार को प्रभावित करता है क्योंकि संविधान ने स्वयं कुलदिप नायर v प्रदान किया है।

यू. क्यू. आई.

3

गुप्त मतदान के माध्यम से चुनाव के लिए केवल वहीं जहां ऐसा करना उचित समझा जाता है–हालाँकि, जहां तक राज्यों की परिषद के चुनाव का संबंध है, यह चुप है।

चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करने और सलाह देने का अधिकार है।

चुनाव, लेकिन संसद प्रावधानों के संदर्भ में ऐसी सलाह से बाध्य नहीं है संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत।

गुप्त मतपत्र प्रणाली की वरीयता में खुली मतपत्र प्रणाली

संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता–आयोजितः यह नहीं हो सकता।

यह कहा जा सकता है कि खुली मतपत्र प्रणाली दसवीं अनुसूची के तहत विधान सभा के सदस्यों की अयोग्यता को उजागर करती है क्योंकि संविधान का वह हिस्सा अलग–अलग उद्देश्यों के लिए है।

संशोधन–गुप्त मतपत्र के बदले खुले मतपत्र प्रणाली की शुरुआत

प्रणाली–प्रभाव और औचित्य–आयोजितः खुला मतपत्र प्रणाली का मतलब यह नहीं है कि सभी के लिए खुला है–संशोधन के संदर्भ में, केवल राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को मतपत्र देखने की अनुमति है–हालाँकि,

मतदाता के पास यह चुनने का विशेषाधिकार रहेगा कि उसे अधिकृत अभिकर्ता को दिखाना है या नहीं, हालांकि मतदाता द्वारा अभिकर्ता को नहीं दिखाने की स्थिति में रद्द किया जा सकता है–इसके अलावा, जहां चुनाव आम चुनावों की तरह सीधे होते हैं, वहां गुप्त मतदान पर जोर दिया जा सकता है क्योंकि मतदाताओं की कोई पार्टी संबद्धता नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव के मामले में, खुली मतपत्र प्रणाली शुरू की जा सकती है क्योंकि यह केवल भ्रष्टाचार को खत्म करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और चुनावों की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक नियामक तरीका है–गोपनीयता का सिद्धांत एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है, विधायी संशोधन को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि अलग या बेहतर दृष्टिकोण है।

संभव है–हालांकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतपत्र की गोपनीयता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हालांकि, यदि गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाती है तो विधायिका के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे हटाने की क्षमता है।

मतदान का अधिकार–खुली मतपत्र प्रणाली उचित प्रतिबंध लगाना

संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के संदर्भ में–आयोजितः खुला मतपत्र प्रणाली राजनीतिक दलों में अनुशासन बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के हित में है–यह क्रॉस वोटिंग को भी रोकता है–इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के संदर्भ में उचित प्रतिबंध लगाने के बराबर है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसा करने से वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है क्योंकि राज्य विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को, जिसे उसने वोट दिया है, यह बताने के एकमात्र प्रतिबंध के अधीन राज्य परिषद को वोट देने का पूरी तरह से हकदार होगा।

सिद्धांतः

समकालीन व्याख्या का सिद्धांत–आयोजित की प्रयोज्यताः नहीं।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अप्रासंगिक के रूप में लागू।

शब्द और वाक्यांशः

' उम्मीदवार 'और' राज्यों '–चुनाव के संदर्भ में संबंध

राज्यों की परिषद को–चर्चा की गई।

' प्रत्येक का अर्थ–संविधान के अनुच्छेद 80 के संदर्भ में।

' सामान्य रूप से निवासी '–के संदर्भ में इसका अर्थ और प्रकृति

संवैधानिक प्रावधान।

' सामान्य निवास '–का अर्थ योग्यता के संदर्भ में

संसद के किसी भी सदन की सदस्यता।

राज्य का प्रतिनिधि '–जिसका अर्थ हैः शब्द हैं।

' राज्य के प्रतिनिधि का किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं है कि निर्वाचक/प्रतिनिधि भी संबंधित राज्य में पंजीकृत निर्वाचक/मतदाता होना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की हैं

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में, जिसके तहत राज्य परिषद में किसी व्यक्ति को निर्वाचित करने के लिए "अधिवास" की आवश्यकता को हटा दिया गया है। उन्होंने इसे संघवाद के सिद्धांत, संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी है; याचिकाकर्ता ने लोक प्रतिनिधित्व की धारा 59,94 और 128 में किए गए संशोधनों को भी चुनौती दी है।अधिनियम, 1951, जिसके तहत 'गुप्त मतदान' के

बदले में 'ओपन बैले सिस्टम' को राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव में पेश किया जाता है क्योंकि यह 'गोपनीयता' के सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सार के साथ–साथ मतदाताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान की मूल विशेषता और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार की विषय वस्तु का भी उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 3 में विवादित संशोधन

आर. पी. अधिनियम, 1951 संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान की मूल विशेषता है; यह गणराज्य के चरित्र को बदलने का प्रयास करता है जो कि हमारे लोकतंत्र की नींव; कि यह संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को विकृत करता है और इसलिए, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है; कि संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दिए गए कारण विवादित संशोधन के लिए किसी भी तर्कसंगत औचित्य का प्रावधान नहीं करते हैं; कि भारत संघ द्वारा, धारा 3 में संशोधन के लिए विवादित संशोधन को सही ठहराने के लिए हलफनामे में दिए गए कारण विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दिए गए कारणों से अलग हैं; कुलदिपनायार v.

0. 1 यू.

5

कि "राज्यों की परिषद" नाम संघीय चरित्र को इंगित करता है

सदन और एक प्रतिनिधि जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है और जो ऐसा करता है

भारत ने लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को अपनाया है जिसमें संघविधायिका एक द्विसामान्य विधायिका है, जो ऐसी विधायिका का प्रतिनिधित्व करती है –

राज्य के लोगों की इच्छा जिसका कारण द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना है

1951 लोकसभा और राज्य के इरादे और उद्देश्य में अंतर को हटा देता है। सभा; कि केवल यह तथ्य कि उल्लंघन के कई उदाहरण मौजूद हैं

निवास की आवश्यकताओं से संबंधित कानून एक वैध गठन नहीं कर सकता हैनिवास की आवश्यकता को हटाने का उद्देश्य या तर्कसंगत कारण; कि

संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 क्रमशः हमेशा एक अभिन्न योजना के हिस्से के रूप में पढ़ा गया है जिसके तहत एक

परिषद का प्रतिनिधि चरित्र; कि 'अधिवास' शब्द को हटाकर या 'निवास' या लेख में 'अधिवास' या 'निवास' शब्द को नहीं पढ़कर

80 (4) संविधान के अनुसार, प्रतिनिधि संघीय निकाय की मूल आवश्यकता समाप्त हो गई है; अधिवास की आवश्यकता इतनी आंतरिक है कि

राज्य परिषद की अवधारणा कि इसका हटाना न केवल संविधान के कामकाज को अलोकतांत्रिक बनाने वाली संवैधानिक योजना को नकारता है, बल्कि संघीय सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है; कि 1951 के अधिनियम की संशोधित धारा 3 और 4 के संदर्भ में, कोई भी व्यक्ति किसी विशेष राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा में जन प्रतिनिधि के रूप में चुना जा सकता है, भले ही वह किसी राज्य में पंजीकृत निर्वाचक हो।

किसी अन्य राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र; कि धारा 3 में आक्षेपित संशोधन द्वारा, राज्य परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता को लोक सभा के साथ "समान" किया गया है; कि आक्षेपित संशोधन ने राज्य परिषद की आवश्यक विशेषता को नष्ट कर दिया है क्योंकि एक व्यक्ति जो एक निर्वाचक है, और इसलिए एक सामान्य निवासी, भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, जो आवश्यक रूप से किसी विशेष राज्य का नहीं है, अब ऐसे राज्य का प्रतिनिधि होने के लिए चुना जा सकता है, केवल इस आधार पर कि वह ऐसे राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य परिषद के लिए इस तरह से चुना गया है; कि दूसरे सदन

की आवश्यकता है अर्थात। राज्य परिषद निरर्थक हो गई है, क्योंकि यह अब केवल लोक सभा की नकल है; कि विवादित संशोधन के परिणामस्वरूप, राज्य परिषद के लिए चुना गया व्यक्ति, यदि वह किसी का भी "प्रतिनिधि" है, तो वह केवल उस राज्य विधानसभा का प्रतिनिधि है जिसने उसे चुना था और राज्य का "प्रतिनिधि" नहीं है, क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होना आवश्यक था; कि संसद द्वारा अधिनियमित कानून को खड़े व्यक्ति के बीच कुछ संबंध निर्धारित करना था।

संविधान की मूल संरचना को मजबूत करने की प्रवृत्ति; किराज्यों की परिषद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुच्छेद 80 (4) में "प्रत्येक" शब्द का उतना महत्व नहीं था जितना कि "प्रत्येक राज्य" को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर जोर दिया गया है ताकि सदन को राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय का चरित्र दिया जा सके; कि अनुच्छेद 80 में विचाराधीन व्यक्ति को निर्वाचित होने से पहले राज्य का प्रतिनिधि होने की आवश्यकता होती है।

उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा; भारत में किसी विशेष राज्य विधानसभा द्वारा किसी "निर्वाचक" के चुनाव का मात्र तथ्य उस व्यक्ति को उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए "योग्य" नहीं बना सकता है; कि विवादित संशोधन वैकल्पिक अतिरिक्त योग्यता प्रदान करने में विफल रहा था, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक, जो भारत में कहीं भी रहता है, अब किसी भी राज्य विधानसभा द्वारा चुना जा सकता है, भले ही उसका निर्वाचक के रूप में पंजीकरण उस राज्य के बाहर हो; राज्य परिषद में होने वाली बहसों या प्रवचनों में उसकी उपयोगिता को इंगित करने के लिए कोई अतिरिक्त योग्यता प्रदान नहीं की गई है; कि विवादित संशोधन द्वारा एक "योग्यता" पेश की गई है जो कि कोई भी योग्यता नहीं है, और जिसका केवल यह अर्थ है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संसदीय मतदाता सूची में है।

अनुच्छेद 80 में "राज्य का प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति का उचित सम्मान है; कि आक्षेपित संशोधन गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है

मतपत्र प्रणाली को खोलना जो और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के गुट द्वारा उनकी अपनी उपलब्धि के लिए एक राजनीतिक कदम है; कि विवादित संशोधन संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं; कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारी राजनीति द्वारा अपनाए गए लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित एक अवधारणा है; संविधान के तहत चुनाव में मतदान करने का अधिकार।

भारत का, जिसमें राज्यों की परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव शामिल है, एक संवैधानिक अधिकार है, यदि एक मौलिक अधिकार नहीं है; कि वोट देने का अधिकार हमेशा वोट की गोपनीयता के अधिकार के साथ होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वोट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तविक है; कि तथ्य यह है कि विधान सभा द्वारा राज्यों की परिषद में सीटों को भरने के लिए चुनाव

राज्य की विधानसभा में 'मतदान' शामिल है, दसवीं अनुसूची के सिद्धांत आकर्षित होते हैं; कि दसवीं अनुसूची के अनुप्रयोग से ही पता चलता है कि 7

कुलदिप नायर "। यू. ओ. आई.

और संविधान और आर. पी. अधिनियम के प्रावधान भी; कि खुला मतपत्र प्रणाली, दसवें के तहत अयोग्यता के आसन्न खतरे के साथ मिलकर

अनुसूची चुनाव को व्हिप जारी करने वाले राजनीतिक दल तक सीमित कर देती है और

उम्मीदवार को शक्ति प्रदर्शन द्वारा चुना जाता है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को

राज्यों की परिषद में सीटों पर कब्जा करने वाले मनीबैग; कि अंतर्राष्ट्रीय

उपकरण "गुप्त मतपत्र" पर जोर देते हैं क्योंकि यह इसकी नींव रखता है

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना जो बदले में एक का गठन सुनिश्चित करता है

लोगों की सच्ची इच्छा दिखाने वाली लोकतांत्रिक सरकार; कि गोपनीयतामतदान हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा की पहचान रहा है।

इस प्रकार हमारी राजनीति में अपनाए गए लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए बहुत आवश्यक है; कि

यह हमारे संवैधानिक कानून की भावना है और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदंड भी है।

और इस संबंध में उससे कोई भी विचलन मौलिक पर निहित है

अधिकार, विशेष रूप से मतदाता द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; कि पवित्रता और

चुनाव की शुद्धता जहां मतदाता बिना किसी डर और पक्षपात के अपनी पसंद डालता है, केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब यह गुप्त मतदान द्वारा हो।

भारत, जिसे संविधान के तहत पूर्ण शक्तियां दी गई हैं

स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनावों का पर्यवेक्षण करें, गुप्त मतपत्र प्रणाली को बदलने के विवादित संशोधन का विरोध किया था, इसलिए इसका विचार उचित है

विवादित संशोधन लाया गया जो न केवल संशोधन को उचित ठहराने में विफल रहा लेकिन यह स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन की संवैधानिक योजना के विपरीत भी है

चुनाव।

भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि विवादित संशोधन बन गए

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के कार्यकरण में अनुभव की गई विभिन्न कमियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि ये संशोधन राज्य परिषद के चरित्र को नहीं बदलते या विकृत नहीं करते हैं; कि निवास की अवधारणा /

अधिवास संविधान के अनुच्छेद 84 (सी) के तहत योग्यता का विषय है जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाना है; कि विधान सभा के सदस्य यह तय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं कि राज्य परिषद में उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा; कि विवादित संशोधन द्वारा, योग्यता को और अधिक व्यापक बनाया गया है और गैर–प्रतिनिधित्व वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संशोधन आवश्यक हो गया है; कि राज्य परिषद के सदस्य के लिए निर्वाचक या उस राज्य का एक सामान्य निवासी होने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।

और, इसलिए, अनुच्छेद 80 के खंड (4) में दिखाई देने वाले "राज्य" शब्द में निवास की आवश्यकता शामिल नहीं है; कि मूल संरचना सिद्धांत क़ानूनों पर लागू नहीं होता है; कि संविधान किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं करता है। अनिवार्य आवश्यकता है कि निर्वाचित सदस्य 8 में एक निर्वाचक होना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

बता दें कि वह कहाँ से चुना गया है; कि कई व्यक्ति जिनकी उपस्थिति हो सकती है

राज्यों की परिषद में बहसों और कार्यवाहियों की गुणवत्ता को जोड़ते हुए, संशोधन से पहले की व्यवस्था के तहत, दूसरे राज्य में मतदाताओं के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए विवश किया गया था और जब तक वे ऐसा नहीं करते, राज्य ऐसे प्रतिभाशाली सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्वहीन रहेगा, और इस प्रकार, आवासीय प्रावधान से बाहर निकलने का उद्देश्य इस संबंध में मदद करना था; कि अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत संविधान एक नागरिक को अपनी पसंद का निवास चुनने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है; कि यह संसद की नैतिकता समिति द्वारा 1 दिसंबर, 1998 की अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचार के अनुसार था, "राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में क्रॉस वोटिंग की उभरती प्रवृत्ति" के मद्देनजर, फिर भी, खुले मतपत्र द्वारा चुनाव कराने के पीछे के सिद्धांत आगे बढ़ते हैं

दसवीं अनुसूची में संवैधानिक प्रावधान; और यह कि चूंकि अधिकांश उम्मीदवार पार्टी प्रणाली के तहत चुने जाते हैं, इसलिए यह सिद्धांत कि किसी पार्टी के निर्वाचित या नामित व्यक्ति को धन शक्ति द्वारा पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए लुभाया नहीं जाना चाहिए, हितकर और हितकारी है।

यह तमिलनाडु राज्य के लिए प्रस्तुत किया गया था कि सिद्धांत

' समकालीन व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 80 (4) में "प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि" शब्दों की व्याख्या के लिए प्रासंगिक है; कि

आर. पी. अधिनियम 1950 और 1951 स्वयं अस्थायी संसद के रूप में कार्य करने वाली संविधान सभा द्वारा बनाए गए समकालीन विधान हैं और वे संविधान के अनुच्छेद 79 और 80 की व्याख्या के लिए उपयोगी सहायक हैं, जैसे कि अधीनस्थ विधान एक अधिनियम की व्याख्या के लिए है; कि केवल एक राज्य से संबंधित व्यक्ति के पास उच्च सदन में राज्य का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होगी और यह कि एक व्यक्ति केवल जन्म, अधिवास से ही किसी राज्य से संबंधित होने का दावा कर सकता है।

या निवास; कि राज्य और उसका प्रतिनिधि बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के बीच कुछ दृश्य सांठगांठ संविधान की योजना में आवश्यक है; कि अनुच्छेद 80 (1) (बी) और (2) में "राज्यों के प्रतिनिधि" शब्द और अनुच्छेद 80 (4) में "राज्यों की परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि" शब्दों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि वे बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे।

संविधान की संरचना, इसके संघीय चरित्र को ध्यान में रखते हुए और 9

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई.

लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता।

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय नेपकड़नाः 1.1 . संविधान ने एक संघीय प्रणाली स्थापित की है

केंद्र में द्वि–कक्षीय विधायिका वाली सरकार जो कुछ नहीं है जिसे पहली बार संविधान में शामिल किया गया था। इसका इतिहास पुराना है।

1919 में भारत सरकार अधिनियम, 1915 में संशोधन किया गया। इसके तहत भी

भारत सरकार अधिनियम, 1919, के संबंध में निवास की योग्यता

विशेष निर्वाचन क्षेत्र को अनावश्यक माना जाता था। यह पद है

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के तहत जिसके तहत केंद्र में विधानमंडल द्वि–कक्षीय था। [42 – बी–सी]

1.2 . व्याख्या का नियम कहता है कि इरादे को समझने के लिए

यदि किसी प्रावधान के अधिनियमन के पीछे अस्पष्टता है और उसकी व्याख्या करने के लिए, किसी को ऐतिहासिक विधायी विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। [41 – एफ]

रीः 2002 [2002] 8 एस. सी. सी. 237 के विशेष संदर्भ संख्या 1 पर भरोसा किया गया।

1.3 . संविधान के पहले मसौदे के खंड 60 में कहा गया है कि सभी मामले महत्वपूर्ण हैं

संघीय के किसी भी सदन के चुनावों से संबंधित या उससे संबंधित

संसद को चौथी अनुसूची द्वारा विनियमित किया जाएगा, जब तक कि संघीय संसद के अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। हालाँकि, चौथी अनुसूची को मसौदा समिति द्वारा हटा दिया गया था। इसलिए, इस विलोपन के साथ, निवास की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। यह दर्शाता है कि निवास कभी भी संवैधानिक आवश्यकता नहीं थी। [43 – डी–ई–एफ]

1.4 . विधायी इतिहास से पता चलता है कि निवास की योग्यता यह कभी भी एक निरंतर कारक नहीं रहा। परिसंपत्तियों, आवास, आय, निवास आदि के स्वामित्व को समय–समय पर संदर्भ और जमीनी वास्तविकता के आधार पर योग्यता माना जाता था। योग्यता जोड़ने की शक्ति संघीय संसद को दी गई थी। इसलिए, विधायी इतिहास संवैधानिक अधिनियमों से पता चलता है कि निवास या अधिवास ऊपरी

सदन की संरचना और संरचना के आवश्यक तत्व नहीं हैं।1.5 . निवास योग्यता का विषय है। इसलिए, यह नीचे आता है

अनुच्छेद 84 संसद को समय–समय पर योग्यता निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।

तथ्य स्थिति के आधार पर समय तक। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, भारत में निवास एक संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान के संदर्भ में, निवास/अधिवास संघवाद की एक घटना है जो होने में सक्षम है

संसद द्वारा एक योग्यता के रूप में विनियमित जो सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. का विषय है।

5 एस सी आर।

10 संविधान का अनुच्छेद 84। [44 – जी–एच; 45–ए।

2.1 . हालाँकि राज्यसभा को एक कक्ष के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ

राज्यों और भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया जाता है, व्यवहार में, यह कार्य नहीं करता है

स्थानीय हितों के एक चैंपियन के रूप में। भले ही राज्य विधानमंडलों द्वारा चुने जाते हैं, इसके सदस्य संबंधित राज्य के आदेश पर मतदान नहीं करते हैं, लेकिन इसके अनुसार

उनके अपने विचार और पार्टी संबद्धता। [45 – ई–एफ. आई.

2.2 . भारतीय संघ को 'एक साथ रखने' के रूप में वर्णित किया गया है

संविधान निर्माताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्र, के 'एक साथ आने' के विपरीत

यू. एस. ए. और कनाडा परिसंघ के मामले में घटक इकाइयाँ। इसलिए, राज्यसभा के पास आकस्मिकता आधारित शक्ति निहित है।

अनुच्छेद 249 के तहत राज्य विधानसभाएं, जो भारतीय संघ की सरकार को 'अर्ध–संघीय' प्रकृति में योगदान देती हैं। [46 – डी–ई।

2.3 . अनुच्छेद 251 जब संविधान के अनुच्छेद 249 के साथ पढ़ा जाता है तो प्रावधान करता है

कि अनुच्छेद 249 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच विसंगति के मामले में, संघ कानून ऐसी विसंगति या 'प्रतिकूलता' की सीमा तक प्रबल होगा। वास्तव में यह प्रावधान राज्य सभा को राज्य सभा की निर्दिष्ट विधायी क्षमता का अतिक्रमण करने की अनुमति देता है।

किसी मामले को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके राज्य विधानमंडल। हालांकि इसे मूल संवैधानिक योजना में एक सुरक्षा के रूप में शामिल किया गया हो सकता है, यह शक्ति केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है।

राज्य सरकार का कार्यकरण, जो अक्सर केंद्र और राज्य स्तर पर विरोधी दल–संबद्धताओं के अस्तित्व से प्रेरित होता है।

[46 – एफ–जी–एच]

2.4 . भारतीय संविधान में संघवाद की प्रकृति अब नहीं रही है

समाकलन। इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि भारतीय मॉडल है

मोटे तौर पर शासन के संघीय रूप पर आधारित। [47 – ए–बी]

2.5 . हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत प्रमुख है और यह

सिद्धांत इसकी बुनियादी विशेषताओं में से एक है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारतीय संविधान के तहत संघवाद एक मजबूत केंद्र के पक्ष में है, एक ऐसी विशेषता जो मजबूत संघवाद की अवधारणा के खिलाफ है। [53 – डी–ई]

एस. आर. बोम्मई और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। , आकाशवाणी [1994] एससी (1918):

[1994] 3 इसके बाद एस. सी. सी. 1 आया।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। भारत संघ, [1964] 1 एससीआर 371; पुनः: के तहत

अनुच्छेद 143, भारत का संविधान, (1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1) एयर कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. आई.

11

(1965) एससी 745; कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. , [1978] 2 एससीआर

1 ; राजस्थान राज्य और अन्य। वी. भारत संघ आदि। आदि, [1978] 1 एस. सी. आर. 1; आईटीसी

लिमिटेड वी. कृषि उपज बाजार समिति और अन्य। , [2002] 9 एस. सी. सी. 232 और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। , आकाशवाणी (2005) एससी 1646: [2004] 10 एस. सी. सी. 201, पर भरोसा किया।

2.6 . भारत पारंपरिक अर्थों में एक संघीय राज्य नहीं है। वहाँ

तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है, और यह उद्देश्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दूसरी ओर, भारत के संदर्भ में, संघवाद का सिद्धांत क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत विभिन्न राज्यों के बीच समझौते द्वारा गठित एक सच्चा संघ नहीं है और क्षेत्रीय रूप से यह संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार के लिए खुला है, न कि केवल संविधान के प्रावधानों को बदलने के लिए।

सीमाएँ, लेकिन यहाँ तक कि एक राज्य को बुझाने के लिए भी। इसके अलावा, जब शक्तियों के प्रयोग की बात आती है, तो उन्हें केंद्र के पक्ष में भारी तौला जाता है। [55 – ई–एफ}

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। भारत संघ, [1964] 1 एस. सी. आर. 371, संदर्भित। 2.7 . संविधान केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान करता है।

लोक सभा का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। राज्य परिषद का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य के मतदाता यह तय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं कि राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, चाहे वह निचले सदन के सदस्य के रूप में हो या ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में। [55 – जी]

2.8 . यह संघीय सिद्धांत का हिस्सा नहीं है कि राज्यों के प्रतिनिधि

उस राज्य से संबंधित होना चाहिए। संघवाद की एक आवश्यक विशेषता के रूप में ऐसा कोई सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। [55 – एच; 56–ए]

2.9 . यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि जब तक राज्य को होने का अधिकार है

राज्यों की परिषद में इसके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो देश के नागरिक हैं, संघवाद प्रभावित नहीं होता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि ऊपरी सदन की सदस्यता के लिए आवासीय आवश्यकता सभी संघीय संविधानों की एक अनिवार्य बुनियादी विशेषता है। इसलिए, यदि भारतीय संसद ने अपने विवेक से आवासीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो वह

निश्चित रूप से संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन नहीं करता है। हमारा संविधान केवल इसलिए एक संघीय संविधान नहीं रह जाता है क्योंकि एक राज्यसभा सदस्य उस राज्य में "सामान्य रूप से निवास नहीं करता है" जहाँ से वह चुना जाता है।

[62 – जी–एच; 63–ए]

3.1 . यह अच्छी तरह से तय है कि कानून को अमान्य घोषित किया जा सकता है या

केवल दो आधारों पर असंवैधानिक, अर्थात् (i) विधायी क्षमता की कमी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी.

5 एस सी आर।

12

और (ii) किसी भी मौलिक अधिकार या संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन।

[65 – बी]

श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, [1975] सप एस. सी. सी. 1, पर भरोसा किया।

3.2 . हमारे संविधान के संदर्भ में 'बुनियादी विशेषता' का सिद्धांत,

साधारण विधान पर लागू नहीं होता है जिसके लिए केवल दोहरे मानदंड हैं;

कि यह अपनी क्षमता के भीतर किसी मामले से संबंधित होना चाहिए; और यह कि यह अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध या एक स्पष्ट संवैधानिक निषेध के प्रतिकूल होने के रूप में अमान्य नहीं होना चाहिए।

[68 – एच; 69–ए–बी]

कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. , [1977] 4 एससीसी 608,

पीछा किया।

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। वी. मैकडॉवेल एंड कंपनी एंड ओआरएस। ,

[1996] 3 एस. सी. सी. 709 और लोक सेवा न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य , [2003] 4 एस. सी. सी. 104, पर भरोसा किया।

3.3 . मूल संरचना सिद्धांत की शक्ति पर सीमा लागू होती है

संविधान की संरचना। एक साधारण कानून को इतना चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर संसद द्वारा अपनी विधायी क्षमता के भीतर बनाए गए कानून को चुनौती याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। चूंकि संसद के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से 'निवास' संवैधानिक आवश्यकता नहीं है, इसलिएबुनियादी संरचना के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। [69 – सी–डी

2002 की विशेष संदर्भ संख्या 1 (गुजरात विधानसभा) के मामले में

चुनाव मामला), [2002] 8 एस. सी. सी. 237 पर भरोसा किया गया।

4.1 . यदि समकालीन प्रदर्शनी का सिद्धांत इसके लिए प्रासंगिक है

अस्थायी संसद के रूप में कार्य करने वाली संविधान सभा द्वारा बनाए गए समकालीन विधान के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 80 (4) में "प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि" शब्दों की व्याख्या करना, जैसा कि अधीनस्थ विधान का उपयोग मूल अधिनियम का अर्थ निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर, इस विषय पर उपरोक्त दृष्टिकोण की भ्रांति इस तथ्य में निहित है कि – अस्थायी संसद ने संवैधानिक शासन नहीं बनाया। इसमें संवैधानिक कानून की पवित्रता या मानक मूल्य नहीं है। [75 – सी–डी–ई]

यू. पी. और अन्य का राज्य। वी. बाबू राम उपाध्याय, [1961] 2 एससीआर 679 (सीबी);

देशबंधु गुप्ता एंड कंपनी एंड ओआरएस। वी. दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. 1.

13

लिमिटेड, [1979] 4 एस. सी. सी. 565; तमिलनाडु राज्य बनाम। एम/एस। हिंद स्टोन और ओआरएस। , [1981] 2 एस. सी. सी. 205 और आयकर आयुक्त, जालंदूर बनाम। अजंता इलेक्ट्रिकल्स,

पंजाब, [1995] 4 एस. सी. सी. 182, पर निर्भर था।

4.2 . "समकालीन प्रदर्शनी" का सिद्धांत पूरी तरह से अप्रासंगिक है यदि

वर्तमान उद्देश्यों के लिए गुमराह नहीं करना। यदि संविधान ने एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति का उपयोग किया था, जिसमें व्याख्या की आवश्यकता थी, तो किस तरीके से

संसद अपनी विधायी क्षमता के भीतर काम कर रही थी। यह सच है कि 1951 में अस्थायी संसद ने राज्य परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता के रूप में राज्य के अंदर निवास निर्धारित किया था। लेकिन यह भी होना चाहिएयह ध्यान में रखते हुए कि उसी संसद ने संविधान सभा के रूप में अपने चरित्र में योग्यता (निवास सहित) को संवैधानिक आवश्यकता के लिए बढ़ाने से इनकार कर दिया था और बल्कि इस बात की चेतना दिखाई थी कि योग्यता के प्रावधान पर समय–समय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है और इसलिए, इसे संविधान में ही निर्धारित करना अनुचित लगता है।

[75 – एफ–जी–एच]

4.3 . विवादित संशोधन से पहले निवास का प्रावधान मौजूद था,

एक संसदीय कानून, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में, लेकिन संविधान में ही योग्यता के रूप में निवास की आवश्यकता का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस चीज के लिए संविधान ने स्वयं प्रावधान नहीं किया था, उसे हटाने के लिए अधिनियम में संशोधन करना असंवैधानिक है। [76 – ए–बी]

5.1 . आर. पी. सहित अस्थायी संसद द्वारा पारित सभी अधिनियम

अधिनियम 1951, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य कानून की तरह कानून हैं। तदनुसार, उनमें से प्रत्येक किसी भी अन्य क़ानून की तरह संशोधन लाने के लिए संसद की शक्ति के अधीन है। [76 – सी]

5.2 . यह प्रस्ताव कि संविधान और आर. पी. अधिनियम हालांकि गठन करते हैं

चुनावों की एक एकीकृत योजना, लेकिन इसका पालन नहीं होता है कि इस कारण से आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 3 में अधिवास की आवश्यकता को एक संवैधानिक आवश्यकता के रूप में माना जाना चाहिए। [76 – ई।

6.1 . अनुच्छेद 80 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "राज्यों के प्रतिनिधि"

और संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक (डी) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "राज्यों का प्रतिनिधित्व" समानार्थक या उसी अर्थ में नियोजित नहीं है। ये अभिव्यक्तियाँ भौतिक रूप से अलग हैं और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. में अलग–अलग संदर्भों में उपयोग की जाती हैं।

5 एस सी आर।

14

दोनों प्रावधान। यह इस सरल तथ्य से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद में राज्यों के "प्रतिनिधियों" की बात कर रहा है, जबकि परंतुक (घ) –

अनुच्छेद 368 (2) संसद में राज्यों के "प्रतिनिधित्व" से संबंधित है। पहला प्रावधान सीमित आयात का है जबकि बाद वाले का व्यापक अर्थ है। अनुच्छेद 4 "संसद में प्रतिनिधित्व" अभिव्यक्ति का भी उपयोग करता है। यह विशेष रूप से अनुच्छेद 2 और 3 में विचार किए गए ऐसे संशोधनों को शामिल नहीं करता है –संवैधानिक संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया की आवश्यकताएँ। अतः अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान (घ) में उपयोग की गई "संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व" अभिव्यक्ति का संसद के लिए कोई उपयोग नहीं हो सकता है।

याचिकाकर्ताओं का मामला। [77 – जी–एच; 78–ए; जी–एच]

6.2 . संविधान की चौथी अनुसूची व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करती है

जो राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। विभिन्न राज्यों के बीच यह संतुलन विवादित कानून के माध्यम से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है।

रिट याचिकाएँ क्योंकि विवादित अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन केवल 'प्रतिनिधियों' की आवासीय योग्यता से संबंधित हैं और संसद में 'राज्यों के प्रतिनिधित्व' से संबंधित नहीं हैं। [80 – जी–एच]

7.1 . अनुच्छेद 79 इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि लोक सभा

और राज्य परिषद दोनों संसद के "सदन" हैं। दिए गए नाम दोनों सदनों के लिए उचित संज्ञाएँ हैं और संविधान के अनुच्छेद 84 (सी) के तहत संसद की विधायी शक्ति पर बहुत कम सीमाएँ, किसी भी अधिकार या दायित्व को नहीं बताते हैं। [82 – जी–एच]

7.2 . निर्वाचक को निर्वाचन क्षेत्र का एक सामान्य निवासी होना चाहिए।

जिसे वह वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत है

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 और 20। कानून में यह कोई आवश्यकता नहीं है कि निर्वाचित व्यक्ति के पास निर्वाचक के समान योग्यता होनी चाहिए।

के पास है। संविधान की योजना से यह और भी स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 171 (3) से स्पष्ट है। [96 – एफ–जी]

7.3 . "सामान्य निवासी" का प्रश्न तैयारी के लिए प्रासंगिक है।

मतदाता सूची और आगे कुछ नहीं। आर. पी. अधिनियम, 1950, विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 13 डी, 14, 15, 17, 18, 19 और 20 में निहित प्रावधानों की योजना को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है। मतदाता सूची मूल रूप से विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार की जाती है और वर्षवार संशोधित की जाती है। एक संयोजन

धारा 17, 18, 19 और 20 को पढ़ने से पता चलता है कि एक व्यक्ति केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक बार मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकता है।जिसके भीतर वह एक साधारण निवासी है। [97 – एफ–जी–एच]

7.4 . कुलदिपनायार v के लिए "सामान्य निवासी" की योग्यता प्रदान की गई है।

यू. ओ. एल

15

योजना, संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रीय रूप से विभाजित हैं और इसलिए क्षेत्रीय संपर्क मतदाता के लिए प्रदान किया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से उम्मीदवारों के लिए नहीं। [98 – डी]

पंपकवी रायप्पा बेलागल बनाम। बी. डी. जट्टी और अन्य। , [1971] 2 एससीआर 611,

पर भरोसा किया।

7.5 . विवादित संशोधन से पहले की व्यवस्था, निर्धारित करने के लिए

इस तरह की घोषणा की शुद्धता विवादित है, चुनौती देने वाले को इसके विपरीत तथ्यों को दिखाने वाले ठोस सबूत के साथ खुद को तैयार करना चाहिए। इस परिदृश्य में, घोषणाएं जो इसके निर्माताओं की जानकारी के लिए गलत थे, ऐसा लगता है कि उनका निर्लज्जता से और दंड से मुक्ति के साथ उपयोग किया गया था। [111 – जी–एच; 112–ए]

7.6 . संसद ने अपने विवेक से इसे समाप्त करने का फैसला किया है

राज्य परिषद में किसी विशेष राज्य के प्रतिनिधि के रूप में एक सीट को भरने के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्यता के रूप में अधिवास की आवश्यकता, गलती नहीं हो सकती है

संसद के ऐसे निर्णय के साथ इस आधार पर पाया जाए कि "सामान्य रूप से निवासी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ था, इसे परिभाषित करने में कठिनाई एक ईमानदार आधार नहीं था। संविधान या कानून में किसी भी समय ऐसा कुछ भी नहीं था जो अधिवास की आवश्यकता को महत्वपूर्ण योग्यता के रूप में प्रस्तुत करता हो। विशेष रूप से राज्य परिषद के उद्देश्य। जबकि विवादित संशोधन पर इन कारणों से हमला नहीं किया जा सकता है, अधिवास को समाप्त करना

आवश्यकता हमेशा जवाब नहीं हो सकती क्योंकि यह विधानमंडल और केंद्र सरकार का दायित्व बना रहेगा कि वे "साधारण निवासी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है, इसे सटीक रूप से परिभाषित करें क्योंकि वह बनी रहेगी।

किसी विशेष राज्य में निर्वाचक के रूप में किसी व्यक्ति के पंजीकरण के लिए कोई शर्त नहीं

निर्वाचन क्षेत्र और इस प्रकार एक ऐसा विषय जिससे कोई पीछे नहीं हट सकता। यह आशा की जाती है कि चुनावों से संबंधित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इसके उचित अनुप्रयोग के उद्देश्यों के लिए संसद और केंद्र सरकार उक्त अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

[112 – सी–डी–ई]

7.7 . संबंधित सीमा तक योग्यता के मामले में समानता

किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक व्यक्ति का निवास एक सदन को दूसरे का डुप्लिकेट न बनाएँ। उनकी भूमिका, कार्य, शक्तियाँ या 16

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

विशेषाधिकार, विशेष रूप से कानून के मामले में, अपरिवर्तित रहते हैं।

[83 – ए]

8. "राज्य" शब्द से पहले "प्रत्येक" शब्द का प्रयोग,

राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व का संदर्भ केवल इस तथ्य को रेखांकित करता है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा का उद्देश्य चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट विशेष राज्य को आवंटित सीट को भरने के लिए एक सदस्य को वापस करने के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल होना था। न कुछ अधिक और न कुछ कम। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक है कि अभिव्यक्ति

" राज्यों के प्रतिनिधि पहले ही दो बार आ चुके हैंअनुच्छेद 80 के पूर्ववर्ती खंड। अनुच्छेद 80 (5) में भाग सी राज्यों (अब केंद्र शासित प्रदेश) के संदर्भ में "प्रत्येक" शब्द का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि मूल रूप से प्रदान किया गया था या बाद में संशोधित किया गया था, क्योंकि प्रतिनिधित्व का तरीका

भारत संघ की ऐसी इकाइयों को संसद द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया था और क्योंकि ऐसी प्रत्येक इकाई का उस समय अपनी विधान सभा प्रदान करने का इरादा नहीं था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि शब्द का उपयोग " अनुच्छेद 80 (4) में प्रत्येक सदन को राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय का चरित्र देता है। [89 – ए–बी–सी–डी]

9. अधिवास की योग्यता के बीच एक भौतिक अंतर था

राज्य परिषद के लिए निर्धारित विशेष राज्य के भीतर और भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अधिवास की योग्यता, जैसा कि लोक सभा के लिए निर्धारित किया गया है। 11 मई 1951 को विधेयक पर विचार के समय यह अस्थायी संसद में बहस का विषय था, जो बाद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का रूप ले लेगा। उक्त बहस के दौरान यह असंगत बताया गया कि राज्य परिषद के उम्मीदवार को संबंधित राज्य का निवासी क्यों होना चाहिए, जबकि लोक सभा के उम्मीदवार को केवल देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। [92 – एफ–जी।

10.1 . एक व्यापक और उदार निर्माण देना वांछनीय हो सकता है

संवैधानिक प्रावधान, लेकिन ऐसा करते समय "सादा अर्थ" या "शाब्दिक" व्याख्या के नियम, जो "प्राथमिक नियम" बना हुआ है, को भी ध्यान में रखना होगा। वास्तव में "शाब्दिक निर्माण" का नियम सुरक्षित नियम है जब तक कि उपयोग की जाने वाली भाषा विरोधाभासी, अस्पष्ट या वास्तव में बेतुके परिणामों की ओर न ले जाए। [94 – डी–ई]

जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेल्वम और अन्य। , [1972) 3 एससीसी 717,

पीछा किया।

10.2 . कुलदिप नायर बनाम के प्रावधानों में कोई विरोधाभास, अस्पष्टता या बेतुकी बात नहीं पाई गई है।

यू. ओ. आई.

17

विवादित संशोधन के परिणामस्वरूप कानून का। यह समझते हुए भी कि

संविधान और आर. पी. अधिनियमों के प्रावधान व्यापक या सबसे अधिकउदार तरीके से, और "सादा अर्थ" या "शाब्दिक" के नियम का पालन करना।

व्याख्या, याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

[94 – एच; 95–ए]

11.1 . राज्य का प्रतिनिधि उतना ही संसद का सदस्य होता है

जैसा कि लोक सभा का एक सदस्य है। अभिव्यक्ति "प्रतिनिधि"

लोक सभा के संदर्भ में समान रूप से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कोई

'सदस्य' और 'प्रतिनिधि' अभिव्यक्तियों के बीच अंतर। इसलिए,

यह याचिका कि लोक सभा के संबंध में उपयोग किए गए शब्द "सदस्य" के विपरीत राज्य परिषद के संबंध में "प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति का चयन प्रमुख है, खारिज कर दिया जाता है। [86 – बी–सी]

11.2 . उनके स्पष्ट अर्थ दिए जाने पर, शब्द "प्रतिनिधि"

अनुच्छेद 80 (1) (बी), अनुच्छेद 80 (2) और अनुच्छेद 80 (4) में राज्यों के

उन व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए व्याख्या की जाती है जो राज्य परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं। यह वह चुनाव है जो व्यक्ति को चुना जाता है

" प्रतिनिधि "। राज्य परिषद में निर्वाचित होने के योग्य होने के लिए, किसी व्यक्ति को पहले राज्य का प्रतिनिधि होने की आवश्यकता नहीं है। जब वह राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है तभी वह राज्य का प्रतिनिधि बन जाता है। जिन्हें निर्वाचक मंडल द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है,

जिसका वर्तमान प्रयोजनों के लिए अर्थ है कि राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, अनिवार्य रूप से राज्य के "प्रतिनिधि" हैं।

[95 – बी–सी]

11.3 . संसद का प्रत्येक सदस्य "राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत" होना चाहिए।

अनुच्छेद 80 (1) (ए) के तहत, या अनुच्छेद 80 (4) और (5) के साथ पठित अनुच्छेद 80 (1) (बी) के तहत निर्वाचित "राज्य का प्रतिनिधि", या अनुच्छेद 81 के तहत निर्वाचित लोक सभा का "सदस्य", संसद में एक सीट भरता है। जब एक उम्मीदवार

राज्य परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, वह चुना जाता है और "राज्य के प्रतिनिधि" के रूप में चुना जाता है। शब्द हैं। " राज्य का प्रतिनिधि "किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि

प्रतिनिधि को राज्य में ही पंजीकृत निर्वाचक या मतदाता भी होना चाहिए। यह विधायिका के सदस्य के रूप में चुनाव पर प्राप्त स्थिति है जो व्यक्ति को "प्रतिनिधि" का चरित्र प्रदान करती है। [95 – ई; 96–सी–डी]

श्री वी. वी. गिरि बनाम दिप्पाला सूरी डोरा और ओआरएस। , [1960] 1 एससीआर 426: एयर

(1959) एससी 1318 और बी. आर. कपूर बनाम टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य , [2001] 7 इसके बाद एस. सी. सी. 331 आया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

18

11.4 . अनुच्छेद 80 (4) में "प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति

संविधान एक योग्यता नहीं है और इसे एक शर्त के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

निर्वाचित होने की मिसाल। संविधान ने विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 84 में "योग्यताओं" के बारे में बात की है, जैसा कि प्रावधान की सामग्री के अलावा सीमांत नोट से भी स्पष्ट होगा। [98 – ई]

11.5 . "प्रतिनिधि" शब्द का सीधा सा अर्थ है–द्वारा चुना गया व्यक्ति।

लोगों द्वारा या विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा संसद के किसी एक सदन में अपने कई हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। एक व्यक्ति बन जाता है

एक प्रतिनिधि निर्धारित तरीके से चुने जाने के बाद ही। वह पहले प्रतिनिधि नहीं थे। सबसे अच्छा, वह एक उम्मीदवार या एक संभावित प्रतिनिधि कहलाने का दावा कर सकता है। यह सिद्धांत कि वह एक प्रतिनिधि बनने से पहले उसके पास लागू कानून द्वारा निर्धारित एक के अलावा कुछ अन्य सांठगांठ होनी चाहिए, स्वीकार्य नहीं है और किसी भी मामले में लिए गए किसी भी कानून या दृष्टिकोण द्वारा समर्थित नहीं है।

[98 – एफ–जी]

11.6 . याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुच्छेद 80 (4) को सही ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा है। द.

सुझाव है कि अभिव्यक्ति 'प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि' का तात्पर्य हैनिवास की स्थिति या प्रतिनिधित्व किए जाने वाले राज्यों के साथ अन्य लिंक की उपेक्षा की जाती है

"राज्यों की परिषद" अभिव्यक्ति से पहले "में" अभिव्यक्ति का महत्व। अनुच्छेद 80 (4) में यह नहीं कहा गया है कि निर्वाचित होने के लिए प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि चुनाव से पहले राज्य का प्रतिनिधि होना चाहिए। इस आवश्यकता को अनुच्छेद 80 (4) में पढ़ने से शब्दों पर हिंसा होगी और व्याकरण की दृष्टि से यह गलत होगा। अनुच्छेद 80 (4) में निहित प्रावधान में, इस प्रकार सक्रिय आवाज में, 'कौन चुनता है' पर जोर दिया गया है। मौजूदा निष्क्रिय रूप में, इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाएगा। परिणाम, दोनों तरह से, समान है। अनुच्छेद 80 (4) चुनाव के तरीके से संबंधित है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए, "प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि" शब्द केवल सदस्यों को संदर्भित करता है और इसकी कोई और अवधारणा या आवश्यकता नहीं है।

राज्य में निवास। [105 – सी–डी; एफ–जी।

11.7 . निस्संदेह, 1951 के अधिनियम की धारा 6 की आवश्यकता बनी हुई है।

राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक योग्यता के रूप में राज्य के भीतर अधिवास। लेकिन, जी. नारायणस्वामी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, इससे अलग होने का कोई उचित कारण नहीं पाया गया है।

इस दलील में कोई योग्यता नहीं है कि राज्य की विधान सभा द्वारा निर्वाचित "राज्य का प्रतिनिधि" भी राज्य का एक सामान्य निवासी होना चाहिए क्योंकि उसे चुनने वाले मतदाताओं के लिए कानून द्वारा ऐसा होना आवश्यक है। [97 – डी–ई] 19

कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई.

जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेल्वम और अन्य। , [1972] 3 एससीसी 717,

पीछा किया।

12. यह तर्क कि संवैधानिक मान्यता दी गई है

राज्य परिषद के सदस्य के बीच क्षेत्रीय संबंध (प्रतिनिधित्व के रूप में) राज्य परिषद में विशेष राज्य) और एक पंजीकृत राज्य के रूप में उनकी स्थिति

स्थानीय निकायों के उद्देश्यों के लिए उस राज्य में किसी भी पंचायत या नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचक ने इस दलील को मजबूत किया कि विशेष रूप से स्थानीय निवास पर जोर दिया जाए

राज्य परिषद में राज्य के प्रतिनिधियों के लिए राज्य निम्नलिखित कई कारणों से योग्यता से रहित पाई जाने वाली संविधान योजना का हिस्सा थाः

(i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रावधान

स्थानीय निकायों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के किसी भी या नगरपालिका क्षेत्र में पंजीकृत निर्वाचक के रूप में उनकी स्थिति के कारण राज्य परिषद के सदस्य के संबंध में संविधान अपवादात्मक नहीं है। वे समान रूप से लागू होते हैं

संबंधित राज्य के लोक सभा और विधान सभाओं (वास्तव में, विधान परिषदों) के सदस्य।

((ii) ये प्रावधान स्थानीय स्वशासन की योजना का हिस्सा हैं।

संविधान में निहित, उद्देश्य को राज्य और संघ स्तरों पर स्थानीय निकायों और विधायिका के बीच एक संबंध प्रदान करने के लिए प्राप्त करने की मांग की गई। राज्य विधानमंडल के सदस्यों और संसद को जमीनी स्तर तक पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य हासिल किया जाना है।

उन्हें स्थानीय समस्याओं, मुद्दों, राय और आकांक्षाओं के बारे में ज्ञान से लैस करना, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। सक्षम प्रावधानों का एक समान अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। इनका प्रभाव प्रत्येक राज्य के लिए संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित या अधिनियमित किए जाने वाले प्रावधानों पर निर्भर करेगा। समर्थकारी प्रावधान स्वयं यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य या संघ विधानमंडल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व के लिए दावापंचायत या नगरपालिका विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जो ऐसे प्रत्येक सदस्य के लिए मौजूद हो सकते हैं या नहीं भी। सक्षम प्रावधान आम तौर पर प्रदान करते हैं

विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की योग्यता के लिए, जिसमें राज्य परिषद के सदस्य शामिल होते हैं, एक पंचायत में प्रतिनिधि होने के लिए

या नगरपालिका, और स्थानीय स्वशासन में भाग लें। चूंकि राज्य परिषद के सदस्य इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे कई स्रोतों में से एक हैं

स्थानीय स्तर पर विचारशील शाखा में विभिन्न हित समूहों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करने के लिए, चयन की कुछ विधि निर्धारित करना अनिवार्य था।

(iii) अंतिम, लेकिन कम से कम, जिन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, वे हैं –

संवैधानिक प्रावधान। यहां तक कि इस आधार पर भी कि उन्हें लागू करने में किसी विशेष पंचायत या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकरण का कारक 20

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

राज्य परिषद के सदस्यों के संबंध में महत्वपूर्ण माना जाता था ताकि उन्हें स्थानीय पंचायत या नगरपालिका में प्रतिनिधित्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सके, यह नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रावधान राज्य परिषद में सदस्यता के लिए योग्यता में अधिवास की आवश्यकता को जोड़ते हैं। इस तरह की अतिरिक्त योग्यता निर्धारित करने वाला ऐसा कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है। [99 – एफ–जी–एच; 100–ए–एच; 101–ए}

13.1 . यहां तक कि उन देशों में भी जहां सख्त संघवाद मौजूद है, मार्ग के साथ

समय के साथ, राजनीतिक इकाइयों के रूप में राज्यों के हितों की रक्षा करने की सीनेट की मूल भूमिका काफी हद तक गायब हो गई है। वैश्वीकरण के साथ, अमेरिकी सीनेट अब स्थानीय हितों के समर्थक के बजाय एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।

[102 – जी]

13.2 . 'निवास' और 'प्रतिनिधि' शब्दों की अवधारणाएँ नहीं हैं।

इसलिए निश्चित अवधारणाओं को समय के साथ बदलना पड़ता है। संवैधानिक निर्माताओं ने उस लचीलेपन को ध्यान में रखा है, उन्होंने संसद की सदस्यता के लिए योग्यता तय करने का काम संसद पर छोड़ दिया है और योग्यता तय करते समय संसद को इन बातों को ध्यान में रखना होगा – प्रासंगिक परिदृश्य। इन अवधारणाओं की एक समान, सुसंगत और आंतरिक परिभाषा या अर्थ नहीं हो सकता है। इन अवधारणाओं में बदलाव आते हैं।

समय के साथ। उन्हें शब्दकोशों के संदर्भ में व्युत्पत्ति के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। [103 – ए–बी]

13.3 . "आम तौर पर" और "निवासी" शब्दों का एक साथ उपयोग किया गया है।

अन्य वैधानिक प्रावधानों में भी और लॉ लेक्सिकन के अनुसार उनका यह अर्थ लगाया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति वह होना चाहिए जो हमेशा निवासी हो या विशेष स्थान पर व्यवसाय करता हो। आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 20 के मामले में, जिस तारीख को कोई व्यक्ति किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, दोनों शब्दों को जोड़कर बनाई गई अभिव्यक्ति की व्याख्या प्रावधान के उद्देश्यों के लिए आवश्यक समय के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस प्रकार, निवास एक ऐसी अवधारणा है जो अस्थायी भी हो सकती है। "आम तौर पर" शब्द द्वारा योग्य होने पर भी "निवासी" शब्द के परिणामस्वरूप निर्माण में आवश्यकता का प्रभाव नहीं होगा।

हमेशा या स्थायी रूप से निर्बाध आधार पर रहने के लिए किसी विशेष स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्ति का। इस प्रकार समझा जाता है कि किसी व्यक्ति के किसी विशेष स्थान पर "सामान्य रूप से निवासी" होने की आवश्यकता भी उसके और विचाराधीन स्थान के बीच संबंध सुनिश्चित करने में असमर्थ है। [104 – बी–डी–ई]

सीकटटी वी। सफ़ोक कंट्री काउंसिल, [1980] 3 सभी। ई. आर. 689, संदर्भित।

3.4 . उम्मीदवार और उस राज्य के बीच सांठगांठ जिसमें से उसे 21 सीटें मिलती हैं।

कुलदिप नायर "। यू. ओ. आई.

राज्यों की परिषद में एक सीट को भरने के लिए निर्वाचित धारणा द्वारा प्रदान किया जाता है और

विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों का वोट जो उन्हें (अनिवार्य रूप से एक भारतीय नागरिक) के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे योग्य मानते हैं

संसद में राज्य। [104 – एफ. आई.

13.5 . चुनाव में किसी उम्मीदवार के लिए मतदान करते समय, उसके कौशल की धारणा

एक विधायक के रूप में, राज्य के मामलों के बारे में उनका ज्ञान, जिस निर्वाचन क्षेत्र का वे प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उसके लिए उनकी सेवाएं और उन्हें विधायक के रूप में रखने में संतुष्टि या विश्वास।

निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधि पर्याप्त विचार या योग्यताएँ हैं।

ये विचार निश्चित रूप से अस्थायी से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

या अक्सर "निवास" की भ्रामक अवधारणा। [104 – जी]

13.6 . हमारी चुनाव प्रणाली को सभी ज्ञात से मुक्त करने की आवश्यकता है।

इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि संसद को ऐसा कानून लाने के अवसर से वंचित किया जाना चाहिए, जो उसके विवेक के अनुसार दुरुपयोग के संभावित कमियों को दूर करेगा, जिसके लिए संसद के पास आवश्यक विधायी क्षमता है। [105 – बी]

14.1 . आर. पी. अधिनियम के तहत एक अलग तंत्र उपलब्ध हो सकता है,

1950 किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की शुद्धता पर सवाल उठाना और पूछताछ करना, एक विशिष्ट उपाय

चुनाव में वापस किए गए घोषित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने के लिए एक चुनाव याचिका से, लेकिन यह तथ्य किसी भी तर्क के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से अधिवास की आवश्यकता को हटाना कानून या सामान्य ज्ञान के खिलाफ है। [108 – एच; 109–ए–बी

हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम। वी. बी. राजू और अन्य। , [1974] 3 एससीसी 415,

प्रतिष्ठित।

14.2 . संविधान ने यह अनिवार्यता नहीं बनाई है कि कोई व्यक्ति

राज्य परिषद में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने वाले को अनिवार्य रूप से उस राज्य में ही मतदाता होना चाहिए। संविधान, कुछ निर्धारित करने के बाद

योग्यताओं और अयोग्यताओं ने ऐसी अन्य योग्यताओं या अयोग्यताओं को प्रदान करने का काम संसद पर छोड़ दिया है। [110 – एफ}

14.3 . संविधान के अनुच्छेद 80 (4) और 327 के तहत प्रावधान

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संविधान ने समय–समय पर चुनावों से संबंधित कानून में बदलाव की आवश्यकता को स्वीकार किया और संसद को विधायिका लाने की जिम्मेदारी के साथ–साथ आवश्यक शक्ति भी सौंपी।इस संबंध में जब भी और जब भी आवश्यक हो उपाय, जिसमें पावर सुपर कोर्ट रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. शामिल होगी।

5 एस सी आर।

22

मौजूदा उपायों में संशोधन करना। [115 – सी–डी।

हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम। वी. बी. राजू और अन्य। , [1974] 3 एससीसी 415:

[1974] 1 इसके बाद एस. सी. आर. 548 आया।

14.4 . संसद के पास अनुच्छेद के तहत एक अनन्य शक्ति है।

246 संघ में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना।सातवीं अनुसूची की सूची। संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अनुच्छेद 84 और 327 और प्रविष्टि 72 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संसद के लिए कानून बनाकर यह तय करने का विषय है कि संविधान में निर्धारित योग्यताओं के अलावा कौन सी "अन्य" योग्यताओं को संविधान में निर्धारित योग्यताओं के अलावा अन्य योग्यताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य बनाया जाए।

राज्यों की परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में सीटें भरें। संविधान इस संबंध में संसद की विधायी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। यदि संविधान का इरादा था कि

" राज्यों के प्रतिनिधियों को उस राज्य का निवासी होना चाहिए या उस राज्य के साथ संबंध या संबंध होना चाहिए जहां से प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, ऐसा प्रावधान इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से किया गया होगा जैसा कि आयु और नागरिकता की आवश्यकता के संबंध में किया गया है। इस तरह की स्पष्ट आवश्यकता के अभाव में, निवास की आवश्यकता या योग्यता के मामले में किसी अन्य सांठगांठ को संविधान के अनुच्छेद 80 या 84 में नहीं पढ़ा जा सकता है।

[115 – एफ, जी, एच; 116–सी; डी]

14.5 . तथ्य यह है कि एक उम्मीदवार को किसी भी संसद में नामांकित होने की आवश्यकता होती है

भारत में निर्वाचन क्षेत्र उन्हें केवल इस आधार पर राज्य का प्रतिनिधि होने के अधिकार से वंचित नहीं करता है कि वे वहां नामांकित नहीं हैं। [116 – ई]

14.6 . यह तर्क कि एक बार संसद एक योग्यता निर्धारित करती है,

यह इसे निरस्त या निरस्त नहीं कर सकता है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि संसद की विधायी शक्ति पर ऐसी कोई सीमा नहीं है, जिसकी पुष्टि सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 72 द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 84 के खंड (सी) की भाषा एक शक्ति का निर्माण करती है न कि कर्तव्य का। यदि यह कोई अतिरिक्त निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं है योग्यता, यह समाप्त किए गए के लिए एक विकल्प प्रदान करने के लिए भी बाध्य नहीं है। [118 – एफ]

14.7 . याचिकाकर्ताओं के तर्क का जोर यह है कि 'बाहरी'

परिषद के चुनाव में एक 'अंदरूनी सूत्र' को प्राथमिकता दी जाएगी राज्यों। यह अनिवार्य रूप से अंतिम परिणाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव का परिणाम किसी भी अन्य कारक की तुलना में राज्य की विधानसभा, निर्वाचक मंडल के चयन पर निर्भर करेगा। किसी भी स्थिति में, भले ही किसी 'बाहरी व्यक्ति' का चयन किया जाए, यह तर्क देना बहुत दूर की बात है कि सदन का 'चरित्र' 23 है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई.,

इसके परिणामस्वरूप परिवर्तन होगा। अनिवार्य रूप से क्या किया गया है

संशोधन यह प्रावधान करने के लिए है कि बाहर के निर्वाचक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति भी

राज्य उस राज्य से राज्य परिषद का चुनाव लड़ सकता है।

ऐसा करके मतदाताओं के चयन का विस्तार और विस्तार किया गया है।

प्रावधान। [118 – जी–एच; 119–ए।

15. किसी प्रस्तावित विधान के उद्देश्यों और कारणों का विवरण है –

सभी संभावित कारणों या औचित्य का संग्रह नहीं। कोई विरोधाभास नहीं इन कार्यवाहियों में भारत संघ द्वारा लिए गए रुख में पाया गया है

आक्षेपित के उद्देश्यों और कारणों के कथन के संबंध में

संशोधन। [112 – जी]

16. यहां तक कि इस बहस में गए बिना कि क्या मतदान का अधिकार एक है

वैधानिक या संवैधानिक अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार निर्विवाद रूप से एक

वैधानिक अधिकार, अर्थात चुनाव में खड़े होने के अधिकार को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है। यह शुद्ध और सरल एक वैधानिक अधिकार है जिसे बनाया जा सकता है।

और संसद द्वारा छीन लिया गया और इसलिए, हमेशा वैधानिक सीमाओं के अधीन होना चाहिए। [116 – जी]

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एन. आर. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. ,

[2003] 4 एससीसी 399; एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य। , [1952] एस. सी. आर. 218; जोसेफ थेबर्गे और एनर। वी. फिलिप लॉड्री, (1876) 2 एसी 102; हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम। वी. बी. राजू और अन्य। , [1974] 3 एस. सी. सी. 415 और ज्योति बसु बनाम। देवी घोषाल, [1982] 1 एस. सी. सी. 691, पर भरोसा किया।

17.1 . विवादित संशोधन आर. पी. अधिनियम की धारा 3 नहीं बनाएगा,

1951 नासमझ। जबकि अनुच्छेद 84 भारत की नागरिकता को निर्धारित करता है

सदस्यता के लिए योग्यता, धारा 3, संशोधन के बाद, राज्यों की परिषद के सदस्य की योग्यता को भारत में रहने वाले निर्वाचक तक सीमित करती है। यह गैर–निवासी भारतीय नागरिकों को बाहर कर देगा। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। अतः यह स्पष्ट है कि धारा 3 जारी है –

राज्यों की परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता प्रदान करें। [119 – सी–डी]

17.2 . यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, संशोधन के बाद भी, (i)

निर्वाचक समान रहते हैं, अर्थात् राज्य विधानसभाएँ; (ii) निर्वाचित व्यक्ति राज्य के प्रतिनिधि बने रहते हैं; और (iii) चुनाव और

किसका चुनाव करना है, इसका निर्णय राज्य विधानसभाओं के पास बना रहता है। [119 – ई–एफ]

17.3 . राज्य विधानसभा के समक्ष विचार के क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

24

लेकिन अंतिम विकल्प और निर्णय हमेशा राज्य विधानमंडलों का होता है।

इसलिए, यदि वे एक ऐसे व्यक्ति को चुनने का निर्णय लेते हैं जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है

राज्य वे सभी परिस्थितियों की पूरी जानकारी के साथ ऐसा करेंगे और यह उनका निर्णय होगा कि उनके राज्य का प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। इसे, किसी भी तर्क के विस्तार से, संसद के दायित्वों या कार्यों का त्याग नहीं कहा जा सकता है। [119 – एफ–जी।

17.4 . आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 में विवादित संशोधन नहीं किया जा सकता है।

असंवैधानिक के रूप में हमला किया जाए। यह विधायी क्षमता को ध्यान में रखते हुए पारित होता है। यह भाग III के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है

संविधान, और न ही उस मामले के लिए संविधान का कोई अन्य प्रावधान, व्यक्त या निहित। [120 – बी]

18.1 . विवादित संशोधनों के माध्यम से एक–एक प्रावधान जोड़ा गया है

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 59,94 और 128। इन संशोधनों ने गोपनीयता के सामान्य नियम के लिए एक अपवाद बनाया है

राज्यों की परिषद में एक सीट को भरने के लिए चुनाव, जो अब "खुले मतपत्र द्वारा" आयोजित किया जाना है, इस प्रकार अब गुप्त मतपत्र के सिद्धांत के अधीन नहीं है।

(120 – एफ]

18.2 . इस न्यायालय द्वारा बार–बार यह अधिकृत रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि

लोकतंत्र भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, जो नहीं है

संविधान के तहत संसद के संशोधन की शक्ति के लिए उत्तरदायी। इस न्यायालय का यह भी निरंतर दृष्टिकोण रहा है कि इस देश में लोकतंत्र की इमारत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रणाली पर टिकी हुई है। ये सिद्धांत न केवल प्रस्तावना से, जिसे हमेशा संविधान का हिस्सा माना जाता रहा है, बल्कि इसके विभिन्न प्रावधानों से भी स्पष्ट होते हैं। [124 – जी–एचजे

केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य और अन्न। , [1973]

4 इसके बाद एस. सी. सी. 225 आया।

18.3 . इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि लोकतंत्र बुनियादी है।

भारत के संविधान की विशेषता और सरकार के लोकतांत्रिक रूप की अवधारणा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर निर्भर करती है। { 129 – जी]

एस. रघबीर सिंह गिल बनाम एस. गुरचरण सिंह टोहरा, [1980] सप। एससीसी

53 ; किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू और ओआरएस। , (1992) सप. 2 एससीसी 651; पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सी. बी. आई./एस. पी. ई.), [1998] 4 एस. सी. सी. 626; भारत संघ बनाम। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड एन. आर. , [2002] 5 एस. सी. सी. 294 और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. , [2003] 4 एस. सी. सी. 399, पर भरोसा किया।

कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई.

25

18.4 . यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि मतदान करने और चुनाव करने का अधिकार है

राज्य परिषद में राज्य के प्रतिनिधि एक संवैधानिक अधिकार है।

अनुच्छेद 80 (4) केवल प्रतिनिधियों के चुनाव के तरीके से संबंधित है।

राज्यों की परिषद में परिषद की संरचना के एक पहलू के रूप मेंराज्यों। अधिकार घोषित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों में कुछ भी नहीं है

संविधान के तहत एक पूर्ण अधिकार के रूप में ऐसे चुनाव में मतदान करना।

[135 – एफ–जी।

ज्योति बसु बनाम। देवी घोषाल, [1982] 1 एस. सी. सी. 691, पर भरोसा किया।

19.1 . यह विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो

चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन, अनुच्छेद 80 के तहतपरिषद में उस राज्य को आवंटित सीट को भरने के लिए राज्य का प्रतिनिधि

राज्यों से। यह पूरी विधानसभा नहीं है जो निर्वाचक बन जाती है महाविद्यालय, लेकिन केवल सदस्यों की निर्दिष्ट श्रेणी। जब ऐसा होता है

सदस्य एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, वे सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा नहीं करते हैं

संविधान से विधान सभा तक। चुनाव में उनकी भागीदारी केवल चुनाव के लिए मतदाताओं की उनकी पदेन क्षमता के कारण होती है। इस प्रकार, उनमें से प्रत्येक द्वारा वोट डालने का कार्य, जो इसके साथ होने की भी आवश्यकता नहीं है

ये सभी एक साथ या एक ही समय में उपस्थित होते हैं, केवल मताधिकार का प्रयोग है, न कि विधायिका की कार्यवाही। [139 – एफ–जी–एच]

19.2 . यह महत्व के बिना नहीं है कि, मामले में अपवाद को छोड़कर

निर्दलीयों की संख्या, जो बहुत कम है, अनुभव से पता चला है कि यह राजनीतिक दल हैं जो ज्यादातर केंद्र या राज्यों में विधानसभाओं के सदस्यों की स्थापना करते हैं। नामांकन पत्र का भी उल्लेख किया जा सकता है।

चुनाव के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत निर्धारित

राज्य परिषद, फॉर्म 2–सी होने के नाते, या राज्य विधान सभा के चुनाव के लिए, फॉर्म 2 बी होने के नाते, जिनमें से प्रत्येक के लिए उम्मीदवार द्वारा उस राजनीतिक दल के विवरण के बारे में घोषणा करने की आवश्यकता होती है जिसने उसे चुनाव में स्थापित किया है। यह घोषणा निर्वाचित विधायकों को इस मामले में बाध्य करती है कि

राज्य परिषद के चुनाव में किसी विशेष उम्मीदवार को पार्टी के समर्थन सहित सभी मामलों में राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा। फिर भी, किहोतो होलोहन बनाम में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए। ज़चिल्लू और ओआरएस। , यह तर्क देना सही नहीं है कि खुली मतपत्र प्रणाली विधान सभा के सदस्यों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए उजागर करती है क्योंकि संविधान का वह हिस्सा अलग–अलग उद्देश्यों के लिए है। [146 – ए–बी–सी–डी]

किहोतो होलोहन बनाम। Zachillhu, [1992] पूरक। 2 एस. सी. सी. 651, पर भरोसा किया।

19.3 . अनुच्छेद 21 के माध्यम से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और

अनुच्छेद 25 26 के माध्यम से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

यह जरूरी नहीं कि गुप्त मतदान द्वारा संतुष्ट किया जाए, बल्कि समान रूप से स्वतंत्र मतदान द्वारा भी संतुष्ट किया जाए प्रक्रियाएँ "। [147 – ई–एफ}

19.4 . यहाँ तक कि चुनावों के तहत जो सिद्धांत पर आधारित हैं

मतदान की गोपनीयता, यह मतदाता को चुनना है कि वह खुलासा करना चाहता है या नहीं

जिनके लिए उन्होंने मतदान किया था या गोपनीयता बरकरार रखना चाहते हैं। अगर वह ऐसा करता है

वह चुनता है, वह अपने विशेषाधिकार को छोड़ सकता है और उस स्थिति में, मतपत्र की गोपनीयता मिलनी चाहिए। ऐसी घटना तब भी हो सकती है जब धोखाधड़ी, जालसाजी या अन्य अवैध कार्य हो और प्रकटीकरण उप–न्याय के प्रशासन के उद्देश्य को पूरा करता है। [152 – ई]

एस. रघबीर सिंह गिल बनाम एस. गुरचरण सिंह टोहरा, [1980] सप। एससीसी

53 , संदर्भित किया गया।

रानी वी। बियर्डसाल, एल. आर. (1875–76) 1 क्यू. बी. 452, संदर्भित।

19.5 . याचिकाकर्ता का निवेदन कि हमेशा मतदान करने का अधिकार

एक निहित शब्द के रूप में, गोपनीयता में मतदान करने का अधिकार, पूरी तरह से सही नहीं है। जहाँ संविधान ने ऐसा करना उचित समझा है, वहाँ उसने स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है –

गुप्त मतदान द्वारा चुनाव। यह इंगित करना उचित है कि चुनाव से संबंधित संविधान के प्रावधानों के मामले में इस विषय पर मौन के विपरीत राज्यों की परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों की सीटें, अनुच्छेद 55 (3) और 66 (1), जो क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव के तरीके से संबंधित हैं, "गुप्त मतदान" द्वारा चुनाव के लिए प्रावधान करते हैं।

[156 – जी–एच; 157–ए]

ए. नीललोहितदासन नादर बनाम। जॉर्ज मैस्क्रीन और ओआरएस। , [1994] पूरक।

2 एस. सी. सी. 619, पर भरोसा किया।

19.6 . यदि अपने आप में मतदान करने का अधिकार गुप्त रूप से मतदान करने का संकेत देता है या स्वीकार करता है,

तब संविधान के अनुच्छेद 55 (3) और 66 (1) में ऐसे शब्दों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती। उक्त अनुच्छेदों में उक्त शर्त को शामिल करने की आवश्यकता से पता चलता है कि "गुप्त मतदान" हमेशा निहित नहीं होता है। यह नहीं है।

आवश्यक निहितार्थ द्वारा मतदान की अवधारणा में शामिल किया गया। यह इस प्रकार है कि 'गुप्त मतपत्र' को मानक बनाने के लिए, इसे स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 80 (4) में पढ़ने के लिए एक गुप्त मतपत्र की आवश्यकता प्रावधान में "और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा" शब्दों को पढ़ना होगा। ऐसा करना संवैधानिक और सांविधिक कुलदिप नायर बनाम के प्रत्येक सिद्धांत के खिलाफ होगा।

यू. ओ. आई.

27

निर्माण। इस प्रकार, इस दृष्टिकोण से, यह मानना मुश्किल है कि राज्यों की परिषद के लिए खुली मतपत्र प्रणाली प्रदान करने में संवैधानिक दुर्बलता है। [157 – सी–डी–ई।

19.7 . जहाँ इस विषय पर कानून चुप है, वहाँ अनुच्छेद 324 एक भंडार है।

निर्वाचन आयोग को घोषित उद्देश्य के लिए कार्य करने की शक्तिएक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य का पीछा करना, और इस दृष्टिकोण में यह भी मानता है

सलाहकार की भूमिका। लेकिन अनुच्छेद 327 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है, जो सर्वोच्च है और इसलिए ऐसी सलाह से बाध्य नहीं है।

[157 – एच; 158–ए]

मोहिंदर सिंह गिल बनाम। मुख्य चुनाव आयुक्त, [1978] 1 एस. सी. सी. 405,

संदर्भित किया गया।

19.8 . वोट को गुप्त रखने का विशेषाधिकार निर्वाचक का है जो

अन्यथा चुन सकता है; अर्थात, वह उस तरीके का खुलासा करने का विकल्प चुन सकता है जिसमें उसने अपना वोट डाला है, लेकिन उसे उस तरीके का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसमें उसने ऐसा किया है, सिवाय उस विषय पर कानून के अनुसार जो आमतौर पर केवल उस स्थिति में लागू होता है जब चुनाव को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाती है। [162 – बी–सी]

19.9 . इस प्रकार, संशोधित नियमों का प्रभाव यह है कि चुनावों में

राज्य परिषद, निर्वाचक द्वारा मतपेटिका में मतपत्र डालने से पहले, राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि को यह सत्यापित करने की अनुमति दी जाएगी कि ऐसा निर्वाचक किसे अपना वोट देता है। यदि ऐसा मतदाता अपना चिह्नित मतपत्र दिखाने से इनकार करता है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया जाएगा कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था। इसलिए, मतदाता पर अपना वोट दिखाने की मजबूरी है। लेकिन फिर, उपरोक्त नियम केवल उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हैं जिसे विवादित संशोधन द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। बल्कि, नियमों से पता चलता है कि खुली मतपत्र प्रणाली का मतलब यह नहीं है कि यह सभी के लिए खुली है। यह केवल राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि को ही देखने और सत्यापित करने की

अनुमति है कि ऐसा मतदाता किसे अपना वोट देता है। मतदाता के पास यह चुनने का विशेषाधिकार रहता है कि अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को अपना वोट दिखाना है या नहीं।

[182 – एफ–जी–एच]

19.10 . राज्य परिषद के चुनावों में मतदान की तुलना नहीं की जा सकती है

आम चुनाव के साथ। आम चुनाव में, मतदाताओं को इस डर के बिना गुप्त तरीके से मतदान करना पड़ता है कि उनके वोट किसी को भी बताए जा सकते हैं या पीड़ित हो सकते हैं। कोई पार्टी संबद्धता नहीं है और इसलिए चुनाव पूरी तरह से मतदाता के पास है। ऐसा तब नहीं होता जब सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं।

5 एस सी आर।

28

निर्वाचक के रूप में राज्य परिषद विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनकी बदले में पार्टी संबद्धता होती है। [163 – ए–बी।

20.1 . 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों' में मतदान का अधिकार हमेशा इस संदर्भ में होता है –

राष्ट्रीय विधान द्वारा निर्धारित एक निर्वाचन प्रणाली। मतदान का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के अधिकार से अपना रंग प्राप्त करता है; कि 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों' के अधिकार के बिना मतदान का अधिकार खाली है। यह एक चुनावी प्रणाली के संदर्भ में 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों' की अवधारणा है जो मतदान के अधिकार को सामग्री और अर्थ प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, 'मतदान का अधिकार' स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का एक घटक नहीं है। यह आवश्यक है लेकिन आवश्यक घटक नहीं है। [167 – एफ–जी]

जुड वी। मैकियॉन, (1926) 38 सी. एल. आर. 380; किंग बनाम। जेम्स, (1972) 128 सीएलआर

221 और न्यू नेशनल पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका बनाम। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार और ए. एन. आर. , (1999) 3 एस. ए. 191, संदर्भित।

" फजेनबाम द्वारा ऑस्ट्रेलियाई संविधान संबंधी कानून का दूसरा संस्करण और

हैंक्स, संदर्भित।

20.2 . यह स्पष्ट है कि मतदान का अधिकार एक ऐसी अवधारणा है जिसे स्वीकार करना पड़ता है

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्राप्ति की अवधारणा के लिए। चुनाव की प्रकृति,

अर्थात्, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतदान के अधिकार की अवधारणा को नियंत्रित करता है। जहाँ चुनाव सीधे होते हैं, वहाँ गुप्त मतदान पर जोर दिया जाता है। जहाँ चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं और जहाँ सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष माध्यमों से किया जाता है, जैसे –

द्वारा

संसद या विधान सभा या कार्यपालिका द्वारा, फिर खुले मतपत्र को मतदान की चुनावी प्रणाली के तहत एक अवधारणा के रूप में पेश किया जा सकता है। प्रत्यक्ष चुनावों के मामले में, सदस्यों को सीधे लोकप्रिय वोट द्वारा चुना जाता है जो अप्रत्यक्ष चुनावों के मामले में नहीं होता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि खुले मतपत्र की अवधारणा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्राप्ति को विफल कर देगी।

[175 – डी–ई–एफ]

" ऑस्ट्रेलियाई संवैधानिक कानून "(दूसरा संस्करण), संदर्भित।

20.3 . यह नहीं भुलाया जा सकता कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व एक

हमारे संसदीय लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता और यह कि यह संसद के लिए चिंता का विषय हो सकता है यदि यह पाया जाए कि मतदाता विवेकपूर्ण मतदान की आड़ में क्रॉस वोटिंग का सहारा ले रहे थे, मतदान की गोपनीयता के नाम पर पार्टी अनुशासन का उल्लंघन कर रहे थे। इससे पार्टी का अनुशासन कमजोर होगा।

त्रुटिपूर्ण विधायक। राजनीतिक दल हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कुलदिप नायर बनाम के मामले में पार्टी अनुशासन की सुरक्षा को चुनावों की शुद्धता की एक आवश्यक विशेषता के रूप में पेश किया जा सकता है।

यू. ओ. आई.

29

चुनाव। [175 – जी–एच; 176–ए]

20.4 . निर्वाचन क्षेत्र आधारित के बीच अंतर करने वाली विशेषता

एक प्रतिनिधि में प्रतिनिधित्व 'और' आनुपातिक प्रतिनिधित्व '

लोकतंत्र यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मामले में सदस्यों का चुनाव दल के आधार पर किया जाता है। वे पार्टी अनुशासन के अधीन हैं। वे उत्तरदायी हैं

अनुशासन के उल्लंघन के लिए निष्कासित किया जाए। इसलिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को प्रभावी बनाने के लिए, संसद 'ओपन बैलेट' का सुझाव दे सकती है। ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव 'खुले मतपत्र' से हार जाएंगे। [180 – ई–एफ]

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाम। दक्षिण गणराज्य के राष्ट्रपति

अफ्रीका और ओआरएस। , (2003) 1 एसए 495 और किंग वी। जेम्स, (1972) 128 सी. एल. आर. 221 का उल्लेख किया गया है।

20.5 . सदन के अंदर एक प्रस्ताव पर प्रत्येक वोट एक खुले मतपत्र द्वारा होता है। द.

अध्यक्ष, लोक सभा के उपाध्यक्ष और राज्य परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव एक विभाजन द्वारा किया जाता है जो खुले मतदान की एक प्रणाली है। इस संबंध में प्रक्रिया और संचालन नियमों के नियम 7,8,364,365,367,367 एए और 367 बी का संदर्भ दिया जा सकता है।

लोकसभा में कार्य और राज्य परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 7,252,253 और 254। इसलिए, इस तर्क पर विवादित संशोधन के औचित्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि खुले मतदान से पार्टी नामांकन के आधार पर किसी विशेष राज्य की विधानसभा के लिए चुने गए मतदाताओं द्वारा क्रॉस वोटिंग की बुराई समाप्त हो जाती है। [180 – एच; 181–ए–बी]

20.6 . यह तर्क कि मतदाता का अभिव्यक्ति का अधिकार

राज्य परिषद के लिए चुनाव खुले मतपत्र से प्रभावित होता है जो मान्य नहीं है, क्योंकि एक निर्वाचित विधायक को एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए सदन की सदस्यता से किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। [181 – ई]

20.7 . चूंकि संशोधन आवश्यकता के आधार पर लाया गया है

क्रॉस वोटिंग से बचें और भ्रष्टाचार की बुराइयों को मिटाने के साथ–साथ हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की अखंडता को बनाए रखने के लिए, इसे राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत एक उचित प्रतिबंध के रूप में भी उचित ठहराया जा सकता है।यह धारणा कि इस तरह के चुनाव में मतदान करना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बराबर है। [181 – एफ–जी]

20.8 . इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मतदान का तरीका

राज्य परिषद के लिए चुनाव निश्चित रूप से क़ानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है। संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि राज्य परिषद के चुनाव के लिए मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। 30 सदस्यीय परिषद के चुनाव के लिए मतदान

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

संसद द्वारा बनाए गए कानून के कारण अब तक राज्य गुप्त मतदान द्वारा होते थे। यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के चुनावों में गुप्त मतदान एक संवैधानिक अधिकार है।

[181 – एच; 182–ए]

एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य। ,

[1952] एस. सी. आर. 218 और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) v. भारत संघ और ए. एन. आर. , [1997] 1 एस. सी. सी. 301, संदर्भित।

20.9 . विवादित संशोधन से मतदान का अधिकार नहीं खोया जाता है।

संबंधित राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य राज्य परिषद के चुनाव में मतदान करने का पूरी तरह से हकदार है। एकमात्र परिवर्तन

यह विवादित संशोधन के कारण आया है कि उसे अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को वोट डालने के तरीके का खुलासा करना होगा। संसद इसे भ्रष्टाचार को रोकने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और इससे भी महत्वपूर्ण रूप से चुनावों की शुद्धता बनाए रखने के लिए केवल एक नियामक विधि के रूप में उचित ठहराएगी। [182 – बी–सी]

20.10 . बहुदलीय लोकतंत्र मूल संरचना का एक आवश्यक हिस्सा है।

संविधान से। संसदीय लोकतंत्र और बहुदलीय प्रणाली में लोगों के विश्वास को बहाल करने के उद्देश्य से कानून में संशोधन को दोष नहीं दिया जा सकता है।

[182 – एफ]

20.11 . गोपनीयता का सिद्धांत एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है। द.

विधायी संशोधन को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि एक अलग या बेहतर दृष्टिकोण संभव है। यह अच्छी तरह से तय है कि यह कानून के लिए एक चुनौती है एक अन्य दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है जो अधिक हो सकता है

उचित या स्वीकार्य। विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर एक मामला बाद वाले के विवेक और विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए जब तक कि यह किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। [182 – जी]

21. स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए मतपत्र की गोपनीयता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

चुनाव। हालाँकि, सर्वोच्च सिद्धांत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और चुनावों की शुद्धता है। यदि गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाती है तो पारदर्शिता में इसे दूर करने की क्षमता होती है। विधायी नीति के अनुसार विधान

यह कि पारदर्शिता उस बुराई को समाप्त कर देगी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बड़े उद्देश्य की सेवा करेगी। [182 – एच; 183–ए]

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः 2004 की रिट याचिका (सी) संख्या 217। (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

कुलदिप नायर बनाम के साथ। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. आई.]

31

लेखन याचिका (सी) सं। 262 , 266 और 2004 का 305।

राजिंदर सचर, एफ. एस. नरीमन, संजय पारिख, ए. एन. सिंह, पवन कुमार,

पी. एच. पारेख, सुभाष शर्मा, शकुम शर्मा, मैरी मिट्जी, रंजीत रोहतगी

(याचिकाकर्ता के लिए मेसर्स पी. एच. पारेख एंड कंपनी), चरणलाल शौ, व्यक्तिगत रूप से, अजय के. अग्रवाल, अलका अग्रवाल और अनामिका अग्रवाल।

मिलन के. बनर्जी, ए. जी., जी. ई. वाहनवती, एस. जी., अरुणेश्वर गुप्ता, ए. ए. जी.,

डी. पी. सिंह, ए. ए. जी., जे. एस. अत्री, ए. ए. जी., अवतार सिंह रावत, ए. ए. जी., राम जेठमलानी, मो. यूसुफ, अरुण जेटली, पी. पी. राव, डॉ. आर. जी. पाडिया, के. राधाकृष्णन, गौरव अग्रवाल (भारत के अटॉर्नी जनरल के लिए), नवीन कुमार सिंह, अवनीत

तूर, संजय जैन, अरुण के. सिन्हा, राजशेखर राव, इंद्र साहनी, अनिल कटिया विमला सिन्हा, गोपाल सिंह, ऋतुराज विश्वास, हेमंतिका वाही, पिंकी बेहरा, जनार्दन दास, श्वेतकेतु मिश्रा, श्यामा सिंह, कामिनी जैसवाल, तारा चंद्र शर्मा, नीलम शर्मा, राजीव शर्मा, अजय शर्मा, रुपेश कुमार, डी. भारती रेड्डी, पी. विनय कुमार, स्नेहा भास्करम (टी. वी. रत्नम के लिए), एस. मुरलीधर, अमित शर्मा, ए. मरियारपुथम, अरुणा माथुर (मेसर्स के लिए)। अर्पुथम, अरुणा एंड कंपनी), रंजन मुखर्जी, बी. एस. बंथिया, इला कपूर, अभिनव मुखर्जी, पूजा महाजन, नियोमा वासदेव, ख्वैरकपम नोबिन सिंह, अनिल श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, संजय आर. हेगड़े, सुब्रोमोनियम प्रसाद, गोपालकृष्णन, आर., अभय कुमार, जय किशोर, के. रमेश, गर्वेश काबरा, अनुव्रत शर्मा। (प्रवीण स्वरूप), रवि पी. मेहरोत्रा, बीना माधवन (मेसर्स के लिए। लॉयर्स निट एंड कंपनी), वी. के. सिद्धार्थन, जे. आर. लुवांग (मेसर्स के लिए। कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप), सुपर्णा श्रीवास्तव, दीप्ति सिंह, राजेश श्रीवास्तव, उपमन्यु हजारिका, सत्य मित्रा, सुमिता हजारिका, एस. रविशंकर, आर. यमुना नचियार, हेमानंदिनी देओरी, लेसी, ए. सुभाषिनी, नवीन प्रकाश, एस. डब्ल्यू. ए. कादरी, देवदत्त कामत, हृषिकेश बरुआ, चिनमॉय प्रदीप शर्मा, सुरुची सूरी, डी. एस. माहरा, गोपाल प्रसाद (अनिल कुमार झा के लिए), जतिंदर कुमार भाटिया, के. एन. मधुसूदनन, आर. सतीश, इंटरवेनर–इन–पर्सन (आई. ए. नंबर 4) (एन.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वाई. के. सभरवाल, सीजे। पृष्ठभूमि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका द्वारा,

याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व में किए गए संशोधनों को चुनौती देना चाहता है

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 2003 का 40 के माध्यम से लोक अधिनियम, 1951 (संक्षेप में, 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951') जो 28 अगस्त, 2003 से लागू हुआ। उक्त संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, राज्य परिषद में निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य में "अधिवास" की आवश्यकता को हटा दिया गया है जो याचिकाकर्ता के अनुसार संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो एक बुनियादी संरचना सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. है।

5 एस सी आर।

32

संविधान से।

रिट याचिका में, संशोधनों को एक और चुनौती दी गई है

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 59, 94 और 128, जिसके द्वारा ओपन बैले प्रणाली शुरू की गई है, याचिकाकर्ता के अनुसार 'गोपनीयता' के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का सार है। मतदाता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान की मूल विशेषता है और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार का विषय है।

2003 के संशोधन अधिनियम 40 से पहले संविधि का पाठ

1951 से 2003 तक मूल रूप से धारा 3, 59, 94 और 128 इस प्रकार थीं:

" 3. राज्य परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता। – एक व्यक्ति

किसी भी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगाया राज्यों की परिषद में केंद्र शासित प्रदेश जब तक कि वह एक निर्वाचक न हो

उस राज्य या क्षेत्र में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

59. चुनाव में मतदान का तरीका। – हर चुनाव में जहां एक मतदान होता है

लिए गए मतपत्रों को मतपत्र द्वारा इस तरह से दिया जाएगा कि

निर्धारित किया गया है और प्रॉक्सी द्वारा कोई वोट प्राप्त नहीं किया जाएगा।

94. मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। कोई गवाह या अन्य व्यक्ति नहीं

यह बताना आवश्यक होगा कि उसने चुनाव में किसे वोट दिया है।

128. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। – (1) प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्ति जो किसी भी चुनाव में मतों की रिकॉर्डिंग या गिनती के संबंध में कोई कर्तव्य निभाता है (कुछ को छोड़कर)

किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अधिकृत उद्देश्य) किसी भी व्यक्ति को सूचित करते हैं।

ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए मानी गई कोई भी जानकारी।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप–धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि बढ़ सकती है।

तीन महीने तक या जुर्माना या दोनों के साथ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या 40) द्वारा, धारा 3 में 'उस राज्य या क्षेत्र में' शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था।

धारा 59, 94 और 128 में अंत में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए थे।

" 59. बशर्ते कि प्रत्येक चुनाव में एक सीट या सीटों को भरने के लिए वोट

राज्यों की परिषद में खुले मतदान द्वारा दिया जाएगा।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

33

94. बशर्ते कि यह धारा ऐसे गवाह या अन्य पर लागू नहीं होगी।

वह व्यक्ति जिसने खुले मतपत्र द्वारा मतदान किया हो।

128. बशर्ते कि इस उप–धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे

ऐसे अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को जो ऐसा कोई कार्य करता है।

राज्यों की परिषद में एक सीट या सीटों को भरने के लिए एक चुनाव में कर्तव्य।

मुद्दे

इस मामले में निर्धारण के लिए दो मुद्दे उठते हैं। पहला मुद्दा संबंधित है

'अधिवास' शब्द की सामग्री और महत्व के लिए जबकि दूसरा

मुद्दा के तहत मतदान में 'गोपनीयता' की अवधारणा के महत्व से संबंधित है

संवैधानिक योजना।

संविधान का व्यापक ढांचा

भारत के संविधान में संघ विधानमंडल का प्रावधान है, जिसे कहा जाता है

" संसद, अनुच्छेद 79 के माध्यम से, राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है जिन्हें क्रमशः "राज्य परिषद" के रूप में जाना जाता है, जिसे राज्यसभा और "लोक सभा" के रूप में भी जाना जाता है, जिसे लोकसभा के रूप में भी जाना जाता है। राज्य विधानमंडल के लिए अनुच्छेद 168 में एक समान प्रावधान है, जिसमें राज्य के राज्यपाल के अलावा, एक "विधान सभा" शामिल है, जिसे प्रत्येक राज्य में विधान सभा के रूप में भी जाना जाता है और "विधान परिषद", जिसे कुछ राज्यों में विधान परिषद के रूप में भी जाना जाता है।

संघ विधानमंडल में, अर्थात संसद, राज्य परिषद,

इसमें 250 सदस्य (अधिक से अधिक नहीं) होते हैं, जिनमें से 12 को अनुच्छेद 80 (3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, शेष 238 सदस्य होते हैं –" राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि "। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा राज्य परिषद में सीटों के आवंटन को निर्धारित करती है।

अनुच्छेद 80 (4) में प्रावधान है कि "प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि

राज्य परिषद का चुनाव विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार राज्य की विधानसभा। अनुच्छेद 80 (5) में आगे प्रावधान किया गया है कि राज्य परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चयन उस तरीके से किया जाएगा जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।

अनुच्छेद 84 को "योग्यता" को इंगित करने के लिए एक प्रावधान के रूप में शैलीबद्ध किया गया है।

संसद की सदस्यता "। खंड (ए) और (बी) में, अनुच्छेद 84 इसे बाध्यकारी बनाता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

किसी भी व्यक्ति के लिए जो नागरिक होने के लिए संसद में एक सीट भरने के लिए चुना जाना चाहता है

भारत का और एक निश्चित आयु का, जो राज्य परिषद में एक सीट के मामले में 30 वर्ष से कम नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 84 (सी) में प्रावधान है कि एक उम्मीदवारसंसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए "ऐसी अन्य योग्यताएँ होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित की जा सकती हैं"।

संविधान का भाग XV "चुनाव" के विषय से संबंधित है। वर्तमान में इसमें अनुच्छेद 324 से 329 शामिल हैं। अधीक्षण, निर्देशन और चुनाव का नियंत्रण चुनाव आयोग के पास निहित है।

अनुच्छेद 327 संसद को शक्ति प्रदान करता है, जिसके अधीन

संविधान के प्रावधान, समय-समय पर कानून द्वारा, "चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों" के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, "संसद के किसी भी सदन" के लिए प्रावधान करना, जिसमें "मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और चुनाव के लिए आवश्यक सभी मामले शामिल हैं।

ऐसे सदन या सदनों पर उचित विचार सुनिश्चित करना।

संविधान का भाग 11 "दोनों देशों के बीच संबंधों" से संबंधित है।

संघ और राज्य "। भाग XI का अध्याय । "विधायी" के संबंध में है।

संबंध "। अनुच्छेद 245 आम तौर पर कहता है कि संसद, संविधान के प्रावधानों के अधीन, भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 246 संसद को सातवीं अनुसूची ("संघ सूची", इसके बाद) में सूची । में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की "अनन्य शक्ति" प्रदान करता है। संघ सूची, जैसा कि सातवीं अनुसूची में दिया गया है, में प्रविष्टि संख्या 72 शामिल है, जो अन्य बातों के अलावा,

"संसद के लिए चुनाव"।

आरपी अधिनियम, 1950 और 1951 का इतिहास

वर्ष 1952 में संसद का विधिवत गठन किया गया और

संविधान के प्रावधानों के तहत पहले सत्र के लिए बैठक के लिए बुलाया गया, तब तक संविधान सभा, जिसने संविधान तैयार किया था और उसे अपनाया था, अनुच्छेद 379 में निहित प्रावधानों के अनुसार

अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी। यहां यह जोड़ा जा सकता है कि पहले आम चुनावों के बाद संसद के दोनों सदनों का गठन किया गया था, अनुच्छेद 379, अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद, 1 नवंबर, 1956 से संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा हटा दिया गया था।

अस्थायी संसद, अनुच्छेद 379 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए

उपरोक्त सक्षम प्रावधानों के साथ पढ़ें, कुलदिपनायार v नामक एक कानून अधिनियमित किया।

यू. ओ. आई. [सभरवाल। सी. जे.]

35

" लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 "(आर. पी. अधिनियम, 1950), जो 12 मई, 1950 से लागू हुआ। यह कानून "लोकसभा और राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन और परिसीमन, ऐसे चुनावों में मतदाता की योग्यता, मतदाता सूची तैयार करने,

और उससे जुड़े मामले "। यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि "राज्यों की परिषद में सीटों को भरने के तरीके" से संबंधित विषय–वस्तु भाग–सी राज्यों (बाद में "केंद्र शासित प्रदेशों") के प्रतिनिधियों द्वारा भरा गया था

1950 के अधिनियम 73 (जिसे कानूनों के अनुकूलन (संख्या 2) आदेश, 1956 के साथ पढ़ा जाएगा) के माध्यम से इस कानून में जोड़ा गया, जिसने अन्य बातों के अलावा, आर. पी. अधिनियम, 1950 में भाग IVA जोड़ा।

आर. पी. अधिनियम, 1950 में चुनावों से संबंधित सभी प्रावधान शामिल नहीं थे।

संसद के सदनों के लिए चुनाव के वास्तविक संचालन के लिए प्रावधान, ऐसे सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता आदि को बाद के उपायों में बनाया जाना था। ऐसे अन्य विषयों के लिए प्रावधान करने के लिए, अनंतिम संसद ने उपरोक्त सक्षम प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 379 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आर. पी. अधिनियम, 1951 लागू किया, जिसे 17 जुलाई, 1951 से लागू किया गया था।

आर. पी. अधिनियम, 1951 के भाग II का अध्याय I "के लिए योग्यता" से संबंधित है।

संसद की सदस्यता "। इसमें दो खंड शामिल हैं, अर्थात् धारा 3 और 4। हम धारा 4 से ज्यादा चिंतित नहीं हैं क्योंकि यह लोक सभा की सदस्यता के लिए योग्यताओं से संबंधित है। आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 अपने मूल रूप में यहाँ विवाद का मुख्य कारण है।

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, निम्नानुसार हैः

" 3. राज्य परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता। — (1) ए. व्यक्ति किसी के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं होगा।

भाग ए या भाग बी राज्य (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा)

राज्य सभा में जब तक कि वह किसी संसदीय निकाय का निर्वाचक न हो।

उस राज्य में निर्वाचन क्षेत्र।

(2) एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं होगा। अजमेर और कुर्ग राज्यों या मणिपुर राज्यों के और

प्रतिनिधि होना है।(3) उप–धारा (2) में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई व्यक्ति 36 नहीं करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

किसी भी भाग सी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होना या राज्य परिषद में ऐसे राज्यों का समूह जब तक कि वह एक निर्वाचक न हो

उस राज्य में या किसी भी राज्य में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए

उस समूह में, जैसा भी मामला हो "।

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 को निम्नलिखित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

कानूनों के अनुकूलन (संख्या 2) आदेश, 1956 के माध्यम से और इस प्रकार पढ़ने के लिए आया निम्नानुसारः

" 3. राज्य परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता। – एक व्यक्ति

किसी भी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा

जम्मू और कश्मीर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अलावा राज्य परिषद जब तक कि वह उस राज्य या क्षेत्र में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो।

उपरोक्त प्रावधान में 14 तारीख से और बदलाव किया गया है।

दिसंबर, 1966,1966 के अधिनियम 47 के परिणामस्वरूप, जिसने इसे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू करने के लिए "इसके अलावा अन्य" शब्दों को हटा दिया।

जम्मू और कश्मीर राज्य "। 2003 के अधिनियम 40 ने 28 अगस्त, 2003 से प्रावधान में संशोधन किया है, ताकि "उस राज्य या क्षेत्र में" शब्दों को "भारत में" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके। संशोधित प्रावधान इस प्रकार हैः

" 3. राज्य परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता। – एक व्यक्ति किसी भी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं होगा। या राज्यों की परिषद में केंद्र शासित प्रदेश जब तक कि वह एक निर्वाचक न हो

भारत में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र "।

मुद्दा संख्या 1: 'अधिवास' को हटाना

जिस प्रश्न के समाधान की आवश्यकता है वह यह है कि शब्द का क्या अर्थ है।

" निर्वाचक "। इसके लिए आर. पी. अधिनियम, 1950 और आर. पी. अधिनियम, 1951 के कुछ अन्य प्रावधानों का उल्लेख करना होगा।

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 में संशोधन का प्रभाव आया

2003 के अधिनियम 40 के अनुसार इस प्रकार है कि राज्य परिषद में एक सीट को भरने के लिए चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की पेशकश करने वाले व्यक्ति को अब "भारत में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक" होना आवश्यक है; अर्थात, उसे अब "राज्य" में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होने की आवश्यकता नहीं है। या क्षेत्र "जिससे वह सीट संबंधित है जिसके लिए वह उम्मीदवार है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

37

"निर्वाचक" शब्द को आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 2 (ई) में परिभाषित किया गया है।

यह नीचे लिखा हैः

" ' निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में 'निर्वाचक' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका नाम

अभी उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया है

लागू है और जो किसी भी अयोग्यता के अधीन नहीं है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में उल्लिखित

(43 1950) "।

आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 16, जिसका उल्लेख उपरोक्त में किया गया है।

मैं "निर्वाचक" शब्द की परिभाषा इस प्रकार देता हूँः

" 16. मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यता। — (1) ए.

व्यक्ति को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह

भारत का नागरिक नहीं है; या अस्वस्थ दिमाग का है और एक सक्षम व्यक्ति द्वारा घोषित किया गया है

न्यायालय; याकुछ समय के लिए प्रावधानों के तहत मतदान करने के लिए अयोग्य ठहराया जा रहा है

में भ्रष्ट प्रथाओं और अन्य अपराधों से संबंधित किसी भी कानून का

चुनाव से जुड़ाव।

पंजीकरण को तुरंत उस मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा जिसमें वह इसमें शामिल हैंः

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया हो

अयोग्यता, इस तरह की सूची लागू होने की अवधि के दौरान, हटा दी जाती है। इस तरह के हटाने को अधिकृत करने वाले किसी भी कानून के तहत।

आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 19 "पंजीकरण की शर्तों" से संबंधित है। यह निम्नानुसार हैः

" 19. पंजीकरण की शर्तें। पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन

इस भाग का हर व्यक्ति जोयोग्यता तिथि पर आयु [अठारह वर्ष] से कम नहीं है, और

एक निर्वाचन क्षेत्र में आम तौर पर निवासी है, उस सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

5 एस सी आर।

निर्वाचन क्षेत्र "।

धारा 19 (बी) में दिखाई देने वाली "साधारण निवासी" अभिव्यक्ति को आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 20 में स्पष्ट किया गया है, जिसे निकाला भी जा सकता है, क्योंकि यह इन मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह नीचे लिखा हैः

" 20. 'साधारण निवासी' का अर्थ–(1) एक व्यक्ति नहीं होगा

केवल जमीनी स्तर पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी माना जाता है

जिसका वह मालिक है; या उसके कब्जे में है, उसमें एक निवास घर है।

(1ए) एक व्यक्ति जो अपने सामान्य स्थान से अस्थायी रूप से अनुपस्थित है निवास अपने कारण से सामान्य रूप से निवासी नहीं रहेगा।

उसमें।

(1(ख) संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होगा।

उनके पद की अवधि के दौरान में सामान्य रूप से निवासी होना बंद हो जाता है

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें वह मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत है

ऐसे सदस्य के रूप में अपने चुनाव के समय निर्वाचक, उसके कारण से

अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थिति

सदस्य।

(2) एक व्यक्ति जो किसी भी प्रतिष्ठान में एक रोगी है जिसे पूरी तरह से बनाए रखा जाता है

या किसी भी स्थान पर अन्य कानूनी अभिरक्षा, उसके कारण से नहीं होगीउसमें सामान्य रूप से निवासी माना जाता है।

(3) सेवा योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति माना जाएगा

निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी तारीख को आम तौर पर निवासी, लेकिन जिसके लिए

उसकी ऐसी सेवा योग्यता होने पर, वह सामान्य रूप से होता

उस तारीख को रहने वाले।

(4) राष्ट्रपति द्वारा घोषित भारत में कोई भी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति

चुनाव आयोग के परामर्श से एक कार्यालय होना जिसके लिए

इस उप–धारा के प्रावधान लागू होते हैं, जिन्हें माना जाएगा

निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी तारीख को आम तौर पर निवासी, लेकिन जिसके लिए

ऐसा कोई पद धारण करने पर, वह सामान्य रूप से निवासी होता।

उस तारीख को।

(5) उप–धारा में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति का बयान

(3) या उप–धारा (4) निर्धारित प्रपत्र में बनाई गई और निर्धारित तरीके से सत्यापित की गई, कि [लेकिन उसके पास सेवा योग्यता होने के कारण]

या लेकिन उसके किसी ऐसे पद पर रहने के लिए जिसे उप–धारा कुलदिप नायर v में संदर्भित किया गया है।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.

39

(4) वह किसी निर्दिष्ट स्थान पर सामान्य रूप से निवासी होता।

तारीख, इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में, स्वीकार किया जाएगा

सही है।

(6) उप–धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की पत्नी

या उप–धारा (4) यदि वह सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही है

निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी माना जाएउप–धारा (5) के तहत ऐसे व्यक्ति द्वारा।

(7) यदि किसी भी मामले में कोई सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से कहाँ है

किसी भी प्रासंगिक समय पर निवासी, प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा

मामले के सभी तथ्यों और ऐसे नियमों का संदर्भ जो बनाए जा सकते हैं

संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना; या एक बल का सदस्य होने के नाते जिसके लिए सेना अधिनियम के प्रावधान हैं,

1950 (46 1950 का), लागू किया गया है चाहे वह साथ हो या बिना

संशोधन; या किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य होना, जो सेवा कर रहा है

भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति होने के नाते, भारत के बाहर एक पोस्ट।

कानून के उपरोक्त सभी प्रावधानों को एक साथ पढ़ना होगा और

इसका संयुक्त प्रभाव यह है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अन्य योग्यताओं को पूरा करने के अलावा, किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसकी आयु योग्यता तिथि पर 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (जिसका अर्थ है आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 14 के आधार पर उस वर्ष के जनवरी का पहला दिन जिसमें निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सूची तैयार की जाती है या संशोधित), और, जो यहाँ महत्वपूर्ण है, उस निर्वाचन क्षेत्र में "सामान्य रूप से निवासी" हो।

आर. पी. अधिनियम की धारा 3 में विवादित संशोधन के परिणामस्वरूप,

1951 , अब यह आवश्यक नहीं है कि राज्य परिषद में किसी सीट को भरने के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार उस राज्य का "सामान्य निवासी" हो जिससे वह सीट संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

उपरोक्त संशोधन, जिसे मोटे तौर पर एक संशोधन के रूप में वर्णित किया जा सकता है

अधिवास की आवश्यकता को समाप्त करने को चुनौती दी गई हैहाथ में रिट याचिकाओं में असंवैधानिक।

अधिवास आवश्यकताओं पर प्रस्तुतियाँ

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री सच्चर ने तर्क दिया कि आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 में विवादित संशोधन इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

संघवाद की, संविधान की मूल विशेषता; यह बदलना चाहता है

गणराज्य का चरित्र जो हमारे लोकतंत्र की नींव है और यह

संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को विकृत करता है और है,

इसलिए यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस संबंध में,

यह आग्रह किया गया कि राज्य परिषद संसद का एक सदन है जिसका गठन किया गया है

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व प्रदान करना; कि इसके सदस्यों को विभिन्न राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करना होगा ताकि वे

उनकी समस्याओं को समझने के बाद कानून बनाएँ; कि "परिषद" नाम

राज्यों का "सदन के संघीय चरित्र और एक प्रतिनिधि को इंगित करता है

जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है और जो संबंधित राज्य से संबंधित नहीं है, वह प्रभावी रूप से राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि भारत ने संसदीय को अपनाया है

लोकतंत्र की प्रणाली जिसमें संघ विधानमंडल एक द्विसदनीय विधानमंडल है,

कि ऐसी विधायिका राज्य के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है जिसका प्रतिनिधित्व सदस्यों द्वारा किया जाना है। यह आग्रह किया जाता है कि विवादित संशोधन लोकसभा के इरादे और उद्देश्य में अंतर को दूर करते हैं और यह कि केवल यह तथ्य कि निवास की आवश्यकताओं से संबंधित कानून के उल्लंघन के कई उदाहरण मौजूद हैं, आवश्यकता को हटाने के लिए एक वैध उद्देश्य या तर्कसंगत कारण नहीं हो सकता है

निवास। राज्य के प्रतिनिधि की योग्यता के रूप में निवास के महत्व को दिखाने के लिए राज्यसभा के नियमों पर भी इस संबंध में भरोसा रखा गया है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि अधिवास की आवश्यकता ऊपरी सदन को निचले सदन का 'अहंकार बदल' बनाती है।

याचिकाकर्ता श्री इंद्रजीत की ओर से श्री नरीमन, जबकि

उपर्युक्त तर्कों को पूरक करते हुए, तर्क दिया कि

संविधान और आर. पी. अधिनियम 1950 और 1951 को क्रमशः एक अभिन्न योजना के हिस्से के रूप में पढ़ा गया है जिसके तहत एक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से रहने वाला व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है और यह कि उक्त योजना संविधान के अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 84 के साथ–साथ आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 17,18 और 19 और आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 में भी प्रदान की गई है, जो योजना कुलदिप नायर बनाम.

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

41

परिषद का प्रतिनिधि चरित्र। यह आग्रह किया जाता है कि इसे हटाकर

शब्द 'अधिवास' या 'निवास' या 'अधिवास' शब्द को न पढ़कर या

' अनुच्छेद 80 (4) में 'निवास', प्रतिनिधि संघीय की मूल आवश्यकता

शरीर नष्ट हो जाता है।

श्री वाहनवती, एल. अधिवास के सवाल पर भारत के सॉलिसिटर जनरल

प्रस्तुत किया कि विभिन्न पहलुओं को देखते हुए विवादित संशोधन आवश्यक हो गए

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के कार्यकरण में अनुभव की गई कमियां; कि उक्त संशोधनों ने राज्य परिषद के चरित्र को नहीं बदला या विकृत नहीं किया और

कि निवास/अधिवास की अवधारणा के तहत योग्यता का मामला है

अनुच्छेद 84 (सी) जिसे अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान के तहत संसद द्वारा निर्धारित किया जाना है। इस संबंध में यह आग्रह किया गया कि

विधान सभा के सदस्य यह तय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं कि राज्य परिषद में उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। प्रस्तुतिकरण यह था कि विवादित संशोधन द्वारा योग्यता को अधिक व्यापक बनाया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन आवश्यक हो गया है

गैर प्रतिनिधित्व वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व। भारत संघ के अनुसार, राज्य परिषद के सदस्य के लिए उस राज्य का निर्वाचक या सामान्य निवासी होने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और,

इसलिए, अनुच्छेद 80 के खंड (4) में दिखाई देने वाले "राज्य" शब्द में निवास की आवश्यकता शामिल नहीं है।

संवैधानिक और विधायी इतिहास

((i) व्याख्या का नियमविधायी इतिहास में आने से पहले, हम कह सकते हैं कि

व्याख्या में कहा गया है कि किसी प्रावधान के अधिनियमन के पीछे के इरादे को समझने के लिए यदि वह अस्पष्ट है और उसकी व्याख्या करने के लिए, किसी को ऐतिहासिक विधायी विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुख्य सवाल यह है कि क्या निवास को कभी एक के रूप में माना जाता था

अनुच्छेद 80 (4) के तहत संवैधानिक आवश्यकता।

पुनः में – विशेष संदर्भ सं। 2002 [2002] 8 एस. सी. सी. 237 का ।, यह था

यह देखा गया किः

" अधिनियम बनाने के पीछे के इरादे को समझने के लिए ज्ञात तरीकों में से एक

संविधान सभा के ऐतिहासिक विधायी विकास पर गौर करेंबहस, और 42 के अधिनियमन से पहले के अधिनियम में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

संवैधानिक

प्रावधान "।

((ii) विधायी इतिहास

संविधान ने सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित की है

संविधान में पहली बार। इसका इतिहास सरकार से जुड़ा है। भारत अधिनियम, 1915 जैसा कि 1919 में संशोधित किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत भी, किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निवास की योग्यता थी

अनावश्यक माना जाता है। यह स्थिति तत्कालीन निर्वाचन नियमों के नियम 11 द्वारा इंगित की गई है। इस स्थिति को प्रावधानों द्वारा भी इंगित किया गया है

भारत सरकार अधिनियम, 1935, जिसके तहत केंद्र में विधानमंडल द्विसदनीय था। निचले सदन को 'विधानसभा सदन' कहा जाता था। द अपर

चैंबर को 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' कहा जाता था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 (संक्षेप में, 'जीआई अधिनियम') के तहत, राज्य परिषद एक स्थायी निकाय था।

इसके एक तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। जीआई अधिनियम की छठी अनुसूची ने मताधिकार के लिए प्रावधान किए। उस अनुसूची के भाग 1 में योग्यताएँ थीं। इसमें निर्वाचक की योग्यता के रूप में निवास शामिल नहीं था। हालाँकि, छठी अनुसूची के अन्य भाग थे जो विभिन्न प्रांतों के लिए विशेष रूप से कुछ विषयों से संबंधित थे जिनमें एक आवश्यकता थी।

निवास का। यह 'सामान्य आवश्यकताएँ' शीर्षक के तहत था। हालांकि,

कोई एकरूपता नहीं थी। कुछ मामलों में, निवास को एक योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया था (उदाहरण के लिए मध्य प्रांत, बरार और बंगाल के मामले में) जबकि प्रांतों, अर्थात् असम में, योग्यता 'एक पारिवारिक निवास स्थान या एक ऐसी जगह थी जहां मतदाता सामान्य रूप से रहता था'। इसलिए, निवास की योग्यता समान नहीं थी। यह स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता था। यह एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थगित हो गया।

इस स्तर पर, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सख्त संघवाद के तहत, निम्न

सदन 'लोगों' का प्रतिनिधित्व करता है और ऊपरी सदन में 'संघ' होता है।

संघ का। सख्त संघवाद में दोनों सदनों के पास समान विधायी और वित्तीय शक्तियाँ थीं। हालाँकि, भारतीय संदर्भ में, सख्त संघवाद को नहीं अपनाया गया था।

जीआई अधिनियम के तहत राज्य परिषद राज्यों की परिषद बन गई

भारत का संविधान। यह तथ्य महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, हमें संघ संविधान समिति के कार्यवृत्त पर गौर करना होगा, जिसने मद 21 के माध्यम से जनसंख्या की संख्या के आधार पर वजन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गणना करने का तरीका दर्ज किया है। उक्त मिनट आगे दिखाते हैं कि

यह सिफारिश कि उच्च सदन में वैज्ञानिक, शिक्षक आदि शामिल होने चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रपति को नामित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

43

उच्च सदन की आवश्यकता भी 28 जुलाई, 1947 को संविधान सभा में बहस का विषय थी। ये बहसें उद्देश्य का संकेत देती हैं ऊपरी कक्ष होने के लिए। उच्च सदन का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर गरिमापूर्ण बहस आयोजित करना और अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव को साझा करना था, जिनसे बहस में भाग लेने की उम्मीद की जाती थी।

अंत में 28 जुलाई, 1947 को संविधान द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया गया।

सभा कि संघीय संसद में दो कक्ष होंगे।

संविधान के पहले मसौदे में, चौथी अनुसूची रचना से संबंधित थी

संघीय संसद। चौथी अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ 1 में सदस्यों के लिए सामान्य योग्यताओं पर चर्चा की गई थी, जिसमें नागरिकता और राज्य परिषद में किसी सीट के मामले में न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम नहीं थी। उक्त पैराग्राफ में आगे कहा गया है कि नागरिकता और आयु योग्यता के अलावा, संसद के लिए किसी भी अन्य योग्यता का वर्णन करने का अधिकार होगा जो उपयुक्त हो। संविधान के पहले मसौदे में संलग्न चौथी अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ 6 में राज्य परिषद में चुने जाने वाले उम्मीदवार के लिए राज्य में निवास की योग्यता का प्रावधान किया गया है। प्रथम प्रारूप संविधान के खंड 60 में कहा गया है कि या से संबंधित सभी मामले संघीय संसद के किसी भी सदन के चुनावों से संबंधित चौथी अनुसूची द्वारा विनियमित किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा संघीय संसद के अधिनियम द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। (जोर दिया गया)। हालांकि, चौथी अनुसूची

प्रारूपण समिति द्वारा हटा दिया गया था। यह 11 फरवरी, 1948 का दिन था। इसलिए, इस विलोपन के साथ, निवास की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।

विधायी इतिहास के संबंध में पूरी चर्चा केवल

यह दर्शाता है कि निवास कभी भी संवैधानिक आवश्यकता नहीं थी। ऐसा कभी नहीं था।

राज्यों की परिषद की संरचना के एक आवश्यक घटक के रूप में माना जाता है। इसे केवल योग्यता का मामला माना गया है। इसके अलावा, विधायी इतिहास से पता चलता है कि निवास की योग्यता कभी भी एक स्थिर कारक नहीं रही है। के रूप में

विधायी इतिहास से पता चलता है कि परिसंपत्तियों, आवास, आय, निवास आदि के स्वामित्व को समय–समय पर योग्यता माना जाता था।

संदर्भ और जमीनी वास्तविकता पर। योग्यता जोड़ने की शक्ति संघीय संसद को दी गई थी। इसलिए, विधायी इतिहास

जीआई अधिनियम जैसे संवैधानिक अधिनियमों से पता चलता है कि निवास या अधिवास ऊपरी सदन की संरचना और संरचना के आवश्यक तत्व नहीं हैं।

इस स्तर पर, एक घटना पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। प्रारूपण समिति 44

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

'चुनाव' के विषय पर भाग XIII के तहत एक अलग अध्याय शामिल किया गया

संविधान का मसौदा जो संविधान के भाग XV में अनुच्छेद 327 के अनुरूप था

संविधान। अनुच्छेद 290 संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है।

के सदन के चुनावों से संबंधित या उससे संबंधित सभी मामलों के लिए

संसद। अंततः, द्विसदनीय विधानमंडल के खिलाफ सभी आपत्तियों के बावजूद,

संविधान सभा ने संघीय संसद के गठन का निर्णय लिया

दो कक्ष। अपनी रिपोर्ट में, मसौदा समिति ने बुनियादी सिफारिश की

संसद की सदस्यता के लिए योग्यता जो एक विषय होना चाहिए

संसद के विवेक पर छोड़ दिया। तदनुसार, प्रारूपण समिति अनुछेद 68 ए की सिफारिश की गई जो संविधान के अनुच्छेद 84 से मेल खाती है।

यह पहली बार था जब योग्यता निर्धारित करने के लिए एक प्रावधान शामिल किया गया था।

जिसमें नागरिकता और किसी अन्य के अधीन न्यूनतम आयु शामिल थी।योग्यता जो संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है। द.

प्रारूप समिति ने निम्नलिखित में अनुच्छेद 68 ए को शामिल करने को उचित ठहराया:

शब्द:

" अनुच्छेद 152 राज्य के सदस्यों के लिए आयु योग्यता निर्धारित करता है।

विधायिकाएँ। सदस्यों के लिए कोई संबंधित प्रावधान नहीं है

संसद। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में एक मजबूत भावना है कि

शिक्षा के प्रिस्क्रिप्शन को निर्धारित करने या अनुमति देने वाला प्रावधान और संसद और दोनों की सदस्यता के लिए अन्य योग्यताएँ

राज्य विधानमंडलों को मसौदे में शामिल किया जाना चाहिए। यदि कोई मानक

सदस्यता के लिए उम्मीदवारों के लिए योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए

इतना सटीक हो कि एक चुनाव न्यायाधिकरण एक दिए गए में कहने में सक्षम होगा

और इस तरह के पर्याप्त मानकों के लिए समय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, यदि कोई हो ऐसी अर्हताएँ संविधान में ही निर्धारित की गई हैं,

यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो उन्हें बदलना मुश्किल होगा। सबसे अच्छा कोर्स

इसलिए, संविधान में एक सक्षम प्रावधान सम्मिलित करना होगा।

और इसे उपयुक्त विधायिका पर छोड़ दें कि वह आवश्यक को परिभाषित करे मानकों को बाद में। जो भी योग्यता निर्धारित की जा सकती है, उनमें से एक

उन्हें निश्चित रूप से भारत की नागरिकता होनी चाहिए।

संक्षेप में, विधायी इतिहास इंगित करता है कि निवास एक नहीं है

अनुच्छेद 80 के खंड (4) की संवैधानिक आवश्यकता। निवास योग्यता का विषय है। इसलिए, यह अनुच्छेद 84 के तहत आता है जो संसद को तथ्य स्थिति के आधार पर समय–समय पर योग्यता निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, निवास एक संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान के संदर्भ में, निवास/अधिवास संघवाद की एक घटना है जो संसद द्वारा 45 के रूप में विनियमित होने में सक्षम है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

योग्यता जो अनुच्छेद 84 का विषय है। इससे पता चलता है कि

विधायी इतिहास।

संसद की संरचना

भारत की संसद द्विसदनीय है। राष्ट्रपति के साथ दोनों सदन

संसद का गठन [अनुच्छेद 79]। सदन कई मायनों में एक–दूसरे से अलग हैं। वे अलग–अलग सिद्धांतों पर गठित होते हैं, और कार्यात्मक दृष्टिकोण से, उन्हें सह–समान दर्जा नहीं मिलता है। लोकसभा लोकतांत्रिक है।

वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित कक्ष। यह.

यह लोकप्रिय इच्छाशक्ति को दर्शाता है। कराधान और व्यय के मामलों में इसका अंतिम शब्द है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

दूसरी ओर, राज्यसभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा किया जाता है।

मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, केंद्र–राज्य संबंधों के क्षेत्र में कुछ शक्तियों को छोड़कर, राज्यसभा की भूमिका लोकसभा की तुलना में कुछ हद तक गौण है।

राज्यसभा एक ऐसा मंच है जहाँ अनुभवी सार्वजनिक हस्तियों को प्रवेश मिलता है

आम चुनाव के हंगामे से गुजरे बिना जो लोकसभा के मामले में अपरिहार्य है। यह लोकसभा पर एक पुनरीक्षण कक्ष के रूप में कार्य करता है। दो बहस कक्षों के अस्तित्व का मतलब है कि सरकार के सभी प्रस्तावों और कार्यक्रमों पर दो बार चर्चा की जाती है। एक पुनरीक्षण कक्ष के रूप में, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों में सुधार करने में मदद करती है। यद्यपि राज्यसभा को एक कक्ष के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ राज्यों और भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया जाता है, व्यवहार में, राज्यसभा स्थानीय हितों के समर्थक के रूप में कार्य नहीं करती है। भले ही राज्य विधानमंडलों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य संबंधित राज्य के आदेश पर नहीं, बल्कि अपने स्वयं के विचारों और पार्टी संबद्धता के अनुसार मतदान करते हैं। वास्तव में, 1973 में एक समय पर, एक निजी सदस्य का प्रस्ताव इस आशय का था कि राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाए।

राज्य सभा की संरचना

राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 सदस्य हैं।

जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और 12 को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ऊपरी सदन में सीटें जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आवंटित की जाती हैं, फॉर्मूला पहले पचास लाख के लिए प्रत्येक दस लाख आबादी के लिए एक सीट और उसके बाद प्रत्येक बीस लाख आबादी के लिए एक सीट है। थोड़ा सा।

इसलिए, राज्यों की तुलना में कम आबादी वाले राज्यों को लाभ दिया जाता है 46

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

अधिक जनसंख्या के साथ। इसे "भारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व" कहा जाता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली उचित प्रतिनिधित्व देने में मदद करती है।

अल्पसंख्यक समूहों के लिए। राज्य सभा में किसी राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।

एकल हस्तांतरणीय के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली वोट [अनुच्छेद 80 (1) (बी) और अनुच्छेद 80 (4)]। राज्यसभा एक निरंतर निकाय है। यह.

सदस्यों को नामित किया है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर नामित किया जाता है। निर्वाचित और निर्वाचित के बीच स्थिति में कोई अंतर नहीं है।

राज्य सभा के मनोनीत सदस्य सिवाय इसके कि निर्वाचित सदस्य कर सकते हैं

ऐसा नहीं कर सकते। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी सीटें होती हैं। नए चुनावों और नामांकनों से भरे जाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की शक्ति

भारतीय संघ को 'एक साथ रखने' के रूप में वर्णित किया गया है

यू. एस. ए. और संघ के मामले में घटक इकाइयाँ कनाडा। इसलिए, राज्यसभा को आकस्मिकता आधारित शक्ति प्रदान की गई थी।

अनुच्छेद 249 के तहत राज्य विधानसभाओं पर, जो भारतीय संघ की सरकार को 'अर्ध संघीय' प्रकृति में योगदान देता है। अनुच्छेद 249 (1) के तहत, यदि राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव द्वारा घोषणा करती है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है कि संसद को इनमें से किसी के संबंध में कानून बनाना चाहिए।

प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट राज्य सूची [अनुच्छेद 246 के साथ पठित सातवीं अनुसूची की सूची 2] में गिने गए मामले, संसद के लिए उस मामले के संबंध में पूरे भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाना विधिसम्मत होगा, जब तक कि प्रस्ताव लागू रहता है। अनुच्छेद 249 खंड (2) और

(3) इस प्रावधान के प्रवर्तन पर सीमाओं को निर्दिष्ट करें। अनुच्छेद 251 को जब अनुच्छेद 249 के साथ पढ़ा जाता है तो यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 249 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच विसंगति की स्थिति में, संघ कानून ऐसी विसंगति या

'प्रतिकूलता' की सीमा तक प्रबल होगा। वास्तव में यह प्रावधान राज्य सभा को किसी मामले को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके राज्य विधानमंडल की निर्दिष्ट विधायी क्षमता का अतिक्रमण करने की अनुमति देता है। हालाँकि इसे मूल संवैधानिक योजना में एक सुरक्षा के रूप में शामिल किया गया हो सकता है, लेकिन यह शक्ति केंद्र सरकार को राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है, जो अक्सर केंद्र और राज्य स्तर पर विरोधी दल–संबद्धताओं के अस्तित्व से प्रेरित होती है। सामान्य परिस्थितियों में 'एकात्मक शक्ति' के प्रति यह पूर्वाग्रह अमेरिका या कनाडा में नहीं देखा जाता है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

47

संघवाद निर्माण के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से बहुत ऊर्जा समर्पित की गई है

क्योंकि भारत का संविधान संघीय है। संघवाद की प्रकृति

एक संविधान अब एकीकृत नहीं है।

इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि भारतीय मॉडल है y शासन के संघीय रूप पर आधारित है। आलोचना का जवाब देते हुए

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी, केंद्र में बहस के दौरान

संविधान के मसौदे पर ट्यूएंट असेंबली ने इस प्रकार कहा थाः

" महोदय, मैं कुछ बुनियादी आपत्तियों में जाना चाहूंगा क्योंकि मैंने कहा कि इन आलोचनाओं को छोड़ना हमारे लिए सही नहीं होगा।

अनियंत्रित। मुझे एक ऐसे मामले को उठाने दें जो शायद आंशिक रूप से है।

सैद्धांतिक लेकिन एक जिसमें औसत आदमी के रूप में अब तक एक वैधता है

यह देश चिंतित है। क्या हम एकात्मक संविधान बना रहे हैं? है। दिल्ली में सत्ता को केंद्रीकृत करने वाला यह संविधान? क्या कोई रास्ता दिया गया है?

जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की स्थिति हो सकती है

सुरक्षित, उनकी आवाज़ उनके स्थानीय मामलों के संबंध में सुनी गई

प्रशासन? मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा शुल्क हैसंविधान एक संघीय संविधान नहीं है, और यह एक एकात्मक संविधान है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सवाल कि भारतीय संविधान

एक संघीय होना चाहिए जो हमारे नेता द्वारा तय किया गया है जो नहीं है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में हमारे साथ और अधिक अठारह

कई साल पहले "।

" मैं अपने माननीय मित्र से अब तक एक बहुत ही सरल परीक्षा देने के लिए कहूंगा।

क्योंकि यह संविधान यह पता लगाने के लिए संबंधित है कि क्या यह संघीय है या

नहीं। सरल प्रश्न जो मुझे जर्मन स्कूल से मिला है

राजनीतिक दर्शन यह है कि पहला मानदंड यह है कि राज्य को

एक दिए गए राजनीतिक प्रवर्तन में बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करें

आदेश, दूसरा यह है कि इन शक्तियों का नियमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए

किसी दिए गए क्षेत्र के सभी निवासियों पर; और तीसरा सबसे अधिक है

महत्वपूर्ण और वह यह है कि राज्य की गतिविधि नहीं होनी चाहिए

द्वारा निष्पादन के लिए दिए गए आदेशों द्वारा पूरी तरह से सीमित

श्रेष्ठ इकाई। महत्वपूर्ण शब्द हैं 'पूरी तरह से नहीं होना चाहिए।

परिवेष्टित ', जिसमें राज्य की कुछ शक्तियों की परिकल्पना की गई है, बाध्य हैं

संघीय प्राधिकरण के प्रयोग द्वारा सीमित किया जाना। सब कुछ होना।

इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, मैं आग्रह करूंगा कि हमारा संविधान एक संघीय है

संविधान। मेरा आग्रह है कि हमारा संविधान ऐसा हो जिसमें हम

उन इकाइयों को शक्ति दी गई जो पर्याप्त और महत्वपूर्ण दोनों हैं 48

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

विधायी क्षेत्र और कार्यपालिका क्षेत्र में "।

(जोर दिया गया)

इस संदर्भ में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर संविधान सभा में बोलते हुए

स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

" संवैधानिक महत्व का केवल एक बिंदु है जिस पर मैं प्रस्ताव करता हूं।

. एक संदर्भ बनाने के लिए। इस आधार पर एक गंभीर शिकायत की जाती है कि

बहुत अधिक केंद्रीकरण है और राज्यों ने किया है

नगरपालिकाओं तक सीमित। यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण केवल एक नहीं है

अतिशयोक्ति, लेकिन यह भी एक गलतफहमी पर आधारित है कि क्या

ठीक संविधान ऐसा करने का प्रयास करता है। बीच संबंध के बारे में

केंद्र और राज्यों को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि

मौलिक सिद्धांत जिस पर यह आधारित है। मूल सिद्धांत

संघवाद यह है कि विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण है

केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी कानून द्वारा विभाजित नहीं किया गया

संविधान ऐसा करता है। हमारे संविधान के तहत राज्य किसी भी तरह से नहीं हैं। अपने विधायी या कार्यकारी अधिकार के लिए केंद्र पर निर्भर।

इस मामले में केंद्र और राज्य समान हैं। यह मुश्किल है देखें कि इस तरह के संविधान को केंद्रीकरण कैसे कहा जा सकता है। हो सकता है कि

संविधान केंद्र को संचालन के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र देता है

इसके विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण की तुलना में जो किसी में पाया जाना हैअन्य संघीय संविधान। यह हो सकता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ हैं

केंद्र को दिया गया, राज्यों को नहीं। लेकिन ये विशेषताएँ नहीं हैं

संघवाद का सार है। संघवाद का मुख्य चिह्न, जैसा कि मैंने कहा

विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण के बीच विभाजन में निहित है

संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयाँ। यह है सिद्धांत हमारे संविधान में सन्निहित। ”

(जोर दिया गया)

संविधान में संघवाद की अवधारणा को विभिन्न क्षेत्रों में शामिल किया गया है

प्रावधान। संघवाद के सार को स्थापित करने वाले प्रावधान अर्थात राज्यों और उनके बीच कार्यों के विभाजन के साथ एक केंद्र

संविधान की मंजूरी में, अन्य बातों के अलावा, सातवीं अनुसूची की सूची II और III शामिल हैं जो राज्य विधानमंडलों को पूर्ण शक्तियां देती हैं; अनुच्छेद 252 के तहत राज्य द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में केवल दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से संसद को कानून बनाने का अधिकार, किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाने के प्रावधान के साथ; कुलदिप नायर v.

यू. ओ. 1. [सभरवाल। सी. जे.]

49

राज्य सूची से संबंधित, केवल एक सीमित अवधि के लिए, अनुच्छेद 249 के तहतराष्ट्रीय हित "और" आपातकाल "के दौरान अनुच्छेद 250 के तहत; राष्ट्रपति को अनुच्छेद 258 (1) के तहत राज्यपाल की सहमति से राज्य सरकार को सौंपने की शक्ति प्रदान करना, उन मामलों के संबंध में कार्य करता है जिनके लिए

संघ की कार्यकारी शक्ति कुछ भी निहित होने के बावजूद विस्तारित होती है। संविधान में; 73 वें और 74 वें संशोधन के माध्यम से स्वतंत्र नगर पालिकाओं और पंचायतों के गठन द्वारा शक्ति का विकेंद्रीकरण; आदि।

पुनः में – भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, (विशेष संदर्भ)

1964 का सं. 1) ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 745 (762 पर पैरा 39)], इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" इस प्रश्न से निपटने के लिए एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है।

संघीय संविधान की मौलिक विशेषता। इंग्लैंड में, संसद

संप्रभु है; और डाइसी के शब्दों में, तीन अलग–अलग

संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषताएँ ये हैं कि

संसद को कोई भी कानून बनाने या उसे हटाने का अधिकार है।

व्यक्ति या निकाय को इंग्लैंड के कानून द्वारा एक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है

संसद के कानून को ओवरराइड या अलग करना, और यह कि

संसद का अधिकार या शक्ति रानी के अधिकार के हर हिस्से तक फैली हुई है।प्रभुत्व (1)। दूसरी ओर, की आवश्यक विशेषताएँ

संघवाद "सीमित कार्यपालिका, विधायी और

निकायों के बीच न्यायिक प्राधिकरण जो और के साथ समन्वय करते हैं

एक–दूसरे से स्वतंत्र "। संविधान की सर्वोच्चता है

रोकने के लिए एक संघीय राज्य के अस्तित्व के लिए मौलिक

या तो संघीय इकाई या सदस्य राज्यों की विधायिका शक्ति के उस नाजुक संतुलन को नष्ट करने या खराब करने से जो

संघ, लेकिन एकता में अपने व्यक्तित्व को विलय करने के लिए तैयार नहीं। यहसंविधान की सर्वोच्चता एक के अधिकार द्वारा संरक्षित है

एक योजना के दुभाषिया के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र न्यायिक निकाय

शक्तियों का वितरण। न ही संविधान में कोई बदलाव संभव है।

संघीय या राज्य विधान की सामान्य प्रक्रिया द्वारा (2)। इस प्रकार यह

ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता का दावा नहीं किया जा सकता है

हमारे जैसे संघीय संविधान द्वारा "।

कर्नाटक राज्य के मामले में v. भारत संघ और ए. एन. आर. , [1978] 2

एस. सी. आर. 1, न्यायमूर्ति उन्तवालिया (न्यायमूर्ति सिंघल, न्यायमूर्ति जसवंत सिंह और स्वयं की ओर से बोलते हुए) ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" कड़ाई से कहें तो हमारा संविधान संघीय चरित्र का नहीं है।

अलग, स्वतंत्र और संप्रभु राज्य को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. कहा जा सकता है।

5 एस सी आर।

संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक राष्ट्र बनाने के लिए शामिल हुए या जैसा भी हो सकता है

दुनिया के कुछ अन्य देशों में स्थिति हो। इसकी वजह यह है कियही कारण है कि कभी–कभी इसे अर्ध–संघीय के रूप में चिह्नित किया गया है

प्रकृति में "।

एस. आर. बोम्मई और अन्य में। वी. भारत संघ और अन्य। , आकाशवाणी (1994) एससी (1918)

4] 3 एस. सी. सी. 1, एक संविधान पीठ जिसमें इस न्यायालय के 9 न्यायाधीश शामिल हैं।भारत के संविधान के तहत संघवाद की प्रकृति को स्वीकार किया। न्याय। अहमदी ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 23 में कहा हैः

..... 'संघीय' या जैसी अभिव्यक्तियों की महत्वपूर्ण अनुपस्थिति

' संवैधानिक शब्दावली में 'संघ' के तहत संसद की शक्तियाँ

अनुच्छेद 2 और 3 में पहले दी गई असाधारण शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए, द्वारा प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियाँ

सातवीं अनुसूची की सूची । में प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ा गया अनुच्छेद 248 संघ, संविधान में संशोधन करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति

राज्यों को निर्देश, एकल नागरिकता की अवधारणा, की स्थापना

भारतीय के लिए 'संघीय' उपनाम की उपयुक्तता पर संदेह हैसंविधान। प्रो. ने कहा। के. सी. व्हीयर ने अपने काम 'संघीय सरकारः

' किस बात से कोई संदेह करता है कि भारत का संविधान सख्ती से लागू होता है

और पूरी तरह से संघीय, हालांकि, में हस्तक्षेप की शक्तियां हैं

केंद्र को संविधान द्वारा दिए गए राज्यों के मामलेसरकार और संसद "।

इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में, संप्रभु राज्यों को अपना आनंद मिलता है।

अलग अस्तित्व जिसे बाधित नहीं किया जा सकता; अविनाशी राज्य

एक अविनाशी संघ का गठन किया। भारत में, इसके विपरीत,

संविधान में संशोधन करके कार्यपालिका और विधायिका दोनों की शक्ति। यही कारण है कि भारत के संविधान को अलग तरह से वर्णित किया गया है, अधिक

उचित रूप से 'अर्ध–संघीय' के रूप में क्योंकि यह संघीय का मिश्रण है

और एकात्मक तत्व, बाद वाले की ओर अधिक झुकते हैं लेकिन फिर क्या

क्या किसी नाम में है, मन में जो सुनना महत्वपूर्ण है वह है जोर और

संविधान के विभिन्न प्रावधानों के निहितार्थ

राष्ट्रपति की शक्ति के दायरे और दायरे के संबंध में विवाद

अनुच्छेद 356 और संबंधित प्रावधानों के तहत।

(जोर दिया गया)

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. एल [सभरवाल, सी. जे.]

51

न्यायमूर्ति के. रामास्वामी ने अपने अलग फैसले के अनुच्छेद 247 और 248 में

समान मामला निम्नानुसार देखा गयाः

" 247. भारत के संविधान में परिकल्पित संघवाद एक बुनियादी बात है

विशेषता जिसमें भारत संघ क्षेत्रीय सीमा के भीतर स्थायी है

संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित सीमाएँ और अविनाशी हैं। द.

राज्य संविधान और अनुच्छेदों द्वारा बनाए गए कानून का सृजन है।

2 4 बिना किसी क्षेत्रीय अखंडता के, लेकिन इसके साथ एक स्थायी इकाई

संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा परिवर्तनीय सीमाएँ। न ही रिश्तेदारअनुसूची VII की सूची I और II में विधायी प्रविष्टियों का महत्व

संविधान, और न ही संघ द्वारा राजकोषीय नियंत्रण स्वयं निर्णायक हैं।

यह निष्कर्ष निकालना कि संविधान एकात्मक है। संबंधित विधायी संविधान के अनुच्छेद 245 से 254 तक शक्तियों का पता लगाया जा सकता है। द.

राज्य संविधान संरचना में संघीय और स्वतंत्र है।

विधायी और कार्यकारी शक्ति के अपने प्रयोग में। लेकिन होने के नाते

संविधान के अनुसार राज्य को अलग होने या दावा करने का कोई अधिकार नहीं हैसंप्रभुता। संघ के अनुसार, राज्य अर्ध–संघीय है। दोनों हैं।

संस्थानों का समन्वय करना और उन्हें अपनी–अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए

सामाजिक प्रदान करने के लिए समायोजन, समझ और समायोजन के साथ

लोगों को आर्थिक और राजनीतिक न्याय, संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए

धर्मनिरपेक्षता सहित संवैधानिक लक्ष्य।248. संविधान की प्रस्तावना इसका एक अभिन्न अंग है –

संविधान। सरकार का लोकतांत्रिक रूप, संघीय संरचना, एकता और राष्ट्र की अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और

न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषताएं हैं।

(जोर दिया गया)

यूस्टिस बी. पी. जीवन रेड्डी, अलग निर्णय लिखते हुए (अपने और अपने लिए)

एस. सी. अग्रवाल, जे.) ने पैराग्राफ 276 में निष्कर्ष निकालाः

" तथ्य यह है कि हमारे संविधान की योजना के तहत, अधिक शक्ति

राज्यों की तुलना में केंद्र को प्रदान किए जाने का मतलब यह नहीं है कि

राज्य केवल केंद्र के उपांग हैं। आवंटित क्षेत्र के भीतर

उनके लिए राज्य सर्वोच्च हैं। केंद्र उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

शक्तियाँ। विशेष रूप से, न्यायालयों को एक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए,

एक व्याख्या, जिसका प्रभाव होता है या प्रभाव पड़ता है

राज्यों के लिए आरक्षित शक्तियों को कम करना। ..... रखना ही होगाशक्तियों के किसी भी सचेत पतन के खिलाफ अदालत चौकस है

राज्यों से। यह कहा जा सकता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] में संघवाद।

5 एस सी आर।

संविधान प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि सिद्धांत हमारी अपनी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम और एक मान्यता

जमीनी वास्तविकताओं के बारे में. यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि हमारे संविधान ने

निश्चित रूप से राज्यों की तुलना में केंद्र के प्रति पक्षपात (ऑटोमोबाइल)

ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य, [1963] 1 एससीआर 491 परपृष्ठ 540: आकाशवाणी (1962) एससी 1406। इस पर जोर देना भी उतना ही आवश्यक है

कि अदालतों को सावधान रहना चाहिए कि वे नाजुक तरीके से तैयार किए गए कार्यों को परेशान न करें

व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक योजना।

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 98 में, जे. सावंत ने आगे कहाः –

" इस संबंध में हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि डॉ. अम्बेडकर को क्या करना था

संविधान सभा में बहस का जवाब देते हुए कहें

अनुच्छेद 355, 356 और 357 का संदर्भ। उन्होंने जोर दिया है

कि इस तथ्य के बावजूद कि कई प्रावधान हैं

संविधान जिसके तहत केंद्र को शक्तियां दी गई हैं

राज्यों पर हावी, हमारा संविधान एक संघीय संविधान है। इसका मतलब है

कि राज्य उस क्षेत्र में संप्रभु हैं जो उनके लिए छोड़ दिया गया है। वे.

शांति, व्यवस्था के लिए कोई भी कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और राज्य की अच्छी सरकार "।

पैराग्राफ 106 में उनकी निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैंः

" इस प्रकार संघीय सिद्धांत, सामाजिक बहुलवाद और बहुलवादी लोकतंत्र

जो हमारे संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, वे माँग करते हैं कि

अनुच्छेद 356 (1) के तहत जारी घोषणा की न्यायिक समीक्षा नहीं है।

केवल एक अनिवार्य आवश्यकता है लेकिन एक कठोर कर्तव्य और अभ्यास है उक्त प्रावधान के तहत शक्ति की सीमा इस उद्देश्य के लिए सख्ती से सीमित है।

और उसमें वर्णित परिस्थितियों के लिए और किसी और के लिए नहीं।

(जोर दिया गया)

आईटीसी लिमिटेड बनाम। कृषि उपज बाजार समिति और अन्य। , [2002]

सी. 232, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः –

" भारत के संविधान की व्याख्या की जानी चाहिए, भाषा

अनुमति देना, इस तरह से कि यह शक्तियों को कम नहीं करता है

राज्य विधानमंडल और संघवाद का संरक्षण करते हुएकेंद्रीय सर्वोच्चता जैसा कि इसके कुछ अनुच्छेदों में विचार किया गया है।

(जोर दिया गया)

कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

53

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। , आकाशवाणी (2005)

एससी 1646: [2004] 10 एस. सी. सी. 201 का निर्णय 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने लिया।

न्यायाधीशों, पैराग्राफ 50 में बहुमत के फैसले में कहा गया हैः

" फिर भी एक और कोण जिसे संवैधानिक न्यायालयों ने सलाह दी होगी

कर कानून से निपटने के दौरान ध्यान में रखना बेहतर है,

संघ की शक्तियों के बीच कथित संघर्ष का प्रकाश और

कानून बनाने के लिए राज्य, जिसे बलपूर्वक कहा गया था और जो था

तार्किक रूप से संवैधानिक योजना की विश्लेषणात्मक परीक्षा पर आधारित

जीवन रेड्डी द्वारा, एस. आर. बोम्मई और ओ. आर. एस. में जे. वी. भारत संघ, [1994]3 एस. सी. सी. 1 को छुआ जा सकता है। हमारे संविधान में एक संघीय संरचना है।

संविधान के कई प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि

संस्थापक पिताओं का इरादा एक मजबूत केंद्र बनाने का था।

(जोर दिया गया)

यह सच है कि हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत प्रमुख है और यह कि

सिद्धांत इसकी बुनियादी विशेषताओं में से एक है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संघवादभारतीय संविधान के तहत एक मजबूत केंद्र के पक्ष में झुकता है, एक ऐसी विशेषता जो मजबूत संघवाद की अवधारणा के खिलाफ है। कुछ प्रावधान जो

इस संदर्भ में संदर्भित किया जा सकता है जिसमें संघ की निपटने की शक्ति शामिल है

असाधारण स्थितियाँ जैसे कि आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 250,252,253) और अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी होने की स्थिति में कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; संसद की शक्ति के संबंध में कानून बनाने के लिएराष्ट्रीय हित में राज्य सूची में कोई मामला, यदि राज्य परिषद का कोई प्रस्ताव निर्धारित बहुमत द्वारा समर्थित है (अनुच्छेद 249);

कम से कम दो–तिहाई बहुमत (अनुच्छेद 312) द्वारा समर्थित राज्य परिषद का प्रस्ताव होने की स्थिति में संघ और राज्यों के लिए समान अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण और विनियमन का प्रावधान करने की संसद की शक्ति; केवल एक ही नागरिकता है अर्थात् भारत की नागरिकता; और, शायद सबसे महत्वपूर्ण, नए राज्यों के गठन और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन के संबंध में संसद की शक्ति (अनुच्छेद 3)।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम के मामले में यह न्यायालय। भारत संघ, [1964]

1 396 पर एस. सी. आर. 371 ने कहा है कि हमारा संविधान संघ के सही या पारंपरिक स्वरूप का नहीं है। इसी तरह के अन्य निर्णय भी हैं – न्यायालय, जैसे राजस्थान राज्य और अन्य। वी. भारत संघ आदि। आदि., [1978] पृष्ठ 4 जी और 33 एफ पर आई. एस. सी. आर. 1, जो इन प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य की बात करता है कि हमारे संविधान में संघीय संरचना का जो भी रूप हो, 54 को देखते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

उस शक्ति की सामग्री के आधार पर जो कई प्रावधान अपने साथ ले जाते हैं और उनका उपयोग इसके संचालन में है, जो संघीय की तुलना में अधिक एकात्मक है।

हमारे संविधान में संघवाद की अवधारणा, यह माना गया है कि

क–विधायी शक्ति जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से स्पष्ट होगी। वास्तव में, यह वितरण के संदर्भ में ध्यान में आया है

अनुच्छेद 246 के तहत विधायी शक्तियाँ। { आईटीसी लिमिटेड बनाम। कृषि उपज बाजार समिति और अन्य। , [2002] 9 एस. सी. सी. 232)

अंतर–राज्य संबंध आयोग (सरकारिया आयोग) ने अपने

रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया है कि संविधान से उभरा है 1949 में संविधान सभा की महत्वपूर्ण संघीय विशेषताएं हैं लेकिन यह शास्त्रीय अर्थों में संघीय नहीं हो सकती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत संघ में शामिल होने के समझौते का परिणाम नहीं था। कोई दोहरी नागरिकता नहीं है, अर्थात

संघ और राज्य। (केंद्र–राज्य संबंधों पर आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 8 और 9, भाग–I, और पैराग्राफ 1.3.04, 1.3.05, 1.3.06, 1.3.07]।

स्थिति, स्थिति, भूमिका के बारे में रिट याचिकाकर्ताओं की दलीलें

और संवैधानिक योजना में राज्य परिषद के चरित्र की जांच भारतीय संघवाद की प्रकृति के बारे में ऊपर दिए गए सुव्यवस्थित कानून के आलोक में की जानी चाहिए।

यह तर्क देने के उनके प्रयास में कि अनिवार्य रूप से एक क्षेत्रीय सांठगांठ होनी चाहिए

किसी संघीय व्यवस्था में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ, तमिलनाडु राज्य के लिए श्री राव ने प्रस्तावना में "हम, भारत के लोग" अभिव्यक्ति के उपयोग का उल्लेख किया, अनुच्छेद 1 में भारत को "राज्यों के संघ" के रूप में वर्णित किया गया है; भारत के क्षेत्र में (1) राज्यों के क्षेत्र और (बी) अनुच्छेद 1 (3) के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र शामिल हैं; अनुच्छेद 326 में एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होने की आवश्यकता है ताकि वह निर्वाचक बन सके; और अनुच्छेद 5, 6, 8 और 9 में निहित भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान जो भारत के क्षेत्र पर जोर देते हैं। उन्होंने कोलिन्स पेपरबैक इंग्लिश डिक्शनरी का भी उल्लेख किया ताकि "देश" [एक ऐसा क्षेत्र जो अपने लोगों, संस्कृति, भूगोल आदि द्वारा प्रतिष्ठित है] के अर्थों को इंगित किया जा सके। ; अपनी राजनीतिक स्वायत्तता; राज्य; किसी क्षेत्र या राज्य के लोग] और "राज्य" [एक संप्रभु राजनीतिक शक्ति या समुदाय, ऐसे समुदाय द्वारा

कब्जा किया गया क्षेत्र; ऐसे समुदाय में शक्ति का क्षेत्रः राज्य के मामले; कई क्षेत्रों या समुदायों में से एक जिनकी अपनी सरकारें हैं और एक संप्रभु सरकार के तहत एक संघ का गठन करते हैं, जैसा कि अमेरिका में है।

श्री सच्चर ने इसी तरह की दलील देते हुए कहा कि अधिवास । की आवश्यकता है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. सभरवाल, सी. जे.]

55

राज्यों की परिषद की अवधारणा के लिए इतना आंतरिक है कि इसका विलोपन न केवल

संविधान के काम करने वाली संवैधानिक योजना को नकारता है

अलोकतांत्रिक लेकिन संघीय सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है जो बुनियादी सिद्धांतों में से एक है।

संविधान की विशेषताएँ। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि केंद्रीय विचार को रखा जाना चाहिए

तर्क की सराहना करने के लिए दिमाग में यह है कि यह "लोगों की सरकार" है

और "लोगों द्वारा"।

इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि "जन्म" और "निवास"

क्या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त दो संबंध हैंसंविधान के अनुसार। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए

राज्य परिषद में अनुच्छेद 80 के अनुसार, एक व्यक्ति को नागरिक होना चाहिए।

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक पहचान योग्य संबंध रखने वाला भारत

क्योंकि राज्यों की परिषद की अवधारणा यह मानती है कि एक संघीय में संवैधानिक व्यवस्था, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी समस्याएं हैं,

कई मुद्दों के बारे में हित, चिंताएं और विचार और इसलिए,

विशेष रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच होना

राष्ट्रीय विधानमंडल, अर्थात संसद। जब तक कि कोई व्यक्ति किसी राज्य या राज्य से संबंधित न हो।

केंद्र शासित प्रदेश, संविधान की योजना में उनके पास नहीं होगा यथास्थिति, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता।

लेकिन फिर, भारत पारंपरिक अर्थों में एक संघीय राज्य नहीं है।

इस तथ्य में कोई संदेह नहीं हो सकता है और इसका अत्यधिक महत्व है।

हाथ में उद्देश्य है कि भारत के संदर्भ में, संघवाद का सिद्धांत है

क्षेत्र से संबंधित नहीं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत विभिन्न राज्यों के बीच समझौते द्वारा गठित एक सच्चा संघ नहीं है और क्षेत्रीय रूप से यह संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार के लिए न केवल सीमाओं को बदलने के लिए, बल्कि एक राज्य (पश्चिम राज्य) को समाप्त करने के लिए भी खुला है।

बंगाल बनाम. भारत संघ, [1964] 1 एस. सी. आर. 371)। इसके अलावा, जब शक्तियों के प्रयोग की बात आती है, तो उन्हें केंद्र के पक्ष में भारी तौला जाता है, इतना कि भारत का वर्णन करने के लिए विभिन्न विवरणों का उपयोग किया गया है जैसे किउभयचर रूप में छद्म–संघ या अर्ध–संघ, आदि।

संविधान केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान करता है।

लोक सभा का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। राज्यों की परिषद का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

प्रत्येक राज्य के मतदाता यह तय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं कि राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, चाहे वह निचले सदन के सदस्य के रूप में हो या ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में।

यह संघीय सिद्धांत का हिस्सा नहीं है कि राज्यों के प्रतिनिधि

उस राज्य से संबंधित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] समर्थन के रूप में ऐसा कोई सिद्धांत स्पष्ट नहीं है।

5 एस सी आर।

56

संघवाद की आवश्यक विशेषता, यहां तक कि उच्च के विभिन्न उदाहरणों में भी

अन्य देशों में कक्ष।

अन्य संविधान–राज्यसभा की भूमिका बनाम उच्च सदन की भूमिका

अन्य संविधानों में सदन

सरकार के संसदीय रूपों में 'द्विसदनीयता' का विकास हुआ है

प्रभावी संघीय संरचनाओं की आवश्यकता के साथ कार्यात्मक रूप से जुड़ा हुआ है।

'द्वितीय सदन' या संसद के उच्च सदनों की भूमिका और केंद्र सरकार और संसद के उच्च सदनों के बीच बेहतर समन्वय के बीच यह संबंध।

घटक इकाइयों में से, शायद पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के साथ निश्चित रूप से निर्धारित किया गया था, जिसे द्वारा अनुमोदित किया गया था

वर्ष 1787 में संघ के तेरह मूल राज्य। यू. एस. ए. की कांग्रेस का ऊपरी सदन, जिसे सीनेट के रूप में जाना जाता है, सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर आधारित था, लेकिन इसकी संरचना और शक्तियों के संबंध में बाद वाले से पूरी तरह से अलग था।

तब से, कई राष्ट्रों ने केंद्रीय के द्विसदनीय रूप को अपनाया है।

विधायिका, भले ही उनमें से कुछ संघ नहीं हैं। औपनिवेशिक शासन के कारण, संसदीय शासन के इन ब्रिटिश संस्थानों को भी ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, 1867, जिसके द्वारा कनाडा का अधिराज्य अस्तित्व में आया और भारत का संविधान, 1950। कनाडा में, संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट ('अपर') शामिल हैं।

घर ')। इसी तरह भारत संघ की संसद में लोक सभा शामिल है।

सभा (लोक सभा) और राज्य सभा (राज्य परिषद, जो ऊपरी सदन है)। प्रतिनिधि लोकतंत्रों की एजेंसियों के रूप में अपने कार्यों के संदर्भ में, भारत, यू. एस. ए. और कनाडा के विधानमंडलों में निचले सदन अर्थात् लोकसभा, प्रतिनिधि सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स मोटे तौर पर संरचना की एक ही प्रणाली का पालन करते हैं। अभी तक, निचले सदनों के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से पूर्व–निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन जनसंख्या के

वितरण के अनुसार है, ताकि देश के पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वोट के मूल्य में समानता हो सके। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों और आबादी के घटक राज्यों के अस्तित्व के साथ,

निचले सदन में इन राज्यों को दिया गया प्रतिनिधित्व अत्यधिक असमान हो जाता है। इसलिए, उच्च सदन की संरचना संघवाद का एक संकेतक बन गई है, ताकि घटक राज्यों के हितों को अधिक पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित किया जा सके और केंद्रीय अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग के खिलाफ नियंत्रण और संतुलन का एक तंत्र सुनिश्चित किया जा सके जो घटक के हितों को प्रभावित कर सकता है।

राज्यों।

हालांकि, ध्यान केंद्रित करने का क्षेत्र दूसरे कक्षों की भूमिका का विश्लेषण करना है।

केंद्र–राज्य संबंधों के संदर्भ में अर्थात विभिन्न स्तरों के अवतार

संघवाद। यह उद्देश्य भारतीय राज्यसभा के चयन को भी दर्शाता है,

अमेरिकी सीनेट और कनाडाई सीनेट, क्योंकि ये तीन राष्ट्र बड़े क्षेत्रों और आबादी पर काम करने वाले संघों के उल्लेखनीय उदाहरण हैं, जिनमें एक ही समय में उच्च स्तर की विविधता है। मुख्य मानदंड

संरचना के तरीकों द्वारा घटक इकाइयों को दिए गए प्रतिनिधित्व की अलग–अलग रूपरेखा और संविधान की संवैधानिक योजना में 'उच्च सदनों' के साथ निहित शक्तियों में अंतर की तुलना की जाएगी।

देशों। कई राजनीतिक सिद्धांतकारों और संवैधानिक विशेषज्ञों की राय है कि समकालीन संदर्भ में, 'सेकंड चैंबर्स' अपना इरादा खो रहे हैं।

राज्यों के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने की विशेषताएँ और अधिक आर्थिक के कारण तेजी से राष्ट्रीय संस्थान बन रहे हैं।

राज्यों के बीच सामाजिक और राजनीतिक संबंध विकसित हो रहा है। इसलिए, द्विसदनीयता के काम करने का एक तुलनात्मक अध्ययन एक संघीय शासन प्रणाली के भीतर ऐसी गतिशीलता को समझने में सहायता कर सकता है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक संघीय में द्वितीय सदन का उदय

संदर्भ पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में देखा गया था। तेरह मूल उपनिवेशों को तब तक अलग–अलग संरचनाओं के तहत शासित किया गया था।

ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और इसलिए राज्यों की पहचान के तत्व को बाद के संघ में ले जाया गया। संघीय विधायिका के उद्देश्यों के लिए, छोटे राज्यों द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की मान्यता अधिक प्रतिनिधित्व और शक्ति प्रदान करेगी

बड़े और अधिक आबादी वाले राज्य। इसके अलावा, उस युग में, मतदान का अधिकार गोरे पुरुषों तक ही सीमित था और इसलिए उत्तरी राज्यों में निर्वाचक मंडल का आकार दक्षिणी राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा था, जिनमें नेग्रॉइड आबादी का तुलनात्मक रूप से अधिक अनुपात था, जिनके पास कोई मताधिकार नहीं था।

इसलिए, संघवाद के उद्देश्यों और विभिन्न आकारों के राज्यों के बीच अधिक समानता सुनिश्चित करने के परिणामस्वरूप संविधान के मसौदे में एक समझौता हुआ। जबकि कांग्रेस के निचले सदन, यानी प्रतिनिधि सभा का गठन जनसंख्या वितरण के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाना था, सीनेट सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व पर आधारित था।प्रारंभ में, प्रत्येक राज्य के दो सीनेटरों को संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, लेकिन 1913 के 17 वें संशोधन के बाद, सीनेटरों को एक राज्य के पूरे मतदाताओं के बीच खुले वयस्क मताधिकार द्वारा चुना गया है। यह स्वाभाविक है

सीनेट के कामकाज में संघीय सरकार और बड़े राज्यों की शक्ति के लिए एक प्रति–संतुलन सुनिश्चित करने का उद्देश्य बना हुआ है। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि अमेरिकी सीनेट को कुछ अतिरिक्त विधायी शक्तियां भी दी गई हैं, जो इसे अन्य 58 में दूसरे सदनों से अलग करती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

देशों। इसके अलावा, सीनेट एक निरंतर निकाय है जिसमें सीनेटर्स हैं।

6 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या फिर से चुनाव चाहते हैं। संघ में और अधिक राज्यों के जुड़ने के साथ, अमेरिकी सीनेट की संख्यात्मक ताकत भी बढ़ गई है।

कनाडा डोमिनियन की संसद अपने वर्तमान में थी

संविधान अधिनियम, 1867)। कनाडा आज तक सरकार के एक संसदीय रूप और एक गवर्नर–जनरल नियुक्त के साथ एक संवैधानिक राजशाही बना हुआ है।ब्रिटिश संप्रभु राज्य के नाममात्र प्रमुख के रूप में कार्य करता है। 1867 के अधिनियम से पहले, बड़े क्षेत्र जो अब कनाडा का गठन करते हैं (क्यूबेक के अपवाद के साथ, जिसका फ्रांसीसी शासन का ऐतिहासिक प्रभाव था) को अलग–अलग क्षेत्रों के रूप में प्रशासित किया जा रहा था। इस अधिनियम ने उनके बीच एक संघ की स्थापना की

घटक प्रांत। इसलिए, डोमिनियन की संसद प्रभावी रूप से संघीय विधायिका थी जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट शामिल थे। संविधान में सीनेट को दो प्रमुख कार्य दिए गए थे। सबसे पहले, यह "शांत दूसरे विचार" का कक्ष होना था। इस तरह की सीमा को निर्वाचित हाउस ऑफ कॉमन्स को कनाडा को एक देश में बदलने से रोकना चाहिए।

" भीड़तंत्र ", जैसा कि परिसंघ (1867 अधिनियम) के निर्माताओं ने यू. एस. ए. के मामले में देखा। इस प्रकार सीनेट को कई प्रकार के कानूनों को पलटने की शक्ति दी गई थी।

संविधान, इस प्रकार 'कॉमन्स को किसी भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने से रोकता है'। जबकि लोकसभा का गठन निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से किया जाना था ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स और अमेरिकी कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तर्ज पर चुनावों के आधार पर, सीनेट ने मौजूदा क्षेत्रों के बजाय नामित क्षेत्रों को समकक्ष प्रतिनिधित्व दिया।

प्रांत। प्रत्येक राज्य से सीनेटरों की संख्या परिणामस्वरूप परिसंघ में परिवर्तन के साथ भिन्न हुई है। हालाँकि, कनाडाई सीनेटरों की नियुक्ति गवर्नर–जनरल द्वारा कार्यपालिका के परामर्श से की जाती है और

इसलिए कनाडाई सीनेट संरचनात्मक रूप से सदन के अधीन रहा है।

के गठन से पहले ओंटारियो और क्यूबेक में विधान परिषदें 1867 में परिसंघ। एक के डिजाइन के पीछे एक और सम्मोहक कारक

कमजोर सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका का हालिया उदाहरण था जहां कुछ वर्गों ने गृह युद्ध को बहुत अधिक अनुमति देने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में देखा था।

राज्यों को शक्ति। हालाँकि, कनाडाई सीनेट की भूमिका व्यापक रूप से रही है।

रचना के अपने तरीके की आलोचना की।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

59

दूसरी ओर भारतीय राज्यसभा की उत्पत्ति से लाभ हुआ

कई राष्ट्रों का संवैधानिक इतिहास जिसने संविधान की अनुमति दी

उच्च सदन के संघीय कार्यों की जांच करने के लिए सभा। हालांकि,

' ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय विधानसभाओं में 'द्विसदनीयता' की शुरुआत की गई थी।

1921 में शासन किया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भी एक उच्च सदन का निर्माण किया।

संघीय विधानमंडल में, जिसके सदस्यों को सदस्यों द्वारा चुना जाना था

प्रांतीय विधानमंडलों और रियासतों के मामले में जिनके द्वारा नामित किया जाएगा

ऐसे क्षेत्रों के शासक। हालांकि, युवा भारतीय संघ द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकताओं के कारण, संघ में राज्यों की एक परिषद (राज्यसभा)

संसद को एक संघीय आदेश के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में देखा गया था। इसके अलावा

पूर्व ब्रिटिश प्रांतों में, रियासतों के विशाल क्षेत्र थे जिन्हें संघ के तहत प्रशासित किया जाना था। इसके अलावा, आर्थिक क्षेत्र में विविधता

और क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक कारकों ने भी नए के लिए एक चुनौती पेश की

स्वतंत्र देश। इसलिए, उच्च सदन की स्थापना की गई थी

संविधान निर्माता जिनमें काफी हद तक राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होंगे और जिनमें गैर–राजनीतिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्यों की एक निश्चित संख्या होगी। हालांकि, राज्यसभा में राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का वितरण न तो समान है और न ही पूरी तरह से जनसंख्या वितरण पर आधारित है। एक बुनियादी सूत्र का उपयोग छोटे राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देने के लिए किया जाता है, लेकिन बड़े राज्यों को अतिरिक्त आबादी के लिए प्रतिगामी रूप से महत्व दिया जाता है। इसलिए राज्यसभा राज्यों के लिए असमान प्रतिनिधित्व को शामिल करती है लेकिन आनुपातिक रूप से छोटे राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सीटों के इस तरह के आवंटन के पीछे का सिद्धांत छोटे राज्यों के हितों की रक्षा करना है, लेकिन साथ ही साथ लघु राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है ताकि अल्पसंख्यक मतदाताओं के प्रतिनिधियों की इच्छा बहुमत पर हावी न हो।

भारत में, भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 निर्धारित करता है –

साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाएँ [अनुच्छेद 80 (1) (ए) और 80 (3)]। राज्यों के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य विधानसभाएँ

एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से [अनुच्छेद 80 (4)]। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका संसद द्वारा निर्धारित किया गया है [अनुच्छेद 80 (5)]। भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन की गणना सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] की चौथी अनुसूची में की गई है।

5 एस सी आर।

60

संविधान, जिसे अनुच्छेद 4 (1) और 80 (2) के साथ पढ़ा जाता है। यह आवंटन

राज्यों के प्रवेश और पुनर्गठन के साथ यह स्पष्ट रूप से भिन्न रहा है। अनुच्छेद 83 (1) के तहत, राज्यसभा सदस्यों के साथ एक स्थायी निकाय है। 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले और हर 2 साल में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का एक तिहाई।

ये 'अस्थिर शर्तें' एक ऐसे परिणाम की ओर भी ले जाती हैं जहां राज्यसभा की सदस्यता लोक सभा में मौजूद राजनीतिक समीकरणों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है।एक ही समय में सभा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है और इसकी सदस्यता के लिए योग्यता भारत की नागरिकता और 30 वर्ष की आयु की आवश्यकता है [अनुच्छेद 84]। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति हैं –

राज्य सभा और सदन के पदेन सभापति का चुनाव करने के लिए बाध्य हैउपसभापति। अनुच्छेद 90, 91, 92 और 93 इन अधिकारियों की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताते हैं।

दूसरी ओर अमेरिकी सीनेट समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

एक खुले मताधिकार द्वारा, और इसलिए सीनेट की कुल सदस्यता है100 पर। आम तौर पर अमेरिकी समाज में यह माना जाता है कि एक सीनेटर का कार्यालय प्रतिनिधि सभा में एक सदस्य की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा रखता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सीनेटरों को 1913 के 17 वें संशोधन से पहले संबंधित राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था, जिसके द्वारा खुले मताधिकार की प्रणाली शुरू की गई थी। इच्छुक उम्मीदवार

सीनेट के लिए चुनाव 30 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए और 9 वर्ष से अधिक समय से यू. एस. ए. का नागरिक होना चाहिए और जिस राज्य से वे चुनाव चाहते हैं, वहां उनका कानूनी निवास भी होना चाहिए। सीनेटर 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें एक तिहाई सदस्य या तो सेवानिवृत्त होते हैं या हर 2 साल में फिर से चुनाव चाहते हैं। सीनेटर असीमित संख्या में पुनः चुनाव लड़ सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति सीनेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

जिसे केवल गतिरोध की स्थिति में मामलों पर मतदान करने का अधिकार है। हालांकि, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पीठासीन कार्य एक राष्ट्रपति प्रो द्वारा किया जाता है।

टेम्पोर (अस्थायी पीठासीन अधिकारी), जो आम तौर पर राज्य से सीनेटर होता है

सबसे लंबे समय तक निरंतर सेवा के साथ बहुसंख्यक दल। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दलों के सदन के नेताओं को दोनों दलों के लिए अलग–अलग बैठकों में चुना जाता है (जिन्हें कॉकस/सम्मेलन के रूप में जाना जाता है) जो प्रत्येक नए सत्र से पहले आयोजित किए जाते हैं।

कांग्रेस। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियाँ भी अपने–अपने दल चुनती हैं।

कॉकस में सचेतक और नीति समितियाँ।

हालाँकि कनाडा की संसद में सीनेट एक निर्वाचित निकाय नहीं है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, कुलदिप नायर बनाम पर गवर्नर–जनरल द्वारा सीनेटरों की नियुक्ति की जाती है।

यू. ओ. 1. [सभरवाल। सी. जे.]

61

प्रधानमंत्री की सलाह। आज तक सदन की सदस्यता

अनिवार्य रूप से घटक प्रांतों और क्षेत्रों। प्रधानमंत्री का सीनेटरों की नियुक्ति के संबंध में निर्णय के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है

कोई और और समीक्षा के अधीन नहीं है। सदस्यता के लिए योग्यताएँ30 वर्ष की आयु की आवश्यकता है, कनाडा के डोमिनियन की नागरिकता द्वारा

प्राकृतिक जन्म या प्राकृतिककरण और प्रांत के भीतर निवास जहाँ से

नियुक्ति की मांग की जाती है। क्यूबेक के मामले में, नियुक्त व्यक्ति निवासी होने चाहिए

जिस निर्वाचन जिले के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। एक बार नियुक्त होने के बाद, सीनेटर

75 वर्ष की आयु तक पद धारण करें जब तक कि वे लगातार दो सत्रों से चूक न जाएं।

संसद। 1965 तक वे आजीवन पद पर रहते थे। भले ही

कनाडाई सीनेट को पूरी तरह से कार्यपालिका पर निर्भर माना जाता है क्योंकि

नियुक्तियों में पार्टी संबद्धता, आयु तक कार्यकाल रखने का प्रावधान

सीनेट में बहुमत और इस प्रकार निचले सदन या से असहमतकार्यपालिका, क्योंकि निचले सदन के सदस्य 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।

अब जब रचना के तरीकों पर एक सामान्य विचार प्राप्त हो गया है

भारत, अमेरिका और कनाडा में द्वितीय सदनों में से कोई भी इसका विश्लेषण कर सकता है

नीति के दायरे के साथ–साथ व्यावहारिक तुलना करने के लिए आगे बढ़ने से पहले प्रणालियाँ और इन सदनों को दी गई अतिरिक्त विधायी शक्तियाँ।

सीनेट में राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व का विचार बनाया गया था

अमेरिकी संविधान। इसलिए 17 वें संशोधन को एक सुधार माना जा सकता है क्योंकि इसने सीनेटरों के चुनाव को आम जनता के लिए खुला कर दिया था।

हालांकि, राज्यों में प्रत्येक वोट को दिया गया महत्व संबंधित राज्य की आबादी के विपरीत आनुपातिक है। इसलिए, अमेरिकी सीनेट में प्रति वोट वास्तविक प्रतिनिधित्व छोटे राज्यों के लिए अधिक है और

इसी तरह अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए बहुत कम है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से, यह ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है जहाँ अल्पसंख्यक मतदाताओं के प्रतिनिधि बहुमत के प्रतिनिधियों पर कानून का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

कनाडा ने समतुल्य प्रतिनिधित्व के परिवर्तन का विकल्प चुना

नामित क्षेत्र और इसलिए प्रांतों और क्षेत्रों को दिया गया प्रतिनिधित्व मोटे तौर पर जनसंख्या वितरण पर आधारित था। हालांकि, जनसांख्यिकीय

कई दशकों में परिवर्तन प्रत्येक क्षेत्र को दिए गए वास्तविक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, कनाडाई सीनेट में नियुक्ति की नाममात्र प्रणाली यह स्थिति पैदा करती है कि सीनेट की इच्छा आम तौर पर संघीय कार्यकारी के साथ प्रवाहित होगी।

असमान लेकिन तौला हुआ आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि अपनाई गई

छोटे राज्यों को प्रतिनिधित्व के मामले में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है, यह आगे देखा गया कि यू. एस. ए. जैसे राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व को लागू करना। समान रूप से विभाजित के प्रतिनिधित्व में अपार विषमता पैदा होगी

निर्वाचक मंडल के भाग। इसके अलावा, स्वतंत्रता के बाद से भारत में राज्यों का गठन और पुनर्गठन काफी हद तक भाषाई आधार पर और समूहों के बीच सांस्कृतिक एकरूपता के अन्य कारकों पर रहा है, जहां इन समूहों के आकार

समुदाय एक–दूसरे की तुलना में बहुत भिन्न होते हैं। इसलिए, राज्य सभा में राज्यों को सीटें आवंटित करना, या तो समान शर्तों पर या पूरी तरह से

जनसंख्या वितरण के अनुसार चरम समाधान होते। इसलिए, सीटों के आवंटन के उद्देश्यों के लिए लागू किया गया सूत्र

चौथी अनुसूची एक उचित समाधान प्रतीत होती है। इस बात को इस प्रवृत्ति से स्पष्ट किया जा सकता है कि 1962 और 1987 के बीच असम से छह नए राज्य बनाए गए थे। अगर भारत ने समान प्रतिनिधित्व मॉडल का पालन किया होता, तो इन नए राज्यों में भारत की आबादी का मुश्किल से 1 प्रतिशत हिस्सा होता।ऊपरी सदन में सभी मतों का 25 प्रतिशत दिया गया। काल्पनिक रूप से, अधिक आबादी वाले राज्यों ने कभी भी इसकी अनुमति नहीं दी होगी। इस प्रकार भारत में संघवाद के काम करने की एक अनिवार्य विशेषता यानी नए राज्यों का निर्माण, जिनमें से कुछ में हिंसक अलगाववादी प्रवृत्तियां थीं, प्रत्येक राज्य के लिए समान रूप से प्रतिनिधित्व के अमेरिकी सिद्धांत के तहत कठिन होता।

भारतीय संविधान की तरह आयरलैंड के संविधान में सख्त नियम नहीं हैं।

बसु द्वारा भारत का संविधान, 6 वीं संस्करण। खण्ड. एफ)। इसी प्रकार, मामले में जापानी संविधान, योग्यताएं क़ानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं न कि द्वारा

संविधान। अन्य देशों के विभिन्न संविधान बताते हैं कि

योग्यता के मामले में निवास एक संवैधानिक आवश्यकता बन जाती है।

केवल तभी जब यह संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया हो। निवास नहीं है उच्च सदन की संरचना का सार। ऊपरी सदन नहीं करेगा

यदि एक तत्व के रूप में निवास को हटा दिया जाता है तो पतन हो जाता है। इसलिए, यह संघवाद की पूर्व शर्त नहीं है।

यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि जब तक राज्य को होने का अधिकार है

राज्यों की परिषद में इसके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो हैं

कहा जा सकता है कि ऊपरी सदन की सदस्यता के लिए आवासीय आवश्यकता एक हैसभी संघीय संविधानों की अनिवार्य बुनियादी विशेषता। इसलिए, यदि भारतीय

संसद ने अपने विवेक से आवासीय योग्यता की आवश्यकता नहीं होने का फैसला किया है, 63

कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

यह निश्चित रूप से संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन नहीं करेगा। हमारा संविधान केवल इसलिए एक संघीय संविधान नहीं रह जाता है क्योंकि एक राज्यसभा सदस्य उस राज्य में "सामान्य रूप से निवास नहीं करता है" जहाँ से वह चुना जाता है।

क्या मूल संरचना सिद्धांत एक की वैधता निर्धारित करने के लिए उपलब्ध है

कानून

सवाल यह उठता है कि क्या मूल के उल्लंघन का आधार है

संविधान की विशेषता संसद के किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने का आधार हो सकती है जैसे कि यह संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का आधार हो सकता है। इसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है

भारत का संघ कि बुनियादी संरचना सिद्धांत क़ानूनों पर लागू नहीं होता है।

श्री सच्चर, हालांकि, के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने के लिए दर्द में थे

इस संबंध में सकारात्मक निवेदन। उन्होंने डॉ. डी. सी. वाधवा और अन्य का उल्लेख किया। वी. बिहार राज्य और अन्य। , [1987] 1 एस. सी. सी. 378 एक पूर्व मामले के रूप में जिसमें बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद अध्यादेश, 1985 को निरस्त कर दिया गया थाअसंवैधानिक और इस आधार पर अमान्य कि यह संवैधानिक योजना के प्रतिकूल था।

उस मामले में यह पाया गया कि बिहार सरकार ने इसे एक व्यवस्थित राज्य बना दिया था।

समय-समय पर अध्यादेशों को फिर से जारी करने का अभ्यास और यह था

पद्धतिगत रूप से और विचार-विमर्श की भावना के साथ किया गया "। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सत्र के समापन के तुरंत बाद, संसदीय कार्य विभाग के विशेष सचिव द्वारा सभी विभागों को एक परिपत्र पत्र भेजा जाएगा जिसमें उन्हें सूचित किया जाएगा कि विधानमंडल का सत्र स्थगित कर दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 212 खंड (2) (ए) के तहत सभी अध्यादेश विधानमंडल के फिर से इकट्ठा होने की तारीख के छह सप्ताह के बाद लागू नहीं होंगे और "इसलिए उन्हें विधि विभाग के संपर्क में रहना चाहिए और सभी संबंधित अध्यादेशों को उनकी समाप्ति की तारीख से पहले फिर से घोषित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए"।

उपरोक्त तथ्य स्थिति में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया:

" जब संवैधानिक प्रावधान यह निर्धारित करता है कि एक अध्यादेश

राज्यपाल द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए घोषित किया गया

छह सप्ताह की समाप्ति पर परिचालन बंद करना

विधायिका और सरकार का पुनर्मिलन यदि वे चाहें

अध्यादेश के प्रावधानों को आगे भी जारी रखा जाएगा

छह सप्ताह की अवधि विधानमंडल के समक्ष जानी होती है जो कि 64 है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

कानून बनाने के कार्य के लिए सौंपा गया संवैधानिक अधिकार, यह

निश्चित रूप से शक्ति का एक रंगीन अभ्यास होगा

सरकार विधायिका की अनदेखी करेगी और अध्यादेश को फिर से लागू करेगी

और इस प्रकार नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को विनियमित करना जारी रखना

कार्यपालिका द्वारा बनाए गए अध्यादेश के माध्यम से। ऐसी रणनीति होगी

संवैधानिक योजना के प्रतिकूल, क्योंकि यह सक्षम करेगाकार्यपालिका के मामले में अपनी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करना

कानून बनाना–एक आकस्मिक स्थिति में और गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका के कानून बनाने के कार्य को अपने लिए अभिमानी बनाएं।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दृष्टिकोण द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों के बारे में लिया गया था

एक्सप्रेस संवैधानिक के स्पष्ट उल्लंघन के सामने बिहार राज्य

प्रावधान।

विद्वान वकील ने इसके बाद एल. चंद्र कुमार बनाम का उल्लेख किया। संघ का

भारत और ओआरएस। , [1997] 3 एस. सी. सी. 261 (7 न्यायाधीश) (अनुच्छेद 17 पृष्ठ 277 और अनुच्छेद 99 पर p./311)], इस मामले में न केवल संविधान संशोधन उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित कर रहा था।

(प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों से) इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उच्च न्यायालयों से न्यायिक समीक्षा लेने से मूल संरचना का उल्लंघन होता है

सिद्धांत लेकिन यहां तक कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 28, जिसके तहत "उच्चतम न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों की अधिकारिता के अपवर्जन" का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 136 को भी निरस्त कर दिया गया था।

उपरोक्त संदर्भ में इंद्र साहनी का भी उल्लेख किया गया है।

वी. भारत संघ और अन्य। , [2000] 1 पृष्ठ 202 पर एस. सी. सी. 168 (पैराग्राफ 65)। इस न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उस मामले में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि

अधिनियमित कानून (मलाईदार परत पर केरल अधिनियम) ने मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लंघन किया। न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से सवाल यह था कि क्या संविधान और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून द्वारा गारंटीकृत समानता के अधिकार को विधायी अधिनियम द्वारा शून्य पर रखा जा सकता है। उठाए गए मुद्दे राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से भी संबंधित थे। फैसले के पैराग्राफ 65 में, यह निम्नानुसार देखा गया थाः

" ..... इस देश में संसद और विधायिका अतिक्रमण नहीं कर सकते। संविधान की मूल विशेषता, अर्थात् अनुच्छेद 14 में निहित समानता का सिद्धांत, जिसका अनुच्छेद 16 (1) एक पहलू है। क्या मलाईदार परत को बाहर नहीं किया गया है या आगे की जातियों को शामिल किया गया है

पिछड़े वर्गों की सूची में, स्थिति समान होगी, अर्थात्, न केवल अनुच्छेद 14 का बल्कि बुनियादी प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। संविधान की संरचना। मलाईदार परत 65 का गैर–अपवर्जन

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

या पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने से,

इसलिए, पूरी तरह से अवैध होनाः इस तरह की अवैधता मूल को आहत करती है

भारत के संविधान को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है संवैधानिक संशोधन। इसलिए केरल विधानमंडल सबसे कम है।

इस तरह के अवैध भेदभाव को कायम रखने के लिए सक्षम। और भी क्या?

संसद ऐसा नहीं कर सकती, केरल विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता।

यह अच्छी तरह से तय है कि कानून को अमान्य या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

केवल दो आधारों पर अर्थात् (i) विधायी क्षमता की कमी और (ii) किसी भी मौलिक अधिकार या संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन (श्रीमती.

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, [1975] एस. सी. सी. 1)। श्री सच्चर द्वारा भरोसा किए गए अन्य मामलों में जहां एक क़ानून के बारे में टिप्पणियां की गई हैं।बुनियादी संरचना के विपरीत होने के कारण, न तो सवाल उठाया गया था और न ही

माना जाता है कि अमान्यीकरण के लिए बुनियादी संरचना सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों के लिए उपलब्ध है न कि कानूनों के लिए।

ए. एन. रे, सी. जे., इंदिरा नेहरू गाँधी के मामले में (ऊपर), में कहा गया

अनुच्छेद 132 निम्नानुसार हैः –

" प्रत्यर्थी की ओर से तर्क कि साधारण विधायी

प्रतिबंधों में संविधान संशोधन जैसे उपाय विषय हैं।

बुनियादी संरचना या बुनियादी विशेषताओं को नुकसान नहीं पहुँचाना या नष्ट नहीं करनापूरी तरह से अस्वास्थ्यकर। यह सीमा पर सराहना की जानी चाहिए कि

तर्क है कि विधायी उपाय प्रतिबंधों के अधीन हैं बुनियादी संरचनाओं या बुनियादी विशेषताओं का सिद्धांत विधायी की बराबरी करना है।

संविधान संशोधन के साथ उपाय।

(जोर दिया गया) "

अपने फैसले के पैराग्राफ 153 में उन्होंने इस प्रकार फैसला सुनायाः –

" प्रत्यर्थी की दलीलें कि 1974 के संशोधन अधिनियम और 1975 बुनियादी विशेषताओं या बुनियादी संरचना या बुनियादी के अधीन हैं।

ढांचा दो आधारों पर विफल रहता है। सबसे पहले, विधायी उपाय नहीं हैं

बुनियादी विशेषताओं या बुनियादी संरचना या बुनियादी के सिद्धांत के अधीन

फ्रेमवर्क। दूसरा, केशवानंद भारती के मामले में बहुमत का दृष्टिकोण

(उपर्युक्त) यह है कि उनतीसवां संशोधन जिसमें दो क़ानून रखे गए हैं नौवीं अनुसूची और अनुच्छेद 31–बी में चुनौती देने के लिए खुला नहीं है

बुनियादी विशेषताओं को नुकसान या विनाश का आधार,

संरचना या बुनियादी ढांचा या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. के उल्लंघन के आधार पर।

5 एस सी आर।

मौलिक अधिकार "।

(जोर दिया गया)

इसी मामले में, के. के. मैथ्यू, जे. ने अपने अलग फैसले के पैराग्राफ 345 में निम्नानुसारः –

" मुझे लगता है कि मूल संरचना को नष्ट करने या क्षतिग्रस्त करने के लिए अवरोध

संविधान का संशोधन शक्ति की सीमा से आता है

अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन को भारती के अनुच्छेद में बहुमत से पढ़ा गया।

मामला (ऊपर) उनकी धारणा के कारण कि वहाँ कुछ हैं

संविधान में मूलभूत विशेषताएं जो इसके निर्माताओं का इरादा था

वहाँ हमेशा के लिए रहें। लेकिन मुझे ऐसा कोई अवरोध नहीं मिलता है

जहाँ तक संसद या राज्य विधानमंडलों की कानून पारित करने की शक्ति है

चिंतित हैं। अनुच्छेद 245 और 246 शक्ति प्रदान करते हैं और यह भी प्रदान करते हैं कानून पारित करने के लिए इन अंगों की शक्ति पर सीमा। यह केवल

संविधान में अधिनियमित विशिष्ट प्रावधान जो

उस शक्ति पर सीमा के रूप में कार्य करें। प्रस्तावना, हालांकि एक हिस्सा है

संविधान का, न तो शक्ति का स्रोत है और न ही इसकी कोई सीमा है

उस शक्ति को। प्रस्तावना की वैचारिक आकांक्षाओं को निर्धारित करता है

लोग। में निर्धारित महान अवधारणाओं की आवश्यक विशेषताएं

संविधान के विभिन्न प्रावधानों में प्रस्तावना का वर्णन किया गया है।

संविधान के मुख्य भाग में ये विशिष्ट प्रावधान हैं जो

लोकतंत्र के किस प्रकार का निर्धारण उस साधन के संस्थापक करते हैं

स्थापित; न्याय की गुणवत्ता और प्रकृति, राजनीतिक, सामाजिक और

आर्थिक जो उनकी इच्छा थी, विचार की स्वतंत्रता की सामग्री

और अभिव्यक्ति जो उन्होंने उस दस्तावेज़ में निहित की, का दायरा

स्थिति और अवसर की समानता जो उन्होंने उसमें निहित की थी।

संविधान में अधिनियमित ये विशिष्ट प्रावधान अकेले कर सकते हैं स्थापित संविधान की मूल संरचना का निर्धारण करना। ये

विशिष्ट प्रावधान, या तो अलग से या संयोजन में निर्धारित करते हैं

प्रस्तावना में निर्धारित महान अवधारणाओं की सामग्री। यह असंभव है।

बुनियादी संरचना की किसी भी ठोस अवधारणा को गॉसमर से बाहर निकालने के लिए

प्रस्तावना में निर्धारित अवधारणाएँ। के विशिष्ट प्रावधान

संविधान वे चीजें हैं जिनसे मूल संरचना का निर्माण होना चाहिए।

बुना हुआ। प्रत्यर्थी के वकील का तर्क आगे बढ़ा

यह धारणा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कुछ मानदंड हैं

एक आदर्श लोकतंत्र और संसद या राज्य द्वारा निर्धारित कानून मेंविधायिकाओं का उन मानदंडों पर परीक्षण किया जाना चाहिए और यदि वे अभाव में पाए जाते हैं, तो

गिराया जाना चाहिए। संसद या कुलदिप नायर बनाम द्वारा निर्धारित चुनाव के मानदंड।

यू. क्यू. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

67

के प्रावधानों के आलोक में राज्य विधानमंडलों का परीक्षण किया गया

संविधान या उससे आवश्यक निहितार्थ कानून का गठन करते हैं

भूमि को। वह कानून परीक्षण की तरह किसी अन्य परीक्षण के अधीन नहीं हो सकता है।

एक आदर्श लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 356 में, उन्होंने निम्नानुसार शासन कियाः –

" भारती के मामले (ऊपर) में बहुमत से कोई समर्थन नहीं है

वकील द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव कि एक साधारण कानून, यदि वह

बुनियादी संरचना को नुकसान पहुँचाने या नष्ट करने को खराब माना जाना चाहिए याप्रस्ताव है कि एक संविधान संशोधन में एक अधिनियम डालना

नौवीं अनुसूची अधिनियम के प्रावधानों को असुरक्षित बना देगी

यह कारण कि वे एक मूल संरचना को नुकसान पहुँचाते हैं या नष्ट करते हैं

मौलिक अधिकारों को छीनने या संक्षिप्त करने से नहीं बल्कि कुछ अन्य अधिकारों से

बुनियादी संरचना। और, सिद्धांत रूप में, मुझे स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता हैप्रस्ताव की शुद्धता "।

(जोर दिया गया)

इसी मामले में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने अलग फैसले के पैराग्राफ 691 में कहाः –

“ सामान्य कानूनों को अपनी वैधता के लिए दो परीक्षणों का उत्तर देना होता हैः (1) द.

संविधान के अध्याय I, भाग XI में परिभाषित और निर्दिष्ट, और(2) इसे अनुच्छेद 13 (1) और (2) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

संविधान "। बुनियादी संरचना ", बहुमत के निर्णय से, है मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है और न ही वास्तव में

संविधान। बुनियादी संरचना का सिद्धांत इससे बुना गया है

संविधान के संदर्भ और संशोधन की शक्ति के अधीन है

इसके लिए क्योंकि यह एक घटक शक्ति है। संशोधन करने की शक्ति

आवश्यक विशेषताएँ–यह, संक्षेप में, बुनियादी सिद्धांत का कमान है।संरचना। वैधता से संबंधित मामलों में यह पूरी तरह से अनुचित है।

संविधान के तहत बनाए गए सामान्य कानूनों का।

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 692 में, वह निम्नानुसार शासन करेगाः

– सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

" कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कुछ सीमाएँ इस पर काम करती हैं

उच्च शक्ति इस कारण से कि यह एक उच्च शक्ति है। एक संवैधानिक

अनुच्छेद 368 (2) द्वारा प्रदत्त राज्यों का आधा। एक साधारणकानून को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। दो शक्तियाँ,

यद्यपि एक ही वंश की प्रजातियाँ, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं और हैं

इसलिए यह विभिन्न सीमाओं के अधीन है।

(जोर दिया गया)

कर्नाटक राज्य में एक संविधान पीठ (7 न्यायाधीश) बनाम। संघ का & एन. आर. , [1977] 4 एस. सी. सी. 608 ने, बहुमत के अनुसार, (अनुच्छेद 120) निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" ..... प्रत्येक मामले में जहां उस पर निर्भरता रखी जाती है,

कानून पर हमला, चाहे वह सामान्य हो या घटक (में

"एक बुनियादी संरचना" के हिस्से के रूप में संदर्भों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए संविधान के प्रावधानों को व्यक्त करें।

पैराग्राफ 197 में, यह निम्नानुसार देखा गया थाः –

" ..... यदि कोई कानून विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर है, तो यह

कथित आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि उसने जोड़ा है

इतने लंबे समय तक एक संवैधानिक प्रावधान के लिए कुछ, या पूरक है क्योंकि जोड़ या पूरकता किसी के साथ असंगत नहीं है

संविधान का प्रावधान "।

इसी निर्णय के पैराग्राफ 238 में निम्नलिखित टिप्पणियां भी हैं –

इस मुद्दे के बारे में:

" श्री सिन्हा ने यह भी तर्क दिया कि एक साधारण कानून इसके खिलाफ नहीं जा सकता है।

मूल योजना या केंद्र–राज्य की मूल रीढ़

संविधान में निहित संबंध। उन्होंने अपना तर्क रखा

यह सम्मान बहुत ही सरल तरीके से किया गया क्योंकि उन्हें इसमें कठिनाई महसूस हुई।इसे सीधे तरीके से यह कहते हुए रखना कि एक साधारण कानून नहीं कर सकता है

संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। श्रीमती के मामले में

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण ने ऐसा तर्क दिया था

इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया।

हमारे संविधान के संदर्भ में 'बुनियादी विशेषता' का सिद्धांत, इस प्रकार,

यह सामान्य विधान पर लागू नहीं होता है, जिसके लिए केवल दोहरे मानदंड हैं, कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

69 .

अर्थात्ः

0 इसे अपनी क्षमता के भीतर किसी मामले से संबंधित होना चाहिए;

7

((ii) अनुच्छेद 13 के तहत इसे अनुचित नहीं माना जाना चाहिए।

किसी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध या उसके प्रतिकूल होने के रूप मेंसंवैधानिक निषेध व्यक्त करें।

इस संबंध में लोक सेवा न्यायाधिकरण को भी संदर्भित किया जा सकता है।

बार एसोसिएशन बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य , [2003] 4 एस. सी. सी. 104 और आंध्र राज्यप्रदेश और ओआरएस। वी. मैकडॉवेल एंड कंपनी एंड ओआरएस। , [1996] 3 एससीसी 709।

मूल संरचना सिद्धांत की शक्ति पर सीमा लागू होती है

संविधान में संशोधन के लिए संसद। संविधान में संशोधन

अनुच्छेद 368 के तहत मूल के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है

संविधान की संरचना। एक साधारण कानून को इतना चुनौती नहीं दी जा सकती है।

संसद द्वारा अपनी विधायी क्षमता के भीतर बनाए गए कानून को चुनौती

संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर इस प्रकार है

याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, 'निवास' संवैधानिक आवश्यकता नहीं है और,

इसलिए, बुनियादी संरचना के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता है।

समकालीन विधान और संवैधानिक योजना का तर्कश्री नरीमन ने आगे कहा कि संविधान और

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को एक "अभिन्न योजना" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

इस संदर्भ में, इस तथ्य का संदर्भ दिया गया था कि अस्थायी संसद

जिसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और प्रतिनिधित्व पारित किया लोक अधिनियम, 1951 वही था जो संविधान निकाय ने पारित किया था

और संविधान को अपनाया।

'चुनाव' की एकीकृत योजना के बारे में विवाद के समर्थन में,

श्री नरीमन सबसे पहले एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम का उल्लेख करेंगे। निर्वाचन अधिकारी,

नमक्कल संस्थान और अन्य। , आकाशवाणी (1952) एससी 64: [1952] एससीआर 218। उस में

मामले में, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा उसकी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया गया है

निर्वाचन अधिकारी के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के आदेश को रद्द करने के लिए

एक चुनाव, इस आधार पर कि उसके पास आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के प्रावधानों के कारण निर्वाचन अधिकारी

संविधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति फजल अली ने कहाः

" मोटे तौर पर, इससे पहले कि एक चुनाव तंत्र लाया जा सके ऑपरेशन, तीन आवश्यकताएँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है,

और यह तय किया जाना चाहिए कि ये कानून और नियम कैसे होंगे।बनाया गया; (2) के कर्तव्य के साथ प्रभारित एक कार्यकारी होना चाहिए

चुनाव के उचित संचालन को सुनिश्चित करना; और (3) एक

न्यायिक न्यायाधिकरण इससे या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए

अनुच्छेद 324 दूसरे के साथ और अनुच्छेद 329 तीसरी आवश्यकता के साथ। ..... संविधान का भाग XV वास्तव में अपने आप में एक संहिता है जो प्रदान करता है

उपयुक्त कानूनों को लागू करने और स्थापित करने के लिए संपूर्ण आधार–कार्य

चुनाव के संचालन के लिए उपयुक्त तंत्र।

" लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, जिसे पारित किया गया था संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत संसद विस्तृत विवरण देती है।

संबंधित सभी मामलों और सभी चरणों के संबंध में प्रावधान

इस देश में विभिन्न विधानसभाओं के लिए चुनाव। " तर्क की भ्रांति इस बात में निहित है कि इसमें एक कदम उठाया गया है।

चुनाव के समतुल्य के रूप में चुनाव को आगे बढ़ाना। का निर्णय हालाँकि यह अपील एक शब्द के निर्माण पर नहीं है

" चुनाव ", लेकिन समग्र अभिव्यक्ति के निर्माण पर –

" इसके संदर्भ और परिवेश में किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

संविधान के भाग XV की योजना को ध्यान में रखते हुए और

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। जाहिर है, तर्क

प्रस्तुत किए गए प्रश्न के दृष्टिकोण की इस विधि से कोई संबंध नहीं है

यह अपील, जो मुझे एकमात्र सही तरीका प्रतीत होता है।

(जोर दिया गया)

एन. मोहिंदर सिंह गिल और अन्र. वी. मुख्य चुनाव आयुक्त,

एल्ही और ओआरएस। , [1978] 1 एस. सी. सी. 405 (427)] में एक समान दृष्टिकोण लिया गया था

शब्दों का उच्चारणः –

" संविधान की सर्वोपरि नीति–यह घोषणा करने में निर्माता कि

कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा सिवाय इसके कि इसे कैसे प्रदान किया गया है।

क्योंकि अनुच्छेद 329 (बी) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में,

यह हमें पढ़ने के लिए मजबूर करता है, जैसा कि जे. फजल अली ने पोन्नुस्वामी में किया था, संविधान कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

71

और एक अभिन्न योजना के रूप में एक साथ अधिनियम। इसका कारणचुनाव मुकदमेबाजी को चुनाव के बाद के चरण तक स्थगित करना यह है कि

चुनाव अनुचित रूप से लंबे या बाधित नहीं होंगे। गति और

निर्वाचकों के लिए उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में शीघ्रता

विधायी निकाय निर्णय के दौरान सुझाए गए वास्तविक कारण हैं।

38. अनुच्छेद 324, जिसे हम पहले निर्धारित कर चुके हैं, एक पूर्ण प्रावधान है।

राष्ट्रीय और राज्य चुनावों की पूरी जिम्मेदारी सौंपना और,

इसलिए, उस कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक शक्ति। यह सच है। कि अनुच्छेद 324 को संवैधानिक योजना के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए

और 1950 का अधिनियम और 1951 का अधिनियम।

उपरोक्त विचार को गुजरात की संविधान पीठ ने दोहराया था।

विधानसभा चुनाव मामला [2002] 8 एससीसी 237। संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को एक योजना के रूप में एक साथ पढ़कर, यह था

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः –

" (ई) न तो संविधान के तहत और न ही के प्रतिनिधित्व के तहत

लोक अधिनियम, सीमा की किसी भी अवधि के लिए निर्धारित किया गया हैसमय से पहले विधान सभा के गठन के लिए चुनाव कराना

मौजूदा का विघटन। हालांकि, योजना को देखते हुए

संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव

विधान सभा के गठन के लिए छह महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए

विधान सभा के विघटन की तारीख से "।

श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया कि वही संसदीय निकाय जो पारित हुआ

संविधान, अनुच्छेद 379 (निरस्त होने के बाद से) के तहत अनंतिम संसद के रूप में कार्य करते हुए, इस संबंध में कानून भी पारित किया कि राज्य परिषद में किसी राज्य का प्रतिनिधि कौन होना था। उन्होंने बताया कि आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 3, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, ने "राज्य परिषद की सदस्यता के लिए योग्यताओं" को निर्धारित करते हुए यह आवश्यक बना दिया था कि राज्य परिषद में किसी भी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने की पेशकश करने वाला व्यक्ति उस राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए "एक निर्वाचक" होना चाहिए, जो सिद्धांत भाग ए या भाग बी राज्यों (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा) पर समान रूप से लागू होता है। मूल अधिनियम में, भाग सी राज्यों के लिए एक अलग व्यवस्था थी, जिनमें से कुछ को अलग–अलग समूहों में रखा गया था

राज्य परिषद में एक आम प्रतिनिधि (राज्य या समूह के लिए) को वापस करने के लिए एकीकृत निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान, हालांकि "उस राज्य में" निर्वाचक की अनिवार्य स्थिति की प्रकृति में योग्यता वहां भी लागू होगी, जिसमें कुछ संशोधन यहाँ और वहाँ होंगे, जिसमें आम तौर पर व्यक्ति 72 वर्ष का था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

उस राज्य में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना आवश्यक है या

उस समूह के किसी भी राज्य में, जैसा भी मामला हो "। अजमेर और कुर्ग राज्यों या मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के मामले में, जो

राज्यों की परिषद में इस उद्देश्य के लिए दो अलग-अलग समूहों का गठन किया गया, व्यवस्था सीटों को घुमाने की थी और इसलिए यह उम्मीदवार के लिए आवश्यक था

राज्य के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना जिसमें

ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव होना है।

तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. पी. राव ने कहा था कि

इस विषय पर एक समान दृष्टिकोण और 'समकालीन' के सिद्धांत की सहायता के लिए दबाव डाला गयाप्रदर्शनी '। उनका निवेदन था कि यह सिद्धांत व्याख्या के लिए प्रासंगिक है।

संविधान के अनुच्छेद 80 (4) में "प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि" शब्द हैं। उनका तर्क था कि आरपी अधिनियम 1950 और 1951 समकालीन हैं।

स्वयं संविधान सभा द्वारा बनाए गए कानून जो अस्थायी के रूप में कार्य करते हैं

संसद और यह कि वे अनुच्छेद 79 और 80 की व्याख्या के लिए एक उपयोगी सहायता हैं, जैसे कि अधीनस्थ विधान एक अधिनियम की व्याख्या के लिए है।

उपरोक्त संदर्भ में श्री राव ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया। वह करेगा।

आग्रह करें कि आई. सी. गोलक में अनुच्छेद 236 से निकाले गए निम्नलिखित शब्द

नाथ और ओआरएस। वी. पंजाब और अन्न राज्य। , [1967] 2 एस. सी. आर. 762:

" संविधान की सबसे अच्छी व्याख्या वह है जो उसे प्राप्त हुई है।

समकालीन न्यायिक निर्णयों और अधिनियमों से। हम एक पाते हैं

बहुत से न्यायाधीशों और विधायकों के बीच दृष्टिकोण की दुर्लभ सर्वसम्मति

संशोधन शक्ति की पहुंच के भीतर। संसद में कोई नहीं इस प्रस्ताव पर संदेह तब हुआ जब संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम

1951 का पारित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इसके अधिकांश सदस्य

संसद भी संविधान सभा की सदस्य थी।

(जोर दिया गया)

इसके बाद वह हैनलोन वी. का उल्लेख करेंगे। द लॉ सोसाइटी, [1980] 2 ऑल ईआर 199,

218 (एच. एल.)], यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" मामलों और प्रमुख पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन क़ानून पर क्रेज़

विधि (7 वीं संस्करण, 1971, पृ. 158), क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल

(12 टी एडन। , 1969 , पी. पी. 74–75) हैल्सबरीज़ लॉज़ (तीसरा संस्करण) 1961 खंड। 36 ,

पैराग्राफ 606, पी। 401) मुझे लगता है कि के गठन का समर्थन करता है

निम्नलिखित प्रस्तावः

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. (सभरवाल, सी. जे.)

73

(1) अधीनस्थ विधान का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है

मूल अधिनियम, लेकिन केवल जहां द्वारा अधिनियम में संशोधन करने की शक्ति दी गई है

विनियम या जहाँ अधिनियम का अर्थ अस्पष्ट है।

(2) अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम एक संसदीय या

प्रशासनिक समकालीन अधिनियम की व्याख्या लेकिन नहींइसके अर्थ को तय या नियंत्रित करने के लिए इसे प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाएगी

नियम बनाने वाला प्राधिकारी या न्यायाधीश दुभाषिया के रूप में और

इस संभावना की उपेक्षा करें कि विनियमन पर भरोसा किया गया था

गलत धारणा या अति अधिकार।

(3) नियम जो एक निश्चित व्याख्या के अनुरूप हैं

अधिनियम उस व्याख्या की पुष्टि करता है।

(4) जहाँ अधिनियम द्वारा निर्मित एक रूपरेखा प्रदान की गई है

समकालीन रूप से तैयार किए गए नियम, बाद वाले एक हो सकते हैंपूर्व के अर्थ के लिए विश्वसनीय मार्गदर्शक।

(5) नियम एक स्पष्ट मार्गदर्शक हैं, और निर्णायक हो सकते हैं, जब

वे अधिनियम को संशोधित करने की शक्ति के अनुसरण में बनाए गए हैं,

एफ.

विशेष रूप से यदि वे उसी दिन परिचालन में आते हैं जबऐसा कार्य करें जिसे वे संशोधित करते हैं।

(6) नियमों से भी स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है जो हैं –

प्रभाव डालने के लिए जैसे कि मूल अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो।

श्री राव ने ब्रिटिश एम्यूजमेंट्स कैटरिंग ट्रेड्स पर भी भरोसा जताया। वेस्टमिंस्टर सिटी काउंसिल, [1988] 1 ऑल ई. आर. 740,745 डी. ई.], एक निर्णय जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लिंग

पैराग्राफ में निर्दिष्ट मामले का अनुसरण करता है।देशबंधु गुप्ता एंड कंपनी एंड ओआरएस में। वी. दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज स्टेशन लिमिटेड, [1979] 4 एस. सी. सी. 565, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" समकालीन व्याख्या के सिद्धांत (समकालीन प्राधिकरण से प्राप्त व्याख्या के संदर्भ में किसी क़ानून या किसी अन्य दस्तावेज़ की व्याख्या करना) का आह्वान किया जा सकता है, हालांकि यह हमेशा निर्माण के प्रश्न के लिए निर्णायक नहीं होगा (मैक्सवेल 12 वां संस्करण। पी. 268)। क्रॉफर्ड ऑन स्टैच्युटरी कंस्ट्रक्शन (1940 संस्करण) में पैराग्राफ 219 में (पीपी पर। 393–395) यह कहा गया है कि प्रशासनिक

द्वारा स्थापित निर्माण (अर्थात समकालीन निर्माण) एक क़ानून को निष्पादित करने के लिए आरोपित प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारी)

आम तौर पर इसे पलटने से पहले स्पष्ट रूप से गलत होना चाहिए; ऐसी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी.

5 एस सी आर।

निर्माण, आमतौर पर व्यावहारिक निर्माण के रूप में जाना जाता है, हालांकि

नियंत्रित नहीं करना, फिर भी काफी वजन का हकदार है; यह है

अत्यधिक प्रेरक। बालेश्वर बगारती बनाम। भागीरथी दास, आई. एल. आर. 35

कैल। 701 713 में सिद्धांत, जिसे मथुरा मोहन में दोहराया गया था साहा बनाम। राम कुमार साहा, आई. एल. आर. 43 कैल. 790 : ए. आई. आर. 1916 कैल 136 को मोकर्जी, जे. द्वारा इस प्रकार कहा गया हैः

यह व्याख्या का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें एक क़ानून उस पर रखी गई व्याख्या को बहुत महत्व देगा,

इसके अधिनियमन का समय और तब से, उन लोगों द्वारा जिनका यह कर्तव्य रहा है इसे बनाना, निष्पादित करना और लागू करना। मैं एक पल के लिए भी यह सुझाव नहीं देता कि

इस तरह की व्याख्या का किसी भी तरह से नियंत्रण प्रभाव पड़ता है

अदालतें; ऐसी व्याख्या, यदि अवसर उत्पन्न होता है, तो होनी चाहिए

त्रुटि, एक अदालत बिना किसी हिचकिचाहट के इस तरह का पालन करने से इनकार कर देगीनिर्माण "।

यू. पी. और अन्य का राज्य। वी. बाबू राम उपाध्याय, [1961] 2 एससीआर 679 (सीबी),

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" कानून के तहत बनाए गए नियमों को सभी उद्देश्यों के लिए माना जाना चाहिए – निर्माण या दायित्व जैसे कि वे अधिनियम में थे और हैं

अधिनियम में निहित होने के समान प्रभाव का होना, और होना चाहिए

निर्माण या दायित्व के सभी उद्देश्यों के लिए न्यायिक रूप से नोटिस किया गयाः देखें

मैक्सवेल "ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स", 10 वां संस्करण। , पीपी। 50–51 . ”

तमिलनाडु राज्य बनाम। एम/एस। हिंद स्टोन और ओआरएस। , [1981] 2 एससीसी 205,

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम एक कानून है।

संसद द्वारा अधिनियमित और संसद द्वारा समीचीन घोषित

जनहित। नियम 8–सी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है।

अधिनियम की धारा 15 द्वारा उस पर। एक सांविधिक नियम, जबकि हमेशा मूल कानून के अधीनस्थ, अन्यथा, भाग के रूप में माना जाना है

कानून का और उतना ही प्रभावी "। कानून के तहत बनाए गए नियम अनिवार्य हैं

निर्माण या दायित्व के सभी उद्देश्यों के लिए ठीक वैसे ही व्यवहार किया जाए जैसे कि

वे अधिनियम में थे और उसी प्रभाव के होने चाहिए जैसे कि निहित

निर्माण या दायित्व ": (यू. पी. राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय, [1961] 2 एससीआर 679, 702; मैक्सवेल को भी देखें। कुलदिप नायर का हस्तक्षेप बनाम।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

75

स्टेट्यूट्स, 11 वीं संस्करण। पीपी। 49–50) . इसलिए, वैधानिक नियमों के अनुसार बनाए गए

संसद द्वारा सौंपी गई शक्तियों के लिए संसद द्वारा बनाया गया कानून है। संविधान के अनुच्छेद 302 के अर्थ के भीतर।

आयकर आयुक्त, जालंदूर बनाम। अजंता इलेक्ट्रिकल्स, पंजाब

[1995] 4 एस. सी. सी. 182, यह इस प्रकार शासित थाः

" यद्यपि नियम धारा को प्रभावित, नियंत्रित या अपमानित नहीं कर सकता है।

अधिनियम का, जब तक इसका वह प्रभाव नहीं है, यह होना चाहिए

अधिनियम की धारा के समान बल होने के रूप में माना जाता है।

प्रस्तुतिकरण, इस प्रकार, समकालीन प्रदर्शन का सिद्धांत है

"प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि" शब्दों की व्याख्या करने के लिए प्रासंगिक है

समकालीन विधान के संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 80 (4)

स्वयं संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जो अस्थायी संसद के रूप में कार्य करता है, ठीक उसी तरह जैसे अधीनस्थ विधान का उपयोग मूल अधिनियम का अर्थ निकालने के लिए किया जाता है।

लेकिन फिर, विषय के लिए उपरोक्त दृष्टिकोण की भ्रांति में निहित है

तथ्य यह है कि अस्थायी संसद द्वारा बनाए गए विधान से संवैधानिक नियम नहीं बना। इसकी पवित्रता या मानक मूल्य नहीं है

संवैधानिक कानून। जब 1951 के अधिनियम पर बहस हुई, तो किसी ने यह तर्क नहीं दिया कि

संविधान सभा द्वारा निवास योग्यता पर पहले ही निर्णय ले लिया गया था और इसलिए, कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मूल और व्युत्पन्न शक्ति के बीच का अंतर मूल संरचना के सिद्धांत का आधार है।

"समकालीन प्रदर्शन" का सिद्धांत, यदि नहीं तो पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

वर्तमान उद्देश्यों के लिए गुमराह करना। यदि संविधान ने एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति का उपयोग किया था, जिसमें व्याख्या की आवश्यकता थी, तो जिस तरह से संविधान को लागू किए जाने के तुरंत बाद इसकी व्याख्या की गई थी, वह इसके लिए एक उपयोगी सहायता होगी।

व्याख्या। इस मामले में ऐसा कोई सवाल नहीं है। वास्तव में, संसद ने पहले आवासीय योग्यता का प्रावधान किया था। लेकिन इसने विवादित संशोधन के माध्यम से इसे निरस्त करने का फैसला किया। दोनों बार, यानी मूल रूप से 1951 में आर. पी. अधिनियम को लागू करते समय और 2003 में इसे संशोधित करते समय, संसद अपनी विधायी क्षमता के भीतर काम कर रही थी। यह सच है कि 1951 में अस्थायी संसद ने सदस्यता के लिए योग्यता के रूप में राज्य के अंदर निवास निर्धारित किया था। राज्यों की परिषद। लेकिन, यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उसी संसद ने संविधान सभा के रूप में योग्यता (निवास सहित) को संवैधानिक आवश्यकता तक बढ़ाने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय इस बात की चेतना दिखाई थी कि योग्यता के प्रावधान की आवश्यकता हो सकती है।

समय–समय पर समीक्षा की जाए और इसलिए, संविधान में ही इसे निर्धारित करना अनुचित पाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

निवास का प्रावधान, विवादित संशोधन से पहले, में मौजूद था

संसदीय कानून, अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (और नहीं)

संविधान)। संविधान में ही कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है

योग्यता के रूप में निवास की आवश्यकता। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस चीज के लिए संविधान ने स्वयं प्रावधान नहीं किया था, उसे हटाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है।असंवैधानिक है।

यह तर्क दिया गया है कि यह अस्थायी संसद थी, जो

संविधान सभा ने आर. पी. अधिनियम, 1951 पारित किया था। हालांकि, अगर उस तर्क को स्वीकार किया जाना था, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि सभी अनंतिम संसद द्वारा पारित कानूनों को वही दर्जा प्राप्त है जो

संविधान या ऐसा कोई विशेष दर्जा। यह न तो स्वस्थ तरीका होगा और न ही स्वीकार्य। आर. पी. अधिनियम 1951 सहित अस्थायी संसद द्वारा पारित सभी अधिनियम, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य कानून की तरह कानून हैं। तदनुसार, उनमें से प्रत्येक किसी भी अन्य क़ानून की तरह संशोधन लाने के लिए संसद की शक्ति के अधीन है। इन वर्षों में आर. पी. अधिनियम, 1950 और आर. पी. अधिनियम, 1951 में कई संशोधन किए गए हैं। यदि याचिकाकर्ता का तर्क सही होना था, तो इन अधिनियमों में अब तक किए गए सभी संशोधनसंवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।

जबकि इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि संविधान

और आर. पी. अधिनियम चुनावों की एक एकीकृत योजना बनाते हैं, यह इस बात का पालन नहीं करता है कि इस कारण से धारा 3 आर. पी. अधिनियम 1951 में अधिवास की आवश्यकता, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, उक्त योजना का हिस्सा है ताकि इसे संवैधानिक माना जा सके।

आवश्यकताएँ।

अनुच्छेद 368 के तहत प्रतिबंध

यह प्रस्तुत किया गया है कि आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3, जैसा कि पहले थी

अनुच्छेद 80 (4) के साथ पठित संशोधन ने संसद में "राज्यों का प्रतिनिधित्व" सुनिश्चित किया था। अनुच्छेद 368 (2) में परंतुक (घ) का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि

यहां तक कि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव करने वाला संवैधानिक संशोधन भी आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन के बिना प्रभावी नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि एक आवश्यक परिणाम के रूप में, यह पालन किया जाना चाहिए कि आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 में किया गया परिवर्तन वह है जो अब संसदीय कानून द्वारा, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित नहीं करता है, या किसी भी मामले में जो मौजूदा कानून में बदलाव करता है, और इस प्रकार एक संशोधन जिसे केवल आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 में संशोधन करके प्रभावी नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है और 77

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

इसके लिए प्रक्रिया। विचाराधीन प्रोविसो की शक्ति पर सीमाएँ लगाती हैं

संविधान में संशोधन के लिए संसद। अनुच्छेद 368 (2), प्रासंगिक सीमा तक, निम्नानुसार हैः –

" संविधान का संशोधन केवल द्वारा शुरू किया जा सकता है

संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करना,

और जब विधेयक प्रत्येक सदन में कुल के बहुमत से पारित किया जाता है

उस सदन की सदस्यता और कम से कम दो के बहुमत से

उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से एक तिहाई

राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो विधेयक को अपनी सहमति देगा और

तदनुसार संविधान में संशोधन किया जाएगा –

विधेयक की शर्तेंः

बशर्ते कि यदि ऐसा संशोधन इसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है

(अ) x

XXXX

(ख) XXXX

☺ ((c) XXXX

((घ) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या

(ई) XXXX,

संशोधन को विधानमंडलों द्वारा भी अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी

कम से कम आधे राज्यों ने उस आशय का प्रस्ताव पारित किया

विधेयक से पहले उन विधानमंडलों द्वारा जिनके लिए प्रावधान किया गया है

संशोधन राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

उपरोक्त प्रावधान से पता चलता है कि कुछ शर्तों के अधीन और

प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार, संसद संविधान में संशोधन करने के लिए सक्षम है, सिवाय इसके कि यदि संशोधन किया जाना चाहिए तो "संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व" में परिवर्तन किया जा सकता है। उस स्थिति में, संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान (घ) में आने वाली "राज्यों के प्रतिनिधित्व" अभिव्यक्ति के दायरे पर सवाल उठाया गया है।

जिस संदर्भ में यह तर्क दिया गया है, उसमें कोई दम नहीं है।

अनुच्छेद 80 में प्रयुक्त "राज्यों के प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति और अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक (डी) में प्रयुक्त "राज्यों का प्रतिनिधित्व" अभिव्यक्ति समानार्थी या उसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं हैं। ये अभिव्यक्तियाँ हैं भौतिक रूप से अलग और दोनों प्रावधानों में अलग–अलग संदर्भ में उपयोग किया गया। थि 78

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

इस सरल तथ्य से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 80 "प्रतिनिधियों" की बात कर रहा हैराज्य परिषद में राज्य जबकि अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक (डी) से संबंधित हैं –

" संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। पहला प्रावधान सीमित है।

आयात जबकि उत्तरार्द्ध का एक व्यापक अर्थ है।

अनुच्छेद 1, अपने उप–अनुच्छेद (1) में घोषित करता है कि भारत "राज्यों का संघ होगा", उप–अनुच्छेद (2) के माध्यम से निम्नानुसार प्रावधान करता हैः

" राज्य और उनके क्षेत्र पहले में निर्दिष्ट किए गए होंगे।अनुसूची "।

पहली अनुसूची में राज्यों और संघ के नामों का उल्लेख किया गया है।

क्षेत्र और उनके संबंधित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 2 अधिकार देता है –

संसद को भारत संघ में कानून द्वारा प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने के लिए। अनुच्छेद 3 संसद को कानून द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ "एक नया राज्य बनाने" का अधिकार देता है।

" "किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना", "किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना" या "किसी राज्य का नाम बदलना"। इस शक्ति का उपयोग संसद द्वारा कई बार किया गया है।

राज्यों और उनके क्षेत्रों का पुनर्गठन करना। अनुच्छेद 4 वर्तमान उद्देश्यों के लिए बहुत प्रासंगिक है। यह नीचे लिखा हैः –

" के संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून

पहली और चौथी अनुसूची और पूरक, आनुषंगिक

अनुच्छेद 3 में प्रथम के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे। अनुसूची और चौथी अनुसूची जो प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो

कानून के प्रावधानों के लिए और इस तरह के पूरक भी हो सकते हैं,

आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान (के रूप में प्रावधानों सहित)

संसद और विधानमंडलों या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व

ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्य) जो संसद समझे

आवश्यक है।

(2) उपरोक्त किसी भी कानून को संशोधन नहीं माना जाएगा –

अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान। ”

इस प्रकार अनुच्छेद 4 "संसद में प्रतिनिधित्व" अभिव्यक्ति का भी उपयोग करता है।

यह विशेष रूप से अनुच्छेद 2 और 3 में विचार किए गए ऐसे संशोधनों को संवैधानिक संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया की आवश्यकताओं से बाहर करता है। अतः अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान (घ) में प्रयुक्त "संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व" अभिव्यक्ति का याचिकाकर्ताओं के मामले में कोई उपयोग नहीं हो सकता है।

अनुच्छेद 80 (1) खंड (बी) में निर्धारित करता है कि 12 सदस्यों के अलावा 79

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राज्य परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक "प्रतिनिधि" शामिल नहीं होंगे। यदि कोई संशोधन इस संरचना को बढ़ाता या घटाता है, तो इसके परिणामस्वरूप संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के अनुपात में परिवर्तन होगा।

अनुच्छेद 80 (1) (बी) में निहित प्रावधान, जहाँ तक यह संबंधित था

सदन का गठन करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या तब से अपरिवर्तित रही है जब से इसे संविधान द्वारा अपनाया गया था।

26 नवंबर, 1949 को विधानसभा। लेकिन सीटों का यह आंकड़ा

राज्यों (और केंद्र शासित प्रदेशों) के प्रतिनिधि चौथी अनुसूची के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटन के अधीन थे, जैसा कि प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 80 (2) में। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद में सीटों के आवंटन के लिए प्रावधान किया गया है और उसमें इंगित सीटों की कुल संख्या समय-समय पर अनुच्छेद 80 (1) (बी) में दी गई 238 की अधिकतम सीमा के अधीन है।

चौथी अनुसूची में, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, के लिए आवंटित सीटें

राज्य 205 थे। संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के माध्यम से, जो 1 नवंबर, 1956 को प्रभावी हुआ, चौथी अनुसूची को प्रतिस्थापित किया गया और इसके परिणामस्वरूप, राज्य परिषद में आवंटित सीटों की कुल संख्या 220 कर दी गई, जो विभिन्न राज्यों के बीच इसके वितरण का भी संकेत देता है। "220" का यह आंकड़ा समय-समय पर संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 और संसद द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न राज्य पुनर्गठन अधिनियमों द्वारा बढ़ाया गया था, अंत में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा जो 30 मई 1987 को लागू हुआ, जिससे गोवा राज्य को चौथी अनुसूची में जोड़ा गया और यह आंकड़ा "233" तक बढ़ गया। आज की तारीख में चौथी अनुसूची में "233" का आंकड़ा मिलता है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि हर बार पुनर्गठन किया गया है

अनुच्छेद 368 में निहित प्रावधान, विशेष रूप से इसके प्रावधान (घ)। यह बताया गया है कि पुनर्गठन से प्रभावित राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधि भी संवैधानिक संशोधनों में नाम से प्रतिबिंबित हुए थे और राज्यों को उनके संबंधित अधिवास को ध्यान में रखते हुए आवंटित किया गया।

संबंधित अधिनियमों के प्रावधान पर आधारित तर्क

राज्यों का पुनर्गठन इस मामले को आगे नहीं ले जाता है। जाहिर है, नए राज्यों के निर्माण के समय, राज्य परिषद के मौजूदा सदस्यों को पुराने या नए राज्यों को आवंटित किया जाना था। यह 80 में किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

प्रासंगिक कानून में अंतर्निहित तत्कालीन मौजूदा सिद्धांतों के अनुरूपता। न्यायालय के समक्ष रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि 27 अक्टूबर 1947 के पहले मसौदा संविधान में चौथी अनुसूची के पैराग्राफ 6 को 11 फरवरी 1948 को हटा दिए जाने के बाद आवासीय आवश्यकता पर विशिष्ट विचार कभी नहीं किया गया था।

संविधान का संशोधन "प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है

संसद में राज्यों ने, ऊपर निकाले गए परंतुक के अर्थ के भीतर, एक से अधिक तरीके जो हम वर्तमान में दिखाएंगे।

अनुच्छेद 80 (4) मतदान और चुनाव के तरीके को निर्धारित करता है।

निम्नलिखित शर्तों में राज्य परिषद के लिए राज्यों के प्रतिनिधिः

" राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होंगे –

विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य एकल हस्तांतरणीय वोट का साधन "।

यदि मतदान और चुनाव का उपर्युक्त निर्धारित तरीका है –

उदाहरण के लिए, विधान परिषदों वाले राज्यों में विधान परिषदों के सदस्यों को शामिल करके या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में परिवर्तन करके, जिसका प्रभाव भी होगा –

राज्यों के प्रतिनिधित्व को बदलना।

अनुच्छेद 83 (1) निम्नलिखित प्रावधान करता हैः –

" राज्य परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, लेकिन

इसके लगभग एक तिहाई सदस्य यथासंभव सेवानिवृत्त होंगे।

जितनी जल्दी हो सके हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर

संसद द्वारा कानून द्वारा उस ओर किए गए प्रावधानों के साथ।

यदि अनुच्छेद 83 (1) में प्रदत्त राज्य परिषद की अवधि है –

इस तरह के संशोधन को बदलने की मांग भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित करेगी राज्यों से।

संविधान की चौथी अनुसूची व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करती है

जो राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। विभिन्न राज्यों के बीच यह संतुलन रिट याचिकाओं में आक्षेपित कानून के माध्यम से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। तत्काल मामले में, विवादित अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन केवल आवासीय योग्यता से संबंधित हैं।

' प्रतिनिधि 'और' राज्यों के प्रतिनिधित्व 'से संबंधित नहीं है

संसद में।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल। सी. जे.]

81

;

यह तर्क कि विवादित संशोधन "प्रतिनिधित्व" को प्रभावित करता है

राज्य परिषद में राज्यों की संख्या सही नहीं है। राज्य अभी भी संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपनी–अपनी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से राज्य परिषद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसलिए, जैसा कि तर्क दिया गया है, संवैधानिक संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

दोनों सदनों के बीच अंतर

श्री नरीमन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि एक के तहत

आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 3 में संशोधन, इसके लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक

राज्य परिषद की सदस्यता के लिए अपनी उम्मीदवारी की पेशकश करने वाला व्यक्ति, शुरू से ही यह रहा है कि वह उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए "निर्वाचक" होना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है। दूसरी ओर, आरपी अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार, सदन के मामले में लोगों में से, एक व्यक्ति उस सदन में एक सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य है यदि वह "किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक" है; अर्थात, एक

एक विशेष राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा में जन प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं, भले ही एक अन्य राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हो।

उन्होंने बताया कि लोक सभा की संरचना, के अनुसार

अनुच्छेद 81 (1) (ए) अलग है, क्योंकि इसमें "राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य" शामिल हैं, ऐसे सदस्य नहीं हैं।

जिन राज्यों से वे चुने गए हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही उनसे प्रतिनिधित्व करने की अपेक्षा की जाती है। यही कारण है कि लोक सभा अधिनियम 1951 की धारा 4 में निर्धारित 'लोक सभा की सदस्यता के लिए योग्यता' ने हमेशा "किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक" को लोक सभा में एक सीट भरने के लिए चुने जाने की अनुमति दी है।

तर्क यह है कि धारा 3 में आक्षेपित संशोधन द्वारा,

राज्यों की परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता अब लोक सभा के साथ "समान" है, केवल अंतर शेष हैचुनाव का तरीका, पहला अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा और दूसरा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा।

जबकि धारा 3 में "उसमें" शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया है।

"भारत में" शब्दों के साथ राज्य या क्षेत्र, धारा 4 पहले की तरह ही बनी हुई है। परिणाम यह हुआ कि दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व के गुणों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है।

"निर्वाचक" शब्द को आर. पी. अधिनियम 1951 82 की धारा 2 (ई) में परिभाषित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

और इसका अर्थ है "एक व्यक्ति जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कुछ समय के लिए दर्ज किया गया है" और जो इनमें से किसी के अधीन नहीं है।

आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 16 में उल्लिखित अयोग्यताएँ।

श्री नरीमन के अनुसार उपरोक्त वैधानिक प्रावधान,

संसद का कोई भी सदन, जो लोक सभा के लिए भारत में कहीं भी निवास हो सकता है, लेकिन उस राज्य में निवास होना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है।राज्य परिषद में, जैसा कि 1951 के अधिनियम की धारा 3 में आवश्यक है, जब तक कि विवादित संशोधन से गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया, तब तक यह अस्तित्व में था।

श्री नरीमन ने तर्क दिया कि विवादित संशोधन ने नष्ट कर दिया है

अनावश्यक है, क्योंकि यह अब केवल लोक सभा की नकल करता है, क्योंकि एक व्यक्ति राज्य परिषद में किसी भी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए योग्य है यदि वह उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक है।राज्य या किसी अन्य राज्य में।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि विवादित संशोधन के परिणामस्वरूप,

राज्य परिषद के लिए निर्वाचित व्यक्ति, यदि वह किसी का भी "प्रतिनिधि" है, तो वह केवल उस राज्य विधानसभा का प्रतिनिधि है जिसने उसे चुना था। और राज्य का "प्रतिनिधि" नहीं, जैसा कि उसे अनुच्छेद के तहत होना आवश्यक था।

80. संविधान का यह इरादा कि वह राज्य का प्रतिनिधि होना चाहिए, कुछ वैधानिक आवश्यकताओं में प्रतिबिंबित होना आवश्यक है कि निर्वाचित व्यक्ति और राज्य, चाहे वह जन्म, निवास के लिए हो।

अतीत या वर्तमान में कुछ अवधि, या सामान्य निवास। संसद द्वारा अधिनियमित कानून में खड़े व्यक्ति के बीच कुछ संबंध निर्धारित करना था चुनाव और उस राज्य के लिए जिसका उसे राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व करना है, जो अब गायब है।

ये तर्क हमें आकर्षित नहीं करते हैं। अनुच्छेद 79 में कोई संदेह नहीं है कि

तथ्य यह है कि लोक सभा और राज्य परिषद दोनों संसद के "सदन" हैं। दोनों सदनों को दिए गए नाम उचित संज्ञा हैं और अनुच्छेद 84 (सी) के तहत संसद की विधायी शक्ति पर बहुत कम सीमाओं के साथ किसी भी अधिकार या दायित्व का वर्णन नहीं करते हैं।

1

83

कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. आई.]

निवास से संबंधित सीमा तक योग्यता के मामले में समानता

किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का एक घर दूसरे का डुप्लिकेट। उनकी भूमिका, कार्य, शक्तियाँ या विशेषाधिकार, विशेष रूप से कानून के मामले में, अपरिवर्तित रहते हैं।

श्री नरीमन ने यह भी आग्रह किया कि संविधान का अनुच्छेद 80 (रचना)

राज्यों की परिषद) को अनुच्छेद 81 (लोक सभा की संरचना) के विपरीत पढ़ा जाना चाहिए। उन्हें यह बताते हुए दुख हो रहा था कि अनुच्छेद 80 के तहत, राज्य परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के "प्रतिनिधि" शामिल होने चाहिए और यह कि राज्य परिषद में केवल "प्रत्येक राज्य" के प्रतिनिधि हैं जिन्हें राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाना है [अनुच्छेद 80 (4)]। दूसरी ओर, के तहत

अनुच्छेद 81, लोक सभा में राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए "सदस्य" होते हैं, यानी भारत के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक में निर्वाचकों द्वारा चुने जाते हैं।

उनका तर्क है कि अगर इरादा यह था कि शरीर को कहा जाता है

राज्यों की परिषद में "चुने गए" सदस्य भी शामिल होने थे, तब अनुच्छेद 80 में "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति के बजाय "राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए सदस्य" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता।

उन्होंने यह प्रस्तुत करते हुए तर्क को आगे बढ़ाया कि

अनुच्छेद 80 (1) (बी) और अनुच्छेद 80 (2) में "राज्य के प्रतिनिधि" की अभिव्यक्ति और अनुच्छेद 80 (4) में "प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि" की अभिव्यक्ति न केवल संक्षिप्त या केवल अतिरंजित है, बल्कि आलोचनात्मक और महत्वपूर्ण महत्व के शब्द होने का इरादा है।

लगभग इसी तर्ज पर, श्री पी. पी. राव, तमिल राज्य के विद्वान वकील

नाडु ने प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान द्वारा गठित लोकतांत्रिक गणराज्य, जैसा कि प्रस्तावना में उपयोग की गई अभिव्यक्ति में परिलक्षित होता है–"हम, लोग।

हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग–दूसरे शब्दों में, भारत के नागरिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासी।

यह तर्क दिया गया है कि "हाउस ऑफ द हाउस" में अंतर्निहित सिद्धांत

लोग अनुच्छेद 79 और 81 से स्पष्ट हैं। यह समग्र रूप से भारत के लोगों का सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा किया जाता है। सदस्य बनने के लिए पहले भारतीय होना चाहिए। एक गैर–भारतीय भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। भारत के किसी भी हिस्से में केवल एक निर्वाचक के पास भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होगी।

84

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

यह अनुच्छेद 79 में "राज्यों की परिषद" शब्द प्रस्तुत किया गया है।

और 80, इसी तरह से सदन का अर्थ है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक राज्य एक है

किसी राज्य से संबंधित व्यक्ति के पास ऊपरी क्षेत्र में राज्य का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होगी। सदन और यह कि कोई व्यक्ति जन्म से ही किसी राज्य से संबंधित होने का दावा कर सकता है,

अधिवास या निवास। इस आधार पर यह प्रस्तुत किया गया है कि कुछ ऐसे

राज्य और उसका प्रतिनिधि बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के बीच स्पष्ट सांठगांठ संविधान की योजना में यह अनिवार्य है।

यह याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि

अनुच्छेद 80 (1) (बी) और (2) में "राज्यों के प्रतिनिधि" शब्द और

अनुच्छेद 80 (4) में "राज्यों की परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों" शब्दों की व्याख्या इस तरह से करने की आवश्यकता है कि यह बुनियादी ढांचे को मजबूत करे।

संविधान की संरचना, अपने संघीय चरित्र और लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता, अर्थात् स्व-शासन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए।

उपरोक्त संदर्भ में, वकील उप-समिति पर भरोसा करेगा -

न्यायिक जवाबदेही v. यूओआई और ओआरएस। , [1991] 4 एससीसी 699 और पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम। राज्य (सी. बी. आई/एस. पी. ई.), [1998] 4 एस. सी. सी. 626।

न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति v. भारत संघ (ऊपर),

इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो नींव को मजबूत करता हैसंविधान की विशेषताएँ और मूल संरचना "।

पी. वी. नरसिम्हा में अनुच्छेद 47 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं।

राव के मामले (ऊपर) पर भरोसा किया गया हैः

" जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रतिरक्षा का उद्देश्यअनुच्छेद 105 (2) प्रत्येक विधायक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है।

अनुच्छेद 105 (2) के प्रावधानों की व्याख्या जो सक्षम बनाएगी एक में अभियोजन से प्रतिरक्षा का दावा करने के लिए संसद का एक सदस्य

किसी भी चीज के संबंध में रिश्वत के अपराध के लिए आपराधिक अदालत

उनके द्वारा कहा गया या संसद या किसी समिति में उनके द्वारा दिया गया मत

और इस प्रकार ऐसे सदस्यों को कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा।

केवल संसदीय लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिए प्रतिकूल हो 85

कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

लेकिन यह कानून के शासन का भी विध्वंसक होगा जो एकसंविधान की मूल संरचना का अनिवार्य हिस्सा। यह तय हो गया है।

एक ऐसा निर्माण अपनाना जो मूलभूत विशेषताओं को मजबूत करता है और संविधान की मूल संरचना। (देखिएः उप–समिति

न्यायिक जवाबदेही v. भारत संघ, [1991] 4 एससीसी 699 एससीसीपी। 719.) "

श्री नरीमन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह योजना के कारण है

संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कहा गया है कि राज्य परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित और सुनिश्चित किया जाना चाहिए। के रूप में जोर देकरराज्य विधानसभा द्वारा राज्य परिषद के लिए चुने गए व्यक्ति और उस राज्य के बीच एक योग्यता, कुछ संबंध या सांठगांठ जिसका वह राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व करेगा। उनके अनुसार, यह संबंध राज्य में "सामान्य निवास" के माध्यम से 53 वर्षों तक एक संबंध था और बना रहा। आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 ने न केवल एक योग्यता प्रदान करने की भूमिका को पूरा किया, बल्कि यह परिभाषित किया कि अनुच्छेद 80 (4) में "प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि" कौन होना था।

यह तर्क दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में चुनकर

किसी विशेष राज्य विधानसभा द्वारा राज्य परिषद ने स्वयं उस व्यक्ति को उस राज्य का 'प्रतिनिधि' बनाया तो आर. पी. अधिनियम की धारा 3 को अधिनियमित करना अनावश्यक था। इसलिए, तर्क के अनुसार, यह निष्कर्ष निकालना होगा कि अनंतिम संसद (जिसने भी मसौदा तैयार किया था और अधिनियमित किया था

संविधान), आर. पी. अधिनियम की धारा 3 को लागू करते समय, "उस राज्य में उनके निवास" के संदर्भ में "राज्य के प्रतिनिधि" को परिभाषित करना आवश्यक समझा था।

उपरोक्त तर्क इस सिद्धांत पर आधारित है कि

बुनियादी संरचना के बारे में हमें और अटकाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वही तर्क है जो संघीय संरचना के संदर्भ में दिया गया है, हालांकि थोड़ा अलग है। छाया। इसके अलावा, लिंक कारक को विवादित संशोधनों द्वारा बरकरार रखा गया है क्योंकि राज्यों की परिषद के चुनाव के लिए उम्मीदवार को अब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक होना आवश्यक है। इसलिए, जोड़ने वाले कारक को व्यापक आधार बनाया गया है।

अनुच्छेद 80 बताता है कि राज्य परिषद में 12 सदस्य होते हैं।

राष्ट्रपति और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 प्रतिनिधियों द्वारा नामित। प्रतिनिधि अनुच्छेद 80 (2) के अनुसार सीटों को भरते हैं। दोनों, राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य और राज्य विधानमंडलों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सामूहिक रूप से राज्य परिषद के 'सदस्य' हैं, जैसा कि स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 83 से निकलता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

इस तर्क का आगे का जवाब अनुच्छेद 84 में ही पाया जा सकता है, जो

संसद की 'सदस्यता' को संदर्भित करता है, और इसमें राज्य परिषद शामिल है।साथ ही लोगों का सदन भी। फिर, अनुच्छेद 84 में संसद की दोनों परिषदों में एक सीट भरने के संदर्भ में 'चुना' शब्द का भी उपयोग किया गया है।

राज्यों के साथ–साथ लोक सभा भी। इसलिए, राज्य का प्रतिनिधि उतना ही संसद सदस्य होता है जितना कि वह लोकसभा का सदस्य होता है।

"प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति का उपयोग लोक सभा के संदर्भ में समान रूप से किया जाता है।

इस प्रकार अभिव्यक्तियों 'सदस्यों' और के बीच कोई अंतर नहीं है।

' प्रतिनिधियों '। विद्वान वकील की प्रस्तुतियाँ असमर्थनीय हैं। द.

याचिका है कि राज्य सभा के संबंध में उपयोग किए गए शब्द "सदस्य" के विपरीत राज्य परिषद के संबंध में "प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति का चयन चाबी रखने वाले लोगों को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

"प्रत्येक" शब्द की प्रासंगिकतायह श्री नरीमन का निवेदन है कि यह संसद के लिए खुला है।

परिषद में चुने जाने के लिए योग्यता निर्धारित करके निर्धारित करना

राज्य, निर्धारित अर्हताएँ ऐसी होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार चुना गया व्यक्ति उस राज्य का प्रतिनिधि है, जिसकी विधानसभा

उसे चुना है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्यों की परिषद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुच्छेद 80 (4) में "प्रत्येक" शब्द का उपयोग इसके बिना नहीं था।

महत्व, जितना जोर "प्रत्येक राज्य" को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर है ताकि सदन को राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय का चरित्र दिया जा सके।

"प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि" शब्दों पर जोर दिया गया है।

राज्यसभा के सांसद राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या में अलग–अलग अनुपात होगा। ऐसा प्रतीत होता है।कि ऐसी धारणा को दूर करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि, इस तथ्य के बावजूद कि वे में किए गए आवंटन के अनुसार चुने गए हैं

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

87

"प्रत्येक" शब्द को सबसे पहले लेख में डाला गया था। उप. अनुच्छेद 80 के एस (4) और (5), अपने मूल रूप में, निम्नानुसार पढ़े जाते हैंः –

" (4) भाग ए या भाग बी में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि

एकल के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के साथ हस्तांतरणीय वोट।

(5) प्रथम के भाग सी में निर्दिष्ट राज्य के प्रतिनिधि

राज्य परिषद में अनुसूची का चयन इस तरह से किया जाएगा कि – संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है।

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा

राज्यों के पुनर्गठन के साथ–साथ अनुच्छेद 80 में भी संशोधन किया गया। द.

संविधान के उद्देश्य और कारण (सातवां संशोधन)

951 , यहाँ जर्मन की सीमा तक, निम्नानुसार पढ़िएः – "

नए राज्यों की स्थापना और क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन मौजूदा राज्यों का, लेकिन तीन श्रेणियों का उन्मूलन भी

राज्य (भाग ए, भाग बी और भाग सी राज्य) और राज्यों का वर्गीकरण

खंड 3. अनुच्छेद 80 में प्रस्तावित संशोधन औपचारिक हैं और परिणामी। क्षेत्रीय परिवर्तन और नए राज्यों का गठन

राज्यों के पुनर्गठन के भाग II में प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश

विधेयक, 1956 में चौथी अनुसूची का पूर्ण संशोधन शामिल है –

संविधान जिसके द्वारा राज्य परिषद में सीटें आवंटित की जाती हैं

मौजूदा राज्यों के लिए। वर्तमान आबंटन के आधार पर किया जाता है –

1941 की जनगणना में निर्धारित प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और

प्रत्येक भाग ए और भाग बी राज्य को आवंटित सीटों की संख्या है

फार्मूले के अनुसार, पहले पांच लाख लोगों के लिए प्रति दस लाख एक सीट और प्रत्येक अतिरिक्त दो लाख या उससे अधिक के हिस्से के लिए एक सीट

एक लाख। सीटों के आवंटन को संशोधित करने का प्रस्ताव है

नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का आधार, लेकिन उसी सूत्र के अनुसार

पहले की तरह "।

खंड 4. भाग सी राज्यों का उन्मूलन और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी.

5 एस सी आर।

88

केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुच्छेद 81 और 82 में व्यापक संशोधन किया

अपरिहार्य है। अनुच्छेद 81 (1) (बी) में प्रावधान है कि "राज्यों कोविभाजित, समूहीकृत या क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में गठित "नहीं होगा

अधिक समय तक उचित रहेगा, क्योंकि पुनर्गठन के बाद प्रत्येक राज्य

कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होने के लिए पर्याप्त बड़ा हो और इसके लिए अन्य राज्यों के साथ समूहबद्ध होने की अनुमति नहीं देंगे।

उद्देश्य या एक एकल क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में "गठित" किया जाना। खंड (2) या अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 को संयुक्त और संशोधित करने की आवश्यकता होगी।

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए। इसके बजाय

उन्हें। संयोग से, संशोधित अनुच्छेद 81 के खंड (1) (बी) में प्रतिनिधियों की कुल संख्या के लिए अधिकतम निर्धारित करने का प्रस्ताव है जो संसद द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा जाए।

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1951 के अनुसार, शब्द

" अनुच्छेद 80 (4) में उपयोग किए गए पहली अनुसूची के भाग ए या भाग बी में निर्दिष्ट को हटा दिया गया था। इसी संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 80 (5) में "पहली अनुसूची के भाग सी में निर्दिष्ट राज्य" शब्दों को "केंद्र शासित प्रदेश" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया था।

राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था। राज्यों का वर्गीकरण

भाग ए, भाग बी या भाग सी राज्यों को समाप्त किया जा रहा था। पहले भाग सी राज्यों के रूप में वर्गीकृत कुछ राज्यों को अब "केंद्र शासित प्रदेश" के रूप में नामित किया जा रहा था। चूँकि चौथी अनुसूची में दी गई राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन अनिवार्य रूप से पहली अनुसूची में उल्लिखित राज्यों (और केंद्र शासित प्रदेशों) के अनुरूप होना चाहिए, अनुच्छेद 1 (2) और अनुच्छेद 4 की आवश्यकता को देखते हुए, अनुच्छेद 80 में निहित प्रावधानों से गुजरना पड़ता था।

परिणामी संशोधन। ध्यान देने योग्य बात यह है कि "प्रत्येक" शब्द केवल राज्यों के प्रतिनिधियों के संदर्भ में अनुच्छेद 80 (4) में दिखाई दिया था। अभिव्यक्ति "प्रतिनिधि"

राज्यों की संख्या पहले अनुच्छेद 80 (1) और फिर अनुच्छेद 80 (2) में दिखाई देती है ताकि क्रमशः संख्या (निर्वाचित होने के लिए) और सीटों के आवंटन (चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाने के लिए) को निर्दिष्ट किया जा सके। दोनों खंडों में "राज्य" शब्द नहीं है

"प्रत्येक" शब्द द्वारा योग्य। चूंकि उप–अनुच्छेद (4) और उप–अनुच्छेद (5) विभिन्न श्रेणियों के राज्यों द्वारा चुनाव के तरीके को इंगित करने के लिए थे, इसलिए उन्हें अलग–अलग प्रावधानों के रूप में बनाया गया था। यदि "प्रत्येक" शब्द का महत्व रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क के दौरान दिया गया था, तो यह न केवल भाग ए और भाग बी राज्यों के संदर्भ में उप–अनुच्छेद (4) में, बल्कि भाग सी राज्यों के संदर्भ में उप–अनुच्छेद (5) में भी हुआ होगा, क्योंकि सभी कुलदिप नायर बनाम राज्य।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

89

श्रेणियाँ भारत संघ की विभिन्न इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती थीं।

उपरोक्त दृष्टिकोण में, "प्रत्येक" शब्द का प्रयोग

"राज्य" शब्द, राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, केवल इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा का उद्देश्य चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट विशेष राज्य को आवंटित सीट को भरने के लिए एक सदस्य को वापस करने के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल होना था। न कुछ अधिक और न कुछ कम। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक है कि

"राज्यों के प्रतिनिधि" शब्द पहले भी दो बार आ चुका है।

उसी अनुच्छेद के पूर्ववर्ती खंडों में। अनुच्छेद 80 (5) में भाग सी राज्यों (अब केंद्र शासित प्रदेश) के संदर्भ में "प्रत्येक" शब्द का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि मूल रूप से प्रदान किया गया था या बाद में संशोधित किया गया था, क्योंकि भारत संघ की ऐसी इकाइयों के प्रतिनिधित्व के तरीके को छोड़ दिया गया था

संसद द्वारा विहित और चूंकि ऐसी प्रत्येक इकाई का उस समय अपनी विधान सभा प्रदान करने का इरादा नहीं था।

उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह तर्क कि "प्रत्येक" शब्द का उपयोग

अनुच्छेद 80 (4) सदन को राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय का चरित्र देता है, जो हमें आकर्षित नहीं करता है।

निर्वाचित होने से पहले प्रतिनिधि चरित्र वाला व्यक्ति

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि "प्रतिनिधि" शब्द में

लोकतंत्र के संदर्भ में दो चीजों की आवश्यकता होती है – अर्थात (क) प्रतिनिधित्व करने की क्षमता और (ख) प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। उनका कहना है कि स्वशासन की प्रणाली में केवल एक वर्ग का सदस्य ही वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

यह तर्क दिया गया है कि शब्दों में "राज्यों के प्रतिनिधि"

अनुच्छेद 80 (1) (बी) और (2) और अनुच्छेद 80 (4) में दिखाई देने वाले "राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि" शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए –

संविधान की मूल संरचना के अनुरूप तरीके सेलोकतंत्र की अवधारणा, अर्थात स्वशासन की प्रणाली को ध्यान में रखें। रिलायंस को एक बार फिर इस संदर्भ में न्यायिक उप–समिति में रखा गया है।

उत्तरदायित्व v. यूओआई और ओआरएस। (ऊपर); पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सी. बी. आई., एस. पी. एफ.) (ऊपर); और एस. आर. बोम्मई बनाम यू. ओ. आई. (ऊपर)।

पहले दो मामलों पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। एस. आर. के बारे में

बोम्मई, पृष्ठ 118 पर निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया गया हैः –

" इस प्रकार संघीय सिद्धांत, सामाजिक बहुलवाद और बहुलवादी लोकतंत्र जो हमारे संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, उनकी मांग है कि 90

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

अनुच्छेद 356 (1) के तहत जारी घोषणा की न्यायिक समीक्षा नहीं है।

केवल एक अनिवार्य आवश्यकता है लेकिन एक कठोर कर्तव्य और अभ्यास है

उक्त प्रावधान के तहत शक्ति की सीमा इस उद्देश्य के लिए सख्ती से सीमित है।

और उसमें वर्णित परिस्थितियों के लिए और किसी और के लिए नहीं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जिस सामग्री के आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसकी सावधानीपूर्वक जांच की जाए।

तर्क यह है कि के संदर्भ में "प्रतिनिधि" शब्द

संसदीय लोकतंत्र के लिए प्रतिनिधित्व करने की क्षमता और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दोनों की आवश्यकता होती है। स्वशासन की प्रणाली में केवल एक वर्ग का सदस्य ही वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह इस प्रकार है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी राज्य का नहीं है, तब तक उसके पास राज्य या राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं होगी। एक व्यक्ति

वह जन्म और निवास से या अधिवास या सामान्य रूप से किसी राज्य से संबंधित है।

राज्य में निवास।

"राज्य" की अवधारणा में न केवल क्षेत्र बल्कि लोग भी शामिल हैं।

क्षेत्र में निवास करना। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसलिए, यह याचिकाकर्ताओं का निवेदन है, अनुच्छेद 80 (4) में "प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जो राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रत्येक राज्य और केवल एक व्यक्ति जो राज्य का है या जो राज्य के लोगों में से एक है, उसके पास राज्य का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होगी, न कि किसी अन्य राज्य का व्यक्ति।

याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 80 (4) में विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव का प्रावधान है।

राज्य इस तथ्य के साथ कि अनुच्छेद 170 के संदर्भ में, विधान सभा के सदस्य वे होंगे जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे और आगे यह आवश्यकता है कि उनमें से प्रत्येक को आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 5 (सी) के संदर्भ में राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना आवश्यक है, यह दर्शाता है कि किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य परिषद के सदस्यों के पास निर्धारित योग्यताएँ होंगीःविधान सभा के सदस्य। दोनों ही लोगों के

प्रतिनिधि हैं; जबकि विधानसभाओं के सदस्य (विधायक) सीधे चुने जाते हैं, राज्य परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लोगों द्वारा अपने विधायकों के माध्यम से चुने जाते हैं।

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 5 (सी) के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए पात्र होने के लिए निर्वाचक होना आवश्यक है। विधान सभा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रतिनिधित्व करने की क्षमता राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए पंजीकृत मतदाता होने से उत्पन्न होती है। इसलिए, किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होने के लिए, यह आवश्यक है कि कुलदिप नायर v.

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

91

संबंधित व्यक्ति राज्य में पंजीकृत मतदाता होगा।

आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 19 होने की आवश्यकता को निर्धारित करती है।

" उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होने के हकदार होने के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में आम तौर पर निवासी। धारा 20 "सामान्य निवासी" का अर्थ देती है।

श्री नरीमन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक निर्वाचित सदस्य

राज्य परिषद केवल इसलिए राज्य का "प्रतिनिधित्व" नहीं करती है क्योंकि वह राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। राज्य परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए (राज्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने से अलग), उसे विधायी निकाय द्वारा चुने जाने से पहले अनुच्छेद 80 (4) के तहत राज्य का प्रतिनिधि होना चाहिए। उन्होंने इस याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि उक्त उप–अनुच्छेद में, "राज्यों की परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति चुनाव के तरीके (एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली) के बारे में निर्देश से पहले है।

वकील ने आगे तर्क दिया कि अभिव्यक्ति "के प्रतिनिधि

अनुच्छेद 80 (1) (बी) और अनुच्छेद 80 (2) में प्रयुक्त राज्यों और अनुच्छेद 80 (4) में प्रयुक्त "प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों" की अभिव्यक्ति को संसद द्वारा अनुच्छेद 84 (सी) के तहत बनाए गए "कानून द्वारा" परिभाषित करने के लिए छोड़ दिया गया है, जिसमें संसद को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि किसी व्यक्ति को कौन सी "ऐसी अन्य योग्यताएं" निर्धारित करनी चाहिए।

संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, जो अनुच्छेद 84 (ए) और (बी) में दी गई योग्यताओं के अलावा अन्य योग्यताएं हैं जो भारत की नागरिकता से संबंधित हैं, संविधान के प्रति निष्ठा और निष्ठा की शपथ या पुष्टि और न्यूनतम आयु के बारे में निर्देश।

यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 80 (4), अभिव्यक्ति का उपयोग करके

" प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि इस बात पर जोर देते हैं कि जो व्यक्ति चुना जाता है, उसे पहले राज्य के प्रतिनिधि के रूप में योग्य होना चाहिए। यदि योग्यता का उद्गम केवल किसी विशेष राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाने से होता, तो खंड में लिखा होताः

" प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राज्यों की परिषद में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें

एकल के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली

हस्तांतरणीय वोट "।

वकील ने प्रस्तुत किया है कि अनुच्छेद 81 के विपरीत, जो नहीं करता है

यह निर्धारित करें कि लोक सभा के लिए निर्वाचित व्यक्ति एक से होगा

किसी विशेष राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र ताकि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. का प्रतिनिधि हो।

5 एस सी आर।

92

लोक सभा में ऐसा राज्य, अनुच्छेद 80 में व्यक्ति की आवश्यकता होती है

उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाने से पहले राज्य का प्रतिनिधि होने का प्रश्न। केवल तथ्य

भारत में किसी भी "निर्वाचक" का विशेष राज्य विधानसभा द्वारा चुनाव उस व्यक्ति को उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए "योग्य" नहीं बना सकता है।

श्री नरीमन ने "निर्वाचक" शब्द का उल्लेख किया जिसे परिभाषित किया गया है

आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 2 (ई), निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका

उस समय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि आर. पी. अधिनियम 1950 की धारा 19 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जो योग्यता तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है और केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में "सामान्य रूप से निवासी" है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि आर. पी. अधिनियम, 1950 और 1951 के प्रावधानों में थे

"सदस्यता के लिए आगे की योग्यताओं" की प्रकृति, जैसा कि आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 के रूप में अधिनियमित किया गया था, जिस पर खंडों पर टिप्पणियों के माध्यम से स्पष्ट किया गया था, जैसा कि भारत के राजपत्र, 23 दिसंबर, 1950–भाग II–Sec.2 में प्रकाशित किया गया था, जो निम्नानुसार हैः

" खंड 3 से 6–संविधान के अनुच्छेद 84 और 173 में निर्धारित किया गया है

संसद की सदस्यता के लिए कुछ योग्यताओं को कम करना औरराज्य विधानमंडलों ने इसे निर्धारित करने के लिए संसद पर छोड़ दिया है

अतिरिक्त योग्यताएँ जो आवश्यक हों। खंड 3 से 6 की मांग सदस्यता के लिए इन अतिरिक्त योग्यताओं को निर्धारित करना।

(जोर दिया गया)

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 4 सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करती है।

"किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक" होने के लिए लोक सभा में एक सीट भरने की कोशिश करना। इस प्रकार के बीच एक भौतिक अंतर था राज्य परिषद के लिए निर्धारित विशेष राज्य के भीतर अधिवास की योग्यता और भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अधिवास की योग्यता, जैसा कि लोक सभा के लिए निर्धारित है। यह था।

विधेयक पर विचार के समय 11 मई 1951 को अस्थायी संसद में बहस का विषय, जो बाद में आर. पी. अधिनियम, 1951 का रूप ले लेगा। श्री नरीमन ने संसद में धारा 3 पर बहस का उल्लेख किया

आर. पी. अधिनियम 1951।

ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त बहस के दौरान यह इंगित किया गया कि कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

93

यह उतना ही असंगत है कि राज्य परिषद के उम्मीदवार को संबंधित राज्य का निवासी क्यों होना चाहिए, जबकि लोक सभा के उम्मीदवार को केवल देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। संसदीय बहसों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि डॉ. अम्बेडकर

संबंधित सदन के राज्य परिषद होने के कारण संबंधित राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता और दूसरे सदन के लिए संबंधित राज्य के भीतर निवास की ऐसी आवश्यकता के अभाव के संदर्भ में अंतर समझाया था क्योंकि यह लोक सभा थी।

यह विद्वान वकील का निवेदन है कि संसदीय बहस

भेद के औचित्य पर स्पष्ट रूप से कारण का संकेत है कि क्यों

राज्यों की परिषद के लिए चुने गए सदस्य के प्रतिनिधि चरित्र को परिभाषित किया गया था, यह कि चुनाव राज्यों की परिषद के लिए था न कि लोक सभा के लिए; अर्थात क्षेत्र में रहने या काम करने वाला व्यक्ति।

" अतः 'क' क्षेत्र 'ख' या उस मामले में किसी अन्य स्थान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था।

यह वकील का तर्क है कि विवादित संशोधन निर्धारित करता है

निर्वाचित व्यक्ति का प्रतिनिधि चरित्र, जैसा कि उस राज्य के साथ उसके संबंध के रूप में संशोधित प्रावधान में ग्राफ्ट किया गया है जिसका वह राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व करता है, इसे या तो "निवास" (अतीत में या वर्तमान में), या जन्म स्थान, या उस राज्य में सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के संदर्भ में परिभाषित नहीं करता है जिसकी विधानसभा उसे राज्य परिषद के लिए चुनती है।

आगे बढ़ने से पहले, हम कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहेंगे।

जी. नारायणस्वामी बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ की। जी. पन्नीरसेल्वम और अन्य। , [1972] 3 एस. सी. सी. 717, पैराग्राफ 4 में दिखाई देता है जो नीचे दिया गया हैः –

" अधिकारी निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं जो इंगित करता है कि अदालतें

सरकार। फिर भी, "सादा अर्थ" या "शाब्दिक" का नियममैक्सवेल के क़ानूनों की व्याख्या में वर्णित व्याख्या

किसी भी दस्तावेज़ की व्याख्या करना। वास्तव में, हम लार्ड एवरशेड, एम. आर. को पाते हैं। कहते हैंः " आधुनिक विधान की लंबाई और विस्तार, निस्संदेह है

एकमात्र सुरक्षित नियम के रूप में शाब्दिक निर्माण के दावे को मजबूत किया। (देखिएः

क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 12 वीं संस्करण। , पी। 28.) हो सकता है कि

आधुनिक कानून का एक बड़ा समूह, जिसका एक बड़ा हिस्सा शामिल है वैधानिक नियमों का, के शाब्दिक नियम से कुछ विचलन करता है

व्याख्या अतीत की तुलना में आज अधिक आसानी से उचित है। लेकिन, 94

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

व्याख्या और "निर्माण" का उद्देश्य (जो हो सकता है

"व्याख्या" से व्यापक) कानून के इरादे की खोज करना है।

पहले प्रासंगिक में उपयोग की जाने वाली भाषा को देखकर प्राप्त किया गया प्रावधान। अर्थ निकालने के अन्य तरीकों का सहारा लिया जा सकता है।

केवल तभी जब उपयोग की जाने वाली भाषा विरोधाभासी, अस्पष्ट या अग्रणी हो

वास्तव में बेतुके परिणाम। यह एक प्राथमिक और बुनियादी नियम है

व्याख्या के साथ–साथ निर्माण प्रक्रियाओं की जो, से

लागू किए गए सिद्धांतों का दृष्टिकोण, एकरूपता और एकर दिशा में अभिसरण

दोनों का सामान्य उद्देश्य वास्तविक अर्थ में प्राप्त करना है और

जिसका अर्थ है, जहाँ तक उचित रूप से ऐसा करना संभव हो,

रखा हुआ पाया जाता है। जिन प्रावधानों का अर्थ है

इसलिए, कोई भी आवेदन करने से पहले विचार की जांच की जानी चाहिए।

निर्माण की विधि बिल्कुल भी "।

हम उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफ में लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन और दोहराते हैं।

निर्णय की। संवैधानिक प्रावधानों को एक व्यापक और उदार निर्माण देना वांछनीय हो सकता है, लेकिन ऐसा करते समय "सादा अर्थ" या "शाब्दिक" व्याख्या के नियम, जो "प्राथमिक नियम" बना हुआ है, को भी ध्यान में रखना होगा। वास्तव में "शाब्दिक निर्माण" का नियम सुरक्षित नियम है जब तक कि उपयोग की जाने वाली भाषा विरोधाभासी, अस्पष्ट या वास्तव में बेतुकी न हो।

परिणाम।

संविधान के अनुच्छेद 80 (4) के शब्दों के बारे में, अर्थात। , " द.

प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हम इस बात से प्रभावित नहीं हैं कि यह अभिव्यक्ति "प्रतिनिधि" में निहित है, कि व्यक्ति को प्रतिनिधि होने के लिए, पहले अनिवार्य रूप से एक निर्वाचक होना चाहिए।

राज्य में। यदि इस अवधारणा को आगे बढ़ाया जाना है, तो इसके लिए किसी विशेष राज्य में जन्म, या उस राज्य की संपत्ति का स्वामित्व या किराए पर लेना या बहुसंख्यक जाति आदि से संबंधित होने की भी आवश्यकता हो सकती है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह कहने के लिए ऐसी कोई योग्यता नहीं जोड़ी जा सकती है। उस राज्य का एक निर्वाचक कर सकता है

उस राज्य का प्रतिनिधित्व करें। राज्य का "प्रतिनिधि" निर्वाचकों द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो निर्वाचकों की राय में, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि एक व्यक्ति जो संबंधित राज्य में एक निर्वाचक है, चरित्र में उस व्यक्ति की तुलना में अधिक "प्रतिनिधि" है जो नहीं है।

हम इसमें कोई विरोधाभास, अस्पष्टता या बेतुकी बात नहीं पाते हैं।

विवादित संशोधन के परिणामस्वरूप कानून के प्रावधान।

यहां तक कि कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

95

संविधान और आर. पी. अधिनियमों के प्रावधानों को व्यापक या सबसे उदार तरीके से समझते हुए, "सादा अर्थ" या "शाब्दिक" व्याख्या का नियम।

हमें याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार नहीं करने के लिए मजबूर करता है।

उनके स्पष्ट अर्थ दिए जाने पर, शब्द "के प्रतिनिधि"

अनुच्छेद 80 (1) (बी), अनुच्छेद 80 (2) और अनुच्छेद 80 (4) में राज्यों की व्याख्या उन व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए की जानी चाहिए जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए हैं।

राज्यों की परिषद। यह वह चुनाव है जो निर्वाचित व्यक्ति को "प्रतिनिधि" बनाता है। राज्य परिषद में निर्वाचित होने के योग्य होने के लिए, किसी व्यक्ति को पहले राज्य का प्रतिनिधि होने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल

राज्य की विधान सभा, अनिवार्य रूप से राज्य के "प्रतिनिधि" हैं।राज्य।

अनुच्छेद 84 राज्य परिषद पर उतना ही लागू होता है जितना यह राज्य परिषद पर लागू होता है।

लोगों का घर। यह लेख इन शब्दों से शुरू होता हैः –

" एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा।

जब तक "।

इस प्रकार, संसद का प्रत्येक सदस्य "राष्ट्रपति द्वारा नामित" होना चाहिए।

अनुच्छेद 80 (1) (ए) के तहत, या अनुच्छेद 80 (4) और (5) के साथ पठित अनुच्छेद 80 (1) (बी) के तहत निर्वाचित "राज्य का प्रतिनिधि", या अनुच्छेद 81 के तहत निर्वाचित लोक सभा का "सदस्य", संसद में एक सीट भरता है।

श्री वी. वी. गिरि बनाम मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। दिप्पाला सूरी

डोरा और ओआरएस। , [1960] 1 एससीआर 426: ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1318 ने अनुच्छेद 81 (2) (बी), 84,101 (2) और 330 में एकल या एक साथ उपयोग किए गए "सीट" और "एक सीट भरने के लिए" अभिव्यक्तियों का अर्थ लगाते हुए कहा थाः

..... संविधान के कुछ अनुच्छेद और अधिनियम की कुछ धाराएँ

लोक सभा के चुनाव के संबंध में सीटों का उल्लेख करें।

उदाहरण के लिए, जब अनुच्छेद 81 (2) (बी) समान अनुपात का प्रावधान करता है।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी के बीच पूरे राज्य में

और इसे आवंटित सीटों की संख्या, यह सीटों को संदर्भित करता है, लेकिन मेंसंदर्भ में "सीट" शब्द का उपयोग अपरिहार्य था। इसी तरह लेख

84 जो संसद के सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित करता है

यह कहने से शुरू होता है कि कोई व्यक्ति चुने जाने के योग्य नहीं होगा

" संसद में एक सीट भरने के लिए जब तक कि वह निर्धारित परीक्षणों को पूरा नहीं करता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

इसके खंड (ए), (बी) और (सी) द्वारा। यहाँ फिर से अभिव्यक्ति "एक सीट भरने के लिए" संदर्भ में उपयोग किया जाना था। एक ही टिप्पणी के बारे में किया जा सकता है

अनुच्छेद 101 (2) और 330 में "सीट" शब्द का उपयोग। वहाँ कोई नहीं है

संदेह है कि जब कोई उम्मीदवार किसी निर्वाचन क्षेत्र से विधिवत निर्वाचित होता है

लोक सभा में वह निर्वाचित सदस्य के रूप में सदन में एक सीट भरता है

उक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि; और इसलिए अभिव्यक्ति "भरना"

सीट "स्वाभाविक रूप से उपयोग किया जाता है जब भी संदर्भ की आवश्यकता होती है।"

(जोर दिया गया)

इसी सादृश्य पर, यह कहा जाना चाहिए कि जब कोई उम्मीदवार चुना जाता है

के विधान सभा के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा

राज्य परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वह चुना जाता है और "राज्य के प्रतिनिधि" के रूप में चुना जाता है। "राज्य का प्रतिनिधि" शब्दों का किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं है कि प्रतिनिधि भी एक निर्वाचक या राज्य में ही पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।

यह विधायिका के सदस्य के रूप में चुनाव पर अर्जित स्थिति है।

जो व्यक्ति को "प्रतिनिधि" का चरित्र प्रदान करता है। इस न्यायालय ने पहले भी यही विचार रखा है। बी. आर. कपूर बनाम टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य , [2001] 7 एस. सी. सी. 211, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पात्रता से संबंधित प्रश्नों पर विचार कर रही थी, न कि विधायिका के सदस्य की। विभिन्न के निर्माण के आधार पर

संविधान के प्रावधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 163 (1), 164 (1) (2) और (4), 173,177 और 191, इस न्यायालय ने पृष्ठ 289 पर अभिनिर्धारित कियाः –

" इन प्रावधानों में अनिवार्य रूप से यह आवश्यकता निहित है कि

मंत्री को विधान सभा का सदस्य होना चाहिए और इस प्रकार राज्य के लोगों का प्रतिनिधि और उनके प्रति जवाबदेह।

निर्वाचक को उस निर्वाचन क्षेत्र का एक सामान्य निवासी होना चाहिए जिसमें

वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 और 20 की वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत है। कानून में कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति

निर्वाचित व्यक्ति के पास निर्वाचक के समान योग्यता होनी चाहिए। यह संविधान की योजना से और स्पष्ट है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 171 (3) से स्पष्ट है जो विधान परिषद की संरचना का प्रावधान करता है, जो संघ के स्तर पर राज्य परिषद के समान राज्यों के स्तर पर एक सदन है।

नगरपालिकाओं और बोर्डों के सदस्य, स्नातक, शिक्षक हैं

97 सदस्यों के एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करने के लिए अनुच्छेद 171 के तहत आवश्यक

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

विधान परिषद। यह आवश्यक नहीं है कि निर्वाचित व्यक्ति या तो नगरपालिका बोर्ड का सदस्य हो या स्नातक हो या स्वयं शिक्षक हो। मतदाता किसी को भी चुन सकते हैं जिसे उनके विवेक के अनुसार सबसे उपयुक्त माना जाता है।

उनका एक प्रतिनिधि।

जी. नारायणस्वामी के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

अनुच्छेद 171 और 173 और धाराओं में निहित प्रावधानों पर विचार कर रहा था

5 और आर. पी. अधिनियम, 1951 का 6. पैराग्राफ में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः 7 निर्णय की प्रासंगिकता यहाँ हैः –

" "निर्वाचक" शब्द का सादा और सामान्य अर्थ सीमित है।

प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाले व्यक्तियों के निकाय की विस्तारित धारणा " आपस में "। इस प्रकार, "निर्वाचक" शब्द का उपयोग,

हमारे संविधान के अनुच्छेद 171 (3) में, अपने आप में, एक सीमा लागू नहीं कर सकता था

निर्वाचक मंडल के सदस्यों की पसंद के क्षेत्र में यह अपेक्षा करके कि चुने जाने वाले व्यक्ति को भी निर्वाचक मंडल का सदस्य होना चाहिए।

निस्संदेह आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 6 में अधिवास की आवश्यकता बनी हुई है।

राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक योग्यता के रूप में राज्य के भीतर। लेकिन, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून को ध्यान में रखते हुए, जिससे हम हाथ में मामले में प्रस्थान करने का कोई अच्छा कारण नहीं पाते हैं, कोई नहीं है इस दलील में योग्यता है कि राज्य की विधान सभा द्वारा निर्वाचित "राज्य का प्रतिनिधि" भी राज्य का एक सामान्य निवासी होना चाहिए

क्योंकि जो मतदाता उन्हें चुन रहे हैं, उनके लिए कानून के अनुसार ऐसा होना आवश्यक है।

"सामान्य निवासी" का प्रश्न तैयारी के लिए प्रासंगिक है

मतदाता सूची और आगे कुछ नहीं। आर. पी. अधिनियम, 1950, विशेष रूप से धारा 13 डी, 14, 15, 17, 18, 19 और 20 में निहित प्रावधानों की योजना को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है। आर. पी. अधिनियमों द्वारा शासित चुनावों के उद्देश्यों के लिए मतदाता सूची धारा 15 के तहत विधानसभा–

क्षेत्रवार तैयार की जाती है। धारा 13 डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची से संबंधित है और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर शामिल सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची को एक साथ मतदाता सूची के रूप में प्रस्तुत करती है।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। मतदाता सूची मूल रूप से विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार की जाती है और वर्षवार संशोधित की जाती है। धारा 17,18,19 और 20 के संयुक्त पठन से पता चलता है कि एक व्यक्ति एक बार मतदान करने के बाद खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत करा सकता है।

केवल एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो वह होना चाहिए जिसके भीतर वह एक सामान्य निवासी हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

98

पम्पकवी रायप्पा बेलगली बनाम। बी. डी. जट्टी और अन्य। , [1971] 2 एस. सी. आर. 611, मैसूर विधान सभा के लिए पहले प्रतिवादी का चुनाव था

चुनौती दी गई, दूसरों के बीच, इस आधार पर कि वह एक होना बंद कर दिया था

जामखंडी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर "सामान्य रूप से निवासी" व्यक्ति और इस प्रकार उसके लिए मतदाता सूची में उसके नाम की प्रविष्टि की वैधता पर सवाल उठाता है।

निर्वाचन क्षेत्र। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आधार सहित चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था। इस न्यायालय ने इसके खिलाफ अपील को खारिज करते हुए

उच्च न्यायालय के निर्णय में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि

मतदाता सूची में निर्वाचक के रूप में पंजीकरण, जैसा कि आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 19 में प्रदान किया गया है, में यह शर्त शामिल है कि व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में "सामान्य रूप से निवासी" होना चाहिए और अभिव्यक्ति का अर्थ "सामान्य रूप से" होना चाहिए।निवासी "धारा 20 में दिया गया है और आगे कहा गया है कि" पंजीकरण के उद्देश्य से किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होने की शर्तें अभिप्रेत हैं।

केवल उसी उद्देश्य के लिए "।

पंजीकरण के लिए "सामान्य निवासी" की योग्यता इस प्रकार प्रदान की जाती है –

निर्वाचक द्वारा मतदान का स्थान तय करने के लिए आम चुनाव में एक मतदाता और मतदाता सूची तैयार करने के लिए। हमारी संवैधानिक योजना के तहत, संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रीय रूप से विभाजित हैं और इसलिए

क्षेत्रीय संपर्क मतदाता के लिए प्रदान किया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से उम्मीदवारों के लिए नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 80 (4) में "प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति

संविधान कोई योग्यता नहीं है और इसे निर्वाचित होने की पूर्व शर्त के रूप में नहीं देखा जा सकता है। संविधान ने विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 84 में "योग्यताओं" के बारे में बात की है, जैसा कि प्रावधान की सामग्री के अलावा सीमांत नोट से भी स्पष्ट होगा।

हम इस निवेदन से सहमत हैं कि परिभाषा के अनुसार, शब्द

संसद के किसी एक सदन में हित। एक व्यक्ति निर्धारित तरीके से चुने जाने के बाद ही प्रतिनिधि बन जाता है। वह पहले प्रतिनिधि नहीं थे। सबसे अच्छा, वह एक उम्मीदवार या एक संभावित प्रतिनिधि कहलाने का दावा कर सकता है। यह सिद्धांत कि प्रतिनिधि बनने से पहले उसके पास लागू कानून द्वारा निर्धारित सांठगांठ के अलावा कोई अन्य सांठगांठ होनी चाहिए, नहीं है। रुचिकर और किसी भी मामले में लिए गए किसी भी कानून या दृष्टिकोण द्वारा समर्थित नहीं।

पंचायती राज संशोधन क्षेत्रीय संबंधश्री नरीमन ने प्रस्तुत किया है कि एक संवैधानिक मान्यता है

राज्य परिषद के सदस्यों के क्षेत्रीय संबंध की अवधारणा (कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ.] [सभरवाल। सी. जे.]

99

राज्य परिषद में विशेष राज्य का प्रतिनिधित्व करना)।

उन्होंने 73 वीं और 74 वीं का उल्लेख करके इस विवाद का समर्थन किया।

संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसने भाग IX और भाग IX A को यह प्रावधान करने के लिए प्रस्तुत किया कि प्रत्येक राज्य, पंचायतों (ग्राम, मध्यस्थ और जिला स्तरों पर) और नगर पालिकाओं में स्वशासन के संस्थानों के रूप में गठन किया जाएगा (अनुच्छेद 243B और अनुच्छेद 243Q)। अनुच्छेद 243 सी (पंचायतों की संरचना), उप-अनुच्छेद (3) के खंड (सी) और (डी) के माध्यम से, किसी राज्य के विधानमंडल को कानून द्वारा, सदस्यों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है। लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य, जो ऐसी पंचायत में ग्राम स्तर के अलावा किसी अन्य स्तर पर पूर्ण या आंशिक रूप से पंचायत क्षेत्र वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य परिषद के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य, जहां वे, यथास्थिति, मध्यवर्ती या जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।

इसी तरह, अनुच्छेद 243 आर (नगर पालिकाओं की संरचना) के तहत,

उप-अनुच्छेद (2), किसी राज्य के विधानमंडल को कानून द्वारा, "लोक सभा के सदस्यों और राज्य की विधान सभा के सदस्यों की नगरपालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की शक्ति निहित की गई है जो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से शामिल हैं।नगरपालिका क्षेत्र "और" राज्य परिषद के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं "।

श्री नरीमन के अनुसार, उन्हें दी गई संवैधानिक मान्यता

राज्य परिषद के सदस्य (राज्य परिषद में विशेष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के रूप में) और स्थानीय निकायों के उद्देश्यों के लिए उस राज्य में किसी भी पंचायत या नगरपालिका क्षेत्र में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में उनकी स्थिति के बीच क्षेत्रीय संबंध इस दलील को मजबूत करता है कि स्थानीय निकायों के भीतर स्थानीय निवास पर आग्रहराज्य परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए विशेष राज्य संवैधानिक योजना का हिस्सा था।

इस तर्क को, बारीकी से जांच करने पर, योग्यता से रहित पाया गया है

कई कारण हैं।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपर उल्लिखित प्रावधान अपवादात्मक नहीं हैं।

स्थानीय निकायों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य में किसी पंचायत या नगरपालिका क्षेत्र में पंजीकृत निर्वाचक के रूप में अपनी स्थिति के कारण राज्य परिषद के किसी सदस्य के संबंध में। वे समान रूप से लोक सभा और विधान सभाओं के सदस्यों पर लागू होते हैं (वास्तव में, विधायी 100)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. एस. सी. आर.

संबंधित राज्य की परिषदें)।

दूसरा, उपरोक्त प्रावधान स्थानीय स्व की योजना का हिस्सा हैं।

संविधान में निहित सरकार का उद्देश्य राज्य और संघ स्तरों पर स्थानीय निकायों और विधायिका के बीच एक संबंध प्रदान करना था। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, वह है राज्य विधानमंडल के सदस्यों और संसद को जमीनी स्तर तक पहुंच प्रदान करना।

मूल स्तर पर, उन्हें स्थानीय समस्याओं, मुद्दों, विचारों और आकांक्षाओं के बारे में ज्ञान से लैस करना, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है।

फिर, सक्षम करने वाले प्रावधानों का एक समान अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। उनके

प्रभाव प्रत्येक राज्य के लिए संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित या अधिनियमित किए जाने वाले प्रावधानों पर निर्भर करेगा। समर्थकारी प्रावधान, जिनका महत्व ऊपर निकाले गए वाक्यांशों में परिलक्षित होता है, स्वयं यह स्पष्ट करते हैं कि पंचायत या नगरपालिका में प्रतिनिधित्व के लिए राज्य या संघ विधानमंडल के सदस्यों का दावा इस पर निर्भर करता है –

ऐसे प्रत्येक सदस्य के लिए विभिन्न कारक जो मौजूद हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। विस्तार से यह कहा जा सकता है कि यदि पंचायत क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्य परिषद का कोई सदस्य हो सकता है तो राज्य परिषद का कोई सदस्य भी हो सकता है जो निर्वाचक के रूप में पंजीकृत नहीं है।

पंचायत क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर। इसके अलावा, प्रासंगिक खंड केवल राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, राज्य परिषद का एक नामित सदस्य भी प्रतिनिधि होने के योग्य होता है।

पंचायत या नगरपालिका में यदि वह निर्धारित योग्यता को पूरा करता है।

इसलिए, राज्य परिषद में निर्वाचित "राज्य के प्रतिनिधियों" के संबंध में इस आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

इसके अलावा, ये प्रावधान आम तौर पर योग्यताओं के लिए प्रदान करते हैं –

व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियां, जिनमें राज्य परिषद के सदस्य शामिल होते हैं, पंचायत या नगरपालिका में प्रतिनिधि होते हैं और स्थानीय स्वशासन में भाग लेते हैं। चूंकि राज्य परिषद के सदस्य उन कई स्रोतों में

से एक थे जिनका उपयोग स्थानीय स्तर पर विचारशील शाखा में विभिन्न हित समूहों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा था, इसलिए चयन की कुछ विधि निर्धारित करना अनिवार्य था।

अंतिम, लेकिन कम से कम, जिन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है वे हैं –

संवैधानिक प्रावधान। यहां तक कि इस आधार पर कि उन्हें लागू करने में किसी विशेष पंचायत या नगरपालिका के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकरण का कारक राज्य परिषद के सदस्यों के संबंध में क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना जाता था ताकि उन्हें स्थानीय पंचायत या नगरपालिका में प्रतिनिधित्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सके, यह नहीं कहा जा सकता है कि इन प्रावधानों में कुलदिप नायर बनाम जोड़ा गया है।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

101

परिषद में सदस्यता के लिए योग्यता के लिए अधिवास की आवश्यकता

राज्यों से। ऐसा कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो ऐसा निर्धारित करता होअतिरिक्त योग्यता।

इस प्रकार यह तर्क 73 वें और 74 वें संविधान पर आधारित है।

1992 के संशोधन अधिनियमों ने भाग IX और भाग IX–A को लागू किया पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए स्वशासन के संस्थानों के रूप में कोई नहीं है

याचिकाकर्ताओं का लाभ उठाएँ।

निवास की अवधारणा समय के साथ बदलती हैयह रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एक तर्कसंगत होना चाहिए

राज्य परिषद में राज्य और उसके प्रतिनिधियों के बीच संबंध। इस तरह

नेक्सस, प्रस्तुतियों के अनुसार, केवल आवश्यकता में पाया जा सकता है

न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य में निवास। राज्य का "प्रतिनिधित्व" करने में सक्षम होने के लिए, यह आग्रह किया गया है कि व्यक्ति को भाषा से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए।

राज्य के लोगों की वर्तमान समस्याएं, आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और हित और राज्य सरकार की चिंताएं। इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं हैएक राज्य के सदस्यों के दूसरे राज्य से चुने जाने के मामले में कर्तव्य और हित के बीच संघर्ष, जिन मुद्दों पर दोनों राज्य

आपस में भिड़ जाते हैं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इसमें निहित प्रावधान

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3, विवादित संशोधन से पहले, राज्य परिषद के सदस्य और जिस राज्य से वह चुना जाता है, उसके बीच एक उचित संबंध का प्रावधान करती है। अधिवास के कारण संबंध। यह तर्क दिया गया है कि संशोधन उक्त प्रावधान को समाप्त कर रहा है अर्थात

राज्य में निवास की आवश्यकता, भारतीय संघ के संघीय चरित्र को ध्यान में रखते हुए राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक तर्कसंगत सांठगांठ को समाप्त करने का प्रभाव डालती है।

श्री नरीमन ने अपने तर्कों के दौरान कहा है कि

आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 3 में व्यवस्था, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, संवैधानिक योजना के रूप में। इस आधार पर, वह तर्क देंगे कि संसद किसी संभावित सदस्य की प्रतिनिधि क्षमता निर्धारित करने के लिए कुछ अन्य मानदंड या लिंक प्रदान करके ही इस योजना से अलग हो सकती है।

राज्यों की परिषद। उन्होंने यह प्रस्तुत करते हुए इसे स्पष्ट किया कि "साधारण निवास" की परीक्षा, जो इसके संशोधन से पहले 1951 के अधिनियम की धारा 3 में निहित है, को केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है ताकि प्रभावी प्रतिनिधित्व की कुछ अन्य विशेषताएँ प्रदान की जा सकें। (i) राज्य में जन्मे, (ii) राज्य में संपत्ति रखने वाले, (iii) राज्य में किए गए परोपकारी या धर्मार्थ कार्य, (iv) शिक्षा सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] उप।

5 एस सी आर।

102

राज्य में, (v) राज्य में कुछ समय के लिए काम किया है, या कुछ ऐसे अन्य मानदंड।

राजनीतिक दलों में शक्तियों की पसंद के उम्मीदवारों को सीटें आवंटित करने के मामले में और उनका चुनाव पैंतरेबाज़ी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है या हेरफेर।

उपरोक्त तर्क शब्द की आंतरिक अवधारणा पर आधारित है।

' प्रतिनिधि '। इस शब्द 'प्रतिनिधि' का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। जैसे –

' निवास ',' प्रतिनिधि 'एक लचीली अवधारणा है। कुछ संघीय देशों में, ऊपरी सदन को उनके विचारों या हितों को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है।

घटक राज्य और अनुचित से राज्यों की रक्षा करने के लिए एक साधन प्रदान करना

संघीय कानून। संयुक्त राज्य अमेरिका में, सीनेट संघीय सिद्धांतों पर बना है। प्रत्येक राज्य, चाहे उसका आकार या जनसंख्या कुछ भी हो, दो सीनेटर भेजता है और इस प्रकार, सदन में प्रतिनिधित्व की समानता है। दूसरी ओर, प्रतिनिधि सभा का गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अमेरिका में सीनेटरों का चुनाव जनसंख्या के मत से किया जाता है। सीनेट एक निरंतर निकाय है और इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं।

कनाडा में, सीनेट एक अलग सिद्धांत पर बना है। प्रत्येक

प्रांत को एक निश्चित संख्या में सीनेटर सौंपे गए हैं, हालांकि वे असमान हैं। द. कनाडा में सीनेटरों की निष्ठा आमतौर पर उस पार्टी के प्रति होती है जो उन्हें नियुक्त करती है।

राज्यसभा अमेरिकी सीनेट से मिलती–जुलती है क्योंकि यह लगातार चलती रहती है।

शरीर। हालाँकि, राज्यसभा अमेरिकी सीनेट से अलग है क्योंकि इसके सदस्य सीधे राज्यों द्वारा नहीं चुने जाते हैं और प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं है। राज्यों से। राज्यसभा ऑस्ट्रेलियाई सीनेट से मिलती–जुलती है क्योंकि दोनों बारी–बारी के सिद्धांत पर आधारित हैं।

जिस बिंदु पर हम यहाँ जोर देना चाहते हैं वह यह है कि इसमें भी

ऐसे देश जहाँ समय बीतने के साथ सख्त संघवाद मौजूद है, मूल

राजनीतिक इकाइयों के रूप में राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए सीनेट की भूमिका

काफी हद तक गायब हो गया। वैश्वीकरण के साथ, अमेरिकी सीनेट अब स्थानीय हितों के समर्थक के बजाय एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। यहकिसी राज्य के लोगों द्वारा सीनेटरों का प्रत्यक्ष चुनाव, मजबूत राजनीतिक विकास जैसे कई कारकों के कारण अमेरिका में परिवर्तन हुआ है।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों और राष्ट्रीय विकास की वकालत करने वाले दल एकीकरण आदि।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

103

इसी तरह, भारत में, 1990 के बाद, केंद्रीय आर्थिक व्यवस्था में छूट के कारण

नियंत्रण, संघवाद के वैचारिक और सैद्धांतिक ढांचे से गुजर चुका है

निश्चित अवधारणाएँ नहीं हैं, इसलिए उन्हें समय के साथ बदलना पड़ता है। संवैधानिकनिर्माताओं ने उस लचीलेपन को ध्यान में रखा है, उन्होंने इसे संसद पर छोड़ दिया है

संसद की सदस्यता के लिए योग्यता तय करना और, जबकि

योग्यता तय करने के लिए संसद को प्रासंगिक परिदृश्य को ध्यान में रखना होगा। इन अवधारणाओं की एक समान, सुसंगत और आंतरिक परिभाषा या अर्थ नहीं हो सकता है। इन अवधारणाओं के साथ परिवर्तन होते हैं

समय की पारगमन। उन्हें व्युत्पत्ति के संदर्भ में तय नहीं किया जा सकता हैशब्दकोश।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उप–धारा (1) स्पष्ट करती है कि केवल

किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले घर के स्वामित्व या कब्जे का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से वहां रह रहा है। उप–धारा (2)

घोषणा करता है कि जेल में कैदी के रूप में कारावास या किसी निश्चित स्थान पर मानसिक बीमारी के रोगी के रूप में कारावास उस स्थान को व्यक्ति का सामान्य निवास नहीं बनाता है।

दूसरी ओर, कुछ उप–अनुभाग सामूहिक रूप से इंगित करते हैं कि

कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं के कारण अस्थायी अनुपस्थिति किसी व्यक्ति की सामान्य निवासी स्थिति को बाधित नहीं कर सकती है।

उप–धारा (1ए) में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की अस्थायी अनुपस्थिति

विशेष स्थान के परिणामस्वरूप वहाँ उनका सामान्य निवास समाप्त नहीं होता है।

उप–धाराएँ (1बी) (3) और (4) सामान्य निवासी चरित्र की रक्षा करती हैं।

एक व्यक्ति उस स्थान की तुलना में जहाँ वह सामान्य रूप से रहता है लेकिन आधिकारिक व्यस्तताओं के लिए। उप–धारा (1बी) उनके द्वारा धारण किए गए पद की जिम्मेदारियों के संबंध में अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों से विधायकों की अनुपस्थिति का ध्यान रखती है। उप–धारा (3) और (4) सेवा की

मजबूरियों (सशस्त्र बलों या पुलिस या विदेशी पोस्टिंग में) से संबंधित हैं। भारत सरकार) उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर होना जहाँ कोई व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है।

आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 20 की धारा (5) और (6) उप –

किसी व्यक्ति की उसके (और उसके पति या पत्नी के) सामान्य निवास के स्थान के बारे में पर्याप्त प्रमाण के रूप में, निर्धारित रूप में घोषणा, हालांकि इसके अधीन उप–धारा (7) के तहत बनाए जाने वाले नियमों के तहत, क्या इस संबंध में कोई प्रश्न उठाया जाना चाहिए।

104

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

लेक्सिकन सीकटटी वी को संदर्भित करता है। सफ़ोक कंट्री काउंसिल, [1980] 3 सभी। ईआर

689] , यह दर्शाने के लिए कि "सामान्य रूप से" शब्द मुख्य रूप से अवधि के लिए निर्देशित नहीं हैलेकिन उद्देश्य के लिए। इस अर्थ में सवाल यह नहीं है कि व्यक्ति को सामान्य रूप से या आदतन और कुछ हद तक निरंतरता के साथ "सामान्य रूप से" कहाँ पाया जाना है, बल्कि यह है कि क्या निवास की गुणवत्ता केवल किसी विशेष या सीमित उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि "सामान्य" और सामान्य है।

"सामान्य" और "निवासी" शब्दों का उपयोग अन्य वैधानिक प्रावधानों में भी एक साथ किया गया है और लॉ लेक्सिकन के अनुसार उनका उपयोग किया गया है।

यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति वह होना चाहिए जो हमेशा निवासी हो या विशेष स्थान पर व्यवसाय करता हो।

इन दोनों शब्दों को जोड़कर बनाई गई अभिव्यक्ति की व्याख्या करनी होगी।

आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 20 के मामले में प्रावधान के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित समय के संदर्भ में यह वह तिथि है जिस पर कोई व्यक्ति किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है।

इस प्रकार, निवास एक अवधारणा है जो अस्थायी भी हो सकती है। तब भी जब

"आम तौर पर" शब्द द्वारा योग्य "निवासी" शब्द के परिणामस्वरूप किसी विशेष शब्द का उपयोग करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता का प्रभाव निर्माण में नहीं होगा।

हमेशा या स्थायी रूप से निर्बाध आधार पर रहने के लिए स्थान। इस प्रकार यह समझ में आता है कि किसी व्यक्ति के किसी विशेष स्थान पर "सामान्य रूप से निवासी" होने की आवश्यकता भी उसके और विचाराधीन स्थान के बीच संबंध सुनिश्चित करने में असमर्थ है।

उम्मीदवार और उस राज्य के बीच सांठगांठ जिससे वह मिलता है

राज्यों की परिषद में एक सीट को भरने के लिए निर्वाचित धारणा द्वारा प्रदान किया जाता है और

विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों का वोट जो उन्हें (अनिवार्य रूप से एक भारतीय नागरिक) संसद में राज्य के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे योग्य मानते हैं।

एक चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए मतदान करते समय, उसके कौशल की धारणा

एक विधायक, राज्य के मामलों के बारे में उसका ज्ञान, जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उसके लिए उसकी सेवाएं और उसे मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में रखने में संतुष्टि या विश्वास पर्याप्त विचार या योग्यताएं हैं। ये विचार निश्चित रूप से अस्थायी या अक्सर "निवास" की भ्रामक अवधारणा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं।

यह न्यायालय के तर्क पर टिप्पणी करने से बचेगा

भारत संघ ने कहा कि यह आम जानकारी की बात है कि विवादित संशोधन लाए जाने से पहले, अच्छे 105 प्राप्त करने की चिंता में

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

उम्मीदवारों, निवास की आवश्यकता को आमतौर पर दरकिनार किया जा रहा था

अवैध सबटरफ्यूज जैसे कि गलत घोषणा करने के लिए मजबूर किया जाना

उनका वास्तविक निवास। या आगे कि अनुभव से पता चला था कि

अधिवास की योग्यता अधिकार प्राप्त करने में बाधा साबित हो रही थी परिषद में सदस्य।

यहाँ यह कहने के लिए पर्याप्त है कि हमारी चुनाव प्रणाली को स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है।

सभी ज्ञात बुराइयों से और इसलिए कोई कारण नहीं है कि संसद क्यों होनी चाहिए

ऐसा विधान लाने के अवसर से इनकार किया गया जो इसके द्वारा माना जाता है,

विवेक, जैसा कि दुरुपयोग के संभावित छेद को बंद कर देगा, जिसके लिए संसद के पास है

आवश्यक विधायी। योग्यता।

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुच्छेद 80 (4) को सही ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा है जब वे

अभिव्यक्ति 'प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि' निवास की शर्त का तात्पर्य है या प्रतिनिधित्व किए जाने वाले राज्यों के साथ अन्य संबंध के महत्व की अनदेखी की जाती है

"राज्यों की परिषद" "अभिव्यक्ति से पहले" "अभिव्यक्ति।"

अनुच्छेद 80 (4) में यह नहीं कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि चुना जाए

अनुच्छेद 80 (4) में आवश्यकता शब्दों के लिए हिंसा करेगी और होगीव्याकरणिक रूप से गलत।

अनुच्छेद 80 (4) के व्याकरणिक खंड विश्लेषण से पता चलता है कि यह कुछ भी नहीं है।

यदि इसे इस प्रकार कहा जाए तो जो प्रतिबिंबित होता है उससे अधिक और कुछ भी कम नहीं हैः –

राज्यों की परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव करनासाधनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार

एकल हस्तांतरणीय वोट "।

अनुच्छेद 80 (4) में निहित प्रावधान में, इस प्रकार सक्रिय आवाज में,

'कौन चुनता है' पर जोर दिया जाता है। मौजूदा निष्क्रिय रूप में, इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाएगा। परिणाम, दोनों तरह से, समान है। अनुच्छेद 80 (4) चुनाव के तरीके से संबंधित है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।

इसलिए, "प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि" शब्द केवल

सदस्य और कोई और अवधारणा या निवास की आवश्यकता का आयात नहीं करते हैं राज्य में।

औचित्य के उद्देश्यों और कारणों की अनुपस्थिति

एक अन्य निवेदन आग्रह किया गया है कि उद्देश्यों और कारणों का कथन 106

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

संशोधन लाने वाला विधेयक स्वयं संसद की इच्छा को समाप्त करने के लिए औचित्य के अभाव को दर्शाता है जैसा कि पहले परिलक्षित हुआ था।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की मूल धारा 3 में, जो संविधान की योजना के अनुरूप थी। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लेख किया गया है कि 'सामान्य निवासी' के लिए एक सटीक परिभाषा बहुत ही सटीक थी।

और यह कि "सरकार द्वारा मामले की गहराई से जांच करने" के बाद किसी विशेष राज्य में निवास की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्य परिषद का चुनाव लड़ने के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, और इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ऐसे व्यक्ति जो सामान्य रूप से राज्य में नहीं रह रहे थे, उन्होंने केवल राज्य परिषद का चुनाव लड़ने के लिए ऐसे राज्य में खुद को मतदाताओं के रूप में पंजीकृत कराया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि "सामान्य निवासी" की परिभाषा

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 और 20 में निहित कोई संशोधन नहीं किया गया है। उनकी प्रस्तुतियों के अनुसार, यदि व्यक्ति वास्तव में निवास नहीं कर रहे हैं

किसी विशेष राज्य में गलत तरीके से खुद को मतदाताओं के रूप में पंजीकृत किया है

राज्य या 'साधारण निवासी' शब्दों को लागू करने में कठिनाई थी, कानून ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 (7) में उपाय प्रदान किया, जिससे केंद्र सरकार को चुनाव आयोग के परामर्श से नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त में चुनाव अधिकारी का निर्णय

मौजूदा कानून के तहत इस संबंध को अंतिम माना जाता है और इसे फिर से नहीं उठाया जा सकता है एक चुनाव याचिका में, जैसा कि हरि प्रसाद में एक संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था

मुलशंकर त्रिवेदी बनाम। वी. बी. राजू और अन्य। , [1974] 3 एस. सी. सी. 415।

यह तर्क दिया गया है कि वस्तुओं के कथन में दिए गए कारण

और संशोधन अधिनियम के कारण कोई तर्कसंगत औचित्य प्रदान नहीं करते हैं। विवादित संशोधन के लिए। समस्या यह है कि कुछ लोग, हालांकि नहीं

राज्य में आम तौर पर रहने वाले, फिर भी खुद को पंजीकृत करने का प्रबंधन करते हैं

राज्य के एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता और के लिए चुने जाते हैं

राज्य परिषद को प्रावधान को और अधिक प्रभावी बनाकर इससे निपटने की आवश्यकता है

ताकि ऐसे पंजीकरण, यदि कोई हो, को रोका जा सके और ऐसे पंजीकरण को रद्द किया जा सके।

मतदाता सूची से उनके नाम का पंजीकरण और विलोपन। यह समस्या,

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एक अलग उपचार की आवश्यकता है लेकिन हड़ताल से नहीं

राज्यों के सार्थक और प्रभावी प्रतिनिधित्व के मूल में

राज्य परिषद धारा 3 में संशोधन करती है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संशोधित धारा 3 तर्कहीन, मनमाना और असंवैधानिक है।

याचिकाकर्ता आगे तर्क देते हैं कि जवाब में हलफनामे में दिए गए कारण, कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

107

3 उद्देश्यों और कारणों के कथन में दिए गए कारणों से अलग हैंबिल के लिए।

भारत संघ के जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि के सदस्य

विधानसभाएँ यह तय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं कि कौन सबसे अच्छा होगा।

राज्य सभा में अपने राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि

नैतिकता समिति के बारे में यह एक संदिग्ध प्रस्ताव है।

राज्यों की परिषद ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बड़ी राशि

राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव में प्रेरक कारक।

याचिकाकर्ताओं को इस बात का भी अफसोस है कि उनके द्वारा व्यक्त सुविचारित विचार

संविधान के कार्यकरण पर राष्ट्रीय आयोग की तरह एक प्रतिष्ठित निकायअनुचित रूप से अलग कर दिया गया है। आयोग पैराग्राफ 5.11 में। 5

अपनी रिपोर्ट में अपना विचार व्यक्त किया कि संसदीय विधान जो था होने के लिए अधिवास योग्यता को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था

परिषद में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया

राज्य "राज्य परिषद के मूल संघीय चरित्र" को प्रभावित करेंगे और उक्त सदन के उक्त मूल संघीय चरित्र को बनाए रखने के लिए, "राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए अधिवास की आवश्यकता"

संबंधित राज्य से आवश्यक है "। भारत संघ ने कहा है कि यह आयोग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सम्मानपूर्वक भिन्न है।

हमें इस सवाल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या राष्ट्रीय के विचार

संविधान के कार्यकरण पर आयोग को इसके सभी आयामों में इस मुद्दे की विस्तृत जांच द्वारा समर्थित किया गया था या नहीं, क्योंकि उक्त विचार नहीं हैं।

सरकार पर बाध्यकारी। आयोग की भूमिका सलाहकार होने की प्रकृति में अधिक थी। हम अन्य प्रस्तुतियों से प्रभावित नहीं हैं, जो पहले ही राजनीति के संघीय चरित्र के आधार पर याचिका को खारिज कर चुके हैं। आयोग के विचार इसी आधार पर आधारित थे।

हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम। वी. बी. राजू (ऊपर), द्वारा निर्भर

याचिकाकर्ताओं, यह न्यायालय इस प्रश्न से चिंतित था कि क्या गुजरात राज्य से राज्य परिषद के सदस्यों के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 का चुनाव, जिसे एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी, इस आधार पर अमान्य था कि वे गुजरात राज्य के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी नहीं थे और उनके नाम गुजरात में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अवैध रूप से दर्ज किए गए थे और क्योंकि वे आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 2 (1) (ई) के अर्थ के भीतर 'मतदाता' नहीं थे, वे उम्मीदवार बनने के योग्य नहीं थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

चुनाव में।

न्यायालय की अधिकारिता के बारे में विवाद से निपटने के दौरान

तय करें कि क्या उत्तरदाताओं के संबंध में मतदाता सूची में प्रविष्टियाँ थीं

वैध है या नहीं, इस न्यायालय ने कहाः –

" मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए एक शर्त के रूप में साधारण निवास की आवश्यकता संसद द्वारा संविधान की धारा 19 द्वारा बनाई गई है।

1950 अधिनियम बनाएँ, और जैसा कि हमने कहा, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि संसद को ऐसा क्यों करना चाहिए

न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपने की कोई शक्ति नहीं है

एक चुनाव याचिका का परीक्षण करने वाला न्यायाधिकरण निर्णय लेने की अनन्य शक्ति अंत में बात। हम पहले ही इस अवलोकन का उल्लेख कर चुके हैं

काबुल सिंह मामले में अदालत ने कहा कि 1950 के अधिनियम की धारा 14 से 24

एकीकृत प्रावधान जो मामले में एक पूर्ण संहिता बनाते हैं

मतदाता सूचियों की तैयारी और रखरखाव। उस अधिनियम की धारा 30

यह स्पष्ट करता है कि दीवानी अदालतों के पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है सवाल करते हैं। इन परिस्थितियों में हमें नहीं लगता कि यह होगा

न्यायालय की अधिकारिता के एक निहित निष्कासन का अनुमान लगाने के लिए असंगत

प्रश्न में जाने के लिए एक चुनाव याचिका का प्रयास करना। यह अनुमान है कि

इस तथ्य से मजबूत कि 1951 की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत

संविधान या उस अधिनियम के प्रावधानों का गैर–अनुपालनया नियमों में से, उस अधिनियम के तहत दिए गए आदेश ताकि उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य घोषित कर सके। प्रावधानों का पालन न करना

1950 के अधिनियम की धारा 19 घोषणा के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं कर सकती है।

उस खंड के तहत एक चुनाव शून्य है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

" हम सोचते हैं कि संसद का इरादा इस सवाल पर विचार करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति मतदाता सूची में निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी है, एक चुनाव याचिका का प्रयास करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटाने का है।

और 1951 के अधिनियम। यह 1950 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा यदि यह सवाल किया जाए कि क्या कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी था। चुनाव की कोशिश करते हुए अदालत या न्यायाधिकरण में नए सिरे से मुकदमा चलाया जाना था

याचिका "।

उपरोक्त टिप्पणियां याचिकाकर्ताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाती हैं।

किसी भी तरह से। आर. पी. अधिनियम के तहत एक अलग तंत्र उपलब्ध हो सकता है,

1950 109 के नाम की प्रविष्टि की शुद्धता पर सवाल उठाना और पूछताछ करना।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में एक व्यक्ति, एक उपाय

के चुनाव को चुनौती देने के लिए एक चुनाव याचिका से अलग

घोषित उम्मीदवार को चुनाव में वापस कर दिया गया है, लेकिन यह तथ्य नहीं हो सकता है

तर्क के किसी भी विस्तार से, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं किसंसद की सदस्यता के लिए योग्यता से अधिवास की आवश्यकता

कानून या सामान्य ज्ञान के खिलाफ है।

भारत संघ निर्वाचन नियम, 1960 के पंजीकरण का उल्लेख करेगा।

आर. पी. अधिनियम, 1950 की धारा 20 के तहत बनाए गए नियम। उक्त नियम,आम तौर पर, मतदाता सूची के रूप और भाषाओं का प्रावधान करें;

भागों में इसकी तैयारी; नामों का क्रम; ऐसे प्रपत्र जिनमें घोषणा की जाती है दावा और योग्यता की पूर्ति के बारे में किया जाना आवश्यक है;

आवासों में रहने वालों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी; तक पहुंच

रजिस्टर; मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन और उसका प्रचार किया जाना;

दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया, अस्वीकृति या स्वीकृति के लिए प्रक्रिया जाँच के बाद या बिना; नामों का समावेश या विलोपन; नामों का अंतिम प्रकाशन

मतदाता सूची; पारित आदेशों के खिलाफ अपील या संशोधन; पहचान पत्रआदि। हम इन नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं पा सके हैं।

निर्धारित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शक माना जा सकता है

एक विशेष तथ्य स्थिति यदि कोई व्यक्ति "सामान्य निवासी" है या नहीं है

समय के एक विशेष बिंदु पर एक विशेष स्थान का।

हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है

चुनावी कानून में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए "सामान्य रूप से निवासी" अभिव्यक्ति की सटीक परिभाषा दें। हम भी देने की कोशिश नहीं करेंगे।

इन कार्यवाहियों में ऐसी परिभाषा क्योंकि वह विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक मामला होगा। हम जिस बात पर जोर देना चाहते हैं वह केवल इस तथ्य पर है कि केंद्र सरकार को अभिव्यक्ति की सटीक परिभाषा देने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और स्पष्ट रूप से इस कठिनाई को स्वीकार किया।

संशोधन।

इस संदर्भ में, न्यायालय के लिए जो खुला हो सकता है वह यह जांच करना है कि क्या

आर. पी. अधिनियम, 1550 की धारा 20 में दी गई अभिव्यक्ति के अर्थ को देखते हुए या शब्दकोश के सामने दिए गए अर्थ को देखते हुए सटीक परिभाषा देने में कठिनाई एक वास्तविक कारण नहीं था, जिसके द्वारा उक्त अभिव्यक्ति को आम तौर पर समझा जा सकता है। हम पहले ही पा चुके हैं कि विचाराधीन प्रावधान वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है और कानून द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन में कमी है कि यह एक स्पष्ट परिभाषा नहीं देता है कि किसी व्यक्ति के सामान्य निवास के प्रश्न का निर्धारण कैसे किया जाना है।

110

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

संविधान के अनुच्छेद 84 में सदस्यता के लिए योग्यता का प्रावधान है।

संसद से। राज्य परिषद सहित संसद के किसी भी सदन में एक सीट भरने के लिए किसी व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 84 की आवश्यकताएँ हैंः

((i) निर्वाचित व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।

((ii) उसे निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रतिज्ञान की शपथ लेनी चाहिए।

तीसरी अनुसूची में;

(iii) राज्य परिषद के मामले में उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

उम्र का;

((iv) उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएँ होनी चाहिए जो निर्धारित की जाएं।

संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस संबंध में।

के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए अयोग्यताएँ

संसद का कोई भी सदन अनुच्छेद 102 में निहित है। एक व्यक्ति को अयोग्यता का सामना करना पड़ता है यदि वहः

(1) लाभ का कोई भी पद रखता है;

((ii) अस्वस्थ दिमाग का है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है; (iii) एक गैर–निर्वहन दिवालिया है;

((iv) भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त की है।

किसी विदेशी राज्य आदि का;

(v) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत इस तरह से अयोग्य है।

इस प्रकार, संविधान में यह कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति को चुना जाए

राज्य परिषद में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनिवार्य रूप से उस राज्य में ही एक मतदाता होना चाहिए। संविधान ने कुछ योग्यताओं और अयोग्यताओं को निर्धारित करने के बाद, ऐसी अन्य योग्यताओं या अयोग्यताओं को प्रदान करने का काम संसद पर छोड़ दिया है। संसद ने शुरू में एक

अतिरिक्त योग्यता निर्धारित की थी कि इस प्रकार चुने गए व्यक्ति को राज्य में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना चाहिए। पाँच दशकों से अधिक समय तक इस प्रावधान पर काम करने के बाद, संसद ने अपने विधायी विवेक में, विवादित संशोधन के माध्यम से निर्णय लिया कि राज्य परिषद में किसी राज्य का प्रतिनिधि बनने के लिए चुने गए व्यक्ति को आवश्यक रूप से किसी विशेष राज्य के भीतर निर्वाचक होने की आवश्यकता नहीं है या, दूसरे शब्दों में, उसे भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वह संबंधित राज्य में हो।

भारत संघ ने प्रस्तुत किया है कि संसदीय बहस और 111

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

स्थायी समिति की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पिछले पचास वर्षों के अनुभव पर विचार किया गया है। इसकी प्रस्तुतियों के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ संसद के साथ जिन विचारों पर विचार किया गया, उनमें शामिल थे –

तथ्य यह है कि संविधान किसी भी अनिवार्य आवश्यकता को निर्धारित नहीं करता है कि निर्वाचित सदस्य उस राज्य में निर्वाचक होना चाहिए जहाँ से वह चुना जाता है।

भारत संघ यह भी दावा करेगा कि कई व्यक्ति जिनकी उपस्थिति है

जनता और राज्य परिषद और इस प्रकार, आवासीय प्रावधान को खोलने का उद्देश्य इस संबंध में मदद करना था। अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत संविधान एक नागरिक को अपना निवास चुनने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। चयन करें। निर्वाचित प्रतिनिधियों के कई मामले हैं जिनके पास कई आवास हो सकते हैं और उन्हें मतदान करने की सुविधा के लिए उनमें से किसी एक को चुनना पड़ सकता है।

कई स्थानों पर कई आवास रखने वाले व्यक्तियों के मामले

कम और दूर के बीच होगा। अन्यथा भी इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि कानून की आवश्यकता सामान्य निवास की थी जो किसी व्यक्ति के कई आवासों में से प्रत्येक पर लागू नहीं होती थी।

हम राजनीतिक मजबूरियों या विचारों से चिंतित नहीं हैं।

जो भारत संघ के उपरोक्त प्रस्तुतियों में से कुछ और उसके रुख का समर्थन करने वाले अन्य लोगों द्वारा निहित हैं। संसद के कुछ विशिष्ट सदस्यों की भागीदारी के कारण संसद में बहस या चर्चा की क्षमता या प्रतिभा, या गुणवत्ता में वृद्धि के बारे में भारत संघ की याचिका की जांच करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है।

रिट याचिकाकर्ताओं की दलीलों को चुनौती देने वाली दलीलों के दौरान विद्वान वकील द्वारा नाम दिए जाने की मांग की गई थी।

यहाँ यह कहने के लिए पर्याप्त है कि दोनों पक्षों की दलीलें दिखाई देंगी

कि कानून में पूर्व व्यवस्था, जो कि विवादित संशोधन से पहले की व्यवस्था है, इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति सामान्य रूप से किसी विशेष स्थान का निवासी है या नहीं, काम नहीं किया था।

संतोषजनक रूप से। कानून इस संबंध में स्पष्ट संक्षिप्त परिभाषा या मार्गदर्शन नहीं देता है। संबंधित व्यक्ति की घोषणा को आमतौर पर 112 के रूप में लिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

सुसमाचार की सच्चाई और इस तरह की घोषणा की शुद्धता पर विवाद होने से पहले, चुनौती देने वाले को इसके विपरीत तथ्यों को दिखाने वाले ठोस सबूत के साथ खुद को तैयार करना चाहिए। इस परिदृश्य में, ऐसी घोषणाएं जो इसके निर्माताओं की जानकारी के लिए झूठी थीं, उनका उपयोग बेशर्मी से और दंड से मुक्ति के साथ किया गया प्रतीत होता है। हम इस प्रवृत्ति का उल्लेख करते हैं क्योंकि इसके अस्तित्व का आरोप कुछ वकीलों द्वारा लगाया गया था और किसी ने भी इससे इनकार नहीं किया था। निस्संदेह यह एक सुखद स्थिति नहीं हो सकती।

फिर भी, अगर संसद ने अपने विवेक से इसे हटाने का फैसला किया है

राज्य परिषद में किसी विशेष राज्य के प्रतिनिधि के रूप में एक सीट को भरने के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्यता के रूप में अधिवास की आवश्यकता के साथ, गलती

संसद के ऐसे निर्णय के साथ इस आधार पर नहीं पाया जा सकता है कि "सामान्य रूप से निवासी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ था, इसे परिभाषित करने में कठिनाई एक ईमानदार आधार नहीं था। यह, सरल कारण के लिए कि संविधान या कानून में किसी भी समय अधिवास प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं था

विशेष रूप से राज्य परिषद के उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण योग्यता के रूप में आवश्यकता।

हालाँकि, हमें यहाँ यह जोड़ना होगा कि हालांकि विवादित संशोधन को उपरोक्त कारणों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिवास को समाप्त कर दिया गया है। आवश्यकता हमेशा जवाब नहीं हो सकती क्योंकि यह विधानमंडल और केंद्र सरकार का दायित्व बना रहेगा कि वे "साधारण निवासी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है, इसे सटीक रूप से परिभाषित करें क्योंकि वह बनी रहेगी।

किसी विशेष राज्य में निर्वाचक के रूप में किसी व्यक्ति के पंजीकरण के लिए कोई शर्त नहींनिर्वाचन क्षेत्र और इस प्रकार एक ऐसा विषय जिससे कोई पीछे नहीं हट सकता। हम केवल चुनाव से संबंधित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इसके उचित अनुप्रयोग के उद्देश्यों के लिए उम्मीद करेंगे कि संसद और केंद्र सरकार उक्त अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

आलोचना के संबंध में कि जवाबी हलफनामे में दिए गए कारण

भारत संघ के कथन उन लोगों से अलग हैं जो के कथन में निर्धारित हैंविधेयक के उद्देश्य और कारण जो विवादित कानून बन गए, हम केवल यह बता सकते हैं कि किसी प्रस्तावित विधान के उद्देश्यों और कारणों का विवरण सभी संभावित कारणों या औचित्य का संग्रह नहीं है। हम विवादित लोगों के उद्देश्यों

और कारणों के कथन के संबंध में इन कार्यवाहियों में भारत संघ द्वारा लिए गए रुख में कोई विरोधाभास नहीं पाते हैं।

संशोधन।

इसे 'कोई योग्यता नहीं' का मामला बनाना–इसके कार्य का उन्मूलन

संसद द्वारा

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि विवादित कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

113

संशोधन ने एकमात्र योग्यता (आवासीय) के साथ छूट दी है।

योग्यता) जिसे देने के प्रावधान में संसद द्वारा बनाया गया था

सदस्य के रूप में चुने गए व्यक्ति के प्रतिनिधि चरित्र का अर्थ

राज्यों की परिषद का, और साथ ही परिभाषित करने या निर्धारित करने में विफल रहा

कोई अन्य मानदंड जिसे संसद उस राज्य के "प्रतिनिधि" के रूप में चुने गए व्यक्ति के लिए प्रासंगिक मानती है। वे प्रस्तुत करेंगे कि सीमांत नोट "राज्यों की परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता" जो था

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 के लिए रखे जाने को अर्थहीन बना दिया गया था।

विद्वान वकील, श्री नरीमन, अनुच्छेद के तहत यह अनुमति देंगे।

84 (ग) संघ सूची के अनुच्छेद 327 और प्रविष्टि 72 के साथ पठित, समय–समय पर कानून बनाकर संसद सदस्य के लिए योग्यताओं को परिभाषित या संशोधित करना संसद की विधायी क्षमता के भीतर है। याचिकाकर्ता यह भी स्वीकार करेंगे कि प्रतिनिधि चरित्र सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका राज्य द्वारा उस राज्य में "सामान्य रूप से निवासी" व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है, जो उनके अनुसार, अपनाई गई मूल विधि थी, जैसा कि आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 3 में परिलक्षित होता है, लेकिन अन्य लिंक पाए जा सकते हैं। इस प्रकार, यह विवादित नहीं है कि "निवास" के संबंध को समय–समय पर परिस्थितियों की मांग पर बदला या संशोधित किया जा सकता है।

हालाँकि, तर्क यह है कि धारा 3 को संशोधित किया जा सकता है

संसद केवल तब तक जब तक वह राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ योग्यता का उल्लेख करती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह राज्य परिषद में किसी विशेष राज्य का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य उपयुक्त तरीके को लागू करके किया जाना चाहिए।

यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित संशोधन प्रदान करने में विफल रहा था

वैकल्पिक अतिरिक्त योग्यता, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक, जो भारत में कहीं भी रहता है, अब किसी भी राज्य विधानसभा द्वारा चुना जा सकता है, भले ही वह सामान्य रूप से निवासी हो, और तब भी जब उसका निर्वाचक के रूप में पंजीकरण उस राज्य से बाहर हो। उसे इंगित करने के लिए कोई अतिरिक्त योग्यता प्रदान नहीं की गई है।राज्य परिषद में होने वाली बहसों या प्रवचनों में उपयोगिता।

यह याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस धारणा पर कि वहाँ

यदि किसी विशेष राज्य में निवास की आवश्यकता के अलावा कोई अन्य मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता होती, तो कुछ अलग या वैकल्पिक योग्यता या प्रतिनिधित्व की विधि निर्धारित की जा सकती थी; जैसे कि जन्म, शिक्षा, व्यवसाय करना या निर्धारित अवधि के लिए उस स्थान पर लाभ के लिए काम करना या राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी राज्य में परोपकारी या धर्मार्थ कार्य करना। उनका तर्क है कि 114 तक कुछ जड़ें या कुछ संबंध सुनिश्चित करने थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

व्यक्ति के प्रतिनिधि चरित्र को बनाए रखने के लिए मौजूद होना

विशेष राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए।

लेकिन, यह याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि विवादित द्वारा

भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कोई भी राज्य कर सकता है। राज्यों की परिषद में उस राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत में विधानसभा।

उपरोक्त तर्क को आगे बढ़ाते हुए, श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया कि,

विवादित संशोधन के बाद, "प्रभावी रूप से" कोई योग्यता निर्धारित नहीं है संसद द्वारा उस विशेष राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए व्यक्ति के लिए, जिसकी विधानसभा ने उसे चुना है, क्योंकि वह "भारत में" किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक हो सकता है, जो वकील के अनुसार विशेष राज्य विधानसभा द्वारा चुने गए व्यक्ति के लिए "उस राज्य का प्रतिनिधि" होने की योग्यता नहीं है। यह अब पूरे व्यक्तिपरक पर छोड़ दिया गया है।

प्रत्येक राज्य विधानसभा का निर्धारण, किसी एक को चुनने के लिए, यहां तक कि एक जो एक है

किसी अन्य राज्य में निर्वाचक (यानी सामान्य रूप से निवासी) या जिसका उस राज्य से कोई संबंध नहीं है जो उसे राज्य में अपना प्रतिनिधि चुनता है।

राज्यों की परिषद।

यह तर्क दिया गया है कि विवादित संशोधन द्वारा, संसद ने

जबकि राज्यों की परिषद की सदस्यता के लिए "योग्यता" स्थापित करने का तात्पर्य अनुच्छेद 80 में "राज्य के प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति को उचित सम्मान देने में विफल रहा। तर्क यह है कि इस संशोधन द्वारा संसद ने अनुच्छेद 84 (4) के तहत अपने आवंटित कार्य को प्रभावी रूप से त्याग दिया है, जिसकी जांच लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 3 को लागू करते समय यह परिभाषित करके की गई थी कि राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि कौन होंगे।

लेकिन अब यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में राज्य विधानसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया है जो एक विशेष व्यक्ति का चुनाव करते हैं अर्थात।

चाहे चुने गए व्यक्ति का जन्म, निवास, सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन या अन्यथा राज्य के साथ कोई संबंध है या नहीं।

तर्क यह है कि इस मुद्दे पर राज्य विधानसभाओं की इच्छा

जो अर्थ के भीतर राज्य का प्रतिनिधि होने के लिए योग्य है

अनुच्छेद 80 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति पर्याप्त या अच्छी मार्गदर्शक नहीं है क्योंकि योग्यता का प्रश्न संविधान द्वारा संसद द्वारा निर्धारित किया गया था न कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। इनकार करना

संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों का राज्य विधानसभाओं द्वारा उल्लेख संविधान में संघ के एक महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से नकारता है। द. राज्य परिषद में राज्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

उपरोक्त पंक्तियों पर याचिकाकर्ताओं की दलीलें हमें प्रभावित नहीं करती हैं। यह.

यह सब संसद की विधायी क्षमता से संबंधित मामला है जिस पर

वैधता के लिए चुनौती अलग हो जाती है।

परिषद के चुनावों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अन्य बातों के साथ–साथ राज्य अनुच्छेद 80 और 327 में निहित हैं। अनुच्छेद 80 (4) में प्रावधान है कि राज्य परिषद के लिए चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा होंगे।

राज्यों की विधान सभाओं से। अनुच्छेद 327, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान करता है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद संसद के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में "समय–समय पर" कानून द्वारा प्रावधान कर सकती है।

उपरोक्त प्रावधान इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि संविधान

समय–समय पर चुनावों से संबंधित कानून में परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार किया और संसद को इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर विधायी उपाय करने की जिम्मेदारी के साथ–साथ आवश्यक शक्ति भी सौंपी, जिसमें मौजूदा उपायों में संशोधन करने की शक्ति शामिल होगी। यदि इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई संदेह व्यक्त किया जाता है, तो हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम के मामले का संदर्भ दिया जा सकता है। वी. बी. राजू और अन्य। , [1974] 3 एससीसी 415: [1974] 1 एस. सी. आर. 548, जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है किः

" अनुच्छेद 327 संसद को प्रावधानों के अधीन पूरी शक्ति देता है।संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संविधान का

चुनाव की तैयारी सहित चुनाव के लिए या उसके संबंध में रोल "।

संसद के पास अनुच्छेद 246 के तहत विशेष शक्ति है।

सातवीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना। संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अनुच्छेद 84 और 327 और प्रविष्टि 72 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संसद के लिए कानून बनाकर यह तय करने का विषय है कि संविधान में निर्धारित योग्यताओं के अलावा कौन सी "अन्य" योग्यताओं को उन

व्यक्तियों द्वारा पूरा करना अनिवार्य बनाया जाए जो संविधान में निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना चाहते हैं।

राज्यों की परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में सीटें भरें। अनुच्छेद 80 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य परिषद में सीटों का आवंटन तदनुसार किया जाएगा।

चौथी अनुसूची में उस संबंध में निहित प्रावधानों के साथ। अनुच्छेद 80 (4) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 116 के अनुसार किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

एकल हस्तांतरणीय के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के साथ

वोट करें।

संविधान का अनुच्छेद 84 इन योग्यताओं को निर्धारित करता है –

संसद की सदस्यता जबकि अनुच्छेद 102 अयोग्यताओं को इंगित करता है। सबसे प्रासंगिक खंड, अनुच्छेद 84 (सी) के तहत, यह संसद को निर्धारित करना है

" राज्य परिषद की सदस्यता के लिए ऐसी अन्य अर्हताएँ जो वह आवश्यक या उचित समझे; अर्थात, दोनों के अलावा अन्य अर्हताएँ।

अनुच्छेद 84 (ए) और (बी) के तहत संवैधानिक रूप से निर्धारित। , भारत की नागरिकता और न्यूनतम आयु (30 वर्ष से कम नहीं)।

उपरोक्त के अलावा, संविधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है

इस संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ।

यदि संविधान का इरादा था कि राज्यों के "प्रतिनिधि" राज्य के निवासी होने चाहिए या राज्य के साथ कोई संबंध या संबंध होना चाहिए।

जहाँ से प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, यानी याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित प्रकार की कड़ी या सांठगांठ, ऐसा प्रावधान इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से किया गया होगा जैसा कि आयु की आवश्यकता के संबंध में किया गया है और

नागरिकता। ऐसी स्पष्ट आवश्यकता के अभाव में, योग्यता के मामले में निवास की आवश्यकता या किसी अन्य सांठगांठ को अनुच्छेद 80 या 84 में नहीं पढ़ा जा सकता है।

तथ्य यह है कि एक उम्मीदवार को किसी भी संसद में नामांकित होने की आवश्यकता होती है

भारत में निर्वाचन क्षेत्र उन्हें केवल इस आधार पर राज्य का प्रतिनिधि होने के अधिकार से वंचित नहीं करता है कि वे वहां नामांकित नहीं हैं।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. ,

[2003] 4 एस. सी. सी. 399, इस न्यायालय ने मतदान के अधिकार को अपने भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के रूप में माना। लेकिन चुनाव में खड़े होने के अधिकार के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह चुनाव आयोग द्वारा विनियमित अधिकार है।

कानून।

यहां तक कि इस बहस में गए बिना कि क्या मतदान का अधिकार एक है

वैधानिक या संवैधानिक अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार निर्विवाद रूप से एक

वैधानिक अधिकार, अर्थात चुनाव में खड़े होने के अधिकार को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है। यह विशुद्ध और सरल एक वैधानिक अधिकार है जिसे संसद द्वारा बनाया और छीन लिया जा सकता है और इसलिए, हमेशा वैधानिक सीमाओं के अधीन होना चाहिए।

पी. पोन्नुस्वामी बनाम। निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र और 117

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. आई.]

ओआरएस। , [1952] एस. सी. आर. 218, इस न्यायालय ने जोसेफ थेबर्गे एंड एन. आर. में प्रिवी काउंसिल के निर्णय को अनुमोदन के साथ देखा। वी. फिलिप लॉड्री (1876) 2 एसी 102, और यह अभिनिर्धारित किया कि चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार एक नागरिक अधिकार नहीं है, बल्कि क़ानून या विशेष कानून का निर्माण है और इसके द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन होना चाहिए। निर्णय के पैराग्राफ 19 में यह निम्नानुसार देखा गया थाः –

" इस निर्णय से जो बिंदु सामने आते हैं, उन्हें इस प्रकार बताया जा सकता हैः" (1) चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में मतदान करने या खड़े होने का अधिकार एक नहीं है

नागरिक अधिकार लेकिन कानून या विशेष कानून का एक प्राणी है और होना चाहिए उसके द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन।

(2) कड़ाई से कहें तो इसकी जांच करना विधायिका का एकमात्र अधिकार है

और अपने सदस्यों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों का निर्धारण करना, और यदि विधायिका इसे अपने हाथों से ले लेती है और एक में निहित होती है

विशेष न्यायाधिकरण एक पूरी तरह से नया और अज्ञात क्षेत्राधिकार, जो विशेष है

अधिकारिता का प्रयोग उस कानून के अनुसार किया जाना चाहिए जो

इसे बनाएँ "।

(जोर दिया गया)

हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी (ऊपर) के मामले में इसे दोहराया गया था।

वहः

" चुनाव के लिए खड़े होने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और क़ानून कर सकता हैइसलिए उस तरीके को विनियमित करें जिसमें अधिकार को लागू किया जाना है

या इसे लागू करने का उपाय। ”

इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा एक बार फिर ज्योति बसु बनाम में व्यक्त किया गया था।

देवी घोषाल, [1982] 1 एस. सी. सी. 691, निम्नलिखित शब्दों मेंः

" चुनने का अधिकार, हालांकि यह लोकतंत्र के लिए मौलिक है,

असंगत रूप से पर्याप्त, न तो एक मौलिक अधिकार और न ही एक सामान्य कानून

सही है। यह शुद्ध और सरल, एक वैधानिक अधिकार है। तो होने का अधिकार है

चुने गए। चुनाव पर विवाद करने का भी यही अधिकार है। कानून के बाहर, वहाँ

चुनाव। सांविधिक सृजन वे हैं, और इसलिए, सांविधिक के अधीन हैं सीमा। चुनाव याचिका सामान्य कानून की कार्रवाई नहीं है, न ही

इक्विटी में। यह एक वैधानिक कार्यवाही है जिसके लिए न तो आमकानून और न ही समानता के सिद्धांत लागू होते हैं, लेकिन केवल वे नियम लागू होते हैं जो

कानून बनाता है और लागू करता है। यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र है और एक विशेष

अधिकारिता का प्रयोग हमेशा क़ानून 118 के अनुसार किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

कथित नीति के विचारों पर उनका सहारा लेने का अधिकार क्योंकिनिर्वाचन विवादों के विचारण से संबंधित ऐसे मामलों में नीति,

कानून यही निर्धारित करता है। चुनाव विवादों के मुकदमे में, अदालत

एक स्ट्रेट–जैकेट में रखा जाता है। इस प्रकार पूरी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है।

एक निर्वाचन क्षेत्र को बुलाने वाली अधिसूचना जारी करने सेके अंतिम संकल्प तक एक सदस्य या सदस्यों का चुनाव करें

चुनाव से संबंधित विवाद, यदि कोई हो, द्वारा विनियमित किया जाता है

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, प्रक्रिया के विभिन्न चरण

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों द्वारा निपटा जा रहा है। नहीं हो सकता है।

द्वारा उपबंधित को छोड़कर संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और फिर से, ऐसा कोई चुनाव नहीं

द्वारा प्रदान किए गए तरीके को छोड़कर पूछताछ की जा सकती है

अधिनियम को एक पूर्ण और स्व–निहित संहिता माना गया है। जिसे चुनाव के संबंध में दावा किए गए किसी भी अधिकार के रूप में पाया जाना चाहिए या

चुनाव विवाद। .....

(जोर दिया गया)

संविधान के अनुच्छेद 84 में निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं –

संसद के किसी भी सदन की सदस्यता। अनुच्छेद 84 (सी) संसद के लिए उनके अलावा कोई अन्य योग्यता निर्धारित करना अनिवार्य नहीं बनाता है।

खंड (क) और (ख) द्वारा विहित। संसद ऐसी कुछ अर्हताओं को निर्धारित कर सकती है या नहीं भी कर सकती है और कुछ को निर्धारित करने के बाद जब चाहे उन्हें निरस्त कर सकती है। इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि एक बार जब संसद कोई योग्यता निर्धारित कर देती है, तो वह उसे रद्द या निरस्त नहीं कर सकती है। संसद की विधायी शक्ति पर ऐसी कोई सीमा नहीं है, जिसकी पुष्टि सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 72 द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 84 के खंड (सी) की भाषा एक शक्ति

का निर्माण करती है न कि कर्तव्य का। यदि यह कोई अतिरिक्त योग्यता निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं है, तो यह समाप्त किए गए योग्यता का विकल्प प्रदान करने के लिए भी बाध्य नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के तर्क का जोर यह है कि 'बाहरी' होगा

एक 'अंदरूनी सूत्र' को वरीयता दी गई। यह अनिवार्य रूप से अंतिम परिणाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव का परिणाम चुनाव के चुनाव पर निर्भर करेगा।

महाविद्यालय, अर्थात। राज्य की विधान सभा, किसी अन्य कारक की तुलना में। किसी भी स्थिति में, भले ही किसी 'बाहरी व्यक्ति' का चयन किया जाए, यह तर्क देना बहुत दूर की बात है कि इसके परिणामस्वरूप सदन का 'चरित्र' बदल जाएगा।

कुलदिप नायर बनाम। यू. क्यू. आई. [सभरवाल। सी. जे.]

119

संशोधन द्वारा जो अनिवार्य रूप से किया गया है वह यह प्रदान करना है कि

राज्य के बाहर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है।

उस राज्य से राज्य परिषद को। यह प्रावधान करके मतदाताओं की पसंद को व्यापक और विस्तारित किया गया है। यदि मतदाता ऐसा चुनते हैं, तो वे हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसका राज्य के साथ संबंध या संबंध है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित प्रकार का संबंध है।

यह तर्क कि आर. पी. अधिनियम, 1951 की संशोधित धारा 3 निरर्थक है या

यह कि आक्षेपित संशोधन धारा 3 को निरर्थक बनाता है, सही नहीं है। जबकि अनुच्छेद 84 सदस्यता के लिए योग्यता के रूप में भारत की नागरिकता निर्धारित करता है।

इस प्रतिबंध को हटाकर कि खड़े होने के योग्य व्यक्ति केवल संबंधित राज्य में निर्वाचक होंगे, राज्य परिषद के चुनाव के लिए विचार करना। जिस उद्देश्य के लिए दूसरे सदन की परिकल्पना की गई थी, उसे ध्यान में रखते हुए, अर्थात, लोगों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिए, संशोधन राज्य परिषद के चरित्र को नहीं बदलता है।

यह कहना कि संसद ने अपने दायित्वों का 'त्याग' कर दिया है, सही नहीं है। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर देखा गया है, संसद के लिए यह अनिवार्य नहीं था कि वह योग्यताओं के संबंध में कोई कानून बनाए या कोई कानून बनाए।

योग्यताएँ। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, संशोधन के बाद भी, (i) निर्वाचक समान रहते हैं, अर्थात् राज्य विधानसभाएँ; (ii) निर्वाचित व्यक्ति।

राज्य के प्रतिनिधि बने रहते हैं; और (iii) किसका चुनाव करना है, इसका चुनाव और निर्णय राज्य विधानसभाओं के पास बना रहता है।

राज्य विधानसभा के समक्ष विचार के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। लेकिन अंतिम विकल्प और निर्णय हमेशा राज्य विधानमंडलों का होता है।

इसलिए, यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का निर्णय लेते हैं जो सामान्य रूप से राज्य का निवासी नहीं है, तो वे सभी परिस्थितियों की पूरी जानकारी के साथ ऐसा करेंगे और यह उनका निर्णय होगा कि उनका प्रतिनिधि कौन होना चाहिए।

राज्य। इसे, किसी भी तर्क के विस्तार से, संसद के दायित्वों या कार्यों का त्याग नहीं कहा जा सकता है।

उपरोक्त संवैधानिक जनादेश के तहत, संसद ने, अन्य बातों के साथ–साथ, 1950 और 1951 के आर. पी. अधिनियमों के साथ–साथ विवादित संशोधन सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. को अधिनियमित किया है।

5 एस सी आर।

120

एक्ट करें। विवादित संशोधन अधिनियम द्वारा किसी विशेष राज्य में मतदाता होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

इस प्रकार, हमारे विचार में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलें मान्य नहीं हैं।

पानी। आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 3 में विवादित संशोधन को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। यह विधायी क्षमता को ध्यान में रखते हुए पारित होता है। यह संविधान के भाग III के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है, न ही उस मामले के लिए संविधान के किसी अन्य प्रावधान, व्यक्त या निहित, का उल्लंघन करता है। निवास की आवश्यकता को संविधान के अनुच्छेद 80 (4) में नहीं पढ़ा जा सकता है।

इसलिए इस चुनौती को दूर किया जाना चाहिए।

मुद्दा No.II: मतदान की गोपनीयता

धारा 59 में 'चुनावों में मतदान करने के तरीके' का प्रावधान किया गया है।

इस तरह से मतदान करें जो निर्धारित किया जाए "। धारा 94 ने 'मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए' पढ़ने वाले सीमांत नोट द्वारा अपने निर्देश को स्पष्ट कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से मतदाता को घोषणा करके खुलासा करने की मजबूरी के खिलाफ प्रतिरक्षा दी गई।

कोई अनिश्चित शर्तें नहीं, कि "किसी भी गवाह या अन्य व्यक्ति को यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसने चुनाव में किसे वोट दिया है"। धारा 128 ने मतदाता के मतदान की गोपनीयता के अधिकार को हमले से बचाने और 'मतदान की गोपनीयता बनाए रखने' की व्यवस्था करने के लिए आगे प्रावधान किया, जिसमें "मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और बनाए रखने में सहायता करने" को चुनाव कर्तव्यों के साथ सौंपे गए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनाया गया और जब तक कि "किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अधिकृत नहीं किया जाता है", तब तक "किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी का उल्लंघन करने के लिए गणना की गई किसी भी जानकारी को संप्रेषित नहीं करना"।

गोपनीयता "।

विवादित संशोधनों के माध्यम से प्रत्येक में एक प्रावधान जोड़ा गया है।

धारा 59, 94 और 128, जैसा कि निर्णय की शुरुआत में उल्लेख किया गया है। इन संशोधनों ने राज्यों की परिषद में एक सीट भरने के लिए चुनावों के उद्देश्यों के लिए गोपनीयता के सामान्य नियम के लिए

एक अपवाद तैयार किया है, जो अब "खुले मतपत्र द्वारा" आयोजित किया जाना है, इस प्रकार अब गुप्त मतपत्र के सिद्धांत के अधीन नहीं है।

खुला मतपत्र और गोपनीयता पर याचिकाकर्ताओं की दलीलेंराज्य परिषद में सीटों को भरने के लिए किए गए संशोधन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59,94 और 128 ने गुप्त मतपत्र के स्थान पर खुले मतपत्र की अवधारणा को पेश किया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में गोपनीयता का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है जो स्वतंत्र और कुलदिप नायर बनाम पर आधारित है।

यू. ओ. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

121

निष्पक्ष चुनाव। मतदाताओं को अपने मत के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विवादित संशोधन गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता हैमतपत्र प्रणाली को खोलना जो और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के गुट द्वारा अपनी उपलब्धि के लिए एक राजनीतिक कदम है।

यह तर्क दिया जाता है कि विवादित संशोधन मौलिक का उल्लंघन करते हैं

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के साथ–साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, मानव की सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों के तहत अधिकार

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय वाचा। याचिकाकर्ताओं का आग्रह है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा में निहित मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों की सहायता के लिए लिया जा सकता है ताकि उन्हें स्पष्ट किया जा सके और उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

जैसा कि विभिन्न मामलों में किया गया है। उपरोक्त आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि धारा 3, 59, 94 और 128 में किए गए संशोधन असंवैधानिक हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करते हैं।

खुला मतपत्र और गोपनीयता पर भारत संघ की प्रस्तुति निवेदन यह है कि चुनाव की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है

राज्यों की परिषद को "गुप्त मतदान द्वारा" आयोजित किया जाना चाहिए, जैसा कि स्पष्ट रूप से किया गया हैभारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए क्रमशः चुनाव के लिए अनुच्छेद 55 (3) और अनुच्छेद 66 (1) के तहत प्रावधान किया गया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि यह व्यक्त किए गए विचार के अनुसार था

संसद की आचार समिति ने 1 दिसंबर, 1998 की अपनी रिपोर्ट में, "राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में क्रॉस वोटिंग की उभरती प्रवृत्ति" के मद्देनजर, "खुले मतपत्र द्वारा" चुनावों के लिए यह जांच की जानी चाहिए कि भारत संघ ने इस तरह के प्रावधान को शामिल किया है।

विवादित अधिनियम। इस संदर्भ में "राज्यसभा चुनावों में धन शक्ति और बाहुबल के प्रभाव" का भी उल्लेख किया गया है।

संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित प्रावधान। भारत संघ का तर्क है कि नैतिकता समिति की उपलब्ध सामग्री और रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकला था कि "गुप्त मतदान प्रणाली वास्तव में

प्रतिकूल हो गई थी और राज्यसभा में राज्यों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के प्रभावी कार्यान्वयन के खिलाफ थी"।

आगे प्रस्तुतिकरण यह है कि "गुप्त मतपत्र एक अनम्य या अनिवार्य नहीं है।

देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए "प्रक्रिया" और इसलिए "चुनाव प्रक्रिया में उभरते रुझानों और एक तर्कसंगत, उचित, लोकतांत्रिक उद्देश्य" को ध्यान में रखते हुए खुली मतपत्र प्रणाली के प्रावधान को शामिल किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

122

भारत संघ ने नैतिकता की पहली रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की है

श्री एस. बी. चव्हाण की अध्यक्षता में संसद की समिति, जिसे 15 दिसंबर, 1999 को अपनाया गया था और राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया था, ने निम्नलिखित रूप में खुली मतपत्र प्रणाली की सिफारिश की थीः –

" 19. समिति ने क्रॉस के उभरते रुझान पर भी ध्यान दिया है

राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों में मतदान

राज्यों में। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि बड़ी रकम और अन्य

विचार इन दोनों निकायों के लिए मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं एक विशेष तरीके से कभी–कभी अधिकारी की हार की ओर ले जाता है

बड़े पैसे और अन्य विचारों को शरारत करने देंचुनाव प्रक्रिया, समिति का विचार है कि गुप्त के बजाय

मतपत्र, राज्यसभा के लिए चुनाव कराने का सवाल और

राज्यों में विधान परिषदों की खुले मतदान द्वारा जांच की जा सकती है।

2003 के अधिनियम 40 द्वारा लाए गए संशोधन जो भी हैं –

इन मामलों में चुनौती का विषय पहले ही देखा जा चुका है।

आर. पी. अधिनियम, 1951 का भाग 5 "चुनाव के संचालन" से संबंधित है।

आर. पी. अधिनियम, 1951 के उक्त भाग के अध्याय 4 में "द पोल" का विषय शामिल है। अन्य बातों के अलावा, इसमें "चुनावों पर मतदान के तरीके" से संबंधित धारा 59 शामिल है।

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 59 को वर्ष 2003 में दो बार संशोधित किया गया था, पहला चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा 22 मार्च, 2003 से प्रभावी था।

2003 (2003 का अधिनियम 24) और फिर 2003 के अधिनियम 40 (आक्षेपित संशोधन) द्वारा 28 अगस्त, 2003 से प्रभावी। 2003 के अधिनियम 24 के माध्यम से संशोधन का वर्तमान उद्देश्यों के लिए बहुत अधिक परिणाम नहीं है और केवल इन शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था कि "और कोई भी वोट छद्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा" और इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए शब्दों के अलावा, कोई भी वोट प्राप्त नहीं किया जाएगा।

प्रॉक्सी द्वारा "।

2003 के अधिनियम 40 के माध्यम से संशोधन ने धारा 59 में एक परंतुक जोड़ा।

आर. पी. अधिनियम, 1951, ताकि "खुले मतपत्र द्वारा" आयोजित होने वाली राज्य परिषद में सीटों को भरने के लिए चुनावों का प्रावधान किया जा सके। धारा 59, संशोधन के बाद, निम्नानुसार हैः –

" 59. चुनाव में मतदान का तरीका। – हर चुनाव में जहां एक मतदान होता है

वोट बैलेट द्वारा इस तरह से दिए जाएँगे कि

विहित और, इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा, कोई भी वोट कुलदिप नायर बनाम नहीं होगा।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

123

प्रॉक्सी द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

बशर्ते कि प्रत्येक चुनाव में एक सीट या सीटों को भरने के लिए वोट

राज्य परिषद खुले मतदान द्वारा दी जाएगी।

आर. पी. अधिनियम, 1951 के दो अन्य प्रावधान थे जिन्हें संशोधित किया गया था।

2003 के अधिनियम 40 द्वारा, जिन्हें संशोधन के रूप में वर्णित किया गया है

धारा 59 में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप। इन अन्य प्रावधानों पर भी इस स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आर. पी. अधिनियम, 1951 का भाग VI "चुनावों से संबंधित विवादों" से संबंधित है।

इन प्रावधानों के तहत चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालयों में दायर की जाती हैं। अध्याय

भाग VI का III "चुनाव याचिकाओं के परीक्षण" से संबंधित है। इस अध्याय के तहत आने वाली धारा 94, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, निम्नानुसार हैः

" मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। कोई गवाह या कोई अन्य व्यक्ति नहीं

यह बताना आवश्यक होगा कि उन्होंने चुनाव में किसे वोट दिया है।

2003 के अधिनियम 40 ने उपरोक्त प्रावधान में एक परंतुक जोड़ा है। द.

संशोधित प्रावधान अब निम्नानुसार हैः –

" मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। – कोई गवाह या कोई अन्य व्यक्ति नहीं

यह बताना आवश्यक होगा कि उसने चुनाव में किसे वोट दिया है।

बशर्ते कि यह धारा ऐसे गवाह या अन्य लोगों पर लागू नहीं होगी।वह व्यक्ति जिसने खुले मतपत्र से मतदान किया हो।

आर. पी. अधिनियम, 1951 का भाग VII "भ्रष्ट आचरण और चुनाव" से संबंधित है।

अपराध "। अध्याय । "भ्रष्ट व्यवहार" को परिभाषित करता है। अध्याय III से संबंधित है –" चुनावी अपराध "। इस अध्याय में आने वाली धारा 128, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया है

नीचे पढ़ेः – "

128. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। – (1) हर अधिकारी, क्लर्क,

एक चुनाव में मतों की रिकॉर्डिंग या गिनती बनाए रखी जाएगी, और सहायतामतदान की गोपनीयता बनाए रखने में और नहीं (सिवाय इसके कि

किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अधिकृत कुछ उद्देश्य) किसी से संवाद करें

ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए गणना की गई कोई भी जानकारी।

• (2) कोई भी व्यक्ति जो उप–धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है

कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि बढ़ सकती है।

तीन महीने तक या जुर्माने या दोनों के साथ। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

2003 के अधिनियम 40 ने उप–धारा (1) में एक परंतुक जोड़ा है ताकि

राज्य परिषद के चुनाव के संबंध में एक अपवाद। संशोधन के बाद, धारा 128 की उप–धारा (1) निम्नानुसार हैः

" 128. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। (1) हर अधिकारी, क्लर्क,

अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो इसके संबंध में कोई कर्तव्य निभाता है

एक चुनाव में मतों की रिकॉर्डिंग या गिनती बनाए रखी जाएगी, और सहायता

मतदान की गोपनीयता बनाए रखने में और नहीं (सिवाय इसके कि

किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अधिकृत कुछ उद्देश्य) किसी से संवाद करें

ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए गणना की गई कोई भी जानकारी।बशर्ते कि इस उप–धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे

ऐसा अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो राज्य परिषद में किसी सीट या सीटों को भरने के लिए चुनाव में ऐसा कोई कर्तव्य निभाता है।

धारा 59,94 और 128 में संशोधनों का संचयी प्रभाव

2003 के अधिनियम 40 द्वारा लाया गया आर. पी. अधिनियम, 1951 इस प्रकार है कि राज्य परिषद में एक सीट को भरने के लिए चुनाव अब "खुले मतदान द्वारा" आयोजित किए जाने हैं। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता अब बना दी गई है

परंतुक में उल्लिखित अपवाद के अधीन।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील, पर बहस करते हुए

राज्यों की परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों की सीटों को भरने के लिए चुनाव में मतपत्र की गोपनीयता का सम्मान करने वाले विवादित संशोधन को चुनौती देते हुए फिर से 'बुनियादी संरचना' सिद्धांत का उल्लेख किया गया और कहा गया कि लोकतंत्र संविधान की बुनियादी विशेषताओं का हिस्सा है। वे कहेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारी राजनीति द्वारा अपनाए गए लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित एक अवधारणा थी।

आग्रह किए गए इन प्रारंभिक प्रस्तावों के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है

याचिकाकर्ताओं की ओर से।

इस न्यायालय द्वारा बार–बार यह अधिकृत रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि

लोकतंत्र भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, जो नहीं है संविधान के तहत संसद के संशोधन की शक्ति के लिए उत्तरदायी। यह भी इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि लोकतंत्र की इमारत

इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था है। ये सिद्धांत न केवल प्रस्तावना से, जिसे हमेशा संविधान का हिस्सा माना जाता रहा है, बल्कि इसके विभिन्न प्रावधानों से भी स्पष्ट होते हैं। यदि किसी के मन में अभी भी कोई संदेह छिपा हुआ है, तो निम्नलिखित मामलों को भेजा जा सकता है

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

इस संदर्भ में, लाभ के साथ।

केशवानंद भारती में सीजे सीकरी के विचार पैराग्राफ में व्यक्त किए गए हैं।

292 , विशेष रूप से, याचिका के संदर्भ में पहले देखा गया है

संघवाद। उन्होंने स्पष्ट रूप से "रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक रूप का उल्लेख किया है।

सरकार "मूल संरचना का गठन करने वाली विशेषताओं में से एक के रूप में

संविधान।

इसी मामले में, शेलट और ग्रोवर जे. जे. ने भी अपने अलग फैसले में,

सरकार और संप्रभुता का रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक रूप पाया गया

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, पूरी योजना से स्पष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 368 सहित इसके प्रासंगिक प्रावधान।

हेगड़े और मुखर्जी जे. जे. ने अपने फैसले में कहा कि

संविधान के विभिन्न अन्य भागों में फैले संविधान के तत्वों और मौलिक विशेषताओं को भी प्रावधानों में निर्धारित किया गया है।

देश की संप्रभुता से संबंधित, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक संविधान का चरित्र "।

जे. जगमोहन रेड्डी के शब्दों में, अपने अलग फैसले में,

" मूल संरचना के तत्वों को प्रस्तावना में दर्शाया गया है और उनका अनुवाद किया गया है।

संविधान के विभिन्न प्रावधानों में "और" हमारे संविधान की इमारत कई आधारों पर बनी हुई है और खड़ी है ", जिन्हें यदि हटा दिया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप संविधान ध्वस्त हो जाएगा और जिसमें सिद्धांत शामिल हैं।

'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' और 'संसदीय लोकतंत्र', एक ऐसी राजनीति जो "एक प्रतिनिधि प्रणाली पर आधारित है जिसमें लोग विरोध करते हैं एक–दूसरे को देखने वाले उम्मीदवार हो सकते हैं और मतदाताओं को उन्हें वोट देने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

इस न्यायालय के विचार, जैसा कि निर्णय के अनुच्छेद 264 में व्यक्त किया गया है।

इंदिरा नेहरू गाँधी को इस फैसले के पहले भाग में निकाला गया है। यहां यह फिर से ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि केशवानंद भारती (उपरोक्त) में बहुमत द्वारा निर्धारित कानून पर ध्यान दिया गया था और इस सवाल पर कि "संविधान की बुनियादी संरचनाएं क्या हैं", यह पाया गया कि इसमें "संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार शामिल है"।

इंदिरा में फैसले के पैराग्राफ 198 में निम्नलिखित टिप्पणियां

नेहरू गांधी (उपरोक्त) पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे इस सिद्धांत के संदर्भ में प्रासंगिक हैं कि 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' लोकतंत्र के मूल में निहित हैंः

– सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

" 198. केशवानंद भारती के मामले में इस न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया

कि अनुच्छेद में निहित संविधान के संशोधन की शक्ति

368 संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है।

बहुमत का गठन करने वाले सभी सात न्यायाधीश भी सहमत थे।

कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मूल संरचना का हिस्सा थी

चुनाव, ताकि लोग या तो पुराने को फिर से चुनने की स्थिति में हों प्रतिनिधि या, यदि वे चाहें। प्रतिनिधियों को बदलना

और उनके स्थान पर अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव करें। लोकतंत्र आगे बढ़ेगा

मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देने की स्थिति में हो सकते हैं। लोकतंत्र वास्तव में केवल इस विश्वास पर काम कर सकता है कि चुनाव हैं।

स्वतंत्र और निष्पक्ष और धांधली और हेरफेर नहीं, कि वे प्रभावी हैं

वास्तविकता और रूप दोनों में लोकप्रिय इच्छा का निर्धारण करने के उपकरण औरकेवल रक्षा का भ्रम पैदा करने के लिए गणना किए गए अनुष्ठान नहीं हैं

जनमत। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार और

उनके एजेंटों को अनुचित साधनों या कदाचार का सहारा नहीं लेना चाहिए

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालना।

(जोर दिया गया)

मोहिंदर सिंह गिल बनाम। मुख्य चुनाव आयुक्त, [1978] 1 एस. सी. सी.

एक अन्य मामला जो वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ 2 में,

कम करने वाले शब्दों ने प्रस्तावना में विवाद का संकेत दियाः

" 2. प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले में एक अलिखित किंवदंती और अमिट सबक है। यह अपील कोई अपवाद नहीं है, चाहे इसका औपचारिक परिणाम कुछ भी हो। संदेश है,

जैसा कि हम निर्णय के अंत में देखेंगे, व्यापक से संबंधित है

लोकतांत्रिक चुनावों का दर्शन जो सर विंस्टन चर्चिल ने किया थाबेजोड़ शब्दों में जीवंतः

" लोकतंत्र को दी जाने वाली सभी श्रद्धांजलि में सबसे नीचे छोटा आदमी है,

चर्चा संभवतः अत्यधिक महत्व को कम कर सकती हैबिन्दु से "।

अगर हम जोड़ सकते हैं, तो छोटे, बड़े भारतीय का अपहरण नहीं किया जाएगा

"थोड़े, संक्षिप्त अधिकार के कपड़े पहने" पुरुषों द्वारा विवेक की विकृति। क्योंकि "चाहे आप कभी भी इतने ऊँचे हों, कानून आपके ऊपर है"। कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

127

न्यायालय ने पैराग्राफ 23 में चुनाव के दर्शन के बारे में बात की

ऑक्रेसी, जो नीचे लिखा हैः –

" लोकतंत्र लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है। यह एक निरंतर सहभागी है।

ऑपरेशन, एक विनाशकारी, आवधिक अभ्यास नहीं। उस छोटे से आदमी में

भीड़, मतदान में अपने वोट को चिह्नित करते हुए उसकी सामाजिक लेखा परीक्षा करती है

संसद और इस प्रॉक्सी का राजनीतिक विकल्प। हालांकि पूरा फूल

भाग लेने वाली सरकार शायद ही कभी खिलती है, न्यूनतम साख

लोक सरकार प्रत्येक कार्यकाल के बाद लोगों से अपील करती है कि

आत्मविश्वास का नवीकरण। इसलिए हमारे पास वयस्क मताधिकार और सामान्य अधिकार हैं।

संवैधानिक मजबूरियों के रूप में चुनाव "। चुनाव का अधिकार है संविधान का बहुत सार "(जूनियस)। इसे थोड़ा तर्क की आवश्यकता है

मान लीजिए कि संसदीय प्रणाली का दिल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है

समय–समय पर आयोजित, वयस्क मताधिकार के आधार पर, हालांकि सामाजिक और

आर्थिक लोकतंत्र बहुत अधिक मांग कर सकता है।

(जोर दिया गया)

कुछ महत्वपूर्ण स्वामित्व अनुच्छेद 92 में निर्धारित किए गए थे

उल्लिखित निर्णय "सुविधा के लिए" और "सारांशित करने के लिए लेशन्स "। होल्डिंग्स में निम्नलिखित शामिल थेः –

" ..... (2) (क) संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर विचार करता है और

पर्यवेक्षण, निर्देशन और संचालन की व्यापक जिम्मेदारियां निहित करती है। निर्वाचन आयोग में निर्वाचनों के संचालन का नियंत्रण। यह

उत्तरदायित्व में कई प्रकार की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य शामिल हो सकते हैं,प्रशासनिक या अन्य, परिस्थितियों के आधार पर।

(ख) इसके पूर्ण स्वरूप पर कम से कम दो सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

उसका अभ्यास करें। सबसे पहले, जब संसद या कोई राज्य विधानमंडलचुनावों से संबंधित या उनके संबंध में वैध कानून बनाया है,

आयोग, अनुरूपता में कार्य करेगा, न कि इस तरह के उल्लंघन में

प्रावधान लेकिन जहां ऐसा कानून मौन है अनुच्छेद 324 का एक भंडार है

घोषित उद्देश्य के लिए कार्य करने की शक्ति, तलाकशुदा नहीं, धक्का देना

अभियान के साथ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को आगे बढ़ाएँ। दूसरा,

आयोग कानून के शासन के प्रति उत्तरदायी होगा और ईमानदारी से कार्य करेगा। प्राकृतिक न्याय के मानदंडों के अनुरूप होना

इस तरह के नियमों के लिए उचित और यथार्थवादी रूप से इसकी आवश्यकता हो सकती हैसंवैधानिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में निष्पक्ष कार्रवाई

अर्थात्। चुनाव। निष्पक्षता यह देखने के लिए एक दायित्व का आयात करती है कि नहीं गलत करने वाले उम्मीदवार को अपनी गलती से लाभ होता है। मामले को 128 रखने के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

सन्देह से परे, प्राकृतिक न्याय विशिष्ट मामले में सक्रिय और लागू होता है

पूर्ण पुनः मतदान के लिए क्रम, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं लेकिन लचीले रूप में

व्यावहारिकता। क्या इसका अनुपालन किया गया है, इसके लिए खुला छोड़ दिया गया है

न्यायाधिकरण का निर्णय "।

(जोर दिया गया)

मामला एस. रघबीर सिंह गिल बनाम के रूप में दर्ज किया गया। एस. गुरचरण सिंह

टोहरा, [1980] सप। एस. सी. सी. 53 हाथ में उद्देश्यों के लिए भी प्रासंगिक है। जबकि

आर. पी. अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए: –

" ..... संविधान की मूल विशेषता को प्रभावी बनाने के लिए एक अधिनियम

संविधान की प्रस्तावना में संक्षिप्त और साहसपूर्वक घोषणा की गई

लोकतांत्रिक गणराज्य की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो इसे हासिल करने में मदद करेसंवैधानिक लक्ष्य। संवैधानिक क्षितिज पर लक्ष्य है

लोकतांत्रिक गणराज्य, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, एक फव्वारा वसंत और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र की आधारशिला है

देश में लोकतांत्रिक संस्था की स्थापना के लिए प्रदान किया गया हैअधिनियम "।

(जोर दिया गया)

मामला किहोतो होलोहन बनाम के रूप में दर्ज किया गया। ज़चिल्लू और ओआरएस। , [1992]

पूरक 2 एस. सी. सी. 651 के परिणामस्वरूप भी इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में इसी तरह के विचारों को दोहराया गया: –

और कानून का शासन, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसकी बुनियादी विशेषताएं हैं। लोकतंत्र। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के अभिधारणाओं में से एक प्रावधान है

चुनाव विवादों के समाधान के साथ–साथ विवादों के निर्णय के लिए भीएक स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा बाद की अयोग्यताओं से संबंधित।

(जोर दिया गया)

कि संसदीय लोकतंत्र की मूल संरचना का हिस्सा है

पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा संविधान को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया थाः

" जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कुलदिप नायर बनाम के तहत प्रदत्त प्रतिरक्षा का उद्देश्य।

यू. ओ. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

129

विधायक। स्वस्थ कार्यप्रणाली के लिए ऐसी स्वतंत्रता आवश्यक है। संविधान में अपनाई गई संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली।

संसदीय लोकतंत्र की मूल संरचना का एक हिस्सा है

संविधान "।

भारत संघ बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक

आरएमएस और ए. एन. आर. , [2002] 5 एस. सी. सी. 294, इस न्यायालय ने निम्नानुसार दोहरायाः –

" 21. इसके अलावा, यह कहा जाना चाहिए किः ((a) मूल संरचनाओं में से एक

हमारा संविधान "सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक रूप" है; (ख) लोक सभा और विधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, अर्थात, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है। ऐसी तिथि जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस निमित्त नियत की जाए और संविधान या किसी विधि के अधीन गैर–निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध व्यवहार के आधार पर अन्यथा अयोग्य न ठहराया जाए,

ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार (अनुच्छेद 326); (ग) किसी भी संपत्ति (अचल या चल) या किसी भी शैक्षणिक योग्यता को धारण करना चुनाव लड़ने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है; और (घ) अनुच्छेद 324 के तहत, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए "सभी चुनावों के संचालन" का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। "चुनाव का संचालन" वाक्यांश को व्यापक आयाम का माना जाता है जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान करने की शक्ति शामिल होगी।

(जोर दिया गया)

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) में, इस न्यायालय ने कहा कि "यह

यह अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र वयस्क मताधिकार पर आधारित है

संविधान की मूल संरचना की कला "।

इस प्रकार इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि लोकतंत्र एक बुनियादी बात है।

भारत के संविधान की धारा और लोकतंत्र के लोकतांत्रिक रूप की अवधारणा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर निर्भर करती है।

यह रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है

मतदाता का संस्थागत अधिकार, जिसमें यह अधिकार शामिल है कि एक मतदाता

अपनी पसंद, स्वतंत्र इच्छा और बिना किसी डर के वोट डालने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] का समर्थन करें।

5 एस सी आर।

130

प्राप्त जानकारी के आधार पर। पसंद या किसी भी डर का खुलासा या

मजबूरी या व्हिप के तहत राजनीतिक दबाव भी अवधारणा के खिलाफ जाता है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और इस तरह के डर या मजबूरी से प्रतिरक्षा केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब चुनाव "गुप्त मतदान" के सिद्धांत पर आयोजित किया जाना हो। इन प्रस्तुतियों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

मतदान का अधिकार–एक संवैधानिक/मौलिक अधिकार विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चुनाव में मतदान करने का अधिकार है

भारत के संविधान के तहत, जिसमें अनुच्छेद 80 (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव शामिल है, एक मौलिक अधिकार नहीं तो एक संवैधानिक अधिकार है।

संघ पर याचिकाकर्ताओं द्वारा रिलायंस को इस संदर्भ में रखा गया है

भारत का वी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड एन. आर. (उपर्युक्त) जिसमें यह न्यायालय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानने के मतदाता के अधिकार पर विचार कर रहा था। यह पता चलने के बाद कि ऐसा अधिकार मौजूद था, पैराग्राफ 22 में यह निम्नानुसार देखा गया थाः

" ..... लोकतंत्र में, समय–समय पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं

देश के लिए और नागरिकों के लाभ के लिए कुशल शासन

मतदाता। सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, मतदाता सबसे अधिक होते हैं

महत्व। उन्हें इसके आधार पर चुनने या फिर से चुनने का अधिकार है – उम्मीदवार का पूर्ववृत्त और पिछला प्रदर्शन। मतदाता ने

उनका प्रतिनिधि बनें। मतदाता को तय करना है कि उसे मतदान करना चाहिए या नहीं।एक उम्मीदवार के पक्ष में जो एक आपराधिक मामले में शामिल है। के लिए

चुनाव की शुद्धता और एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखते हुए, मतदाता हैं

प्रतियोगिता के बारे में शिक्षित और अच्छी तरह से सूचित होना आवश्यक हैउम्मीदवार "।

(जोर दिया गया)

फैसले के पैराग्राफ 46 में, कानूनी और संवैधानिक स्थिति

चर्चा का सारांश इस प्रकार दिया गयाः

(4

4. चुनावों की शुद्धता बनाए रखने और विशेष रूप से लाने के लिए

चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता, आयोग कुलदिप नायर बनाम से पूछ सकता है।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

131

राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च और चुनाव की प्रक्रिया में इस पारदर्शिता के बारे में उम्मीदवारों में चुनाव या पुनः चुनाव चाहने वाले उम्मीदवार की पारदर्शिता शामिल होगी। लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की एक रणनीतिक भूमिका होती है। इस देश के छोटे आदमी को एक उम्मीदवार का पूरा विवरण जानने का बुनियादी प्राथमिक अधिकार होगा जो संसद में उसका प्रतिनिधित्व करेगा जहां उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति को बांधने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं।

5. लोकतंत्र में सूचना प्राप्त करने के अधिकार को पूरे समय मान्यता प्राप्त है और यह लोकतंत्र की अवधारणा से बहने वाला एक स्वाभाविक अधिकार है। इस स्तर पर, हम नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 19 (1) और (2) का उल्लेख करेंगे, जो इस प्रकार है – इसके अंतर्गतः

" (1) हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार होगा। हस्तक्षेप।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा;

लेखन या मुद्रण में, कला के रूप में, या किसी अन्य माध्यम के माध्यम सेअपनी पसंद से "।

7. हमारे संविधान के तहत, अनुच्छेद 19 (1) (ए) स्वतंत्रता प्रदान करता है भाषण और अभिव्यक्ति। चुनाव के मामले में मतदाता का भाषण या अभिव्यक्ति

इसमें वोट डालना शामिल होगा, अर्थात, मतदाता बोलता है यावोट देकर व्यक्त करें। इस उद्देश्य के लिए, जानकारी

चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवार के आपराधिक अतीत सहित पूर्ववृत्त को जानने के लिए एम. पी. या एम. एल. ए. के लिए चुनाव बहुत अधिक मौलिक और बुनियादी है

लोकतंत्र का अस्तित्व। छोटा आदमी बनाने से पहले सोच सकता है

कानून निर्माताओं के रूप में कानून तोड़ने वालों को चुनने की उनकी पसंद।

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने इस प्रकार उपरोक्त मामले में निर्णय दिया कि एक उचित प्रकटीकरण

एक लोकतांत्रिक समाज में एक चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा पूर्ववर्ती हो सकता है

सी. ई. बुद्धिमानी से मतदाताओं द्वारा अपने निर्णय लेते समय किए गए निर्णय

गलत जानकार और गैर–जानकार मतदाता द्वारा वोट डालना, या

केवल एकतरफा जानकारी देना लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए बाध्य है 132

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

गंभीरता से। इसलिए, इस न्यायालय ने प्रत्येक उम्मीदवार की जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बारे में कुछ निर्देश दिए। ज्योति बसु (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचार पहले ही निकाले जा चुके हैं। यह फिर से ध्यान दिया जा सकता है कि उस मामले में इस न्यायालय ने पाया था कि

" चुनने का अधिकार, हालांकि यह लोकतंत्र के लिए मौलिक है, विसंगत रूप से पर्याप्त है, न तो एक मौलिक अधिकार है और न ही एक सामान्य कानून अधिकार है। यह शुद्ध और सरल, एक वैधानिक अधिकार है "और यह कि" कानून के बाहर, चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं है, निर्वाचित होने का कोई अधिकार नहीं है और चुनाव पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है "।

कानून में कुछ संशोधन लाए गए थे

भारत संघ बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। एसोसिएशन। लोकतांत्रिक सुधारों के लिए (ऊपर)। यह न्यायालय इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या संशोधन

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) में कानूनी थे।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में उपरोक्त विचार ज्योति बसु के हैं।

यह जोड़ा जा सकता है कि यही विचार राम कांत पांडे बनाम में भी दोहराए गए थे। भारत संघ, [1993] 2 एस. सी. सी. 438, जिसमें यह कहा गया था, "चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में मतदान करने या खड़े होने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही नागरिक अधिकार है।"

फैसले के पैराग्राफ 62 में शाह, जे. की निम्नलिखित टिप्पणियां

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) (ऊपर) में, ध्यान में रखने की आवश्यकता हैः

" ..... ऐसा मतदाता जो अन्यथा अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान करने का पात्र है, उसे अधिनियम के तहत मतदाता होने का वैधानिक अधिकार है और

यह भी एक मौलिक अधिकार है जैसा कि अध्याय III में निहित है। यदि कोई वैधानिक

प्रावधान मौलिक अधिकार का हनन करता है, कि वैधानिक प्रावधानशून्य हो जाओ। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वयस्क का अधिकार

एक मतदाता या उम्मीदवार के रूप में एक वैध कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है जो यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

इसी मामले में, पी. वी. रेड्डी जे. ने अपने अलग फैसले में पैराग्राफ 94 में कहाः –

..... एक लोकतांत्रिक गणराज्य में, यह लोगों की इच्छा है कि

सर्वोपरि और सरकार के अधिकार का आधार बन जाता है।

गुप्त मतदान के माध्यम से आयोजित मताधिकार। इसलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक राजनीति के निर्वाह के लिए कुलदिप नायर बनाम को मतदाता बनाने की तुलना में महत्वपूर्ण है।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. आई.]

133

अपने प्रतिनिधि का एक बुद्धिमान और तर्कसंगत चयन। इसके लिए,

मतदाता को प्रभावी ढंग से तैयार करने की स्थिति में होना चाहिए।

राय देना और अंततः मतदान के माध्यम से उस राय को व्यक्त करना

वोट देते हैं। मतदान के अधिकार का सहवर्ती जो मूल है

इस प्रकार लोकतंत्र का अभिधारणा दो गुना हैः सबसे पहले, राय तैयार करना।

उम्मीदवारों के बारे में और दूसरा, कास्टिंग द्वारा पसंद की अभिव्यक्ति

मतदान केंद्र पर पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान। द.

मतदाता/नागरिक के पास कम से कम इसके बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए

लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। इस प्रकार, उचित की उपलब्धता औरउम्मीदवार के बारे में प्रासंगिक जानकारी को बढ़ावा देती है और

दोनों के दृष्टिकोण से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

जानकारी देना और प्राप्त करना। मैं कहूंगा कि ऐसे जानकारी निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता के लिए अनुकूल होगी।

और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। जानकारी का खुलासा होगा

दोनों बिंदु से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाना और बढ़ाना। मतदाता के साथ-साथ मीडिया का दृष्टिकोण जिसके माध्यम से जानकारी दी जाती है

इसे प्रचारित किया जाता है और खुले तौर पर बहस की जाती है।

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 95 में, उन्होंने निम्नानुसार अवलोकन कियाः – " .

..... जैसा कि इस न्यायालय ने एसोसिएशन में कहा है। लोकतांत्रिक सुधार मामले के लिए

एक मतदाता "मतदान करके बोलता है या व्यक्त करता है"। स्वतंत्रता

अभिव्यक्ति, जैसा कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा विचार किया गया है जो कई मामलों में

ओवरलैप करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ मेल खाता है, कई गुना हैअर्थ। इसे अभिव्यक्ति तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही होना चाहिए।

मौखिक या लिखित रूप में कुछ। द्वारा प्रकट होने का कार्य

क्रिया या भाषा का अर्थ रामनाथ अय्यर के ग्रंथ में दिया गया है।

लॉ लेक्सिकन (न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ द्वारा संपादित)। ध्यान रखें।

वाक्यांश "अभिव्यक्ति" के व्यापक अर्थ के लिए, मतदान कर सकते हैं वैध रूप से अभिव्यक्ति का एक रूप माना जाए। मतपत्र है

उपकरण जिसके द्वारा मतदाता उम्मीदवारों के बीच अपनी पसंद व्यक्त करता है या प्रस्तावों के संबंध में, और उसका "वोट" उसकी पसंद या चुनाव है,

जैसा कि उनके मतपत्र द्वारा व्यक्त किया गया है (ए डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न लीगल यूसेज के माध्यम से,

2 एन. डी. ई. एन. , ए. गार्नर ब्रायन द्वारा) "। व्यक्त की गई राय, संकल्प या

मतदान द्वारा लिया गया निर्णय "को दिए गए अर्थों में से एक है न्यू ऑक्सफोर्ड इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी में अभिव्यक्ति "वोट"।

यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] का अच्छा समर्थन है। 5 एस सी आर।

यह तय हो गया और इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार

और अच्छी तरह से स्थापित। मैं केवल दोहराता हूँ और कहता हूँ कि स्वतंत्रता उम्मीदवार के लिए वरीयता व्यक्त करके मतदान करना स्वतंत्रता के अलावा और कुछ नहीं है

प्रमुख चिंता के मामले के संबंध में खुद को व्यक्त करने के लिएदेश और स्वयं मतदाता "।

(जोर दिया गया)

ज्योति बसु बनाम में व्यक्त विचार का उल्लेख करने के बाद। देवी घोषाल) कि चुनने का अधिकार "न तो एक मौलिक अधिकार है और न ही एक सामान्य अधिकार" बल्कि "शुद्ध और सरल, एक वैधानिक अधिकार" है, पैराग्राफ 97 में जे. रेड्डी

निर्णय को आगे निम्नानुसार देखा गयाः

" ..... प्रतिष्ठित न्यायाधीशों के प्रति बहुत सम्मान के साथ, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा

कि मतदान का अधिकार, यदि मौलिक अधिकार नहीं है, तो निश्चित रूप से एक

संवैधानिक अधिकार। अधिकार संविधान से उत्पन्न होता है और

अनुच्छेद 326 में निहित संवैधानिक जनादेश के अनुसार, अधिकार को क़ानून, अर्थात् आर. पी. अधिनियम द्वारा आकार दिया गया है। कि, में

वैधानिक अधिकार, शुद्ध और सरल। इस स्पष्टीकरण के बावजूद, विद्वान महान्यायवादी का तर्क कि मतदान का अधिकार नहीं है

एक मौलिक अधिकार होने के नाते, वह जानकारी जो सबसे अच्छी सुविधा प्रदान करती है

उस अधिकार के सार्थक प्रयोग को एक अभिन्न अंग के रूप में नहीं देखा जा सकता है

किसी भी मौलिक अधिकार को पूरी तरह से पूरा किया जाना बाकी है। यहाँ, एक अंतर हैमतदान का अधिकार प्रदान करने के बीच खींचा जाना है

अपेक्षित मानदंडों की पूर्ति और उस अधिकार की पराकाष्ठा

किसी विशेष उम्मीदवार के प्रति अपनी पसंद व्यक्त करने का अंतिम कार्य

मतदान से। हालांकि प्रारंभिक अधिकार को पीठ पर नहीं रखा जा सकता है।

मौलिक अधिकार का, लेकिन, उस स्तर पर जब मतदाता के पास जाता है

मतदान केंद्र और अपना वोट डालते हैं, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पैदा होती है। द.

एक या दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना

अपनी राय और वरीयता की अभिव्यक्ति और उस अंतिम चरण में

मतदान के अधिकार का प्रयोग स्वतंत्रता की उपलब्धि का प्रतीक है

मतदाता की अभिव्यक्ति। यही वह जगह है जहाँ अनुच्छेद 19 (1) (ए) आकर्षित होता है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

135

मतदान की स्वतंत्रता इस प्रकार मतदान के अधिकार से अलग एक प्रजाति है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसलिए इसके साथ सहायक और

जानकारी सुरक्षित करने के अधिकार जैसे पूरक अधिकार

उम्मीदवार जो स्वतंत्रता के लिए अनुकूल हैं "।

(जोर दिया गया)

धर्माधिकारी, जे. ने अपने अलग फैसले में शाह, जे. से सहमति व्यक्त की।

इस प्रकार देखा गयाः –

" 129. "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों" पर आधारित लोकतंत्र को माना जाता है

केशवानंद भारती के मामले में संविधान की एक बुनियादी विशेषता।सुधार के लिए कानून में रिक्तता को भरने के लिए पर्याप्त विधायी इच्छाशक्ति का अभाव

इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुसार चुनाव प्रक्रिया एस. एन. के मामले में। लोकतांत्रिक सुधारों के लिए इस न्यायालय को बाध्य करता है

संवैधानिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग "।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मामले में बहुमत का विचार है

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसलिए, यह था कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसके अलावा यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार का एक पहलू भी है।

हम उपरोक्त निवेदन से सहमत नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि एक जुर्माना

मतदान के अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता के बीच अंतर किया गया था

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक प्रजाति, ज्योति बसु बनाम में विचार को दोहराते हुए। देवी घोषाल (ऊपर) कहते हैं कि चुनाव करने का अधिकार, भले ही यह लोकतंत्र के लिए मौलिक हो, न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानून का अधिकार, बल्कि शुद्ध और सरल, एक वैधानिक अधिकार है।

अन्यथा भी, यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि मतदान का अधिकार और

राज्य परिषद में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 80 (4) केवल चुनाव के तरीके से संबंधित है राज्य परिषद की संरचना के एक पहलू के रूप में राज्य परिषद में प्रतिनिधि। घोषणा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों में कुछ भी नहीं है

संविधान के तहत एक पूर्ण अधिकार के रूप में ऐसे चुनाव में मतदान करने का अधिकार।

विधायी विशेषाधिकारों और दसवीं अनुसूची पर आधारित तर्क

जो भी हो, विवादास्पद विवाद जो द्वारा उठाया गया है

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान संविधान में किया गया है और इसलिए यह संविधान का एक हिस्सा है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत की अंतर्निहित आवश्यकता है कि –

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

वोट देने का अधिकार हमेशा वोट की गोपनीयता के अधिकार के साथ होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वोट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तविक है।

विधायी विशेषाधिकारों और दसवीं अनुसूची पर आधारित तर्क

श्री राव का तर्क है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अलावा, विधानसभा के सदस्य को मतदान की स्वतंत्रता की संवैधानिक रूप से गारंटी है।

अनुच्छेद 194 (1) और (2) द्वारा पूर्ण रूप से। जबकि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है जो अनुच्छेद 19 (2) के तहत कानून द्वारा लगाए जा सकते हैं, अनुच्छेद 194 (1) और (2) के तहत मतदान करने की स्वतंत्रता निरपेक्ष है। वह 1964 [1965] 1 एस. सी. आर. 413 के विशेष संदर्भ संख्या 1 और तेज किरण जैन और अन्य का उल्लेख करेंगे। वी. एन. संजीव रेड्डी और अन्य। , [1971] 1 एससीआर 612।

अनुच्छेद 194 सदनों की शक्तियों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित है।

विधानमंडलों और उनके सदस्यों और समितियों का। यह अनुच्छेद 105 में निहित प्रावधानों के समान है जो "संसद के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों आदि" से संबंधित है। विचाराधीन प्रावधानों पर एक नज़र डालना उचित होगा।

अनुच्छेद 105 और 194 इस प्रकार हैंः

" 105. संसद के सदनों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, आदि

(1) प्रावधानों के अधीन रहते हुए इसके सदस्य और समितियाँ

इस संविधान और विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के लिए

संसद की प्रक्रिया में बोलने की स्वतंत्रता होगी। संसद।

(2) संसद का कोई भी सदस्य किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी न्यायालय द्वारा कही गई किसी भी बात या उसके द्वारा दिए गए किसी भी मत के संबंध में

संसद या उसकी कोई समिति, और कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रकाशन के संबंध में ऐसा उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही की संसद।

(3) अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो समय–समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जा सकें, और जब तक इस तरह परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक वे उस सदन और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होंगी। लागू होने से तुरंत पहले सदस्य और समितियाँ

संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम की धारा 15,

1978 .

137

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

(4) खंड (1), (2) और (3) के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे।जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर बोलने का अधिकार है

किसी सदन की कार्यवाही में भाग लेना और अन्यथा संसद या उसकी कोई समिति जो उनके संबंध में लागू होती है –

इस संविधान और विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के लिए विधान–मंडल की प्रक्रिया में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

प्रत्येक राज्य का विधानमंडल।

किसी भी अदालत में किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में कार्यवाहीउसके द्वारा विधानमंडल या उसकी किसी समिति में, और कोई व्यक्ति नहीं

प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन प्रकाशन के संबंध में इतना उत्तरदायी होगा

ऐसे विधानमंडल के किसी सदन की किसी रिपोर्ट, कागज, मतों या

कार्यवाही।

(3) अन्य मामलों में, एक की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

परिभाषित, उस सदन और उसके सदस्यों के होंगे औरधारा 26 के लागू होने से तुरंत पहले समितियाँ

संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978)। (4) खंड (1), (2) और (3) के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे।

जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर बोलने का अधिकार है

किसी राज्य का विधानमंडल या उसकी कोई समिति, जिसमें वे लागू होते हैं, उस विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में।

1964 [1965] 1 एस. सी. आर. 413 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में, यह न्यायालय

अनुच्छेद 194 में निहित प्रावधानों की जांच की। ये मुद्दे उच्च न्यायालय और राज्य विधानमंडल के बीच संवैधानिक संबंधों से संबंधित थे। भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 (1) के तहत इसका संदर्भ दिया था।

उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा और उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में न्यायालय। मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है कि राज्य विधानसभा ने अपनी अवमानना के लिए एक व्यक्ति को जेल भेज दिया था। कैदी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. को प्राथमिकता दी थी।

5 एस सी आर।

138

याचिका दायर करके और जमानत देते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने राज्य विधानमंडल की अवमानना भी की थी और इस प्रकार उक्त उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ प्रक्रिया जारी की थी। इस न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 194 (1) यह स्पष्ट करता है कि "प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता जो वह निर्धारित करता है, इसके अधीन है –

संविधान के उपबंधों और विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के लिए और उक्त खंड की व्याख्या करते समय इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि संविधान के वे उपबंध जिनके अधीन रहते हुए बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है,

संविधान के सामान्य प्रावधान नहीं, बल्कि उनमें से केवल वही प्रावधान हैं जो विधानमंडल की प्रक्रिया के विनियमन से संबंधित हैं। इस दृष्टिकोण में, यह इस न्यायालय की राय थी कि जबकि अनुच्छेद 194 (1) "विधायी कक्ष के भीतर विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है", अनुच्छेद 194 (2) "यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता शाब्दिक रूप से पूर्ण और निरंकुश है"।

तेज किरण जैन बनाम। एन. संजीव रेड्डी (ऊपर), मुद्दा था

क्या संविधान के अनुच्छेद 105 (2) को ध्यान में रखते हुए संसद में जो कहा गया था, उसके संबंध में अदालत में कार्यवाही की जा सकती है। यह इस आरोप पर प्रतिवादियों के खिलाफ दायर किए गए हर्जाने के मुकदमे से उत्पन्न हुआ कि उन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में मानहानिकारक बयान दिए थे। उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव के खिलाफ फैसला सुनाया था। 1964 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में इस न्यायालय के एक अवलोकन के लिए अपील में संदर्भ दिया गया था, जहां संविधान के अनुच्छेद 212 के प्रावधानों से निपटने वाले इस न्यायालय ने बताया था कि उस अनुच्छेद के तहत प्रतिरक्षा की कथित अनियमितता के खिलाफ थी प्रक्रिया लेकिन एक अवैधता के खिलाफ नहीं, और तर्क दिया कि वही सिद्धांत यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि क्या जो कहा गया था वह कॉलिंग अटेंशन मोशन पर चर्चा के बाहर था। यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद 105 (2) द्वारा दी गई प्रतिरक्षा संसद के कार्य के लिए प्रासंगिक थी न कि किसी ऐसी चीज के लिए जो पूरी तरह से अप्रासंगिक थी।

अपीलार्थियों की दलीलों पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" हमारे निर्णय में लेख के प्रावधानों को पढ़ना संभव नहीं है।

सुझाए गए तरीके से। लेख का अर्थ वही है जो वह भाषा में कहता है।

जो इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। यह लेख अन्य बातों के साथ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। "संसद में कुछ भी कहा गया" के संबंध में। शब्द "कुछ भी" कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

139

यह सबसे व्यापक महत्व का है और "सब कुछ" के बराबर है। एकमात्र

सीमा "संसद में" शब्दों से उत्पन्न होती है जिसका अर्थ है

संसद की बैठक और कार्य के दौरान

संसद। हम केवल लोकसभा में भाषणों के बारे में चिंतित हैं।एक बार यह साबित हो गया कि संसद की बैठक चल रही थी और इसका काम था

लेन–देन किया जा रहा है, उस व्यवसाय के दौरान कुछ भी कहा गया था

किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से मुक्त यह प्रतिरक्षा केवल नहीं है

पूर्ण लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा ही है। यह संसद का सार है।

सरकार की प्रणाली जिसके लिए जन प्रतिनिधियों को स्वतंत्र होना चाहिए

कानूनी परिणामों के डर के बिना खुद को व्यक्त करें। वे क्या कहते हैं।

सदस्यों की भावना और अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही का नियंत्रण।इस मामले में अदालतों का कोई कहना नहीं है और वास्तव में उनका कोई कहना नहीं होना चाहिए।

(जोर दिया गया)

विद्वान वकील का यह तर्क है कि ऐसा ही होना चाहिए

राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 194 (2) में निहित प्रावधान के दायरे और अवधि के बारे में व्याख्या जो चुनाव के लिए राज्यवार निर्वाचक महाविद्यालयों का गठन करते हैं।

अनुच्छेद 80 (4) के प्रावधानों के तहत राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि। वकील का तर्क है कि अनुच्छेद 194 (2) से निकलने वाले कानूनी परिणामों के डर के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 80 (4) के तहत निर्वाचक मंडल के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करते समय विधान सभाओं के सदस्यों को मिलनी चाहिए।

यह तर्क, हालांकि आकर्षक है, इसमें किसी भी विश्वास के योग्य नहीं है

हाथ में संदर्भ। अनुच्छेद 80 के तहत चुनाव से संबंधित कार्यवाही अनुच्छेद 194 के अर्थ के भीतर "राज्य विधानमंडल के सदन" की कार्यवाही नहीं है। यह विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो प्रतिनिधि के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन, अनुच्छेद 80 के तहत

राज्य की परिषद में उस राज्य को आवंटित सीट को भरने के लिए। यह उल्लेखनीय है कि यह पूरी विधानसभा नहीं है जो निर्वाचक मंडल बन जाती है, बल्कि केवल सदस्यों की निर्दिष्ट श्रेणी होती है। जब ऐसे सदस्य किसी स्थान पर इकट्ठा होते हैं, तो वे संविधान के तहत विधानसभा को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। चुनाव में उनकी भागीदारी केवल मतदाताओं की उनकी पदेन क्षमता के कारण होती है। चुनाव। इस प्रकार, उनमें से प्रत्येक द्वारा वोट डालने का कार्य, जो उन सभी के साथ एक साथ या एक ही समय में उपस्थित होने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल मताधिकार का प्रयोग है, न कि विधायिका की कार्यवाही।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

140

यह दसवीं अनुसूची के आधार पर तर्कों को लेने का समय है।

संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया था (पचास)

दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1985,1 मार्च 1985 से प्रभावी। उद्देश्यों और कारणों में घोषित उक्त संशोधन का उद्देश्य मुकाबला करना था

"राजनीतिक दलबदल की बुराई" जो "राष्ट्रीय चिंता का विषय" रही है और जिसके खतरे में "राजनीतिक दलबदल को कमजोर करने" की शक्ति है।हमारे लोकतंत्र की नींव और इसे बनाए रखने वाले सिद्धांत "।

उक्त संशोधन में अनुच्छेद 102 में उप–अनुच्छेद (2) भी जोड़ा गया और

191 जो क्रमशः संसद के सदनों और राज्य विधानमंडल के सदनों की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से संबंधित था। का अनुच्छेद 1 (ए)

दसवीं अनुसूची "सदन" के लिए अपने आवेदन की भी पुष्टि करती है जिसका अर्थ "संसद का सदन या विधान सभा या,यथास्थिति, किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदन। नए उप–अनुच्छेदों ने समान शब्दों में घोषणा की कि "यदि कोई व्यक्ति दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसे उक्त सदनों में से किसी एक का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।" दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 को, यहाँ सामान्य रूप से, निम्नानुसार निकाला जा सकता हैः ––

" 2. दलबदल के आधार पर अयोग्यता। (1) विषय के अधीन पैराग्राफ 4 और 5 के प्रावधान, से संबंधित सदन का सदस्य

किसी भी राजनीतिक दल को सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगाघर।

(क) XXXXXXX; या ((ख) यदि वह उस राजनीतिक दल, जिससे वह संबंधित है, या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से अनुपस्थित रहता है,

किसी भी मामले में, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त करना और इस तरह के मतदान या अनुपस्थितिऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा माफ कर दिया गया

इस तरह के मतदान या अनुपस्थिति की तारीख से पंद्रह दिन।

स्पष्टीकरण। इस उप–अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए

(क) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य उस राजनीतिक दल, यदि कोई हो, का सदस्य समझा जाएगा, जिसके द्वारा उसे उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया गया था।

ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव;

(ख) किसी सदन का नामित सदस्य 141 होगा।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

((i) जहां वह अपनी तिथि पर किसी राजनीतिक दल का सदस्य है।

ऐसे सदस्य के रूप में नामांकन, ऐसे राजनीतिक से संबंधित माना जाएगा पार्टी;

((ii) किसी अन्य मामले में, राजनीतिक दल से संबंधित माना जाएगा।

जिसमें से वह पहले सदस्य बन जाता है या, जैसा भी मामला हो, बन जाता है।

छह महीने की समाप्ति से पहले जिस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करता है।

मामला अनुच्छेद 188 का हो सकता है। XXXXXXX "

यह याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि तथ्य यह है कि चुनाव को भरने के लिए

राज्य की विधान सभा द्वारा राज्य परिषद में सीटों में 'मतदान' शामिल है, दसवीं अनुसूची के सिद्धांत आकर्षित होते हैं। उनका तर्क है कि दसवीं अनुसूची के लागू होने से ही पता चलता है कि खुली मतपत्र प्रणाली में रुझान हैसंविधान और आर. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अलावा पूरी चुनाव प्रक्रिया के साथ-साथ इसकी पवित्रता को भी विफल करने के लिए। उनका कहना है कि खुली मतपत्र प्रणाली, दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के खतरे के साथ मिलकर एक राजनीतिक दल को व्हिप जारी करने और उम्मीदवार को शक्ति प्रदर्शन द्वारा चुने जाने के लिए चुनाव को कम कर देती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप मनीबैग वाले लोग राज्य परिषद में सीटों पर कब्जा कर लेंगे।

याचिकाओं का विरोध करने वाले उत्तरदाता दूसरी ओर तर्क देंगे

कि दसवीं अनुसूची राज्य परिषद में चुनाव पर लागू नहीं होती है। इसका अनुप्रयोग विधानमंडल की कार्यवाही तक ही सीमित है और इसका आर. पी. अधिनियम के तहत आयोजित चुनाव पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। फिर भी, विद्वान वकील तर्क देंगे, बनाने के पीछे के सिद्धांत खुली मतपत्र द्वारा चुनाव दसवीं अनुसूची में संवैधानिक प्रावधानों को आगे बढ़ाते हैं।

यह ध्यान में रखना होगा कि पार्टी प्रणाली में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है

भारतीय संदर्भ। आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए से 29-सी राजनीतिक दलों के पंजीकरण और उनके कुछ विशेषाधिकारों और दायित्वों की बात करती है।

एस. आर. बोम्मई में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

हमारे संवैधानिक कानून के पहलू को हमने बहुलवादी तरीके से अपनाया है।लोकतंत्र। इसका अर्थ है, अन्य बातों के अलावा, एक बहुदलीय प्रणाली।

संघवाद की प्रकृति जो भी हो, तथ्य यह है कि जैसा कि कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी.

5 एस सी आर।

ऊपर, संविधान के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य है

घटक राजनीतिक इकाई और एक विशेष कार्यकारी होना चाहिए और

संघ के रूप में एक ही प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित और गठित विधानमंडल

सरकार। हमारी राजनीतिक और चुनावी प्रणाली के तहत, राजनीतिक दल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर या विशेष रूप से राज्य में काम कर सकते हैं।

स्तर। विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दल हो सकते हैं और

राष्ट्रीय स्तर पर। नतीजतन, परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि वास्तव में

उनके पास है, जब विभिन्न राज्यों में सत्ता में राजनीतिक दल और

केंद्र में अलग हो सकता है। यह भी हो सकता है–जैसा कि हुआ है आज तक राजनीतिक सौदेबाजी, समायोजन और

समझते हुए, एक राज्य स्तर की पार्टी एक के उम्मीदवारों को चुनने के लिए सहमत हो सकती है

संसद में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और इसके विपरीत। का यह मोज़ेक

राजनीतिक जीवन का विविध स्वरूप संभावित रूप से एक बहुलवादी में निहित है।

हमारे जैसे बहु–दलीय लोकतंत्र। इसलिए राजनीतिक प्रलोभन

सत्ता में पार्टी या दल (गठबंधन सरकार में) को अस्थिर करने के लिए

या राज्य में सरकार को बर्खास्त कर दें जो एक ही राजनीतिक संगठन द्वारा नहीं चलाई जा रही है।

पार्टी या पार्टियाँ दुर्लभ नहीं हैं और वास्तव में काम करने का अनुभव

संविधान की स्थापना के बाद से अनुच्छेद 356 (1) से पता चलता है कि

राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया है और विधायी

अप्रासंगिक, आपत्तिजनक और अनुचित होने पर विधानसभाओं को भंग कर दिया गया

आधार। अब तक प्रावधान के तहत बिजली का उपयोग अधिक पर किया गया है।

90 से अधिक मौकों पर और लगभग सभी मामलों में सरकारों के खिलाफ विपक्ष में राजनीतिक दल। अगर बहुलवाद और बहुलवाद का ताना–बाना

लोकतंत्र और देश की एकता और अखंडता होनी चाहिए

संरक्षित, परिस्थितियों में न्यायपालिका एकमात्र संस्था है जोव्यवस्था और राष्ट्र के रक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

(जोर दिया गया)

केशवानंद में पृष्ठ 485–486 पर दिखाई देने वाली कुछ टिप्पणियाँ

¡ भी प्रासंगिक हैं और यहाँ नीचे निकाले गए हैंः –

" इसके अलावा हमारी तरह एक संसदीय लोकतंत्र आधार पर कार्य करता है

पार्टी प्रणाली। पार्टी प्रणाली के संचालन के तंत्र साथ ही कैबिनेट सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि लोग

विस्तृत कानून बनाने के मामले में समग्र रूप से बहुत कम नियंत्रण हो सकता है।

" ग. आधुनिक राज्य में व्यावहारिक रूप से हर मुद्दे पर, लाखों लोगों ने चिंता व्यक्त की

मतदाता प्रस्तावित समाधानों को स्वीकार या अस्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मात्रा के अच्छे रंगों की अनुमति देने के लिए मंच बहुत बड़ा है।

भेद जनता के दिमाग पर खुद को प्रभावित करते हैं।

इसमें शायद ही कभी कुलदिप नायर बनाम होता है। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

143

सूक्ष्म समायोजन किए जाने चाहिए। " (लास्कीः एक व्याकरणराजनीति, पाँचवाँ संस्करण। , पीपी। 313–314) . "

(जोर दिया गया)

संविधान की दसवीं अनुसूची के महत्व को मान्यता देती है –

परिषदें। दसवीं अनुसूची की वैधता को विभिन्न मुद्दों पर चुनौती दी गई थी अन्य बातों के साथ–साथ यह आधार कि एक राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक इकाई नहीं है और संसद सदस्यों पर चाबुक लगाना इसके अनुसार नहीं था –

संवैधानिक योजना। इस तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि संसद के लिए यह प्रावधान करने के लिए खुला है कि उसके सदस्य, जो चुने गए हैं

पार्टी के टिकट पर पार्टी द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्य करें, न कि उसके खिलाफ।

किहोतो होल्लोहन बनाम। ज़चिल्लू (ऊपर), यह माना गया था किः

" 43. संसदीय लोकतंत्र में इस बात की परिकल्पना की गई है कि इससे संबंधित मामले

सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा की जानी चाहिए

जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि। बहस, चर्चा और

इसलिए, अनुनय लोकतांत्रिक व्यवस्था का साधन और सार है।प्रक्रिया। बहस के दौरान सदस्यों ने विभिन्न बिंदुओं को सामने रखा

देखने के लिए। एक ही राजनीतिक दल के सदस्य भी हो सकते हैं किसी मामले पर मतभेद हैं और उन्हें व्यक्त कर सकते हैं।

इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त संशोधन, और यहां तक कि वापसी भी हुईविचाराधीन प्रस्ताव। विभिन्न विषयों पर बहस और अभिव्यक्ति

इस प्रकार, दृष्टिकोण एक आवश्यक और स्वस्थ उद्देश्य की पूर्ति करते हैं

संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली। कभी–कभी ऐसी अभिव्यक्ति

सदन में बहस के दौरान विचारों के कारण मतदान हो सकता है या

दलगत आधार के अलावा सदन में मतदान करने से परहेज करना।

इसकी अपनी राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक उपयोगिता इस तरह के साझा कार्यों पर निर्भर करती है।उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इसके सदस्यों की मान्यताओं और ठोस कार्रवाई

आम तौर पर माने जाने वाले सिद्धांत। इसके सदस्यों को मतदान करने की कोई भी स्वतंत्रतावे राजनीतिक दल की घोषित नीतियों से स्वतंत्र रूप से खुश हैं

यह न केवल अपनी सार्वजनिक छवि और लोकप्रियता को शर्मिंदा करेगा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. को भी शर्मिंदा करेगा।

5 एस सी आर।

इसमें जनता के विश्वास को कम करता है, जो अंतिम विश्लेषण में, इसके निर्वाह का स्रोत है–नहीं, वास्तव में, इसका अस्तित्व ही है। पार्टी के भीतर बहस निश्चित रूप से एक अलग बात है। लेकिन एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा अलग–अलग रुख की सार्वजनिक छवि पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

राजनीतिक परंपरा, चीजों की एक वांछनीय स्थिति के रूप में। संसद के कार्यों, अभ्यास और प्रक्रिया पर ग्रिफ़िथ और राइल (1989 संस्करण, पी। 119)

कहोः

" साझा मान्यताओं पर आधारित होने के कारण पार्टी के प्रति वफादारी आदर्श है। ए.

विभाजित पार्टी को मतदाता संदेह के साथ देखते हैं। यह है।

सदस्यों के लिए अपने नेताओं की राय स्वीकार करना स्वाभाविक है और

विभिन्न प्रकार के मामलों पर प्रवक्ता जिन पर वे सदस्य

इसलिए यह समझ में आता है कि एक सदस्य जो पार्टी को अस्वीकार करता हैएक अवसर पर भी चाबुक ध्यान आकर्षित करेगी और अधिक

सहानुभूति की तुलना में आलोचना। आवश्यकता पड़ने पर मतदान से दूर रहना

पार्टी द्वारा वोट देना कुछ हद तक अविश्वसनीयता का सुझाव देना है। वोट करने के लिए

पार्टी के खिलाफ बेवफाई है। परहेज़ में दूसरों के साथ शामिल होना या

दूसरे पक्ष के साथ मतदान करने से साजिश की गंध आती है।

(जोर दिया गया)

एक सदस्य पर अयोग्यता जो राजनीतिक दल द्वारा जारी "किसी भी निर्देश" के विपरीत मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है। हालाँकि, प्रावधान दो अपवादों को मान्यता देता हैः एक जब सदस्य राजनीतिक दल से मतदान करने या मतदान से दूर रहने की पूर्व अनुमति प्राप्त करता है और दूसरा जब सदस्य ने ऐसी अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान किया है लेकिन राजनीतिक दल द्वारा उसकी कार्रवाई को माफ कर दिया गया है। यह प्रावधान स्वयं इस संभावना को समायोजित करता है कि ऐसे अवसर हो सकते हैं जब कोई सदस्य उस पार्टी के निर्देश के विपरीत मतदान कर सकता है या मतदान से दूर रह सकता है जिससे वह संबंधित है। यह अपने आप में फिर से पैराग्राफ 2 (1) के खंड (बी) में "किसी भी निर्देश" की अभिव्यक्ति की उचित समझ और निर्माण के लिए एक संकेत प्रदान कर सकता है कि क्या वास्तव में पक्ष के सभी निर्देशों या चाबुकों में वैधानिक परिणाम शामिल हैं या क्या असाधारण प्रकृति और

शक्ति के व्यापक होने और बहुत गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए जो ", सीजे. जे. के अत्यधिक दंड सहित प्रवाहित होते हैं।

145

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल

अयोग्यता अभिव्यक्ति को एक सीमित अर्थ दिया जाना चाहिए

के उद्देश्यों और उद्देश्यों द्वारा इंगित संदर्भों के लिए इसका संचालन दसवीं अनुसूची। हम इस पहलू पर अलग से विचार करेंगे।

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 122 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

122. पैराग्राफ 2 (1) (बी) का अर्थ लगाते हुए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि

संविधान के तहत संसद के साथ-साथ राज्य के सदस्यविधायिका को इस स्वतंत्रता के बावजूद सदन में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

संविधान और नियमों के प्रावधानों के अधीन है और सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले स्थायी आदेश [अनुच्छेद 105 (1)]

और अनुच्छेद 194 (1)]। पैराग्राफ द्वारा लगाई गई अयोग्यता

2 (1) (ख) इसका इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि उक्त पर अनुचित प्रभाव न पड़े।

किसी सदस्य की बोलने की स्वतंत्रता। यह संभव होगा यदि अनुच्छेद

2 (1) (ख) अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने दायरे में सीमित है।

दसवीं अनुसूची में निहित संशोधन, अर्थात्,

पद के प्रलोभन से प्रेरित राजनीतिक दलबदल की बुराई या शरारतया अन्य समान विचार। उक्त उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा यदि

मतदान करने या अनुपस्थित रहने के आधार पर अयोग्यता

एक सदस्य द्वारा मतदान से उन मामलों तक सीमित है जहाँ एक परिवर्तन

सरकार के लाए जाने या रोके जाने की संभावना है, जैसा कि मामला है

इस तरह के मतदान या बहिष्कार के परिणामस्वरूप या जब ऐसा मतदान हो सकता है

या संयम एक ऐसे मामले पर है जो एक प्रमुख नीति और कार्यक्रम था।

जिस पर सदस्य जिस राजनीतिक दल से संबंधित है, चला गया

जनमत संग्रह। इस उद्देश्य के लिए राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश

इससे संबंधित सदस्य, जिसका उल्लंघन हो सकता है पैराग्राफ 2 (1) (बी) के तहत अयोग्यता को सीमित करना होगा

सरकार में विश्वास या अविश्वास के प्रस्ताव पर मतदान

या जहाँ विचाराधीन प्रस्ताव किसी ऐसे मामले से संबंधित है जोराजनीतिक दल की एक अभिन्न नीति और कार्यक्रम था

जिसके आधार पर यह मतदाताओं तक पहुँचा। मतदान या बहिष्कार राजनीतिक दल के निर्देश के खिलाफ किसी सदस्य द्वारा मतदान करने से

इस तरह के प्रस्ताव पर कार्यक्रम की अस्वीकृति होगी

जिसके आधार पर वह मतदाताओं के सामने गए और खुद को प्राप्त किया

निर्वाचित और इस तरह के मतदान या बहिष्कार का उल्लंघन होगा

मतदाताओं द्वारा उन पर विश्वास व्यक्त किया गया।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

यह महत्व के बिना नहीं है कि, मामले में अपवाद को छोड़कर

निर्दलीयों ने, जो बहुत कम हैं, अनुभव से पता चला है किराजनीतिक दल हैं जो ज्यादातर विधानसभाओं के सदस्यों की स्थापना करते हैं

केंद्र में या राज्यों में। हम निर्धारित नामांकन पत्रों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

राज्य परिषद के चुनाव के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत, फॉर्म 2–सी होने के नाते, या राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए,

फॉर्म 2 बी होने के कारण, जिनमें से प्रत्येक के लिए एक घोषणा की आवश्यकता होती है

उम्मीदवार उस राजनीतिक दल के विवरण के बारे में जिसने उसे चुनाव में स्थापित किया है। यह घोषणा निर्वाचित विधायकों को इस मामले में बाध्य करती है कि सभी मामलों में राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा, और हम पाते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने राज्यों की परिषद के चुनाव में किसी विशेष उम्मीदवार को पार्टी का समर्थन देने में कोई गलती नहीं की है। फिर भी, किहोतो होलोहन बनाम में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए। ज़चिल्लू (ऊपर), यह सही नहीं है

यह तर्क दिया जाता है कि खुली मतपत्र प्रणाली विधान सभा के सदस्यों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए उजागर करती है क्योंकि संविधान का वह हिस्सा अलग–अलग उद्देश्यों के लिए है।

अंतर्राष्ट्रीय समझौते

याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अंतर्राष्ट्रीय

उपकरण "गुप्त मतदान" पर जोर देते हैं क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की नींव रखता है जो बदले में लोगों की सच्ची इच्छा दिखाने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करता है। इस जोर का महत्व इस मान्यता में निहित है कि यह एक लोकतांत्रिक सरकार है जो अंततः जिम्मेदार है।

लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। , नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार।

उपरोक्त संदर्भ में, सार्वभौमिक घोषणा का संदर्भ दिया गया था

मानवाधिकार और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन(आई. सी. सी. पी. आर)।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, अनुच्छेद 21 के माध्यम से इस प्रकार प्रदान करती है

इसके अंतर्गतः –

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार है।देश।

(3) लोगों की इच्छा कुलदिप नायर बनाम के अधिकार का आधार होगी।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

147

सरकार; यह आवधिक और वास्तविक रूप में व्यक्त किया जाएगा

चुनाव जो सार्वभौमिक और समान मताधिकार द्वारा होंगे और

गुप्त मतदान या समकक्ष मुक्त मतदान प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीसीपीआर)

अनुच्छेद 25 निम्नलिखित प्रावधान करता हैः –

" प्रत्येक नागरिक के पास बिना किसी अधिकार के अधिकार और अवसर होंगे। अनुच्छेद 2 में उल्लिखित भेद और बिना अनुचित

प्रतिबंधः

(क) सार्वजनिक मामलों के संचालन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना, या

स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से;

(ख) मतदान करना और वास्तविक आवधिक चुनावों में निर्वाचित होना जो

सार्वभौमिक और समान मताधिकार द्वारा आयोजित किया जाएगा

गुप्त मतदान, इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गारंटी

निर्वाचक;

(ग) समानता की सामान्य शर्तों पर लोक सेवा तक पहुँच प्राप्त करना।

अपने देश में।

इस प्रकार दोनों दस्तावेजों में सरकार के गठन का प्रावधान है।

गुप्त मतदान। इन दो मानवाधिकार उपकरणों में सरकार के अधिकार को आधार देते हुए "मतदाताओं की इच्छा" को प्रमुख महत्व दिया गया है। हालाँकि यह ध्यान दिया जा सकता है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 21 में आवश्यकता को गुप्त मतदान द्वारा नहीं बल्कि "समान मुक्त मतदान प्रक्रियाओं" द्वारा भी पूरा किया जाता है। विद्वान परामर्शदाता इंटर–अमेरिकन कन्वेंशन नामक साधन पर भी भरोसा करेगा, जिसमें सिद्धांतगुप्त मतपत्र प्रणाली के रूप में मतदाता की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को स्वीकार किया गया है।

श्री सच्चर ने बताया कि उपरोक्त अभिव्यक्तियाँ थीं –

भागीदारी के एक दृष्टिकोण के मद्देनजर आई. सी. सी. पी. आर. के अनुच्छेद 25 (बी) में जोड़ा गया

तीसरी समिति, 16 वें सत्र (1961) में शामिल देशः –

मताधिकार 'और' गुप्त मतदान 'वास्तविक चुनावों के तत्व थे।जो बदले में मतदाताओं की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गारंटी देता है

(ए/सी. 3/SR.1096, $36 (सीएल), $55 (सीएचआई), $63 और $75–76 (यूएआर), $66

(आरएल)]। इसलिए इन तत्वों को एक साथ समूहीकृत रहना चाहिए।

विद्वान वकील को यह तर्क देने के लिए दर्द हो रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय 148

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

निर्देशों का उपयोग नगरपालिका कानूनों की व्याख्या करने और उनके समर्थन में किया जा सकता है

उनका निवेदन था कि वे बार–बार परम पूज्य केशवानंद भारती का उल्लेख करेंगे।

श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य और अन्न। , [1973] 4 एस. सी. सी. 225; जॉली जॉर्ज वर्गीज और एनर। वी. द बैंक ऑफ कोचीन, [1980] 2 एस. सी. सी. 360; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) v. भारत संघ और ए. एन. आर. , [1997] 1 एस. सी. सी. 301; नीलाबती बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य। , [1993] 2 एस. सी. सी. 746; कपिला हिंगोरानी

वी. बिहार राज्य, [2003] 6 एस. सी. सी. 1 और राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम। केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। , [2004] 10 एस. सी. सी 201

श्री सच्चर के अनुसार, उपरोक्त निर्णयों में जोर दिया गया है

यह है कि क़ानूनों की व्याख्या में मानवाधिकारों के विकसित न्यायशास्त्र का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह तर्क इस सामान्य तर्क के अतिरिक्त है कि किसी भी कानून के अभाव में, यह न्यायालय निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्धारित कर सकता है –

अंतर्राष्ट्रीय लिखतों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप ताकि संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया जा सके।

इस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई वाचाओं और घोषणाओं का सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें दिया गया अर्थ ऐसा होना चाहिए जो उसमें घोषित अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रयोज्यता औरयदि आवश्यक हो, तो इसके सिद्धांतों को घरेलू में पढ़ना पड़ सकता है।

न्यायशास्त्र।

यह केशवानंद भारती बनाम में कहा गया था। केरल राज्य

(ऊपर दिया गया है) कि "निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और गंभीर के आलोक में संविधान की भाषा की व्याख्या करनी चाहिए, यदि कठिन नहीं है, जो आखिरकार एक नगरपालिका कानून है।

भारत द्वारा सदस्यता प्राप्त घोषणा। ”

लेकिन फिर, भारत में तय किए गए विषय पर कानून काफी स्पष्ट है

ताकि इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक न हो कि वह यहां उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए कहीं और देखे। इसके अलावा, संघर्ष के मामले में, नगरपालिका कानूनों को प्रबल करना होगा।

मतदान की गोपनीयता–स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि गोपनीयता

मतदान हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा की पहचान रहा है, जो हमारी राजनीति के रूप में अपनाए गए लोकतांत्रिक सिद्धांतों में बहुत आवश्यक है। उनका कहना है कि यह हमारे संवैधानिक कानून की भावना है और सार्वभौमिक रूप से कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

149

मान लिया गया मानदंड और यह कि इस संबंध में कोई भी विचलन मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से मतदाता द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है।

एस. रघबीर सिंह गिल बनाम के मामले का संदर्भ दिया गया है। एस.

गुरचरण सिंह टोहरा, [1980] सप्लीमेंट एस. सी. सी. 53, जिसमें मुख्य समस्या की अपील इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या "चुनाव की शुद्धता और मतपत्र की गोपनीयता, संविधान में परिकल्पित संसदीय लोकतंत्र की इमारत का समर्थन करने वाले दो केंद्रीय स्तंभ" एक दूसरे के साथ टकराव में खड़े हैं या एक दूसरे के पूरक हैं।

एस. रघबीर सिंह गिल बनाम। एस. गुरचरण सिंह टोहरा (ऊपर)

विवादित संशोधन के पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित। जैसा कि पहले देखा गया है, आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 94, जैसा कि तब था, ने यह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया कि किसी भी चुनाव में "मतदान की गोपनीयता" का उल्लंघन न हो। क्रम में

ऐसा करने के लिए, यह प्रावधान प्रत्येक गवाह या अन्य व्यक्ति को "यह बताने की आवश्यकता से मुक्त कर देगा कि उसने चुनाव में किसे वोट दिया है"।

इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में पाया कि धारा 94 ऐसा नहीं कर सकती

अलग–अलग व्याख्या या जांच की जानी चाहिए और इसके दायरे, दायरे और अंतर्निहित उद्देश्य का पता उस अधिनियम के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए जिसमें यह अपना स्थान पाता है। आर. पी. अधिनियम, 1951 और आगे इस तथ्य के संदर्भ में कि यह अधिनियम स्वयं संविधान में "चुनाव" शीर्षक वाले भाग XV में अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था। यह इस न्यायालय का विचार था कि "कोई भी

धारा 94 की व्याख्या अनिवार्य रूप से उस उद्देश्य के लिए होनी चाहिए जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है। व्याख्यात्मक प्रक्रिया को लोकतांत्रिक संस्था की स्थापना के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल अभिधारणा को आगे बढ़ाना चाहिए और इसे धीमा नहीं करना चाहिए। धारा 94 की व्याख्या संविधान में निहित संवैधानिक मूल्यों से अलग नहीं की जा सकती है।

इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः –

" 13. मतपत्र की गोपनीयता निस्संदेह स्वतंत्र मतपत्र का एक अनिवार्य संयोजन है। और निष्पक्ष चुनाव। एक मतदाता को वैधानिक रूप से आश्वस्त किया जाना था कि वह

किसी भी प्राधिकारी द्वारा यह खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि वह किसके लिए है

वोट दिया ताकि एक मतदाता बिना किसी डर या पक्षपात के वोट दे और मतदान से मुक्त हो।

उसके अपने होंठों से उसकी इच्छा के खिलाफ इसके प्रकटीकरण की कोई आशंका।

जैसा कि धारा 94 साक्ष्य की धारा 132 के लिए एक अपवाद तैयार करती है

11

अधिनियम के साथ–साथ अधिनियम की धारा 95 के लिए भी प्रावधान करना आवश्यक था

गवाह का संरक्षण यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर है

जो उसे दोषी ठहरा सकता है। धारा 95 अनुदान का प्रावधान करती है –

उसमें निर्धारित परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति का प्रमाण पत्र।

ए 150

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

साक्ष्य अधिनियम और धाराओं के प्रासंगिक प्रावधानों का अवलोकन

93 , 94 और अधिनियम का 95 सकारात्मक रूप से दिखाएगा कि वे प्रदान करते हैं

गवाहों की परीक्षा की प्रक्रिया सहित किसी प्रक्रिया के लिए,

चुनाव याचिका के मुकदमे में उनके अधिकार और दायित्व। द.

अभिव्यक्ति "अन्य व्यक्ति" सुरक्षा को बाहर के मंच तक बढ़ाती हैअदालतें।

(जोर दिया गया)

अन्य प्रावधानों के अलावा, धारा 94 और 128 पर ध्यान देने के बाद

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और नियम 23 (3), 23 (5) (ए) और (बी), 31 (2), 38 (4), 39 (1), (5), (6) और (8), दूसरा परंतुक 40 (1), 38–ए (4), 39–ए (1) और (2) के रूप में

चुनाव संचालन नियम, 1961 (संक्षेप में "नियम") और इसी तरह के अन्य नियमों में निहित, इस न्यायालय ने पाया कि

मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए, उनका उद्देश्य "किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति से मुक्त करना था जहां वह यह बताने के लिए बाध्य हो सकता है कि उसने किसके लिए गवाही की मजबूरी में मतदान किया है।" तब पैराग्राफ 14 में यह देखा गया था किः

26..... मतपत्र की गोपनीयता को एक अभिधारणा के रूप में उचित रूप से शैलीबद्ध किया जा सकता है

संवैधानिक लोकतंत्र। यह संसद के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करता है।

संविधान के तहत स्थापित संस्थान। यह बहुत महत्वपूर्ण है

लोक हित कि एक निर्वाचक या मतदाता पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए

अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी बाधा से मुक्त जो

इसमें प्रकटीकरण के बारे में बाधाएं शामिल हैं। एक दूरस्थ या विशिष्ट संभावना

कि किसी समय किसी मतदाता को कानून की मजबूरी में मजबूर किया जा सकता है

यह खुलासा करना कि उन्होंने किसे वोट दिया है, एक सकारात्मक बाधा के रूप में कार्य करेगा

और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी स्वतंत्रता की जाँच करें जिस तरह से वह

स्वतंत्र रूप से व्यायाम करना चुनते हैं। इसलिए यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है

कि संवैधानिक लोकतंत्र का यह अभिधारणा सार्वजनिक नीति पर आधारित है।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार यह माना गया कि मतपत्र की गोपनीयता, संवैधानिक व्यवस्था का एक बुनियादी अभिधारणा है।

लोकतंत्र को "किसी भी अमूर्त स्थिति में तैयार नहीं किया गया था या एक आधार पर रखा गया था और पूजा की गई थी, बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव "।

इस अदालत ने पाया कि धारा 94 मतदाता के विशेषाधिकार के रूप में थी

उसे जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर होने से बचाने के लिए जिसके लिए

उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया था। यदि मतदाता अपना कुलदिप नायर बनाम खोलने का विकल्प चुनता है तो उसे कुछ भी नहीं रोकता है।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

151

व्यक्ति "। इस प्रकार, यह अदालत में मतदाता की रक्षा करने के लिए है जब कोई व्यक्तिएक गवाह के रूप में और अदालत के बाहर जब उससे पूछताछ की जा सकती है

उन्होंने कैसे मतदान किया। यह पाया गया कि ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था जो इसका खुलासा कर सके

किसी भी दंड के लिए मतदाता यदि वह स्वेच्छा से यह खुलासा करने का विकल्प चुनता है कि उसने कैसे या उसके लिए मतदान किया

जिसे उन्होंने वोट दिया।

बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ कि 'मतपत्र की गोपनीयता' जैसा कि खंड में प्रदान किया गया है

94 "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए", अदालत ने इस प्रकार राय दीः –

" ..... यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के बजाय मतपत्र की गोपनीयता है

उपयोग किया जाता है, जैसा कि इस मामले में किया जाता है, के लिए बहुत सार्वजनिक उद्देश्य को विफल करने के लिए

जिसे यह अधिनियमित किया गया है, प्रकाश में आने वाले गलत को दबाने के लिए और

चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी को रोकने के लिए या किसी अपराध का बचाव करने के लिए भी।

मतपत्रों की जालसाजी, मतपत्र की गोपनीयता का यह सिद्धांत होगा

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के व्यापक सिद्धांत को स्वीकार करना।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने यह ध्यान देने के बाद कि आर. पी. अधिनियम, 1951 एक स्व–निहित संहिता है

चुनाव के विषय पर और दोहराते हुए कि "एक बुनियादी बात है

सिद्धांत जो सभी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संसदीय माध्यमों से व्याप्त है संस्थान अर्थात। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव द्वारा उन्हें स्थापित करने के लिए ", ने कहाः

..... मतपत्र की गोपनीयता का सिद्धांत अलग या अलग–थलग नहीं रह सकता है।

और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की नींव के टकराव में।

चुनाव की शुद्धता। वे सह–अस्तित्व में हो सकते हैं लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है, जहां एक

बी

इसका उपयोग दूसरे को नष्ट करने के लिए किया जाता है, पहले वाले को इस सिद्धांत के अधीन होना चाहिए,

" व्यापक लोक हित में चुनाव की शुद्धता। वास्तव में मतपत्र की गोपनीयता,

मतदाता का एक विशेषाधिकार, अलंघनीय नहीं है और उसके द्वारा माफ किया जा सकता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में

संयुक्त राष्ट्र

और गलत खेल को उजागर करने के लिए "।

(जोर दिया गया)

इसके विचारों को तैयार करने में, कुछ टिप्पणियों में समर्थन पाया गया

केली, सी. बी., क्वीन बनाम में। बियर्डसाल, [एलआर (1875–76) 1 क्यूबी 452], निम्नलिखित के लिए

प्रभावः –

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायिका ने यह प्रावधान किया है कि गोपनीयता को संरक्षित रखा जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

मतपत्रों और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों के संबंध में

अब इसे चुनाव का एक गुप्त तरीका बना दिया गया है। लेकिन यह गोपनीयता इसके अधीन है न्याय के उचित प्रशासन के लिए आवश्यक शर्त और

धोखाधड़ी, जालसाजी और शुद्धता को प्रभावित करने वाले अन्य अवैध कार्यों की रोकथाम

और चुनावों की वैधता "।

(जोर दिया गया)

इस आशंका को खारिज करते हुए कि गोपनीयता का सिद्धांत इसमें निहित है

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 94 को माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह जनहित में अधिनियमित किया गया था और यह साव जनिक नीति पर आधारित निषेध है, और इस तर्क से सहमत होते हुए कि जहां सार्वजनिक नीति अदालतों पर लागू निषेध छूट के सिद्धांत को लागू करने में धीमा होना चाहिए, यह माना गया कि गोपनीयता का विशेषाधिकार किसी व्यक्ति के लाभ के लिए दिया गया था, भले ही सार्वजनिक हित में अधिनियमित सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया हो, इसे माफ किया जा सकता है क्योंकि विशेषाधिकार की अवधारणा में ही इसे माफ करने का अधिकार है। इस प्रकार न्यायालय ने इसे एक "अपरिहार्य निष्कर्ष" पाया कि धारा 94 में गोपनीयता का सिद्धांत एक मतदाता के पक्ष में एक योग्य विशेषाधिकार को लागू करता है कि उसे खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, लेकिन अगर वह जानकारी को स्वेच्छा से देने का विकल्प चुनता है तोनियम का उल्लंघन नहीं किया जाता है।

इस प्रकार, उन चुनावों के तहत भी जो सिद्धांत पर आधारित हैं

मतदान की गोपनीयता के संबंध में, यह मतदाता को चुनना है कि वह यह खुलासा करना चाहता है कि उसने किसे वोट दिया था या गोपनीयता को अक्षुण्ण रखना चाहता है। अगर

वह ऐसा चुनता है, वह अपने विशेषाधिकार को छोड़ सकता है और उस स्थिति में, मतपत्र की गोपनीयता सामने आनी चाहिए। ऐसी घटना तब भी हो सकती है जब धोखाधड़ी, जालसाजी या अन्य अवैध कार्य हो और प्रकटीकरण उप–न्याय के प्रशासन के उद्देश्य को पूरा करता है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि क्या

महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई मतदाता अपना वोट डाल रहा होता है तो उसे बिना किसी डर, दबाव या जबरदस्ती के अपनी अंतरात्मा के अनुसार ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। यह डर कि किसी भी

कानून के तहत, वह यह खुलासा करने के लिए मजबूर हो सकता है कि उसने किसे वोट दिया था, उसकी पसंद को भी बाधित नहीं कर सकता है। इस तरह की स्वतंत्रता का आश्वासन मतपत्र की गोपनीयता का एक सार है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक सहायक है। धोखाधड़ी के कारण अपने मतपत्र का खुलासा करने का विकल्प चुनने की मतदाता की स्वतंत्रता याजालसाजी केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह स्वतंत्रता किसी भी तरह से इस सामान्य सिद्धांत को प्रभावित नहीं करती है कि मतपत्र की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्षता का आधार है।

चुनाव, जो लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

153

श्री सच्चर ने चार्ल्स डब्ल्यू. बर्सन बनाम में निर्णय की सहायता के लिए भी जोर दिया।

मैरी रेबेका फ्रीमैनः (1992) 119 एल. एड. 2d 5 = 504 US 119, जिसमें यह यह माना गया था किः

एक लोकतांत्रिक समाज का सार "। " एक स्वतंत्र देश में किसी भी अधिकार से अधिक मूल्यवान कोई नहीं है।

उन लोगों के चुनाव में चुनाव जो कानून बनाते हैं, जिनके तहत

अच्छे नागरिक, उन्हें जीना चाहिए। अन्य अधिकार, यहां तक कि सबसे बुनियादी, हैं

अगर वोट देने के अधिकार को कम किया जाता है तो यह भ्रम है "।

उपर्युक्त मामले में, इससे जुड़ी बुराई से निपटने के बाद

' वाइवा वॉयस सिस्टम 'और गोपनीयता को सुरक्षित करने में कानून की विफलता जो खुल गई थी

रिश्वत के दरवाजे का सारांश इस प्रकार दिया गया थाः

" संक्षेप में, इस में चुनाव विनियमन के इतिहास की जांच

देश ने दो बुराइयों के खिलाफ लगातार लड़ाई का खुलासा किया; मतदाताओं को डराना–धमकाना

और चुनाव धोखाधड़ी। एक अनौपचारिक के साथ एक असफल प्रयोग के बाद

मतदान प्रणाली, सभी 50 राज्य, कई अन्य पश्चिमी राज्यों के साथ

लोकतंत्रों ने एक ही समाधान पर समझौता कियाः एक गुप्त मतपत्र में सुरक्षित

मतदान कक्षों के आसपास एक प्रतिबंधित क्षेत्र द्वारा भाग "।

" अंत में, असहमति का तर्क है कि हम इतिहास को आवश्यकता के साथ भ्रमित करते हैं।

फिर भी असहमति स्वीकार करती है कि इलाज के लिए एक गुप्त बैलॉट आवश्यक था

चुनावी दुरुपयोग। असहमति के विवाद के विपरीत, बीच की कड़ीमतपत्र की गोपनीयता और मतदान क्षेत्र के आसपास कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र

यह केवल समय नहीं है–यह सामान्य ज्ञान है। बचाने का एकमात्र तरीका

मतपत्र की गोपनीयता मतदाता के आसपास के क्षेत्र तक पहुंच को सीमित करना है।

तदनुसार, हम मानते हैं कि मतदान के आसपास कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं

राज्य के बाध्यकारी हितों को सुरक्षित करने के लिए क्षेत्र आवश्यक है।

श्री पी. पी. राव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि मतदान एक

लिली थॉमस बनाम में निर्णय के पैराग्राफ 2 में टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, अभिव्यक्ति का रूप और एक गुप्त मतपत्र मतदान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य। , [1993] 4 एस. सी. सी. 234, जिसमें न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 (4) के तहत प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा था। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अनुच्छेद 124 (4) के तहत परिकल्पित प्रकृति की कार्यवाही पहले न्यायिक जवाबदेही पर उप–समिति v में आयोजित की गई थी। भारत संघ, [1991] 4 एस. सी. सी. 699, संसद के सदनों में कार्यवाही नहीं होगी और बल्कि न्यायिक चरित्र में भाग लेगी क्योंकि 154

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

इसे जाँच और जाँच के बाद हटाया जाता है।

श्री राव ने फैसले के पैराग्राफ 2 से निम्नलिखित अंश का हवाला दिया

उपरोक्त मामले में: –

" ऐसा प्रतीत होता है कि वैधानिक प्रक्रिया तब शुरू होती है जब अध्यक्ष अभ्यास करते हैं।

{

तत्पश्चात संसद में प्रस्ताव पर चर्चा औरमतदान राजनीतिक प्रकृति का अधिक प्रतीत होता है। मतदान एक औपचारिक अभिव्यक्ति है।

अधिकार का प्रयोग करने के हकदार व्यक्ति की इच्छा या राय

विचाराधीन विषय या मुद्दा। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में इसकी व्याख्या की गई है।

के रूप में, "किसी की इच्छा, वरीयता या पसंद की अभिव्यक्ति, औपचारिक रूप से किसी विधायी या विचारशील निकाय के सदस्य द्वारा प्रकट किया गया, या

निर्णय के संबंध में एक निर्वाचन क्षेत्र या योग्य मतदाताओं का एक निकाय

किसी भी प्रस्तावित उपाय पर समग्र रूप से निकाय द्वारा किया जाना या कार्यवाही या कानून, नियम या विनियमों को पारित करने में, या चयन

एक अधिकारी या प्रतिनिधि का "। मतदान का अधिकार का अर्थ है प्रयोग करने का अधिकार।

प्रस्ताव या संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अधिकार। इस तरह की

अधिकार का अर्थ तटस्थ रहने का अधिकार भी है।

(जोर दिया गया)

श्री सच्चर, यह प्रस्तुत करते हुए कि चुनाव की पवित्रता और शुद्धता

जहां मतदाता बिना किसी डर और पक्षपात के अपनी पसंद का चुनाव करता है, यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब यह गुप्त मतदान द्वारा हो, यह तर्क दिया कि यह गुप्त मतदान है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आधार है। लोक सभा के चुनाव में डाले गए वोट और राज्य परिषद में डाले गए वोट के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य में लोकप्रिय सदन के लिए इस तरह के

प्रत्यक्ष चुनावों और भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए इस तरह के अप्रत्यक्ष चुनाव या विषय के करीब, राज्य परिषद में "राज्यों के प्रतिनिधियों" की सीटों को भरने के लिए चुनाव के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।

उपरोक्त संदर्भ में, वह एस. आर. के निम्नलिखित अंश का हवाला देंगे।

चौधरी बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। , [2001] 7 एससीसी 126:

" 34. जिम्मेदार सरकार और प्रतिनिधि की अवधारणा

लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा सरकार। संवैधानिक रूप से,

यह दर्शाता है कि संप्रभु शक्ति जो लोगों में निवास करती है

उनकी ओर से उनके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा और कुलदिप नायर v के लिए प्रयोग किया गया।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

155

उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से हैं

वे जो कुछ भी करते हैं उसके लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सदस्यों ने इस प्रकार, विधायिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का श्रेय देना चाहिए –

लोग। लोकसभा की तरह राज्य विधानसभाओं के सदस्य

उनकी शक्ति सीधे लोगों द्वारा चुनी गई है जबकि के सदस्य

राज्यसभा जैसी राज्य परिषद अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रति ऋणी है क्योंकि वे लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। परिषद

मंत्री जिनका मुख्यमंत्री राज्य में प्रमुख होता है और

अतः, जिसकी सहायता और सलाह पर राज्यपाल को कार्य करना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को अपनी शक्ति का श्रेय दें।

यह श्री सच्चर का निवेदन है कि कारण का उपयोग न्यायसंगत ठहराने के लिए किया गया है

संशोधन गलत है क्योंकि यह मानता है कि मतदान की गोपनीयता केवल एक

प्रक्रिया की नियमित बात और इसका यह भी अर्थ होगा कि संसद भविष्य में यह प्रावधान कर सकती है कि लोक सभा का चुनाव खुले मतदान द्वारा होगा क्योंकि संविधान में गोपनीयता के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उनका कहना है कि मतदान की गोपनीयता लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और इसकी अनुपस्थिति का अर्थ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अभाव है।

ए. नीललोहितदासन नादर बनाम। जॉर्ज मैस्क्रीन और ओआरएस। , [1994]

मान लीजिए 2 एस. सी. सी. 619, संघर्ष दो सिद्धांतों के बीच पाया गया था

चुनाव कानून–एक "चुनावों की शुद्धता" और दूसरा "मतपत्र की गोपनीयता" है। पूर्व के आधार पर, केरल उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के चुनाव को रद्द कर दिया था जो बाद में इस न्यायालय के समक्ष आया था। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती बाद के सिद्धांत पर आधारित थी।

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलेगा कि अपीलार्थी और

इस मुद्दे पर दलों के नेतृत्व में साक्ष्य में पाया गया कि कुछ मतपत्र संबंधित मतपेटियों से चुने जाने के योग्य थे जिन्हें अमान्य करार दिया गया था। इस उद्देश्य के लिए मंत्रिस्तरीय कार्य संयुक्त पंजीयक को

सौंपा गया था उच्च न्यायालय से। इस तरह की कवायद शुरू होने पर, चुनाव याचिकाकर्ता अपीलार्थी के बजाय खुद को निर्वाचित घोषित करने का हकदार था।

उच्च न्यायालय ने इस धारणा पर शून्य मतों का पता लगाया था कि दोनों

प्रतियोगियों ने 156 की धारा 64 (4) में सन्निहित सिद्धांत को स्वीकार किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

आर. पी. अधिनियम "चुनाव की शुद्धता" सिद्धांत के लिए और इच्छुक भागीदार थे

शून्य तत्व की पहचान करना और वोट किए गए लॉट से निकालना। इस दृष्टिकोण में, "गोपनीयता" के सिद्धांत के उल्लंघन पर अपील में तर्क को अस्वीकार करना।

", इस न्यायालय ने एस. रघबीर सिंह गिल बनाम में कानून से उद्धृत किया। एस. गुरचरण सिंह टोहरा (ऊपर) और पैराग्राफ 10 में कहा गया हैः –

" "मतपत्र की गोपनीयता" के सिद्धांत के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है।

यह निस्संदेह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का एक अनिवार्य संयोजन है।

अधिनियम सांविधिक रूप से एक मतदाता को आश्वस्त करता है कि वह इसके लिए मजबूर नहीं होगायह प्रकट करने का कोई प्राधिकारी कि उसने किसे वोट दिया है, ताकि वह

बिना किसी डर या पक्षपात के और किसी भी आशंका से मुक्त होकर मतदान करें। उसके अपने होंठों से उसकी इच्छा के खिलाफ प्रकटीकरण। इस संबंध में देखें।

रघबीर सिंह गिल बनाम। गुरचरण सिंह टोहरा। लेकिन यह अधिकार

मतदाता निरपेक्ष नहीं होता है। इसे "शुद्धता" के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

चुनाव "व्यापक लोक हित में। शून्य को निकालने का अभ्यासअधिनियम की धारा 62 (4) के तहत वोट किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे।

मतपत्र की गोपनीयता पर विशेष रूप से जब शून्य वोट वे होते हैं जो

इसे बिल्कुल भी कोई वोट नहीं माना जाना चाहिए। मतपत्र की गोपनीयता का सिद्धांत

एक वैध रूप से डाले गए वोट, की पवित्रता और पवित्रता का अनुमान लगाता है

जिसे सभी स्थितियों में संरक्षित किया जाना चाहिए। जब यह सुनिश्चित करने की बात की जाती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ है मौलिक आधार पर आयोजित चुनाव

शुद्धता की नींव और एक सहयोगी महत्वपूर्ण के रूप में "मतपत्र की गोपनीयता"

सिद्धांत. 27

(जोर दिया गया)

इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा ए. नीललोहितदासन नादर बनाम में इसे दोहराया गया था।

जॉर्ज मास्क्रीन (ऊपर) ने कहा कि दो प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों में से, चुनाव सिद्धांत की शुद्धता का अपना तरीका होना चाहिए और गोपनीयता के शासन को "प्रकाश में आने वाली गलतियों को दबाने और चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी को बचाने के लिए" सेवा में नहीं डाला जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन कि हमेशा मतदान करने का अधिकार

एक निहित शब्द के रूप में, गोपनीयता में मतदान करने का अधिकार, पूरी तरह से सही नहीं है। जहाँ संविधान ने ऐसा करना उचित समझा है, वहाँ उसने स्वयं प्रावधान किया है –

गुप्त मतदान द्वारा चुनाव, उदाहरण के लिए, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामले में। यह इंगित करना उचित है कि राज्य परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों की सीटों को भरने के लिए चुनाव से संबंधित संविधान के प्रावधानों के मामले में इस विषय पर मौन के विपरीत,

अनुच्छेद 55 (3) और 66 (1), जो क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव के तरीके से संबंधित हैं, 157 तक चुनाव का प्रावधान करते हैं।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल। सी. आई.]

" गुप्त मतदान "।

संविधान के अनुच्छेद 55 (3) और 66 (1) में चुनावों का प्रावधान है।

क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, निर्वाचन द्वारा मतदान का उल्लेख करते हुए

महाविद्यालय, जिसमें संसद और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं

पूर्व पद के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा और बाद के पद के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दोनों ही मामलों में यह महसूस किया गयासंविधान निर्माताओं द्वारा यह प्रावधान करना आवश्यक है कि ऐसे चुनावों में मतदान "और" शब्दों को शामिल करके गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। अगर खुद से मतदान करने का अधिकार है

गुप्तता में मतदान का तात्पर्य या अभिधारणा, तब अनुच्छेद 55 (3) और 66 (1) होगा

इस तरह के शब्दों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अनुच्छेदों में उक्त शर्त को शामिल करने की आवश्यकता से पता चलता है कि "गुप्त मतदान" हमेशा निहित नहीं होता है। इसे आवश्यक मतदान की अवधारणा में शामिल नहीं किया गया है।

निहितार्थ।

यह इस प्रकार है कि 'गुप्त मतपत्र' को मानक बनाने के लिए, यह स्पष्ट रूप से होना चाहिए

इस प्रकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 80 (4) में पढ़ने के लिए एक गुप्त मतपत्र की आवश्यकता प्रावधान में "और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा" शब्दों को पढ़ना होगा। ऐसा करना हर सिद्धांत के खिलाफ होगा

संवैधानिक और वैधानिक निर्माण।

यह देखते हुए कि यह संविधान की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे कानून को पारित करते समय संसद के लिए यह अनुमति थी कि वह गुप्त मतदान या खुले मतदान की प्रणाली के बीच चयन करे। मतदान करें। इस प्रकार, इस दृष्टिकोण से, यह मानना मुश्किल है कि राज्यों की परिषद के लिए खुली मतपत्र प्रणाली प्रदान करने में संवैधानिक दुर्बलता है।

अन्य तर्क और निष्कर्ष

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग

भारत, जिसे संविधान के तहत पूर्ण शक्तियां दी गई हैं

स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनावों का पर्यवेक्षण करते हुए, गुप्त मतपत्र प्रणाली को बदलने के विवादित संशोधन का विरोध किया था। इसलिए, इसके दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में हम कहेंगे कि जहां इस विषय पर कानून चुप है,

अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को प्राप्त करने के स्वीकृत उद्देश्य के लिए कार्य करने की शक्ति का भंडार है और इस दृष्टिकोण से यह एक सलाहकार की भूमिका भी ग्रहण करता है। लेकिन 158 के तहत कानून बनाने की शक्ति

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

अनुच्छेद 327 संसद में निहित है, जो सर्वोच्च है और इसलिए ऐसी सलाह से बाध्य नहीं है। हम इस न्यायालय का उल्लेख करके तर्क को अस्वीकार कर देंगे।

मोहिंदर सिंह गिल (ऊपर) में पहले ही कहा जा चुका है और जो दोहराने योग्य है

यहाँ यह है कि चुनाव आयोग के "पूर्ण चरित्र" के प्रयोग की सीमाओं में इस प्रभाव के लिए एक शामिल है कि "जब संसद या कोई

राज्य विधानमंडल ने चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में वैध कानून बनाया है।

आयोग ऐसे प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा, न कि उनका उल्लंघन करते हुए।

रिट याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुतिकरण यह है कि

संशोधन संविधान का उल्लंघन करता है, जो मतदान के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, अनुच्छेद 19 (1) (ए) का एक पहलू और गुप्त मतदान को संरक्षित करता है।

यह अधिकार। इसके अलावा गुप्त मतपत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक सहायक है और इसलिए, एक संसदीय लोकतंत्र का एक हिस्सा है और इसलिए, गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान के अधिकार को छीनना संविधान की मूल विशेषता को प्रभावित करता है। उनका तर्क है कि विवादित संशोधन की मांग नहीं की गई थी।याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, संशोधन इस आधार पर आगे बढ़ता प्रतीत होता है कि यह केवल राजनीतिक दलों का नेतृत्व है

औसत विधायक के बजाय भरोसा किया जाना चाहिए, जो बहुत अधिक नहीं है

वास्तव में अस्वीकार्य होने के अलावा, विधायकों के सम्मान और गरिमा के लिए पूरक।

उपरोक्त संदर्भ में, वकील ने डॉ. के निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख किया।

राजनीतिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति की गरिमा को कैसे बनाए रखा जाना चाहिए, इस मुद्दे पर बी. आर. अम्बेडकरः –

1

स्टुअर्ट मिल ने उन सभी को दिया है जो रखरखाव में रुचि रखते हैंलोकतंत्र, अर्थात्, अपनी स्वतंत्रता को किसी के पैरों पर भी नहीं रखना।

महान व्यक्ति, या उस पर उन शक्तियों के साथ भरोसा करना जो उसे नष्ट करने में सक्षम बनाती हैं

उनके संस्थान "। महान व्यक्ति के प्रति आभारी होने में कुछ भी गलत नहीं है।

जिन लोगों ने देश की जीवन भर सेवा की है। लेकिन वहाँ

कृतज्ञता की सीमाएँ हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त ने अच्छी तरह से कहा है

डैनियल ओ 'कॉनेल, कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर आभारी नहीं हो सकता है,

कोई भी महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर आभारी नहीं हो सकती और कोई भी राष्ट्रअपनी स्वतंत्रता की कीमत पर आभारी हो सकता है। यह सावधानी कहीं अधिक है।

भारत के मामले में किसी अन्य देश के मामले में आवश्यक है।

क्योंकि भारत में, भक्ति या जिसे भक्ति का मार्ग कहा जा सकता है या

नायक–पूजा, दुनिया के किसी भी अन्य देश की राजनीति में एक भूमिका निभाती है। धर्म में भक्ति आत्मा के मोक्ष का मार्ग हो सकती है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

159

लेकिन, राजनीति में भक्ति या नायक–पूजा पतन का एक निश्चित मार्ग है।

और अंततः तानाशाही "।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने विवादित संशोधन का समर्थन किया

वे तर्क देंगे कि मतदान की गोपनीयता ने भ्रष्टाचार और क्रॉस वोटिंग को जन्म दिया था। वे इंगित करेंगे कि विधानसभाओं में सभी मुद्दों पर मतदान, जिसमें शामिल हैं

राज्य परिषद और विधान सभाएँ हमेशा खुली रहती हैं और

गुप्त मतदान द्वारा नहीं। एक प्रतिनिधि का चुनाव अब अन्य के बराबर है।महत्वपूर्ण बातें। वे स्वीकार करेंगे कि आम आदमी भाग ले रहा है

प्रत्यक्ष चुनाव में मतदाता के रूप में एक मतदान केंद्र में अपने वोट का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है

गोपनीयता की रक्षा। लेकिन विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, के अनुसार

विद्वान वकील से मजबूत नैतिक फाइबर और सार्वजनिक होने की उम्मीद की जाती है साहस रखें।

विद्वान महान्यायवादी ने बताया कि उद्देश्यों का वक्तव्य

और विवादित अधिनियम के कारण संसद की आचार समिति की रिपोर्ट को संदर्भित करते हैं। नैतिकता समिति ने 08 दिसंबर 1998 की अपनी पहली रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि खुले मतपत्र प्रणाली से संबंधित मुद्दे के लिएराज्यसभा के चुनाव की जांच की जाए। द्विवार्षिक चुनावों के संबंध में धन शक्ति के आरोपों के बाद यह मुद्दा फिर से उठा

2000 में आयोजित राज्य परिषद।

नैतिकता समिति की प्रासंगिक टिप्पणियाँ पहले ही की जा चुकी हैं

विस्तार से, इस निर्णय के पहले भाग में निकाला गया। यहां यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि समिति ने "राज्यसभा के चुनावों में क्रॉस वोटिंग की उभरती प्रवृत्ति" का संज्ञान लिया और आरोप लगाया कि "बड़ी राशि और अन्य विचार मतदाताओं को" इस उद्देश्य के लिए "एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे कभी–कभी उनके अपने राजनीतिक दल से संबंधित आधिकारिक उम्मीदवारों की हार हो जाती है"। समिति ने "राज्यों में राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव खुले मतदान द्वारा कराने" की सराहना की ताकि चुनावी प्रक्रिया के साथ "बड़े धन और अन्य विचारों" द्वारा की गई शरारत को दूर किया जा सके।

यह याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का निवेदन है कि

नैतिकता समिति की टिप्पणियाँ, जिन पर विवादित संशोधन लाया गया था, न केवल संशोधन को उचित ठहराने में विफल रहती हैं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक योजना के विपरीत हैं, जो लोकतंत्र के संरक्षण के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर, महान्यायवादी ने कहा कि चूंकि अधिकांश उम्मीदवार पार्टी प्रणाली के तहत चुने जाते हैं, इसलिए यह सिद्धांत है कि किसी पार्टी के निर्वाचित या नामित व्यक्ति को धन शक्ति द्वारा पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए लुभाया नहीं जाना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

हितकारी और हितकारी।

श्री सच्चर ने बताया है कि चुनाव संचालन नियम, 1961

आर. पी. अधिनियम, 1951 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें तैयार और अधिसूचित किया गया था। आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 59,94 और 128 के विवादित संशोधन के मद्देनजर, केंद्र सरकार द्वारा उक्त नियमों में भी संशोधन किया गया है।एस. ओ. 272 (ई) दिनांक 27.02.2004 के माध्यम से सरकार। इस संशोधन के परिणामस्वरूप भाग V। में प्रदत्त राज्य परिषद के चुनाव में मतदान के संचालन के नियमों में नियम 39–ए. ए. जोड़ा गया है। इससे पहले गुप्त मतदान प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए उक्त नियमों में नियम 39–ए जोड़ा गया था।

नियम 39–ए पर पहले ध्यान दिया जा सकता है। यह नीचे लिखा हैः –

" 39 – ए. मतदान केंद्र और मतदान प्रक्रिया के भीतर मतदाताओं द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। – (1) प्रत्येक निर्वाचक, जिसे नियम 38–ए या किसी अन्य प्रावधान के तहत मतपत्र जारी किया गया है।

इन नियमों में से, मतदान के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखेंगे।

स्टेशन और उस उद्देश्य के लिए इसके बाद मतदान प्रक्रिया का पालन करें

रखा गया। (2) मतपत्र प्राप्त करने पर निर्वाचक तुरंत –

(क) मतदान विभाग में से एक में आगे बढ़ें;

(ख) नियम 37 के उप–नियम (2) के अनुसार अपना वोट दर्ज करें।

ए, उद्देश्य के लिए आपूर्ति की गई वस्तु के साथ;

(ग) मतपत्र को मोड़ें ताकि वह अपने वोट को छिपा सके।

(ग) यदि आवश्यक हो, तो पीठासीन अधिकारी को प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिखाएँ।

मतपत्र पर निशान;

(ई) मतपेटी में मुड़ा हुआ कागज डालें, और

(च) मतदान केंद्र छोड़ दें।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी अनुचित देरी के मतदान करेगा।

(4) किसी भी निर्वाचक को मतदान कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब

इसके अंदर एक और निर्वाचक है।

(5) यदि कोई निर्वाचक जिसे मतपत्र जारी किया गया है, तो मना कर देता है।

प्रक्रिया का पालन करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई चेतावनी

उप–नियम (2) में निर्धारित, उसे जारी किया गया मतपत्र, चाहे कुलदिप नायर बनाम।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.

161

उसने उस पर अपना वोट दर्ज किया है या नहीं, उससे वापस ले लिया जाए

के निर्देशन में पीठासीन अधिकारी या एक मतदान अधिकारी

पीठासीन अधिकारी।

(6) मतपत्र वापस लिए जाने के बाद पीठासीन अधिकारीअपनी पीठ पर "रद्द की गई मतदान प्रक्रिया" शब्द दर्ज करेंगे।

प्रक्रिया का उल्लंघन "दर्ज किया जाता है, एक अलग आवरण में रखा जाएगा जिसके चेहरे पर "बैलेट पेपर्स" शब्द होंगेः मतदान की प्रक्रिया

उल्लंघन किया "।

(8) किसी अन्य दंड के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जिसके लिए एक निर्वाचक, जिसे उप–नियम (5) के तहत मतपत्र वापस ले लिया गया है, हो सकता है

उत्तरदायी, ऐसे मतपत्र पर दर्ज वोट, यदि कोई हो, की गिनती नहीं की जाएगी।

नियम 39–ए. ए. नियम 70 के आधार पर ऐसे चुनावों पर लागू होता है

" वोट डालने के बारे में जानकारी। – (1) बावजूद इसके। नियम 39–ए में निहित कुछ भी, पीठासीन अधिकारी, उस अवधि के बीच जब कोई निर्वाचक किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है, अभिलेख करेगा।

बैलेट पेपर पर उसका वोट और इस तरह के निर्वाचक के बैलेट बॉक्स में उस बैलेट पेपर को डालने से पहले, उस राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को यह सत्यापित करने की अनुमति दें कि ऐसे निर्वाचक ने किसे अपना वोट डाला हैः बशर्ते कि यदि ऐसा निर्वाचक अपने राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि को अपना चिह्नित मतपत्र दिखाने से इनकार करता है, तो उसे जारी किया गया मतपत्र पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी और मतपत्र के निर्देश पर वापस ले लिया जाएगा।

इस प्रकार वापस लिए गए कागज को आगे नियम 39–ए के उप–नियम (6) से (8) में निर्दिष्ट तरीके से निपटाया जाएगा जैसे कि ऐसा मतपत्र।

उस नियम के उप–नियम (5) के तहत वापस ले लिया गया था।

(2) प्रत्येक राजनीतिक दल, जिसका सदस्य निर्वाचक के रूप में मतदान केंद्र पर मतदान करता है, उप–नियम (1) के प्रयोजनों के लिए फॉर्म 22–ए में दो अधिकृत एजेंटों की नियुक्ति करेगा। (3) उप–नियम (2) के तहत नियुक्त एक अधिकृत प्रतिनिधि मतदान केंद्र पर मतदान के पूरे घंटों के दौरान मौजूद रहेगा और दूसरा उसे मतदान केंद्र से बाहर जाने पर या इसके विपरीत मुक्त करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

चूँकि नियम 39–ए. ए. को नियम 39–ए. के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है, इसलिए पूर्व वाला है –

अनिवार्य रूप से चुनाव आयोग द्वारा आर. पी. अधिनियम, 1951 के तहत आयोजित अन्य सभी चुनावों में सामान्य नियम के लिए एक अपवाद। विवादित संशोधन से पहले यह नियम रहा है कि मतदान एक गुप्त मतपत्र द्वारा किया जाएगा, जिसमें मतदाताओं सहित सभी संबंधितों से अपेक्षा की जाती है कि वेइसे गुप्त रखते हुए वोट की पवित्रता। लेकिन जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, विशेषाधिकार

वोट को गुप्त रखना उस निर्वाचक का है जो अन्यथा चुन सकता है; अर्थात, वह अपने वोट डालने के तरीके का खुलासा करने का विकल्प चुन सकता है लेकिन

उसे उस तरीके का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसमें उसने ऐसा किया है, सिवाय उस विषय पर कानून के अनुसार जो आम तौर पर केवल उस स्थिति में लागू होता है जब चुनाव को पहले चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाती है।

उच्च न्यायालय। राज्यों की परिषद के चुनाव के मामले में, संशोधन के बाद के परिदृश्य में, मानदंड में बदलाव आया है, कि जिस राजनीतिक दल से राज्य की विधानसभा का कोई विशेष सदस्य संबंधित है, वह मतदान केंद्र पर औपचारिक रूप से नियुक्त अधिकृत एजेंट के माध्यम से यह पता लगाने का हकदार है कि किस तरह से विचाराधीन सदस्य, जो ऐसे उद्देश्यों के लिए एक निर्वाचक है, ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अपवाद केवल विधान सभा के ऐसे सदस्यों पर लागू होता है, जैसे कि एक राजनीतिक दल के सदस्य और बोर्ड के सभी सदस्यों पर नहीं। इस तरह के चुनाव में मतदाता अपने राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को अपना वोट दिखाने से इनकार कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वह अपना वोट देने का अधिकार खो देता है, जिसे मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया जाता है।

चुनाव प्रक्रिया।

इस प्रकार, संशोधित नियमों का प्रभाव यह है कि राज्य परिषद के चुनावों में, निर्वाचक द्वारा मतपत्र को मतपेटी में डालने से पहले,राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि को यह सत्यापित करने की अनुमति होगी कि ऐसा निर्वाचक किसे अपना वोट देता है। यदि ऐसा मतदाता अपना चिह्नित मतपत्र दिखाने से इनकार करता है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया जाएगा कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था। इसलिए, मतदाता पर अपना वोट दिखाने की मजबूरी है।

लेकिन फिर, उपरोक्त नियम केवल मांगे गए उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हैं

विवादित संशोधन द्वारा प्राप्त किया जाना। बल्कि, नियमों से पता चलता है कि खुली मतपत्र प्रणाली का मतलब यह नहीं है कि यह सभी के लिए खुली है। यह केवल राजनीतिक दल का अधिकृत अभिकर्ता जिसे यह देखने और सत्यापित करने की अनुमति है कि ऐसा निर्वाचक किसे अपना वोट देता है। मतदाता के पास यह चुनने का विशेषाधिकार रहता है कि अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को अपना वोट दिखाना है या नहीं।

163

कुलदिप नायर "। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

राज्य परिषद के चुनावों में मतदान की तुलना इसके साथ नहीं की जा सकती है

एक आम चुनाव। आम चुनाव में, मतदाताओं को इस डर के बिना गुप्त तरीके से मतदान करना पड़ता है कि उनके वोट किसी को भी बताए जा सकते हैं या पीड़ित हो सकते हैं। कोई पार्टी संबद्धता नहीं है और इसलिए चुनाव पूरी तरह से मतदाता के पास है। ऐसा तब नहीं होता जब राज्य परिषद के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं क्योंकि निर्वाचक विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो बदले में पार्टी से संबद्ध होते हैं।

दुनिया भर की चुनावी प्रणालियाँ भिन्नताओं पर विचार करती हैं। कोई नहीं।

चुनावी प्रणाली पर मापदंड लागू किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या चुनाव

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है और जिसके लिए सदन के सदस्यों का चयन किया जाना है

प्रासंगिक पहलू। दुनिया भर के लोकतंत्रों में, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को सीधे लोकप्रिय वोट द्वारा चुना जाता है। गोपनीयता आवश्यक है और उस पर जोर दिया जाता है; प्रतिनिधि लोकतंत्र में, विशेष रूप से उच्च सदन के लिए,

पार्टी लाइन पर अपनाए गए चुनाव के अप्रत्यक्ष साधन अच्छी तरह से स्वीकृत प्रथा है।

फजेनबाम द्वारा "ऑस्ट्रेलियाई संवैधानिक कानून" [दूसरा संस्करण] में और

हैंक्स, पृष्ठ 51 पर यह कहा गया है किः

" ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 24 में तीन सिद्धांत शामिल हैं,

प्रतिनिधि लोकतंत्र का सदन मताधिकार की भविष्यवाणी करता हैनिर्वाचकों का, देने में सक्षम एक चुनावी प्रणाली का अस्तित्व

उनके प्रतिनिधियों के चयन और प्रदान करने पर प्रभाव

चयनित प्रतिनिधियों पर विधायी कार्य। का विस्तारमताधिकार "निर्वाचकों के मताधिकार" शीर्षक के तहत आता है।

मतदान के तरीकों सहित असंख्य विवरणों के साथ चुनाव प्रणाली

और प्रतिनिधियों की योग्यताओं के साथ-साथ आनुपातिकविभिन्न रूपों आदि में प्रतिनिधित्व ऐसे मैटर हैं जिनमें नहीं हो सकता है

लोकतंत्र। विधायी कार्यों की विस्तृत श्रृंखला जो एक विधायिका है ऐसे मामलों में अधिकार को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक परिदृश्य का पूरा दायरा शामिल है।

संस्थान, प्रत्येक अनगिनत मामलों में भिन्न हैं। हालांकि, किसी भी बिंदु पर नहीं ऐसे स्पेक्ट्रम के भीतर समय की कोई एकल आवश्यकता मौजूद है तो

प्रतिनिधि के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए आवश्यकलोकतंत्र, ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 24 में प्रावधान है –

लोगों द्वारा सदस्यों का प्रत्यक्ष चयन। विविधताओं का अस्तित्व

निर्वाचन प्रभाग में व्यक्तियों या मतदाताओं की संख्या में

राज्य हाउस ऑफ सुपर कोर्ट रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. के विवरण से अलग नहीं है।

5 एस सी आर।

आनुपातिकता "सदस्यों के चयन" का एक तत्व है जबकियोग्यता 'सदस्यों के चयन' की अवधारणा से अलग है।

ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 30 योग्यताओं को संदर्भित करती है –

निर्वाचकों। ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 24 चयन से संबंधित है।

जिन सदस्यों में आनुपातिकता का तत्व होता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान की प्रणाली है।

(जोर दिया गया)

ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 8, 24, 30 और 128 निम्नानुसार हैंः

" 8. सीनेटरों के निर्वाचकों की योग्यता प्रत्येक राज्य में होगी किजो संविधान द्वारा या संसद द्वारा निर्धारित किया गया है,

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के निर्वाचकों के लिए योग्यता

लेकिन सीनेटरों के चयन में प्रत्येक निर्वाचक केवल एक बार मतदान करेगा।

24. प्रतिनिधि सभा सदस्यों से बनी होगी।

राष्ट्रमंडल के लोगों द्वारा सीधे चुना गया, और संख्या

ऐसे सदस्यों की संख्या, यथासंभव, लगभग दोगुनी होगी। सीनेटरों से।

कई राज्यों में चुने गए सदस्यों की संख्या इस प्रकार होगी –

उनके लोगों की संबंधित संख्या का अनुपात, और, जब तक

संसद अन्यथा प्रावधान करती है, जब भी आवश्यक हो, निर्धारित किया जाए,

निम्नलिखित तरीके सेः

(i) लोगों की संख्या को विभाजित करके कोटा निर्धारित किया जाएगा।

राष्ट्रमंडल के, जैसा कि नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है

राष्ट्रमंडल, सीनेटरों की संख्या से दोगुना; ((ii) प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या होगी –

राज्य के लोगों की संख्या को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है, जैसे

राष्ट्रमंडल के नवीनतम आंकड़ों द्वारा, कोटा द्वारा दिखाया गया है;

और यदि इस तरह के विभाजन पर एक आधे से अधिक शेष है

कोटा, एक बार फिर राज्य में सदस्य चुना जाएगा।

लेकिन इस धारा में कुछ भी होने के बावजूद, पाँच सदस्य

प्रत्येक मूल राज्य में कम से कम चुना जाएगा।

30. जब तक संसद अन्यथा प्रदान नहीं करती है, योग्यताएँ

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के निर्वाचक प्रत्येक में होंगे।

राज्य के कानून द्वारा निर्धारित योग्यता 165 का उल्लेख करें।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

128. इस संविधान में निम्नलिखित के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगाःतरीका –

उसके परिवर्तन के लिए प्रस्तावित कानून एक द्वारा पारित किया जाना चाहिए

संसद के प्रत्येक सदन का पूर्ण बहुमत, और इससे कम नहीं

दो, न ही दोनों सदनों के माध्यम से इसके पारित होने के छह महीने से अधिक समय बाद, प्रस्तावित कानून प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान करने के लिए योग्य मतदाताओं को प्रस्तुत किया जाएगा।

लेकिन अगर कोई भी सदन इस तरह के किसी भी प्रस्तावित कानून को पूर्ण रूप से पारित करता है

बहुमत, और दूसरा सदन इसे अस्वीकार करता है या पारित करने में विफल रहता है या इसे किसी भी संशोधन के साथ पारित करता है जिसके लिए पहला–उल्लिखित सदन सहमत नहीं होगा, और यदि तीन महीने के अंतराल के बाद पहला–उल्लिखित उसी या अगले सत्र में सदन फिर से प्रस्तावित कानून को किसी भी संशोधन के साथ या उसके बिना पूर्ण बहुमत से पारित करता है जो दूसरे सदन द्वारा किया गया है या सहमति व्यक्त की गई है, और ऐसा अन्य सदन इसे अस्वीकार करता है या पारित करने में विफल रहता है या इसे किसी भी संशोधन के साथ पारित करता है जिसमें

प्रथम उल्लिखित सदन सहमत नहीं होगा, गवर्नर जनरल प्रस्तावित कानून प्रस्तुत कर सकता है जैसा कि प्रथम उल्लिखित सदन द्वारा अंतिम रूप से प्रस्तावित किया गया था, और बाद में किसी भी संशोधन के साथ या उसके बिना

दोनों सदनों द्वारा, प्रत्येक राज्य और क्षेत्र के निर्वाचकों को प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए मतदान करने के लिए योग्य बनाया जाता है।

जब कोई प्रस्तावित कानून निर्वाचकों को प्रस्तुत किया जाता है तो मतदान होगा –

संसद द्वारा विहित तरीके से लिया जाए। लेकिन जब तक प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के निर्वाचकों की योग्यता पूरे राष्ट्रमंडल में समान नहीं हो जाती, तब तक प्रस्तावित कानून के पक्ष और विपक्ष में मतदान करने वाले केवल आधे निर्वाचकों की गिनती किसी भी राज्य में की जाएगी जिसमें वयस्क मताधिकार प्रचलित है।

और अगर अधिकांश राज्यों में निर्वाचकों का बहुमत मतदान करता है

प्रस्तावित कानून को मंजूरी दें, और यदि सभी मतदाताओं का बहुमत मतदान करता है

प्रस्तावित कानून को भी मंजूरी दें, इसे महारानी की सहमति के लिए गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व को कम करने वाला कोई विकल्प नहीं

संसद के किसी भी सदन में कोई राज्य, या प्रतिनिधि सभा में किसी राज्य के प्रतिनिधियों की न्यूनतम संख्या, 166 में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, कम करना या अन्यथा बदलना, या किसी भी तरह से संविधान के प्रावधानों को प्रभावित करना।

इसके लिए, कानून तब तक बन जाएगा जब तक कि निर्वाचकों का बहुमत मतदान न करे

उस राज्य में प्रस्तावित कानून को मंजूरी दी जाती है।

इस धारा में, "क्षेत्र" से इस संविधान की धारा एक सौ बाईस में निर्दिष्ट कोई भी क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके संबंध में

सदन में इसके प्रतिनिधित्व की अनुमति देने वाला एक कानून लागू है

प्रतिनिधि "।

धारा 24 काफी हद तक अनुच्छेद 80 (4) और धारा 30 से अनुच्छेद 84 के समान है।

हमारा संविधान।

जुड बनाम के मामले में। मैकियॉन, पृष्ठ 385 पर (1926) 38 सी. एल. आर. 380 में रिपोर्ट किया गया है, यह निम्नानुसार कहा गया हैः

" लोकतंत्र में मताधिकार का विस्तार मौलिक महत्व का विषय है। ऑस्ट्रेलियाई अधिनियम की धारा 24 के पीछे का उद्देश्यसंविधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सीनेट के सदस्यों को सीधे लोकप्रिय वोट द्वारा चुना जाता है न कि अप्रत्यक्ष माध्यमों से, जैसे कि

संसद या विधान सभा या कार्यपालिका द्वारा या

निर्वाचक महाविद्यालय। ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 24 कहती है कि

सीनेट के सदस्यों को लोगों द्वारा चुना जाएगा, जो

जिसका अर्थ है, वोट देने के योग्य लोगों द्वारा। (जोर दिया गया)

राजा वी के मामले में। जेम्स, (1972) 128 सी. एल. आर. 221 में पृष्ठ 229 पर रिपोर्ट किया गया है, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

" तथ्य यह है कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 24 में विश्व 'लोगों' का उपयोग किया गया है–धारा 8 में 'निर्वाचक' शब्द के विपरीत। 30 और 128 से पता चलता है कि संविधान के निर्माताओं ने उस धारा में चुनने का तरीका प्रदान करने के विचार के साथ धारा 24 का मसौदा तैयार किया था

उन लोगों पर जोर देने के बजाय जिन्हें चुनना था। (जोर दिया गया)

न्यू नेशनल पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका बनाम के मामले में दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार और ए. एन. आर. , 1999 (3) एस. ए. 191 में रिपोर्ट किया गया, जिसका मुख्य नोटयह नीचे लिखा हैः

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

167

गोल्डस्टोन जे, मदाला जे. मोक्गोरो जे और सैक्स जे सहमत हैं) कि मतदान का अधिकार अनिवार्य था, और इसके बिना खाली था

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव; बाद वाले ने सामग्री और अर्थ दिया

पूर्व में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार ने महत्व को रेखांकित किया

मतदान के अधिकार का प्रयोग और आवश्यकता है कि प्रत्येक

चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए जिसका अधिकार के तरीके पर प्रभाव पड़ता है।वोट देने के लिए अधिक ठोस सामग्री और वैध रूप से दिया जा सकता है

व्यायाम किया। इनमें से दो निहितार्थ वर्तमान के लिए महत्वपूर्ण थे।

मामलाः ऐसा करने के हकदार प्रत्येक नागरिक को एक से अधिक बार मतदान करना चाहिए।

किसी भी चुनाव और किसी भी व्यक्ति को वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

ऐसा करने के लिए। ये विचलन किस हद तक हुए होंगेचुनाव की निष्पक्षता पर प्रभाव। इसका मतलब था कि नियम

मतदान के अधिकार का प्रयोग आवश्यक था ताकि ये

उचित सुनिश्चित करने के लिए विचलन को समाप्त या प्रतिबंधित किया जा सकता है।

मतदान के अधिकार का कार्यान्वयन। (201 ए/बी–डी पर अनुच्छेद (12)। आयोजित, आगे (प्रति याकूब जे; चास्कल्सन पी, लंगा डी. पी., एकरमैन जे.,

गोल्डस्टोन जे, मदाला जे, मोकगोरो जे और सैक्स जे सहमत हैं; ओ 'रेगन

जे असहमति व्यक्त करते हुए), कि मतदान का अधिकार की धारा 19 (3) द्वारा विचार किया गया है इसलिए संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में मतदान करने का अधिकार था

राष्ट्रीय विधान द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में

जो संविधान द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करता था।

प्रणाली का विवरण संसद पर छोड़ दिया गया था। राष्ट्रीय

निर्वाचन प्रणाली को निर्धारित करने वाला विधान निर्वाचन था

एक्ट करें। (202 सी/डी–डी/ई पर अनुच्छेद (14) "

(जोर दिया गया)

यह दर्शाता है कि 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों' में मतदान करने का अधिकार हमेशा होता है।

राष्ट्रीय विधान द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रणाली की शर्तें। मतदान का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के अधिकार से अपना रंग प्राप्त करता है; कि 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों' के अधिकार के बिना मतदान का अधिकार खाली है। यह एक चुनावी प्रणाली के संदर्भ में 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों' की अवधारणा है जो प्रदान करती है

मतदान के अधिकार की सामग्री और अर्थ '। दूसरे शब्दों में, 'मतदान का अधिकार' स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का एक घटक नहीं है। यह आवश्यक है लेकिन आवश्यक घटक नहीं है।

उपरोक्त मामले में, विवाद यह था कि क्या निर्वाचन अधिनियम ऐसा कर सकता है

मतदान के लिए मतदाता सूची में नामांकन के प्रमाण के रूप में केवल एक विशिष्ट साधन निर्धारित करें। चुनावी अधिनियम के तहत, आई. डी. कार्ड को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. के एकमात्र प्रमाण के रूप में निर्धारित किया गया था।

5 एस सी आर।

मतदाता सूची में प्रवेश करें। इसे चुनौती दी गई थी। आपत्ति को खारिज करते हुए,

बहुमत की ओर से याकूब, जे के माध्यम से संस्थागत न्यायालय ने कहाः

उत्तर यह है कि क्या ये आवश्यकताएँ उल्लंघन का गठन करती हैं मतदान का अधिकार। यह केवल एक संदर्भ में ठीक से किया जा सकता है

विचाराधीन अधिकार की प्रकृति, परिधि और महत्व का विश्लेषण,

अन्य संबंधित संवैधानिक अधिकारों का प्रभाव और महत्व,

इन सभी अधिकारों का अंतर–संबंध, मतदान के अधिकार के प्रभावी प्रयोग की आवश्यकता का महत्व और विनियमन की मात्रा

अधिकार के प्रभावी प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है। [11] संविधान प्रभावी रूप से विधायी के लिए मतदान का अधिकार प्रदान करता है।

सरकार के सभी स्तरों पर निकाय केवल उन दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों पर

जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। इस स्तर पर इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि

यह स्वयं स्पष्ट है और इसे कभी भी अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है इसके महत्व को कम करने की ओर इशारा करते हुए यह कहना पर्याप्त है कि

अधिकार लोकतंत्र के लिए मौलिक है क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है।

यह खाली और बेकार दोनों है। [12] संविधान ने मान्यता देने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है

वोट का प्रयोग करने के अधिकार का महत्व यह प्रदान करके कि सभी

दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव का अधिकार है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी दक्षिण अफ्रीकी नागरिक चाहे उनके

इन चुनावों में उम्र का अधिकार है। मतदान का अधिकार निश्चित रूप से हैस्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के अधिकार के लिए अपरिहार्य और इसके बिना खाली;

उत्तरार्द्ध पूर्व को सामग्री और अर्थ देता है। मुक्त होने का अधिकार

मतदान का अधिकार और यह आवश्यकता कि प्रत्येक चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए जिस तरह से मतदान का अधिकार दिया जा सकता है, उसके निहितार्थ हैं

इस मामले के लिए निहितार्थ सामग्री हैंः प्रत्येक नागरिक को ऐसा करने का अधिकार हैकिसी भी चुनाव में एक से अधिक बार मतदान करना चाहिए; कोई भी व्यक्ति जो हकदार नहीं है

वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन हद तक

विचलन होने से चुनाव की निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ेगा।

इसका मतलब है कि मतदान के अधिकार के प्रयोग का विनियमन 169 है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

आवश्यक है ताकि इन विचलनों को समाप्त या प्रतिबंधित किया जा सके

मतदान के अधिकार का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए।

[13] संविधान मानता है कि इसे विनियमित करना आवश्यक है

मतदान के अधिकार का प्रयोग ताकि मूल सामग्री प्रदान की जा सके

सही है। धारा 1 (डी) एक राष्ट्रीय आम के अस्तित्व पर विचार करती है।मतदाता लुढ़कते हैं। संविधान की धारा 46 (1), 105 (1) और 157 (5) सभी

अभ्यास के विनियमन के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण प्रावधान करें

मतदान का अधिकार। इनका प्रभाव इस प्रकार हैः

(क) राष्ट्रीय, प्रांतीय और नगरपालिका चुनाव संदर्भ में आयोजित किए जाने चाहिए।

एक चुनावी प्रणाली जो राष्ट्रीय विधान द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

(ख) चुनाव प्रणाली का परिणाम, सामान्य रूप से, आनुपातिक होना चाहिए। प्रतिनिधित्व।

(ग) राष्ट्रीय विधानसभा के लिए चुनाव राष्ट्रीय सामान्य मतदाता सूची पर आधारित होना चाहिए।

प्रांत के खंड और नगरपालिका के खंड पर आधारित हो क्रमशः राष्ट्रीय आम मतदाताओं की सूची।

मतदाता सूची का अस्तित्व और उचित कार्यप्रणाली है –

इसलिए एक संवैधानिक आवश्यकता संविधान द्वारा अनिवार्य चुनावों और उनमें से किसी में भी मतदान करने के अधिकार दोनों के लिए अभिन्न है।

[15] आवश्यकता है कि केवल वे व्यक्ति जिनके नाम दिखाई देते हैं

राष्ट्रीय मतदाता सूची में मतदान किया जा सकता है, यह आवश्यकता प्रदान करता है कि दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को अपने वोट का प्रयोग करने से पहले पंजीकरण करना होगा, जो एक संवैधानिक अनिवार्यता है। यह मतदान के अधिकार की एक संवैधानिक आवश्यकता है, न कि अधिकार की सीमा।

[16] पंजीकरण और मतदान की प्रक्रिया को प्रबंधित करने की आवश्यकता है

और यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किया जाता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। चुनाव के प्रबंधन के लिए एक आयोग का निर्माण एक और आवश्यक है, हालांकि इस प्रक्रिया में पर्याप्त घटक नहीं

है। समस्या की व्यापकता को समझने के लिए, लाखों दक्षिण अफ्रीकियों के सभी प्रकार के सबूतों के साथ पंजीकरण केंद्रों या मतदान केंद्रों पर पहुंचने की कल्पना करनी होगी और वे पंजीकरण या मतदान करने के हकदार हैं, केवल पंजीकरण या निर्वाचन अधिकारी से यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एसयूपीपी।

5 एस सी आर।

ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को पंजीकरण करने या मतदान करने का अधिकार है। इस कठिनाई से बचने के लिए निर्वाचन अधिनियम में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं

पंजीकरण, मतदान और संबंधित मामलों से संबंधित जिसमें आम मतदाता सूची में पंजीकरण करने और मतदान करने के लिए मतदाताओं को अपनी पहचान बनाने का तरीका शामिल है।

[17] निर्वाचन अधिनियम के विस्तृत प्रावधान सेवा प्रदान करते हैं

यह सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य कि जो लोग वोट के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं

मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करें, कि इन व्यक्तियों के नाम राष्ट्रीय सामान्य मतदाता सूची में रखे गए हैं, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी प्रकार की आसान और विश्वसनीय पहचान आवश्यक है। यह इस संदर्भ में है किकुछ पहचान दस्तावेजों के उत्पादन के लिए वैधानिक प्रावधान

स्थित होना चाहिए। इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति मतदान के अधिकार के प्रयोग को निरर्थक बना सकती है और इसके लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं चुनाव की निष्पक्षता। इसलिए विधायिका इस तरह का प्रावधान करने के लिए बाध्य है।

जाँच की प्रकृति

[18] अपीलार्थी ने पहचान के उस प्रमाण पर विवाद नहीं किया और

पंजीकरण के लिए नागरिकता, और मतदान के लिए मतदाता सूची में नामांकन का प्रमाण, चुनाव प्रणाली के आवश्यक घटक हैं

संविधान द्वारा विचार किया गया। जिस बात पर विवाद था वह यह था कि क्या निर्वाचन अधिनियम इस तरह के प्रमाण के लिए एकमात्र साधन निर्धारित कर सकता है

पंजीकरण के लिए बार–कोडेड आईडी या टीआरसी और मतदान के लिए बार–कोडेड आईडी या टीआईसी था। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ दो स्तरों पर की गई थीं। सबसे पहले, यह तर्क दिया गया कि उनके चेहरे पर प्रासंगिक प्रावधान और संवैधानिक के संबंध में मूल्यांकन किया गया

मतदान का अधिकार इस अधिकार का उल्लंघन करता है। संविधान में निहित मतदान के अधिकार और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार के साथ विवादित प्रावधानों की चेहरे पर विसंगति का सवाल होना चाहिए

प्रावधान की तर्कसंगतता के संबंध में दोनों को संबोधित किया और

चाहे वह अधिकार का उल्लंघन करता हो। यद्यपि न्यायालय के एक सदस्य द्वारा प्रश्नों के उत्तर में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी

चेहरे की असंगतता पर भरोसा करते हुए, इस तरह के विवाद के समर्थन में कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया था। दूसरा, तर्क यह था कि दस्तावेजी आवश्यकताओं के परिणाम एक इनकार का गठन करते हैं

दक्षिण अफ्रीका के लाखों नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो नहीं थे

बार–कोडित आई. डी. का सत्र। इनमें से कई लोग (लाखों)

में लोगों का), इसलिए यह तर्क दिया गया था, विभिन्न प्रकार के कुलदिप नायर बनाम के लिए मतदान करने में सक्षम नहीं होगा।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

171

परस्पर संबंधित कारणों से। प्रस्तुतियाँ थीं कि विभाग

गृह कार्य (विभाग), जिसकी जिम्मेदारी ली गई है

इन दस्तावेजों को जारी करना, उन्हें प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं थी

समय के साथ, कि दस्तावेजों को प्राप्त करने की लागत एक वास्तविक

बाधा और कि संभावित मतदाता जागरूक नहीं थे, या नहीं थे

सक्षम करने के लिए दस्तावेजी आवश्यकताओं के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक किया गया

उन्हें समय पर दस्तावेजों के लिए आवेदन करना चाहिए। इसमें तर्क दिया गया था कि

संदर्भ कि दक्षिण अफ्रीकी नागरिक जिनके पास पहचान थी

कानून के अनुसार जारी किए गए दस्तावेज जो पहले से लागू थे

1986 के अधिनियम को लागू होने की अनुमति दी जानी चाहिए थीउन्हें।

[19] इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह संसद को तय करना है

वे साधन जिनके द्वारा मतदाताओं को अपनी पहचान बनानी चाहिए। यह बात नहीं है

न्यायालय का कार्य। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संसद खाली है।

यह निर्धारित करने में कि चुनावी योजना किस तरह से होनी है

संरचित। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं

इसे प्रयोग करने की इच्छा रखने वाले नागरिकों के लिए उचित सुरक्षा मूलभूत अधिकार। संवैधानिक बाधाओं में से पहला रखा गया

संसद पर यह है कि दोनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।वह योजना जिसे वह अपनाता है और एक वैध योजना की उपलब्धि

सरकारी उद्देश्य। संसद मूर्खतापूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकती या

मनमाने ढंग से। इस तरह के तर्कसंगत संबंध की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप होगा

यह उपाय असंवैधानिक है। एक आक्षेपकर्ता जो चुनौती देता है

इन आधारों पर चुनावी योजना की स्थापना की जिम्मेदारी है

वैध सरकारी उद्देश्य की अनुपस्थिति, या माप और उस उद्देश्य के बीच तर्कसंगत संबंध।

[20] दूसरी बाधा यह है कि चुनावी योजना नहीं होनी चाहिए।

संविधान के अध्याय 2 में निहित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना।

संविधान। एक बार फिर जिम्मेदारी उस पार्टी की है जो आरोप लगाती है कि

इसे स्थापित करने के अधिकार का उल्लंघन। इस अपील में तर्क

यह है कि निर्वाचन अधिनियम के विवादित प्रावधान एक खंडन का गठन करते हैं दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों की एक बड़ी संख्या को वोट देने का अधिकार।

इस अधिकार के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई गई कोई भी योजना लागू होती है।

इस संभावना के साथ कि कुछ लोग इसका पालन नहीं करेंगे

प्रावधान। लेकिन यह योजना को असंवैधानिक नहीं बनाता है। द.

इस मामले में विचार के लिए जो निर्णायक प्रश्न उत्पन्न होता है, वह है –

निम्नलिखितः यह वैध रूप से कब कहा जा सकता है कि लोगों को वोट देने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक विधायी उपाय के परिणामस्वरूप उस सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है।

5 एस सी आर।

सही? इस प्रश्न का उत्तर देने की प्रक्रिया में एक दल यह आरोप लगाता है कि संसद के एक अधिनियम ने मतदान के अधिकार का उल्लंघन किया है, जो सफल होने के लिए स्थापित करने की आवश्यकता है।

[21] अदालत द्वारा की जाने वाली कवायद में एक मूल्यांकन शामिल होता है

यह अस्वीकार्य है। वर्तमान मामले में जो परिणाम अस्वीकार्य होगा, उसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके सबसे अच्छा निर्धारित किया जा सकता है।संसद को क्या हासिल करना चाहिए। संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग अन्यथा मतदान करने के योग्य होंगे, वे चाहें तो ऐसा कर सकें

मतदान करना और यदि वे मतदान के अधिकार की खोज में उचित कदम उठाते हैं। संसद से इससे अधिक की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह इस प्रकार है कि एक अस्वीकार्य परिणाम सामने आएगा यदि वे जो मतदान करना चाहते हैं और

जो अधिकार की खोज में उचित कदम उठाते हैं, वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं।

[22] उन परिस्थितियों को निर्धारित करना आवश्यक है जिन्हें यह तय करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या विवादित प्रावधान हैं।

मतदान के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसकी दो संभावनाएँ हैं। एक अदालत उस समय की परिस्थितियों के आलोक में मूल्यांकन कर सकती है जब प्रावधानों को अधिनियमित किया गया था, या जो बाद की तारीख में मौजूद हैं जब प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है। यह

न्यायालय ने वैधानिक प्रावधानों की संवैधानिकता के मुद्दे पर एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया है। एक पूर्व–विद्यमान कानून बन जाता है

संविधान के साथ इसकी असंगतता की सीमा तक अमान्य है, जिस क्षण संविधान लागू होता है। यह अप्रासंगिक है कि यह न्यायालय कई वर्षों के बाद ही इसे असंगत घोषित कर सकता है। इसी तरह, एक वैधानिक प्रावधान जो संविधान के बाद पारित किया जाता है

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि इसकी अयोग्यता पर केवल हमला किया जाता है, या हमले का आधार बनने वाली ठोस परिस्थितियाँ इसके अधिनियमन के लंबे समय बाद ही स्पष्ट हो जाती हैं। वैधानिक अयोग्यता के लिए इस उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण के अनुरूप, परिस्थितियाँ जो स्पष्ट हो जाती हैं ऐसा समय जब किसी न्यायालय द्वारा प्रावधान की वैधता पर विचार किया जाता है, आवश्यक रूप से इसकी परिणामी अयोग्यता के प्रश्न के लिए अप्रासंगिक नहीं है। हालांकि, बदलती परिस्थितियों के आधार पर किसी क़ानून की वैधता एक दिन वैध और दूसरे दिन अमान्य नहीं हो सकती है। इसकी वैधता होनी चाहिए।

आमतौर पर यह निर्धारित किया जाता है कि यह किस तारीख को पारित किया गया था।

फिर भी, कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

173

एक अधिनियम का कार्यान्वयन जो संवैधानिक जांच को पारित करता है

इसके अधिनियमन का समय, एक संवैधानिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है

शिकायत, यदि, परिस्थितियों के परिणामस्वरूप जो स्पष्ट हो जाती हैं

बाद में, इसके कार्यान्वयन से संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। में।

ऐसी शिकायत की वैधता का आकलन करना, यह आवश्यक हो जाता है कि –यह निर्धारित करें कि क्या अधिकार के उल्लंघन का निकटवर्ती कारण स्वयं वैधानिक प्रावधान है, या क्या अधिकार का उल्लंघन है।

अधिकार को किसी अन्य कारण से प्रेरित किया गया है, जैसे कि किसी सरकारी एजेंसी की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफलता। यदि यह स्थापित किया जाता है कि उल्लंघन का निकटवर्ती कारण, परिस्थितियों के आलोक में, निम्नलिखित वैधानिक प्रावधान में निहित हैविचार करने पर, वह प्रावधान अधिकार का उल्लंघन करता है। यह असंवैधानिकता के प्रति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से प्रस्थान नहीं है। यह केवल एक

इस तथ्य की मान्यता कि किसी वैधानिक प्रावधान में संवैधानिक दोष हमेशा इसके अधिनियमन के समय आसानी से स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन बाद में तभी सामने आ सकता है जब कोई ठोस मामला निर्णय के लिए खुद को प्रस्तुत करता है।

[23] यह तय करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण लागू करना आवश्यक है कि क्या

संसद का अधिनियम, जो वर्तमान मामले में चुनौती दी गई चुनावी योजना के लिए प्रावधान करता है, वैध है। संसद उस तंत्र, तंत्र या प्रक्रिया के लिए प्रावधान करने के लिए बाध्य है जो यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में यथोचित रूप से सक्षम है कि सभी व्यक्ति जो मतदान करना चाहते हैं, और जो उस अधिकार की खोज में उचित कदम उठाते हैं, वे ऐसा करने में सक्षम हैं। इसलिए, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि यह अधिनियम मतदान के अधिकार का उल्लंघन करेगा यदि यह दिखाया जाता है कि, उपाय को अपनाने की तारीख पर, इसका संभावित परिणाम यह होगा कि जो लोग मतदान करना चाहते हैं, वे मतदान करेंगे।ऐसा करने में सक्षम नहीं हुए हैं, भले ही उन्होंने अधिकार की खोज में उचित रूप से काम किया हो। कोई भी योजना जो यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में यथोचित रूप से सक्षम होने के लिए पर्याप्त रूप से लचीली नहीं है कि जो लोग मतदान करना चाहते हैं वे ऐसा करने में सक्षम होंगे यदि वे अधिकार की खोज में उचित रूप से कार्य करते हैं, तो अधिकार का उल्लंघन करने की क्षमता है। यह संभावना तभी स्पष्ट होती है जब कोई ठोस मामला अदालत के समक्ष लाया जाता है। अपीलार्थी

पर यह स्थापित करने की जिम्मेदारी है कि प्रदान की गई मशीनरी या प्रक्रिया उचित रूप से सक्षम नहीं है

उस उद्देश्य को प्राप्त करना। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है, यह अच्छी तरह से हो सकता है कि अधिकार का उल्लंघन या धमकी दी जा सकती है क्योंकि एक सरकारी एजेंसी में कुशलता से प्रदर्शन नहीं करती है कानून का कार्यान्वयन। इसका मतलब यह नहीं होगा कि क़ानून अमान्य है। इसका उपाय कहीं और है।

अपीलार्थी को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] प्रस्ताव में विफल होना चाहिए। 5 एस सी आर।

आयोग द्वारा स्थापित किया गया। हालाँकि, यह मामला अलग है, क्योंकि कहा जाता है कि कथित मताधिकार का हनन क़ानून की शर्तों से होता है, न कि आरोपित एजेंसी के कार्यों या चूक से।कानून को लागू करने के साथ।

[24] ओ 'रेगन जे ने अपने असहमत निर्णय में मापा

इसके संबंध में वैधानिक प्रावधान के उद्देश्य का महत्व प्रभाव, और सवाल पूछता है कि क्या चुनावी योजना है

उचित है। वह यह निष्कर्ष निकालती है कि यह योजना उचित नहीं है, और इस कारण से, यह मानते हुए कि निर्वाचन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान संविधान के साथ असंगत हैं। मेरे विचार में यह समस्या के लिए सही दृष्टिकोण नहीं है। वैधानिक प्रावधानों की तर्कसंगतता के बारे में निर्णय आमतौर पर संसद की अनन्य क्षमता के भीतर होते हैं। यह सिद्धांत के लिए मौलिक है

लोकतांत्रिक समाज में शक्तियों का पृथक्करण और न्यायालयों की भूमिका। न्यायालय संसद के अधिनियमों के प्रावधानों की इस आधार पर समीक्षा नहीं करते हैं कि वे अनुचित हैं। वे ऐसा तभी करेंगे जब वे संतुष्ट होंगे कि कानून तर्कसंगत रूप से किसी वैध कानून से जुड़ा नहीं है।

सरकारी उद्देश्य। ऐसी परिस्थितियों में, समीक्षा सक्षम है क्योंकि कानून मनमाना है। मनमानी के साथ असंगत है

कानून का शासन जो संविधान का मूल मूल्य है। यह निर्धारित करना संसद की शक्ति के भीतर था कि चुनाव के लिए कौन सी योजना अपनाई जानी चाहिए। यदि योजना को परिभाषित करने वाला कानून तर्कसंगत है, तो संसद के अधिनियम को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती हैः

" अनुचितता "। तर्कसंगतता तभी प्रासंगिक होगी जब यह स्थापित किया जाए कि यह योजना, हालांकि तर्कसंगत है, नागरिकों के मतदान के अधिकार का उल्लंघन करने का प्रभाव डालती है। तब सवाल उठेगा कि क्या संविधान की धारा 36 के प्रावधानों के तहत सीमा उचित है, और यह केवल इस धारा 36 की जांच के हिस्से के रूप में है कि तर्कसंगतता प्रासंगिक हो जाती है। यह इस प्रकार है कि जांच के उस स्तर पर ही तर्कसंगतता का सवाल होना चाहिए।

विचार किया। इसलिए तय किया जाने वाला पहला सवाल यह है कि क्या निर्वाचन अधिनियम द्वारा निर्धारित योजना तर्कसंगत है।

वैधानिक प्रावधानों की तर्कसंगतता कुलदिप नायर v.

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

175

[25] यह निर्धारित करना, मेरे विचार में, सुविधाजनक है कि क्या

विवादित प्रावधान तर्कसंगत रूप से एक वैध सरकार से संबंधित हैं।

संविधान के संबंध में मुद्दे के प्रावधानों का विश्लेषण किया गया हैतर्कसंगतता की कमी दिखाई गई; दूसरा यह है कि क्या ये प्रावधान हैं

कुछ के प्रकाश में मनमाना या मज़बूत कहा जा सकता है

कानून को अपनाने की तारीख तक मौजूद परिस्थितियाँ।

प्रासंगिक परिस्थितियों का प्रभाव

[28] चेहरे के विश्लेषण से पता चलता है कि वैधानिक प्रावधान

विवादित दस्तावेजी आवश्यकताओं पर जोर देना तर्कसंगत रूप से संबंधित है

प्रभावी बनाने के वैध सरकारी उद्देश्य के लिए मतदान के अधिकार का प्रयोग। अब मैं जाँच करूँगा कि क्या विवादित

उपायों को मनमाना या मनमौजी कहा जा सकता हैपरिस्थितियाँ जो अपीलार्थी के अनुसार प्रासंगिक थीं। ”

इसलिए, यह स्पष्ट है कि मतदान का अधिकार एक अवधारणा है जिसे

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्राप्ति की अवधारणा को बढ़ावा देना। की प्रकृति

चुनाव, अर्थात्, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मतदान के अधिकार की अवधारणा को नियंत्रित करते हैं। जहाँ चुनाव सीधे होते हैं, वहाँ गुप्त मतदान पर जोर दिया जाता है। जहाँ चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं और जहाँ सदस्यों को अप्रत्यक्ष माध्यमों से चुना जाता है, जैसे कि

संसद या विधान सभा या कार्यपालिका द्वारा, फिर खुले मतपत्र को मतदान की चुनावी प्रणाली के तहत एक अवधारणा के रूप में पेश किया जा सकता है। प्रत्यक्ष चुनावों के मामले में, सदस्यों को सीधे लोकप्रिय वोट द्वारा चुना जाता है जो अप्रत्यक्ष चुनावों के मामले में नहीं होता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि खुले मतपत्र की अवधारणा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्राप्ति को विफल कर देगी। वर्तमान मामले में, मतदान के अधिकार से इनकार करने का सवाल स्वयं उठाया जाएगा।

केवल विधान सभा के सदस्य द्वारा पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि को अपना वोट दिखाने से इनकार करने पर। यदि कोई विधायक किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में मतदान करता है जिसे वह उचित समझता है और अधिकृत व्यक्ति को अपना मत दिखाता है।

उस राजनीतिक दल का प्रतिनिधि जिससे वह संबंधित है, नियम नहीं

इस तरह के मतदान को रद्द करने पर विचार करें।

यह नहीं भुलाया जा सकता कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व आवश्यक है।

हमारे संसदीय लोकतंत्र की विशेषता और यह कि यह संसद के लिए चिंता का विषय हो सकता है यदि यह पाया जाए कि मतदाता विवेकपूर्ण मतदान की आड़ में क्रॉस वोटिंग का सहारा ले रहे थे, मतदान की गोपनीयता के नाम पर पार्टी अनुशासन का उल्लंघन कर रहे थे। यह गलती करने वाले विधायकों पर पार्टी के अनुशासन को कमजोर कर देगा। राजनीतिक दल हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त हैं।

देश और पार्टी अनुशासन के संरक्षण को एक आवश्यक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. पी. के रूप में पेश किया जा सकता है।

5 एस सी आर।

176

अप्रत्यक्ष चुनावों के मामले में चुनावों की शुद्धता की विशेषता।

संसदीय लोकतंत्र और बहुदलीय व्यवस्था एक अंतर्निहित अंग हैं।

भारतीय संविधान की मूल संरचना। यह राजनीतिक दल हैं जो स्थापित करते हैं

एक चुनाव में उम्मीदवार जो मुख्य रूप से राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के रूप में चुने जाते हैं। जिस संदर्भ में आम चुनाव होते हैं, चुनाव प्रणाली की शुद्धता बनाए रखने के लिए मतदान की गोपनीयता आवश्यक है।

प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताना है कि उसने कैसे मतदान किया है। लेकिन यहाँ हम एक ऐसे मतदाता के बारे में चिंतित हैं जो

एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुना जाता है। इस दृष्टिकोण से, संदर्भ पूरी तरह सेपरिवर्तन होता है।

यह कि 'निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व' की अवधारणा 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' से अलग है, के मामले में स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाम। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति और अन्य। , (2003) आई. एस. ए. 495 में प्रतिवेदित, जहाँ उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न थाः क्या 'फ्लोर क्रॉसिंग' संविधान के लिए मौलिक था

दक्षिण अफ्रीका। इस निर्णय में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा

निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैंः

" 24. संविधान की धारा 1 (डी) के संदर्भ में "लोकतांत्रिक सरकार की एक बहुदलीय प्रणाली" वाक्यांश का अर्थ पहला प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से एक–पक्षीय राज्य, या सरकार की एक प्रणाली को बाहर करता है जिसमें सीमित संख्या में दल होते हैं।

25. वाक्यांश अनुच्छेद का शब्द नहीं है। हमें नहीं संदर्भित किया गया थाराजनीति विज्ञान या दक्षिण अफ्रीकी संविधान पर अधिकार जो

इन शब्दों का एक अर्थ प्रदान करता है। न ही दक्षिण अफ्रीकी संविधान पर टिप्पणियों से कोई सहायता प्राप्त की जा सकती है। अधिकांश लेखक

ऐसा प्रतीत होता है कि वाक्यांश का अर्थ स्वयंसिद्ध है और इसके लिए शब्दों से परे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

26. एक बहुदलीय लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था पर विचार करता है जिसमें

विभिन्न राजनीतिक समूहों को संगठित करने, बढ़ावा देने की अनुमति है।

सार्वजनिक बहस के माध्यम से उनके विचार और स्वतंत्र और निष्पक्ष में भाग लें

चुनाव। ये गतिविधियाँ उचित विनियमन के अधीन हो सकती हैं।

एक खुले और लोकतांत्रिक समाज के साथ संगत। कानून जो चलते हैं इसके अलावा, और जो बहुदलीय लोकतंत्र को कमजोर करता है, वह अमान्य होगा। इसलिए यह तय करना होगा कि क्या यह प्रभाव 177 है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. क्यू. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

विवादित कानून।

27. आवेदकों का तर्क है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली संविधान का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य है दलबदल का प्रावधान इस प्रणाली और किसी भी हस्तक्षेप की रक्षा के लिए है।

इन प्रावधानों के साथ धारा 1 (डी) द्वारा अनुध्यात लोकतांत्रिक सरकार की बहुदलीय प्रणाली में हस्तक्षेप है। संविधान।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

28. इस विवाद के समर्थन में आवेदकों द्वारा संवैधानिक सिद्धांत VIII पर निर्भरता रखी गई थी जो उन सिद्धांतों में से एक था जिसका संविधान को पालन करना था। संवैधानिक सिद्धांत VIII

प्रदान करता हैः" बहु–दलीय लोकतंत्र, नियमित चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाने वाली प्रतिनिधि सरकार होगी।

मतदाता सूची, और, सामान्य रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

29. महत्वपूर्ण रूप से, हालांकि, संविधान की धारा 1 (डी) में अंतिम को छोड़कर, संवैधानिक सिद्धांत VIII के सभी प्रावधान शामिल हैं।

आवश्यकता जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व को संदर्भित करती है। यदि यह विचार किया गया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में से एक होना चाहिए

यह समझना मुश्किल है कि उन शब्दों को धारा 1 (डी) से क्यों हटा दिया गया था। पाठ्य रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है

संस्थापक मूल्यों में शामिल नहीं। न ही, हमारे विचार में, इसे बहुदलीय लोकतंत्र की आवश्यकता के रूप में निहित किया जा सकता है। बहुदलीय लोकतंत्र की कई प्रणालियाँ हैं जिनमें चुनाव प्रणाली नहीं है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर।

30. हालाँकि, आवेदकों का तर्क है कि दलबदल विरोधी प्रावधान आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित चुनावी प्रणाली का एक अनिवार्य घटक है। यह, इसलिए तर्क जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि चुनाव के परिणाम उन व्यक्तियों के दलबदल से प्रभावित न हों जिन्होंने केवल पार्टी सूची में अपनी स्थिति के कारण विधायिका में अपनी सीटें हासिल कीं। यह पार्टी है, न कि सदस्य, जो सीटों का हकदार है, और यदि किसी सदस्य को दलबदल करने की अनुमति दी जाती है, तो

उस आनुपातिकता को विकृत करता है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को डिज़ाइन किया गया था।

31. मतदाताओं की अपेक्षा और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए सदस्यों के आचरण के बीच तनाव है।

एक बार निर्वाचित सदस्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

विधायिका के सदस्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और आम तौर पर मतदाताओं द्वारा वापस बुलाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं यदि लिए गए निर्णय इसके विपरीत हैं

चुनाव अभियान के दौरान की गई प्रतिबद्धताएँ।

32. अक्सर कहा जाता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की उस पार्टी की इच्छा के विपरीत निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जिससे वे संबंधित हैं, लोकतंत्र का एक अनिवार्य तत्व है। वास्तव में, इस तरह के तर्क को प्रमाणन कार्यवाही के समय इस न्यायालय को संबोधित किया गया था

जहां संविधान की अनुसूची 6 में शामिल दलबदल से पहले के संक्रमणकालीन प्रावधान पर आपत्ति जताई गई थी। यह तर्क दिया गया था कि विधायकों को उनके दलों के अधिकार में प्रस्तुत करना "जवाबदेह, उत्तरदायी, खुले, प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक" के लिए शत्रुतापूर्ण था

सरकार; जो सार्वभौमिक रूप से अधिकारों और स्वतंत्रताओं को स्वीकार करती है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता

राजनीतिक विकल्प और सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने के अधिकार और निर्वाचित होने पर पद धारण करने के अधिकार को कम किया जाता है; और यह कि दलबदल विरोधी खंड 'प्रतिनिधि सरकार' के सिद्धांतों के खिलाफ है।

प्रतिक्रियाशीलता और खुलापन और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व। 33. इस न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दियाः

" आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक सूची प्रणाली के तहत, यह वे दल हैं जिनके लिए मतदाता जांच करते हैं, और वे दल जो मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। एक पार्टी जो अपने घोषणापत्र को एक तरह से छोड़ देती है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता है

मतदाता संभवतः अगले चुनाव में हार जाएंगे। ऐसी प्रणाली में दलबदल विरोधी खंड यह सुनिश्चित करने के लिए अनुचित नहीं है कि मतदाताओं की इच्छा का सम्मान किया जाए। एक व्यक्तिगत सदस्य रहता है।

व्यक्तिगत विवेक के आदेशों का पालन करने के लिए स्वतंत्र। यह लोकतंत्र के साथ असंगत नहीं है।

..... एक दलबदल–पूर्व खंड एक राजनीतिक दल को रोकने में सक्षम बनाता है इसके निर्वाचित सदस्यों का दलबदल, इस प्रकार यह सुनिश्चित करना कि वे उस पार्टी का समर्थन करना जारी रखें जिसके तत्वावधान में वे चुने गए थे। यह सत्ता में बैठे दलों को छोटे दलों के सदस्यों को दलबदल करने के लिए लुभाने से भी रोकता है

उस पार्टी से जिसकी सूची में वे सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने के लिए चुने गए थे। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो यह सत्तारूढ़ दल को एक विशेष बहुमत प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है जिसे वह अन्यथा इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हो सकता है और जो मतदाताओं के विचारों का प्रतिबिंब नहीं है। इस आपत्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है। 34. हालाँकि, इससे यह नहीं पता चलता है कि एक आनुपातिक कुलदिप नायर v।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

179

पूर्व–दलबदल खंड के बिना प्रतिनिधित्व प्रणाली असंगत है।

लोकतंत्र के साथ। ऐसा हो सकता है कि मतदाताओं के बीच एक करीबी संबंध हो।

और आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी प्रणालियों में पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र आधारित निर्वाचन प्रणालियों में मामला हो, और इसके लिए

कारण दलबदल के खिलाफ तर्क अधिक मजबूत हो सकता है

निर्वाचन क्षेत्र आधारित चुनावों में मामला। लेकिन निर्वाचन क्षेत्र आधारित चुनावों में भी पार्टी की सदस्यता और पार्टी के बीच घनिष्ठ संबंध है।

विधायिका के लिए चुनाव और एक सदस्य जो दूसरे दल में शामिल हो जाता है

एक विधायिका के जीवन के दौरान इस आरोप के लिए समान रूप से खुला है कि उन्होंने मतदाताओं को धोखा नहीं दिया है।

47. तथ्य यह है कि एक विशेष प्रणाली विशेष दलों के नुकसान के लिए काम करती है इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंवैधानिक है। के लिए

उदाहरण के लिए, निर्वाचन क्षेत्र आधारित चुनाव प्रणाली की शुरुआत छोटे दलों के पूर्वाग्रह के लिए काम कर सकती है, फिर भी यह शायद ही हो सकता हैसुझाव दिया कि ऐसी प्रणाली लोकतंत्र के साथ असंगत है। अगर

दलबदल की अनुमति है, कानून का विवरण संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए, बशर्ते कि प्रावधान हमेशा संविधान के साथ असंगत न हों। केवल यह तथ्य कि संसद निर्णय लेती है कि किसी दल से दलबदल के लिए 10 प्रतिशत की सीमा आवश्यक है, हमारे विचार में संविधान के साथ असंगत नहीं है।

:

कानून का शासन

55. हमारे संविधान में कानून को एक वैध सरकारी उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से संबंधित होने की आवश्यकता है। यदि नहीं, तो यह नियम के साथ असंगत है

कानून और अमान्य।

68. फार्मास्युटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स के मामले में यह बताया गया था कि जनता के अभ्यास के लिए न्यूनतम आवश्यकता के रूप में तर्कसंगतता

कार्यात्मक, और जब तक कार्यात्मक का निर्णय, वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाता है, तर्कसंगत है, तब तक अदालत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।केवल इसलिए कि यह इससे असहमत है या यह मानता है कि शक्ति का प्रयोग अनुचित तरीके से किया गया था।

1 180

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

यह भी लागू होता है और संभवतः व्यायाम के लिए अधिक बल के साथ

संविधान द्वारा निहित शक्तियों की संसद, जिनमें शामिल हैं –

संविधान में संशोधन करने की शक्ति।

71. संस्थापक मूल्यों और कानून के शासन के संबंध में अंतिम मुद्दा

यह रिक्त सीटों को भरने से संबंधित है। पार्टी सूचियों पर चुने गए सदस्य पार्टी अनुशासन के अधीन हैं और उनसे निष्कासित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं

अनुशासन के उल्लंघन के लिए पार्टी। अगर ऐसा होता है तो वे बंद हो जाते हैं

विधायिका के सदस्य।

72. दलबदल करने वाले सदस्य जो दूसरी पार्टी बनाते हैं या उसमें शामिल होते हैं, वे विषय बन जाते हैं

उस पक्ष के अनुशासन के लिए और निष्कासन के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं

अनुशासन का उल्लंघन। इस प्रकार, यदि एक दोषपूर्ण सदस्य बाद में है

उसकी नई पार्टी से निष्कासित किया जाता है, या यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो खाली सीटों को कैसे भरा जाए, इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

75. इसके परिणामस्वरूप चार अधिनियमों पर इस आधार पर आपत्ति की गई कि

वे संस्थापक मूल्यों और अधिकारों के विधेयक के साथ असंगत हैं।

असफल होना चाहिए। इससे यह विचार करना अनावश्यक हो जाता है कि क्या ऐसा है।प्रावधानों को अनुमान द्वारा संशोधित किया जा सकता है, या क्या यह आवश्यक है

यदि किसी संशोधन का उद्देश्य वह है तो धारा 74 (5) के नोटिसों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना और विशेष रूप से यह बताना कि धारा 74 (1) या 74 (2) के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, ऐसे लोगों पर लागू होते हैं।

संशोधन "।

निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व के बीच की विशिष्टता क्या है? और एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' यह है कि

सूची प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मामले में, सदस्यों को चुना जाता हैपार्टी लाइनें। वे पार्टी अनुशासन के अधीन हैं। उन्हें निष्कासित किया जा सकता है।

अनुशासन के उल्लंघन के लिए। इसलिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को प्रभावी बनाने के लिए, संसद 'ओपन बैलेट' का सुझाव दे सकती है। ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव 'खुले मतपत्र' से हार जाएंगे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्वाचन क्षेत्र आधारित चुनाव में लोग ही मतदान करते हैं

(ऊपर)। निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व में 'गोपनीयता' आधार है जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मामले में

आधार 'खुला मतपत्र' हो सकता है और यह 'स्वतंत्र और स्वतंत्र' की अवधारणा का उल्लंघन नहीं करेगा।

निष्पक्ष चुनाव 'कौन सी अवधारणा लोकतंत्र के स्तंभों में से एक है।

इसके अलावा, सदन के अंदर एक प्रस्ताव पर प्रत्येक वोट एक खुले मतपत्र द्वारा होता है।

कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

181

एक अध्यक्ष, लोक सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव और

राज्य परिषद का उपाध्यक्ष एक प्रभाग द्वारा होता है जो एक

खुले मतदान की प्रणाली। इस संबंध में लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 7, 8, 364, 365, 367, 367 ए, 367 एए और 367 बी और राज्य परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 7, 252, 253 और 254 का संदर्भ दिया जा सकता है।

उपरोक्त दृष्टिकोण में, पर आक्षेपित संशोधन का औचित्य

यह तर्क कि खुले मतदान से पार्टी नामांकन के आधार पर किसी विशेष राज्य की विधानसभा के लिए चुने गए मतदाताओं द्वारा क्रॉस वोटिंग की बुराई समाप्त हो जाती है, को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतिकरण ध्यान में रखने में विफल रहता है।

प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव के बीच अंतर। यह किसी विशेष चुनाव में एक व्यक्तिगत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव का मामला नहीं है। यह विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव का मामला है जो संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित और पदोन्नत होने के कारण विधान सभा के लिए अपनी सदस्यता के लिए चुने गए हैं।

यह तर्क कि चुनाव में मतदाता की अभिव्यक्ति का अधिकार

क्योंकि राज्य परिषद खुले मतपत्र से प्रभावित है, यह मान्य नहीं है, क्योंकि एक निर्वाचित विधायक को एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए सदन की सदस्यता से किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह सबसे अधिक उस राजनीतिक दल से कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है जिससे वह संबंधित है। जिस राजनीतिक दल के टिकट पर वह विधायक चुने गए थे, उसके सदस्य होने के नाते, आम तौर पर उनसे पार्टी के निर्देशों का पालन करने की उम्मीद की जाती है, जो हमारे लोकतंत्र की बुनियादी राजनीतिक इकाइयों में से एक है।

चूंकि संशोधन से बचने की आवश्यकता के आधार पर लाया गया है

क्रॉस वोटिंग और भ्रष्टाचार की बुराइयों को मिटाने के साथ-साथ हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की अखंडता को बनाए रखने के लिए, इसे राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत एक उचित प्रतिबंध के रूप में भी उचित ठहराया जा सकता है, इस धारणा पर कि इस तरह के चुनाव में मतदान करना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बराबर है।

भले ही हम एन. पी. पोन्नुस्वामी में लिए गए दृष्टिकोण को दरकिनार कर दें और

इस धारणा पर आगे बढ़ते हुए कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के मामले में लिए गए दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्यों की परिषद के चुनाव में मतदान का तरीका निश्चित रूप से क़ानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है। संविधान में 182 नहीं है

बशर्ते कि राज्य परिषद के चुनाव के लिए मतदान गुप्त रूप से किया जाएगामतदान करें। अब तक राज्य परिषद के चुनाव के लिए मतदान संसद द्वारा बनाए गए कानून के कारण गुप्त मतदान द्वारा किया जाता था। यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के चुनावों में गुप्त मतदान एक संवैधानिक अधिकार है।

संशोधन द्वारा मतदान का अधिकार नहीं खोया जाता है। संबंधित राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य पूरी तरह से हकदार है।

राज्यों की परिषद के चुनाव में मतदान करना। विवादित संशोधन के कारण जो एकमात्र बदलाव आया है, वह यह है कि उसे रास्ता बताना होगा

उन्होंने अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को वोट दिया है। संसद इसे भ्रष्टाचार को रोकने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और इससे भी महत्वपूर्ण रूप से चुनावों की शुद्धता बनाए रखने के लिए केवल एक नियामक विधि के रूप में उचित ठहराएगी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मतपत्र की गोपनीयता और चुनावों की शुद्धता सामान्य रूप से सह–अस्तित्व में होनी चाहिए। लेकिन राज्य परिषद के मामले में, संसद ने अपने विवेक से यह उचित माना है कि चुनाव की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अप्रत्यक्ष चुनाव में मतपत्र की गोपनीयता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

जिस प्रक्रिया के द्वारा चुनाव आयोजित किया जाना है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उद्देश्य। संसद द्वारा यह नोट किया गया है कि राज्य परिषद के चुनावों में, राजनीतिक दलों की ओर से चुने गए सदस्य गुप्त मतपत्र और क्रॉस वोट का दुरुपयोग करते हैं। यह बताया गया था कि कुछ सदस्य विचार के लिए क्रॉस वोटिंग में शामिल होते हैं। संसद का यह कर्तव्य है कि वह इस तरह के दुर्व्यवहार और कदाचार का संज्ञान ले और इसके लिए उपचारात्मक उपाय करे। संपार्श्विक और भ्रष्ट विचारों के लिए राजनीतिक दलों के अनुशासन का उल्लंघन बहुदलीय लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को दूर करता है। इसलिए, संसद ने अनिवार्य रूप से एक खुले मतदान का प्रावधान करने के लिए कानून बनाया। बहुदलीय लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का एक आवश्यक हिस्सा है। संसदीय लोकतंत्र और बहुदलीय प्रणाली में लोगों के विश्वास को बहाल करने के उद्देश्य से कानून में संशोधन को दोष नहीं दिया जा सकता है।

गोपनीयता का सिद्धांत एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है। विधायी

संशोधन को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि एक अलग या बेहतर दृष्टिकोण संभव है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधान को चुनौती देने का निर्णय किसी अन्य दृष्टिकोण के आधार पर नहीं किया जा सकता है जो अधिक उचित या स्वीकार्य हो सकता है। विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर एक मामला बाद वाले के विवेक और विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए जब तक कि यह किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए मतपत्र की गोपनीयता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।चुनाव। हालाँकि, उच्च सिद्धांत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और शुद्धता कुलदिप नायर बनाम है। चुनावों से। अगर गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाती है तो सूरज की रोशनी और पारदर्शिता में इसे हटाने की क्षमता होती है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि विधान एक विधायी नीति के अनुसार कि पारदर्शिता बुराई को समाप्त कर देगी उम्मीद है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बड़े उद्देश्य की पूर्ति होगी। हम इंदिरा के मामले में इस न्यायालय के निम्नलिखित विचारों को याद करना चाहेंगे।नेहरू गांधी बनाम. राज नारायणः –संविधान अनुपलब्ध है। यदि सरकार का लोकतांत्रिक रूपहमारे संविधान की आधारशिला है, मूल विशेषता व्यापक हैआवश्यकताएँ माँग कर सकती हैं लेकिन इसलिए नहीं कि केवल एक के भूसे को छोड़ दें लोकप्रिय नियम। लोकतंत्र एक हठधर्मी सिद्धांत नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता हैसुझाव है कि एक नियम सत्तावादी है क्योंकि कुछ अधिकार और सुरक्षा उपाय हैंसंक्षिप्त या निरस्त या क्योंकि, एक संवैधानिक के परिणामस्वरूपसंशोधन, सरकार का रूप सख्ती से अनुरूप नहीं हैअवधारणा की कुछ शास्त्रीय परिभाषा। राष्ट्र की आवश्यकताएँगंभीर त्याग का आह्वान करें, हालांकि शासकों की जरूरतों को कभी नहीं औरदेश के मौलिक कानून में विकासवादी परिवर्तन नहीं होते हैं अनिवार्य रूप से अपनी सरकार के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देता है। क्या करता है? कानून जीवित है, अगर यह जीवित जरूरतों के लिए मृत है? .....

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, हम द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद में योग्यता नहीं पाते हैंराज्य परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों की सीटों को भरने के लिए चुनाव की "खुली मतपत्र" प्रणाली के विवादित संशोधन के माध्यम से परिचय की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने के लिए याचिकाकर्ता।

अनुच्छेद 80 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि परिषद में सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होंगे। अनुच्छेद 80 (4) में यह प्रावधान किया गया है किएकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से प्रतिनिधित्व। इसके अलावा, संविधान की विधायी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं हैइस संबंध में संसद। 1 की धारा 3,59,94 और 128 में संशोधनलोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 40) द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को निम्नलिखित अभ्यास में बनाया गया हैःअनुच्छेद 246 के तहत संसद को प्रदत्त शक्तियां84 और संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की 327 और प्रविष्टि 72।

विवादित संशोधन किसी भी संविधान का उल्लंघन नहीं करता हैप्रावधान। इसे संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला नहीं पाया जा सकता है। यह विवादित नहीं है कि संसद के पास विधायी क्षमता है संशोधन अधिनियम को लागू करना। इन तथ्यों और परिस्थितियों में, विवादित कानून को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है।

संविधान की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली सभी रिट याचिकाएं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम No.40) के माध्यम से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में लाए गए संशोधनों को गुणदोष से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है। अंतरिम आदेश जारी हैंखाली कर दिया। सभी पक्षों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

लिखित याचिका खारिज की गई।

एसकेएस.